

Kumar Edutainment Presents

Current Affairs Magazine

OCT 2025

महत्वपूर्ण घटनाक्रम

- इशिबा ने क्यों दिया इस्तीफा? जापान में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण
- धनखड़ के इस्तीफे से लेकर राधाकृष्णन की जीत तक: जाने विस्तार से
- यूएनएससी ने लेबनान में शांति मिशन समाप्त करने का प्रस्ताव रखा
- भारत के जीएसटी में बदलाव: नई पीढ़ी के टैक्स सुधारों की व्याख्या
- नेपाल, लिथुआनिया, थाईलैंड, फ्रांस और गुयाना ने नए प्रमुख चुने
- ग्लोबल पीस इंडेक्स, नारी रिपोर्ट और एनआईआरएफ रैंकिंग जारी
- आरटीई एक्ट एवं अल्पसंख्यक संस्थान: मुख्य बिंदुओं का विवरण
- पंजाब में बार-बार बाढ़ क्यों आती है? 2025 की बाढ़ के कारण
- एजुकेटेड गर्ल्स एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला
- रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की



विशेषता:

- लघु लेख
- प्रश्न बैंक
- क्विक बाइट्स
- इन्फोग्राफिक्स

सी पी
राधाकृष्णन

मुकेश कुमार



8882388888



Kumar Edutainment



your_kumar_sir



kumarsias.com

कुमार एडुटेन्मेंट

सभी कॉपीराइट सुरक्षित

पता: 7 जवाहर नगर, खंदारी, आगरा, उत्तर प्रदेश

दूरभाष: 8882388888

मेल: Kumariasacademy@gmail.com

वेब: <https://kumarsias.com/index-2.html>



अस्वीकरण

यह पुस्तक शैक्षिक और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। पुस्तक के लेखक (ओं) ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित देखभाल की है कि पुस्तक की सामग्री किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के किसी भी मौजूदा कॉपीराइट या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। घटना में लेखक किसी भी स्रोत को ट्रैक करने में असमर्थ है / और यदि कोई कॉपीराइट अनजाने में उल्लंघन किया गया है, तो कृपया प्रकाशक को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए लिखित रूप में सूचित करें।

इस प्रकाशन में त्रुटियों या चूक से बचने का हर संभव प्रयास किया गया है। इसके बावजूद, त्रुटियों में कमी हो सकती है। विख्यात किसी भी गलती, त्रुटि या विसंगति को हमारे ध्यान में लाया जा सकता है जिसे अगले संस्करण में ध्यान रखा जाएगा। यह अधिसूचित किया गया है कि प्रकाशक या लेखक या विक्रेता किसी भी प्रकार के, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार की किसी भी क्षति या कार्रवाई के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी सदेह से बचने के लिए पाठक को मूल प्रकाशन या सूचनाओं के साथ प्रकाशन के सभी तथ्यों, कानून और सामग्री को पार करना चाहिए।

बाइंडिंग मिस्टेक, मिसप्रिंट्स या गुम पृष्ठों आदि के लिए, प्रकाशक की देनदारी समान संस्करण द्वारा खरीद के सात दिनों के भीतर बदलने तक सीमित है। इस संबंध में सभी खर्च क्रेता द्वारा वहन किए जाने हैं।

सभी कॉपीराइट सुरक्षित

इस पुस्तक का कोई भी भाग किसी भी रूप में या किसी भी तरह से (ग्राफिक, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, टेपिंग, या सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली सहित) या किसी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य सूचना भंडारण पर पुनः प्रस्तुत या कॉपी आदि, प्रकाशकों की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। इस शर्त का उल्लंघन कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

लेखक प्रतिनिधित्व करता है और वारंट करता है कि लेखक ही संपूर्ण रूप से सभी अधिकारों का एकमात्र मालिक है, कि कॉपीराइट के कार्यों के ऐसे अंशों को छोड़कर कार्य मूल है क्योंकि कॉपीराइट स्वामी की अनुमति के साथ शामिल किया जा सकता है, जिससे कार्य किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन या उल्लंघन नहीं करता है और साथ ही यह किसी भी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या दूसरों के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।



8882388888



Kumar Edutainment



your_kumar_sir



kumarsias.com



Kumar Edutainment Presents **CURRENT AFFAIRS MAGAZINE**

प्रिय अभ्यर्थी,

मैं पूरे संस्थान की ओर से आपका स्वागत करता हूँ और हम में आपकी रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद।

वर्षों से हम युवा छात्र एवं छात्राओं को शिक्षित कर रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़ कर एक जिम्मेदार नागरिकों और कॉर्पोरेट्स प्रमुख में अपना परिवर्तन अनुभव किया। हमारे साथ जुड़कर, आप एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कर रहे हैं जो परिवर्तनकारी है - अकादमिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से। "उत्कृष्टता और मूल्य" हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो संस्थान की प्रत्येक गतिविधि में परिलक्षित होते हैं।



हमारी हैंडबुक कई प्रतियोगी और सरकारी परीक्षाओं में बड़ी भूमिका निभाती है। यह आपकी सफलता के अवसर को बनाने या तोड़ने की शक्ति रखता है। इसलिए, उम्मीदवारों को करेंट अफेयर्स को अच्छी तरह और स्मार्ट तरीके से कवर करना चाहिए। विभिन्न परीक्षाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारी हैंडबुक को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। दिए गए करेंट अफेयर्स की प्रस्तुति की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि यह पाठकों के जेहन में लंबे समय तक बना रहे।

हमारा मिशन एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है जिसमें प्रत्येक छात्र हमेशा बदलते, वैश्विक समुदाय के कुशल, उत्पादक सदस्य बनने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करेगा। हमारे संकाय व्यक्तियों का एक बहुत ही समर्पित समूह है जो हमारे छात्रों के लिए सर्वोत्तम संभव निर्देश प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है।

एक बार फिर, साझा सिद्धांतों एवं मूल्यों के हमारे समुदाय में आपका स्वागत है। आने वाले वर्षों में आपके सुखद, स्वस्थ और फलदायी होने की कामना करते हैं।

संस्थान में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

मुकेश कुमार



8882388888



Kumar Edutainment



your_kumar_sir



kumarsias.com



समाचार श्रेय:

बीबीसी/

रॉयटर्स/

अलजजीरा/

पीआईबी/

पीटीआई/

बिजनेस स्टैंडर्ड/

द हिंदू/

इंडियन एक्सप्रेस/

टाइम्स ऑफ इंडिया/

इकोनॉमिक टाइम्स/

बिजनेस लाइन/

इंडिया टुडे/

मनीकंट्रोल एवं अन्य

सभी प्रमुख समाचार

पत्र



Kumar Edutainment Presents

CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

इस संस्करण में शामिल हैं

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	नियुक्तियाँ	1
2	राजतन्त्र एवं शासन	14
3	अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाएँ	19
4	अर्थव्यवस्था एवं व्यापार	27
5	रक्षा एवं सुरक्षा	40
6	सामाजिक मुद्दे एवं योजनाएँ	46
7	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	49
8	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	52
9	संस्कृति एवं इतिहास	57
10	खेल-कूद	63
11	निधन	71
12	परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण दिन	74
13	पुस्तकें एवं लेखक	75
14	अभ्यास हेतु प्रश्न बैंक	76
15	क्विक बाइट्स	107
16	इन्फोग्राफिक्स	110

हमारे बारे में:

संस्करण: अक्टूबर 2025

संपादक का नाम: कुमार एडुटिमेंट

सलाहकार का नाम: मुकेश कुमार

पता: 7 जवाहर नगर, खंदारी, आगरा, उत्तर प्रदेश

दूरभाष: 8882388888

मेल: Kumariasacademy@gmail.com

वेब: <https://kumarsias.com/index-2.html>

नियुक्तियाँ

एसीसी ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ाया



कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में जनरल अनिल चौहान के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। सीडीएस के साथ-साथ, वह भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के रूप में भी कार्यरत रहेंगे। पहली नियुक्ति: 28 सितंबर 2022 को भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में।

पुरस्कार और सम्मान

जनरल अनिल चौहान को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

- परम विशिष्ट सेवा पदक (पीवीएसएम)
- उत्तम युद्ध सेवा पदक (यूवाईएसएम)
- अति विशिष्ट सेवा पदक (एवीएसएम)
- सेना पदक (एसएम)
- विशिष्ट सेवा पदक (वीएसएम)

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी):

भारत सरकार में वरिष्ठ नियुक्तियों के लिए कैबिनेट की उच्च-स्तरीय समिति।

संरचना:

- भारत के प्रधानमंत्री - अध्यक्ष
- गृह मंत्री - सदस्य
- (आवश्यकतानुसार अन्य मंत्रियों को सहयोजित किया जा सकता है)
- मंत्रिमंडल कार्यकारिणी समिति: मनीषा सक्सेना

कार्य और भूमिका

- भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और वैधानिक निकायों में शीर्ष पदों पर नियुक्तियों का निर्णय लेती है।
- वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों, विस्तार और समाप्ति को मंजूरी देती है।

निम्नलिखित की नियुक्तियों का प्रबंधन करती है:

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस)
- थल सेना, नौसेना और वायु सेना प्रमुख
- पीएसयू, बैंकों, नियामक निकायों के प्रमुख

- अन्य शीर्ष-स्तरीय नौकरशाही पद (जैसे, सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव)।
- कार्य संचालन नियम, 1961 के अंतर्गत कार्य करती है।

दिल्ली के पूर्व बल्लेबाज मिथुन मन्हास अगले बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार



दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अगले अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में हुई एक बैठक में मन्हास को इस शीर्ष पद के लिए उम्मीदवार चुना गया।

उन्होंने इससे पहले ये पद संभाले हैं:

- दलीप ट्रॉफी के लिए उत्तरी क्षेत्र के संयोजक
- आईपीएल फ्रैंचाइजी गुजरात टाइटन्स के सहयोगी स्टाफ
- जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) के प्रशासक

नियुक्ति का संदर्भ

पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने पदाधिकारियों के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा के नियम के कारण पद छोड़ दिया। अन्य संभावित उम्मीदवारों में हरभजन सिंह और रघुराम भट्ट शामिल थे।

प्रमुख पदाधिकारी और भूमिकाएँ

- सचिव: देवजीत साकिया (कार्यकाल जारी रहेगा)
- उपाध्यक्ष: राजीव शुक्ला (अपने पद पर बने रहेंगे, पाँच वर्ष पूरे कर चुके हैं)
- कोषाध्यक्ष (अग्रणी): रघुराम भट्ट (कर्नाटक)
- संयुक्त सचिव (संभावित): प्रभतेज सिंह भाटिया (छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ)
- आईपीएल अध्यक्ष: अरुण धूमल (शांति अवधि पर कानूनी स्पष्टीकरण लंबित)

पवनकुमार भीमप्पा बजंथरी ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्यायमूर्ति पवनकुमार भीमप्पा बजंथरी ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। इस नियुक्ति के साथ, न्यायमूर्ति बजंथरी भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में

से एक का कार्यभार संभालेंगे और बिहार के न्यायिक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।



पटना उच्च न्यायालय:

- स्थापना: 3 फ़रवरी 1916
- स्थान: पटना, बिहार
- अधिकार क्षेत्र: संपूर्ण बिहार राज्य
- प्रथम मुख्य न्यायाधीश: सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैंप्स चैमियर

मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत की जाती है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और (मुख्य न्यायाधीश के अलावा) न्यायाधीश के मामले में, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।

- बिहार के वर्तमान राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान (केरल के भी राज्यपाल, जिन्हें 2025 में बिहार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है)।
- बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार।
- बिहार के उप-मुख्यमंत्री: सम्राट चौधरी।

भारत में न्यायपालिका:

- भारत में कुल उच्च न्यायालय: 25 (2025 तक)।
- नवीनतम उच्च न्यायालय: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (2019 में अमरावती में पुनर्स्थापित)।

गौरांगलाल दास दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त



वरिष्ठ राजनयिक गौरांगलाल दास को दक्षिण कोरिया (कोरिया गणराज्य) में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।

सेवा पृष्ठभूमि:

- भारतीय विदेश सेवा (IFS) के 1999 बैच से संबंधित।
- वर्तमान में विदेश मंत्रालय (MEA), नई दिल्ली में पूर्वी एशिया प्रभाग का नेतृत्व कर रहे हैं।

कूटनीति में भूमिका:

- पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध (2020 से) के दौरान भारत-चीन वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- वर्तमान पद: राजदूत के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत।

राजदूत पद के बारे में

- राजदूत: विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च पदस्थ राजनयिक।
- नियुक्ति प्राधिकारी: भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

राजनयिक संबंध स्थापित: 1973

प्रमुख समझौते:

- व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) - 2010 में हस्ताक्षरित।
- विशेष रणनीतिक साझेदारी - 2015 में उन्नत।
- आर्थिक संबंध: दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, जहाज निर्माण और इस्पात (भारत में हुंडई, सैमसंग, पोस्को) में एक प्रमुख साझेदार है।
- रक्षा संबंध: रक्षा उत्पादन में सहयोग (दक्षिण कोरियाई तकनीक से निर्मित K9 वज्र-T हॉवित्जर तोपें)।
- सांस्कृतिक संबंध: भारत में के-पॉप, के-ड्रामा और कोरियाई भाषा की बढ़ती लोकप्रियता।

दक्षिण कोरिया (कोरिया गणराज्य):

- राजधानी: सिंगोल
- मुद्रा: दक्षिण कोरियाई वोन (KRW)
- राष्ट्रपति: यूं सुक येओल
- प्रधानमंत्री: हान डक-सू
- प्रमुख बहुपक्षीय सदस्य: G20, OECD, APEC, ASEAN+3

नेस्ले नेतृत्व परिवर्तन: पॉल बुल्के पद छोड़ेंगे, पाब्लो इस्ला अध्यक्ष नियुक्त



स्विस बहुराष्ट्रीय खाद्य और पेय कंपनी नेस्ले एसए ने घोषणा की है कि उसके लंबे समय से कार्यरत अध्यक्ष पॉल बुल्के (71) सीईओ लॉरेंट फ्रीक्से के निष्कासन के मामले में निवेशकों की आलोचना के बाद, निर्धारित समय से पहले ही पद छोड़ देंगे। इंडीटेक्स (ज़ारा के मालिक) के पूर्व प्रमुख पाब्लो इस्ला, 1 अक्टूबर 2025 को नेस्ले के अध्यक्ष का पद संभालेंगे और कंपनी के पहले बाहरी अध्यक्ष बनेंगे।

सीईओ परिवर्तन:

पिछले साल सीईओ नियुक्त किए गए लॉरेंट फ्रीक्से को दो आंतरिक जाँचों के बाद कदाचार के कारण हटा दिया गया था। नेस्ले की नेस्प्रेस्सो इकाई के एक अनुभवी फिलिप नवरातिल को इसी महीने नया सीईओ नियुक्त किया गया।

नेस्ले:

नेस्ले एसए की स्थापना 1866 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वेवे, स्विट्जरलैंड में है।

प्रसिद्ध ब्रांड: किटकेट, नेस्कैफे, नेस्प्रेस्सो, मैगी, सेरेलैक, मिलो। नेस्ले राजस्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय कंपनी है।

न्यायमूर्ति एम. सुंदर मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

न्यायमूर्ति एम. सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वे न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर का स्थान लेंगे, जो 14 सितंबर, 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है।

नियुक्ति विवरण

- नियुक्ति तिथि: 13 सितंबर, 2025
- पद: मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- पूर्ववर्ती: न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर

व्यावसायिक पृष्ठभूमि

- वर्तमान पद: मद्रास उच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश
- न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति: अक्टूबर 2016 में मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त
- कानूनी कार्य: 1989 में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित, मुख्यतः मद्रास उच्च न्यायालय में दीवानी मामलों में वकालत।

मणिपुर

- राजधानी: इम्फाल
- ज़िले: 16
- राज्यपाल: अजय कुमार भल्ला
- मुख्यमंत्री: वर्तमान में राष्ट्रपति शासन

अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए दुनिया का पहला AI-जनित मंत्री नियुक्त किया

अल्बानिया ने पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। यह घोषणा प्रधानमंत्री एडी रामा ने की, जिन्होंने इस डिजिटल मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। इस AI सहायक का नाम डिएला है, जिसका अर्थ है 'सूर्य', और यह जनवरी 2025 से नागरिकों को सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग करने में मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री रामा ने कहा कि डिएला को सार्वजनिक निविदाओं के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे 100% भ्रष्टाचार-मुक्त और पूरी तरह से पारदर्शी हों। इस पहल के तहत, सरकारी निविदाओं के लिए जमा किए गए सभी सार्वजनिक धन की निगरानी की जाएगी ताकि पूरी स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके और दुरुपयोग को रोका जा सके। डिएला का आभासी अवतार पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में एक महिला के रूप में दिखाई देता है, जो तकनीकी प्रगति के साथ-साथ राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है।

सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली

नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और देश का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू स्थित राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति रामबरन यादव और अन्य गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित थे। उनकी नियुक्ति नेपाल में राजनीतिक अशांति के दौर के बाद हुई है। हाल ही में जेनेरेशन जेड के प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुए, जो सरकार द्वारा प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने और भ्रष्टाचार को लेकर व्यापक जनक्रोध के बाद भड़के थे। इस अशांति के परिणामस्वरूप घातक झड़पें हुईं, जिनमें कई लोगों की जान चली गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास में

तीन दिनों तक चली चर्चा और औपचारिक वार्ता के बाद, सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। वह नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी हैं, जिन्हें उनकी ईमानदारी और न्यायिक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति पौडेल प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकते हैं, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व करने के लिए जेनेरेशन जेड के युवाओं के प्रतिनिधियों सहित एक टीम का गठन करेंगे। यह कदम प्रदर्शनकारियों की उन मांगों का जवाब है जो जड़ जमाए राजनीतिक भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार की मांग कर रहे हैं और तत्काल सुधारों की मांग कर रहे हैं।

अतिरिक्त तथ्य:

सुशीला कार्की ने 2016 से 2017 तक नेपाल की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वह नेपाल में मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर आसीन होने वाली पहली महिला हैं। केपी शर्मा ओली ने राजनीतिक अस्थिरता के बीच 2025 में अपने इस्तीफे से पहले कई बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।

आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया



सीपी राधाकृष्णन के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राधाकृष्णन, जो पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, 9 सितंबर, 2025 को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। उन्हें 452 मत मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। सीपी राधाकृष्णन भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार थे और उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए। अपने निर्वाचन के बाद, उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया और अब आचार्य देवव्रत को गुजरात के अपने कर्तव्यों के अलावा महाराष्ट्र के शासन का कार्यभार भी सौंपा गया है।

आचार्य देवव्रत के बारे में

अगस्त 2015 से जुलाई 2019 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। जुलाई 2019 में गुजरात के राज्यपाल नियुक्त हुए।

उल्लेखनीय जानकारी:

- भारत के उपराष्ट्रपति: उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है।

- सीपी राधाकृष्णन: एक अनुभवी राजनेता और पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का प्रतिनिधित्व किया।
- राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार: रिक्ति या परिवर्तन की स्थिति में, राज्य के कर्तव्यों की देखरेख के लिए अस्थायी रूप से किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है।
- राज्यपाल की भूमिका: राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जो केंद्रीय और राज्य कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।
- चुनाव प्रक्रिया: उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (एकल संक्रमणीय मत) के माध्यम से किया जाता है।

डॉ. गीता वाणी रायसम ने सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की निदेशक का कार्यभार संभाला



डॉ. गीता वाणी रायसम ने सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान (एनआईएससीपीआर) की नई निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। संस्थान का विषय "कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड" समावेशी विज्ञान संचार को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए। सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत एक घटक प्रयोगशाला है जो विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान पर केंद्रित है। एसटीआई (विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार) नीति अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों को आकार देने में मदद करती है। डब्ल्यूएचओ, संयुक्त राष्ट्र, ओईसीडी और विश्व बैंक जैसे संगठनों के साथ वैश्विक साझेदारी विज्ञान में अंतराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करती है।

इरफ़ान अली तेल-समृद्ध गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित



इरफ़ान अली को उनकी पार्टी, पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी/सिविक (पीपीपी/सी) द्वारा 65 सीटों वाली संसद में 55% मत प्राप्त करने के बाद, दूसरे पाँच-वर्षीय कार्यकाल के लिए गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया।

पृष्ठभूमि:

इस चुनाव ने अली की सरकार को वेनेजुएला के साथ एस्सेकिबो क्षेत्र को लेकर चल रहे क्षेत्रीय विवाद के बीच गुयाना की नई तेल संपदा का प्रबंधन करने का जनादेश दिया।

देश की जनसंख्या लगभग 800,000 है।

आर्थिक महत्व:

एक्सॉनमोबिल द्वारा अपतटीय तेल उत्पादन शुरू करने के बाद, 2019 से गुयाना ने तेल की बिक्री और रॉयल्टी से 7.5 बिलियन डॉलर कमाए हैं। यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसकी 2024 में जीडीपी वृद्धि दर 43.6% होगी। राज्य का बजट 2025 तक चार गुना बढ़कर 6.7 अरब डॉलर हो जाएगा। गुयाना में प्रति व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जिसके 2030 तक प्रतिदिन 10 लाख बैरल तेल उत्पादन करने की उम्मीद है।

विकास पहल:

सरकार ने तेल राजस्व का निवेश सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों में किया है और विश्वविद्यालय शिक्षा को मुफ्त कर दिया है।

राजनयिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दे:

वेनेजुएला की सरकार एस्सेकिबो क्षेत्र पर गुयाना के नियंत्रण पर विवाद करती है, जिससे तनाव बढ़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका अली की सरकार का समर्थन करता है, जबकि वेनेजुएला कैरिबियन में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का विरोध करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) सीमा विवादों में शामिल है, लेकिन वेनेजुएला इसके अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार करता है।

सेबेस्टियन लेकोर्नु फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त



फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद अपने सहयोगी सेबेस्टियन लेकोर्नु को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वे फ्रांस्वा बायरू की जगह लेंगे।

पृष्ठभूमि:

फ्रांस्वा बायरू को उनकी अल्पमत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बजट पारित न कर पाने के बाद पद से हटा दिया गया था। 39 वर्षीय सेबेस्टियन लेकोर्नु इससे पहले सशस्त्र सेना मंत्री के रूप में कार्यरत थे और रूस-यूक्रेन युद्ध में फ्रांस की भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे।

राजनीतिक संदर्भ:

लेकोर्नु मैक्रों के कार्यकाल में सातवें और अपने दूसरे कार्यकाल में पाँचवें प्रधानमंत्री हैं। 2024 के मध्यावधि चुनावों के बाद से फ्रांस में संसद में गतिरोध बना हुआ है, जिसमें तीन प्रमुख गुट हैं: वामपंथी, अति-दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी।

अतिरिक्त बिंदु:

फ्रांस एक अर्ध-राष्ट्रपति गणतंत्र है, जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शक्तियों को साझा करते हैं। त्रिशंकु संसद का अर्थ है कि संसद में किसी एक दल या गठबंधन का बहुमत नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद के 100% से अधिक सार्वजनिक ऋण को एक गंभीर आर्थिक चुनौती माना जाता है, क्योंकि इससे उधार लेने की लागत बढ़ जाती है।

श्रीनिवास इंजेती नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के अध्यक्ष नियुक्त



नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने श्रीनिवास इंजेती को अपने गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस नियुक्ति को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने भी मंजूरी दे दी है। पिछले सप्ताह, उन्हें एनएसई का जनहित निदेशक नियुक्त किया गया था। पृष्ठभूमि: 1983 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, जिन्हें शासन, कॉर्पोरेट विनियमन, वित्तीय सेवाओं और सार्वजनिक नीति में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

प्रमुख भूमिकाएँ:

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के संस्थापक अध्यक्ष (2020-2023), भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियामक की स्थापना और वैश्विक बैंकिंग, फिनटेक, सतत वित्त और निधि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। केंद्रीय सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (2017-2020), दिवाला कानून, प्रतिस्पर्धा कानून और कंपनी कानून में सुधारों का नेतृत्व किया; एनएफआरए और स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक की स्थापना की; कॉर्पोरेट प्रशासन और सीएसआर ढांचे को मजबूत किया। केंद्रीय खेल सचिव और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की संकल्पना की और भारत के खेल प्रशासन में सुधार किया।

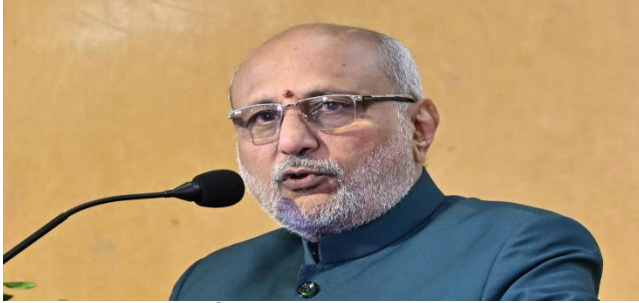
बोर्ड अनुभव: सेबी, एलआईसी और विभिन्न राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सेवारत।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड:

- स्थापना: 1992।
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत।

➤ एमडी एवं सीईओ: आशीष कुमार चौहान

सी. पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित



एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भारतीय जनता पार्टी (आई.डी.ए.) के ब्लॉक उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराया। राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पी. सी. मोदी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 781 मतदाताओं में से 767 सांसदों ने मतदान किया, जिनमें से 752 वैध और 15 अवैध थे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया था।

सी. पी. राधाकृष्णन:

- पूरा नाम: चंद्रपुरम पोन्नूसामी राधाकृष्णन
- जन्म स्थान: तिरुपुर, तमिलनाडु

राजनीतिक जीवन:

- छात्र जीवन के दौरान आरएसएस और जनसंघ में सक्रिय।
- कोयंबटूर से दो बार सांसद (लोकसभा) रहे।
- झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में राज्यपाल के पदों पर रहे।
- पेशा: कृषक और उद्योगपति
- प्रतिष्ठा: ईमानदारी, दूरदर्शिता और स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए जाने जाते हैं।

भूपेंद्र गुप्ता ने एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला



भूपेंद्र गुप्ता ने फरीदाबाद स्थित एनएचपीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पदभार ग्रहण किया। एनएचपीसी में शामिल होने से पहले, वे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) थे और वर्तमान में एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त

प्रभार संभाल रहे हैं। उनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और संचालन प्रबंधन में एमबीए की डिग्री है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य

1975 में स्थापित, एनएचपीसी लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत कंपनी है जो जलविद्युत ऊर्जा के नियोजन, विकास और उत्पादन में संलग्न है। एसजेवीएन लिमिटेड (सतलुज जल विद्युत निगम) विद्युत उत्पादन और पारेषण पर केंद्रित है और भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में संलग्न है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देती है।

हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को सीईओ नियुक्त किया, जो जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।



भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने हर्षवर्धन चितले को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है, जो 5 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। कार्यवाहक सीईओ, विक्रम कस्बेकर, चितले के पदभार ग्रहण करने पर अपने पद से हट जाएंगे, लेकिन बोर्ड में कार्यकारी निदेशक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में बने रहेंगे।

परिवर्तन योजना

एक सुव्यवस्थित परिवर्तन की योजना बनाई गई है, जिसमें विक्रम कस्बेकर चितले को सुचारू रूप से कार्यभार सौंपने में सहायता करेंगे। कस्बेकर कंपनी के साथ कार्यकारी निदेशक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में जुड़े रहेंगे।

अन्य मुख्य तथ्य:

हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। यह मात्रा के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया वाहन निर्माताओं में से एक है। एथर एनर्जी, जिसमें हीरो का निवेश है, भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माण में अग्रणी कंपनी है।

न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने मुंबई स्थित राजभवन में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई।



नियुक्ति प्रक्रिया

इस नियुक्ति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी घोषणा की। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के परामर्श से संवैधानिक प्रावधानों के तहत इस नियुक्ति को मंजूरी दी। 25 अगस्त, 2025 को, सीजेआई बीआर गवई के नेतृत्व वाले तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की।

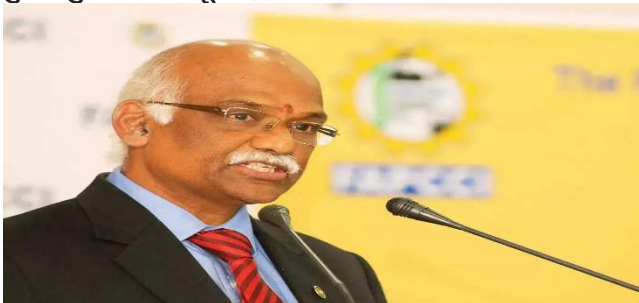
न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर का परिचय

17 जनवरी, 2013 को झारखंड उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त। 27 जून, 2015 को स्थायी न्यायाधीश बने। 29 दिसंबर, 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत। बाद में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य

1862 में स्थापित बॉम्बे उच्च न्यायालय, भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसका क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा पर है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से होती है। न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं।

RBI ने आर गांधी की यस बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी



भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आर गांधी की यस बैंक के गैर-कार्यकारी, अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी RBI के 1 सितंबर 2025 के पत्र के माध्यम से जारी की गई, जिससे उनका कार्यकाल 20 सितंबर 2025 से बढ़कर 13 मई 2027 हो गया। नियामक मानदंडों के अनुसार, RBI ने इस पद के लिए उनके पारिश्रमिक को मंजूरी दे दी है।

आर गांधी की व्यावसायिक पृष्ठभूमि

राम सुब्रमण्यम गांधी ने 2014 से 2017 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य किया। वे वित्तीय क्षेत्र में 37 वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी केंद्रीय बैंकर हैं। गांधी ने भारत के पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) में तीन साल के लिए सेकेंडमेंट पर भी काम किया।

इसके अतिरिक्त, वे हैदराबाद स्थित बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (IDRBT) के निदेशक भी रहे।

यस बैंक:

- स्थापना: 2003
- संस्थापक: राणा कपूर, अशोक कपूर
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

अनुतिन चार्नविराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए



व्यापारी और भूमजैथाई पार्टी के नेता अनुतिन चार्नविराकुल को संसद द्वारा थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। पिछले दो वर्षों में वे तीसरे प्रधानमंत्री हैं, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता उजागर हुई है। अनुतिन ने पैतोंगटार्न शिनावत्रा का स्थान लिया, जिन्हें कंबोडिया के साथ सीमा विवाद से निपटने में नैतिक उल्लंघन के लिए संवैधानिक न्यायालय ने पद से हटा दिया था। अनुतिन की पार्टी को 247 वोट मिले, जो 492 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में बहुमत की सीमा को पार कर गया, जिसके लिए आधे से ज्यादा वोटों की आवश्यकता होती है।

थाईलैंड:

- राजधानी: बैंकॉक
- मुद्रा: थाई बाट (THB)

यूटीआई एएमसी ने नए सीईओ की नियुक्ति की; बंधन एएमसी को एसआईएफ में प्रवेश के लिए सेबी की मंजूरी मिली



यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) ने वर्तमान में मुख्य निवेश अधिकारी (सीआईओ) के पद पर कार्यरत वेत्री सुब्रमण्यम को 1 फरवरी, 2026 से अपना अगला प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। वह तत्काल प्रभाव से एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त होंगे। वर्तमान एमडी और सीईओ, इम्तियाजुर रहमान, जून 2026 तक रणनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य करते रहेंगे।

यूटीआई एएमसी, यूटीआई म्यूचुअल फंड (यूटीआई एमएफ) का निवेश प्रबंधक है, जिसे प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) के आधार पर भारत में 7वां सबसे बड़ा फंड हाउस माना जाता है।

श्री पीयूष गोयल ने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया



नागालैंड कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी श्री पीयूष गोयल ने खान मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति से पहले, वे गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत नेटग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्यरत थे। वे 1992 बैच के आईएएस अधिकारी श्री वी.एल. कांता राव का स्थान लेंगे, जिन्होंने अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव का पदभार ग्रहण किया है।

खान मंत्रालय के बारे में

कार्य: भारत में खनिज संसाधनों के अन्वेषण, विकास और उपयोग सहित खानों और खनिजों के नियमन के लिए उत्तरदायी।

प्रमुख निकाय:

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) - खनिज अन्वेषण।
- भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) - खनिज संरक्षण, विकास और नियमन।
- राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान (एनआईआरएम) - अनुसंधान एवं प्रशिक्षण।

भारत की खनिज संपदा:

- भारत कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक और क्रोमाइट के शीर्ष उत्पादकों में से एक है।
- प्रमुख खनन राज्य: झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश।
- रणनीतिक महत्व: खान क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

श्री रजित पुन्हानी, आईएएस, ने FSSAI के सीईओ का पदभार ग्रहण किया



वरिष्ठ नौकरशाह श्री रजित पुन्हानी, जो बिहार कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पदभार ग्रहण किया है।

श्री रजित पुन्हानी के बारे में

सेवा पृष्ठभूमि: केंद्र, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 वर्षों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव।

पूर्व भूमिकाएँ:

- सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय - उद्योग एवं वैश्विक मानकों के अनुरूप कौशल विकास।
- सचिव, राज्यसभा और सीईओ, संसद टीवी।
- प्रधान सचिव, बिहार सरकार।
- विशेष सचिव, गृह मंत्रालय।
- यूरोपीय संघ में राजनयिक और प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया।

नीतिगत योगदान:

- 45 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन और बीमा योजनाएँ तैयार कीं।
- दुनिया की सबसे बड़ी मातृ संदेश सेवा का नेतृत्व किया।
- अप्रत्यक्ष कर समिति में योगदान दिया जिसने जीएसटी की नींव रखी।

एफएसएसआई के बारे में

- स्थापना: 2008 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत)।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।
- नोडल मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- भूमिका: भारत भर में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और मानकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी वैधानिक निकाय।
- सीईओ की नियुक्ति: कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा की गई।
- वर्तमान अध्यक्ष: सुश्री पुण्य सलिला श्रीवास्तव।

डॉ. दीपक मित्तल यूआई में भारत के अगले राजदूत नियुक्त



विदेश मंत्रालय (MEA) ने डॉ. दीपक मित्तल (1998 बैच के IFS अधिकारी) को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वह संजय सुधीर का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होंगे।

डॉ. दीपक मित्तल का परिचय

- 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में दो कार्यकालों तक सेवा की।
- कतर में पूर्व राजदूत (2020-2022)।

इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई:

- तालिबान के साथ भारत का पहला औपचारिक राजनयिक संपर्क स्थापित करना (2021)।
- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नागरिकों का बचाव करना।

भारत-यूएई संबंध

- राजनयिक संबंध स्थापित: 1972।
- यूएई में भारतीय प्रवासी: 35 लाख से अधिक (सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय)।
- सहयोग के प्रमुख क्षेत्र: ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, रक्षा, अंतरिक्ष और संस्कृति।
- प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यूएई यात्रा (2015): 34 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा, जिसने संबंधों को गति दी।

यूएई का महत्व:

- प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता (तेल और गैस)।
- भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक (द्विपक्षीय व्यापार: 2022-23 में 85 बिलियन डॉलर)।
- I2U2 समूह (भारत, इज़राइल, यूएई, अमेरिका) में भागीदार।
- यूएई में भारत का दूतावास: अबू धाबी में स्थित, दुबई में एक वाणिज्य दूतावास।
- अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर (2024): संयुक्त अरब अमीरात का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर, सांस्कृतिक सन्दाव का प्रतीक।

J&K बैंक ने एस. कृष्णन को गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया

J&K बैंक ने एस. कृष्णन को 26 मार्च, 2028 तक के कार्यकाल के लिए अपना नया गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अनुमोदन की

तिथि से प्रभावी होगी। यह निर्णय 25 अगस्त, 2025 को हुई बैंक की बोर्ड बैठक में लिया गया।



एस. कृष्णन की व्यावसायिक पृष्ठभूमि:

वर्तमान में जेएंडके बैंक के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक (सरकारी स्वामित्व वाले) के पूर्व एमडी और सीईओ। सेवानिवृत्ति के बाद सितंबर 2022 में तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला।

J&K बैंक के बारे में:

- स्थापना: 1938।
- मुख्यालय: श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर।
- स्थिति: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक; "पुराने निजी क्षेत्र के बैंक" के रूप में वर्गीकृत।
- स्वामित्व: जम्मू और कश्मीर सरकार के पास अधिकांश स्वामित्व (लगभग 68%) है।
- यह RBI और जम्मू-कश्मीर सरकार के दोहरे विनियमन के अंतर्गत संचालित होता है।
- यह कृषि, लघु और मध्यम उद्यमों (SME) और खुदरा क्षेत्रों को ऋण देकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उर्जित पटेल IMF के कार्यकारी निदेशक नियुक्त



भारत सरकार ने RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को तीन साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दे दी है।

पृष्ठभूमि

पटेल, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यन का स्थान लेंगे, जिन्हें IMF में उनके छोटे कार्यकाल के बाद सरकार ने वापस बुला लिया था। इससे पहले, उर्जित पटेल ने 2016 में RBI के 24वें गवर्नर के रूप में रघुराम राजन की जगह ली थी

और 2018 में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिससे उनका कार्यकाल RBI के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल बन गया। गवर्नर के रूप में, उन्हें सख्त मौद्रिक नीतियों के लिए जाना जाता था, खासकर कम मुद्रास्फीति (जो 1.5% तक गिर गई थी) के बावजूद उच्च ब्याज दरों को बनाए रखने के लिए।

करियर की मुख्य उपलब्धियाँ

- RBI के डिप्टी गवर्नर (2013-2016)।
- RBI के गवर्नर (2016-2018)।
- अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) (2020)।
- उपाध्यक्ष, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी), दक्षिण एशिया प्रभाग (पूर्व भूमिका)।

आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक पद के बारे में

24 कार्यकारी निदेशकों में से प्रत्येक या तो एक देश या देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है (भारत एक बहु-देशीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है)। कार्यकारी निदेशक आईएमएफ के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, जिसमें ऋण, निगरानी और नीतिगत मामलों पर निर्णय शामिल हैं।

आईएमएफ:

- मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., अमेरिका।
- स्थापना: 1944 (ब्रेटन वुड्स सम्मेलन), 1945 से कार्यरत।
- सदस्यता: 190 देश (2025 तक)।
- वर्तमान आईएमएफ प्रबंध निदेशक: क्रिस्टालिना जॉर्जिवा (2019 से, बुल्गारिया से)।
- आईएमएफ में भारत का कोटा: 2.75% (आठवाँ सबसे बड़ा कोटा धारक देश)।

भारत ने दिनेश के. पटनायक को कनाडा में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया



भारत ने 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी और स्पेन में वर्तमान राजदूत दिनेश के. पटनायक को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। दूसरी ओर, कनाडा ने 35 वर्षों से अधिक सेवा अनुभव वाले वरिष्ठ राजनयिक क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है।

राजनयिक तनाव की पृष्ठभूमि

ये नियुक्तियाँ 10 महीने के अंतराल के बाद हुई हैं, जिसके दौरान भारत ने अक्टूबर 2024 में अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को वापस बुला लिया था। यह निर्णय कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री

जस्टिन ट्रूडो के भारत पर दिए गए विवादास्पद बयानों के कारण उत्पन्न तनावपूर्ण संबंधों के बाद लिया गया था।

सामान्यीकरण की ओर कदम

मार्क कार्नी के कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में सुधार होने लगा। जून 2025 में, कनानसकीस में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कार्नी ने एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने इस चर्चा को "सकारात्मक और रचनात्मक" बताया, जिसके परिणामस्वरूप संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमति बनी।

नए दूतों का परिचय

- दिनेश के. पटनायक: यूरोप, अफ्रीका और विदेश मंत्रालय में विविध पदों पर रह चुके एक अनुभवी राजनयिक।
- क्रिस्टोफर कूटर: इससे पहले दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, लेसोथो, मॉरीशस और मेडागास्कर में उच्चायुक्त और भारत एवं नेपाल में कनाडा के उच्चायोग में प्रथम सचिव के रूप में कार्यरत रहे। हाल ही में, वे इज़राइल में कनाडा के प्रभारी राजदूत थे।

भारत-कनाडा संबंध

- राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए।
- भारत कनाडा में सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है (1.6 मिलियन से अधिक लोग)।
- संबंधों में शिक्षा, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, व्यापार और कृषि में सहयोग शामिल है।

कॉलेजियम की सिफ़ारिश के 2 दिन बाद केंद्र ने न्यायमूर्ति आलोक अराधे और विपुल पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया



केंद्र ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल पंचोली को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (मुख्य न्यायाधीश भूषण आर गवई की अध्यक्षता में) की सिफ़ारिश के दो दिन बाद हुई।

- कॉलेजियम के अन्य सदस्य: न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, जे के माहेश्वरी और बी वी नागरत्ना।
- न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने न्यायमूर्ति पंचोली की सिफ़ारिश पर असहमति जताते हुए उनके स्थानांतरण इतिहास (2023

में गुजरात उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय), वरिष्ठता के मुद्दों और क्षेत्रीय असंतुलन का हवाला दिया।

मुख्य तथ्य:

- अनुच्छेद 124(2): मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान सदस्य संख्या (इन नियुक्तियों के बाद): 34 न्यायाधीश (अधिकतम स्वीकृत संख्या)।
- कॉलेजियम प्रणाली: द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) के माध्यम से शुरू की गई, तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) द्वारा इसे और मजबूत किया गया।
- न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना (कॉलेजियम सदस्य): सितंबर 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हैं।
- इसके साथ ही, केंद्र ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 14 अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी दी (19 अगस्त 2025 को अनुशंसित)।

आकाश त्रिपाठी भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त



1998 बैच के आईएएस अधिकारी आकाश त्रिपाठी को भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) का प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन पर मंजूरी दी है। SECI का नेतृत्व अब संतोष सारंगी (सचिव, MNRE) अध्यक्ष और आकाश त्रिपाठी प्रबंध निदेशक के रूप में करेंगे।

SECI के बारे में

भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अंतर्गत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को लागू करने के लिए नामित एजेंसी है, जिनमें शामिल हैं:

- सौर, पवन, हाइड्रिड, ऊर्जा भंडारण, अपतटीय पवन और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली।
- निवेशकों का विश्वास और भुगतान सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दीर्घकालिक विद्युत बिक्री समझौतों (PSA) को सुगम बनाना।
- स्थापना: 2011 (कंपनी अधिनियम के तहत धारा-25 कंपनी के रूप में, बाद में एक सरकारी कंपनी में परिवर्तित)।
- स्थिति: 2023 में नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम में अपग्रेड किया गया।

- मूल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।

यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बीच नायरा एनर्जी ने नए सीईओ की नियुक्ति की



रूस की रोसनेफ्ट द्वारा समर्थित मुंबई स्थित तेल कंपनी नायरा एनर्जी लिमिटेड ने तैमूर अबसगुलियेव को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। वह सितंबर 2025 में कार्यभार संभालेंगे। अबसगुलियेव इससे पहले SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. में मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने कॉर्पोरेट प्रशासन, वित्तपोषण, विलय और अधिग्रहण, और बड़े पैमाने पर पुनर्गठन का कार्यभार संभाला था।

अंतरिम प्रबंधन और पूर्व सीईओ

जुलाई 2025 में, मुख्य विकास अधिकारी सर्गेई डेनिसोव को अंतरिम प्रभार दिया गया था, जब नायरा पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बाद पूर्व सीईओ एलेसेंड्रो डेस डोरिडेस ने इस्तीफा दे दिया था।

नायरा एनर्जी पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध

18 जुलाई 2025 को, यूरोपीय संघ (ईयू) ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के तेल राजस्व से जुड़े होने का हवाला देते हुए, नायरा की 20 मिलियन टन क्षमता वाली वाडिनार रिफाइनरी (गुजरात) पर प्रतिबंध लगा दिए। नायरा ने इन प्रतिबंधों को "निराधार, एकतरफा और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन" करार दिया है और कानूनी उपायों की तलाश कर रही है।

कंपनी की निवेश योजनाएँ

नायरा एनर्जी ने पेट्रोकेमिकल्स, इथेनॉल संयंत्रों और विपणन अवसंरचना विस्तार में दीर्घकालिक रूप से ₹70,000 करोड़ निवेश करने की योजना की घोषणा की है। अगस्त 2017 से, कंपनी ने रिफाइनरी उन्नयन, एक नए पेट्रोकेमिकल संयंत्र और अवसंरचना परियोजनाओं में ₹14,000 करोड़ का निवेश किया है।

वर्तमान संचालन

प्रतिबंधों के बावजूद, नायरा ने पुष्टि की है कि उसके रिफाइनरी संचालन और पेट्रोलियम आपूर्ति श्रृंखला अप्रभावित हैं और "स्वस्थ दर" पर चल रही हैं। कंपनी सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्राधिकरणों और वैश्विक भागीदारों के साथ समन्वय कर रही है।

मुख्य तथ्य:

- नयारा एनर्जी: पहले एस्सार ऑयल लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, जिसे बाद में रोसनेफ्ट (रूस) और एक अंतरराष्ट्रीय निवेशक संघ ने 2017 में अधिग्रहित कर लिया।
- वाडिनार रिफाइनरी: भारत की दूसरी सबसे बड़ी एकल-साइट रिफाइनरी, जिसकी क्षमता 20 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) है।
- रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी: नयारा एनर्जी में 49.13% हिस्सेदारी है।
- भारत में नयारा की भूमिका: पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल का प्रमुख आपूर्तिकर्ता, 6,500 से अधिक ईंधन खुदरा दुकानों का संचालन करता है।

इंगा रुगिनिन को लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी

लिथुआनियाई संसद ने सोशल डेमोक्रेट इंगा रुगिनिन को लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है। संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, वह अपनी भूमिका में सफल होंगी और अब उनके पास राष्ट्रपति के परामर्श से नई कैबिनेट सूची प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय है।

आधिकारिक नियुक्ति प्रक्रिया

लिथुआनिया के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद, रुगिनिन औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगी। प्रस्तुत कैबिनेट सूची को अंतिम अनुमोदन के लिए संसदीय मतदान की भी आवश्यकता होगी।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

इस नियुक्ति से पहले, इंगा रुगिनिन सामाजिक सुरक्षा और श्रम मंत्री के रूप में कार्यरत थीं। वह 2024 में संसद के लिए चुनी गईं और सामाजिक एवं श्रम संबंधी नीति-निर्माण में सक्रिय रही हैं।

राजनीति से पहले का करियर

राजनीति में प्रवेश करने से पहले, रुगिनिन लिथुआनियाई ट्रेड यूनियन परिसंघ की अध्यक्ष थीं, जहाँ उन्होंने श्रमिकों के कल्याण और श्रम अधिकारों के लिए काम किया।

लिथुआनिया:

- राजधानी: विनियस
- मुद्रा: यूरो (€)
- वर्तमान राष्ट्रपति: गीतानास नौसेदा
- सदस्यताएँ: यूरोपीय संघ (ईयू), नाटो, शेंगेन क्षेत्र
- भूगोल: बाल्टिक क्षेत्र में स्थित; लातविया, बेलारूस, पोलैंड और रूस (कैलिनिनग्राद) के साथ सीमाएँ साझा करता है।

- ऐतिहासिक: लिथुआनिया 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य था।

न्यू डेवलपमेंट बैंक ने RBI के राजीव रंजन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया

ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन को पाँच साल के कार्यकाल के लिए अपना उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी (CRO) नियुक्त किया है। वह सितंबर 2025 से कार्यभार संभालेंगे।

राजीव रंजन के बारे में

- 35+ वर्षों के अनुभव वाले एक पेशेवर केंद्रीय बैंकर।
- मई 2022 से RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्य।

कार्यकाल:

- मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख, MPC के सचिव।
- आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग के प्रमुख।
- सेंट्रल बैंक ऑफ़ ओमान में आर्थिक नीति विशेषज्ञ (2012-15)।
- RBI के अंतर्राष्ट्रीय विभाग और बाह्य निवेश एवं संचालन विभाग में कार्यरत।
- G20, IMF, विश्व बैंक, BIS, FSB, OECD, SAARC और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के बारे में

- स्थापना: 2014, ब्रिक्स देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) द्वारा।
- मुख्यालय: शंघाई, चीन।
- उद्देश्य: उभरते बाजारों और विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
- फोकस: दीर्घकालिक विकास और वैश्विक दक्षिण विकास को समर्थन देने वाली परियोजनाएँ।
- अध्यक्ष: डिल्मा रूसेफ (ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति)।

राजीव आनंद इंडसट्रियल बैंक के सीईओ और एमडी नियुक्त

वरिष्ठ बैंकर राजीव आनंद ने आधिकारिक तौर पर इंडसट्रियल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) का कार्यभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा

पहले अगस्त 2025 में की गई थी और स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल एक फाइलिंग के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई थी।



कार्यक्रम पृष्ठभूमि

इससे पहले एक्सिस बैंक में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। विभिन्न वैश्विक वित्तीय संस्थानों में नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाई हैं।

इंडसइंड बैंक में संकट

आंतरिक डेरिवेटिव ट्रेडों के गलत लेखांकन के कारण इंडसइंड बैंक को 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 23 करोड़ डॉलर (लगभग ₹1,920 करोड़) का नुकसान हुआ। इस संकट के कारण अप्रैल 2025 में सीईओ सुमंत कठपालिया और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ने इस्तीफा दे दिया। राजीव आनंद की नियुक्ति निवेशकों का विश्वास बहाल करने और बैंक को स्थिर करने के प्रयासों के तहत की गई है।

इंडसइंड बैंक

- स्थापना: 1994
- संस्थापक: श्रीचंद परमानंद हिंदुजा (एसपी हिंदुजा)
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
- टैगलाइन: "हम आपको अमीर महसूस कराते हैं"
- विनियमित: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

"मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है !
लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता !!

"जिन्दगी में तकलीफ कितनी भी हो कभी हताश मत होना
क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ क्यों न हो समंदर कभी
सुखा नहीं होता !!

COCONUT DAY



Edition: 27th

02
SEP

Importance

To commemorate the formation of Asian Pacific Coconut Community (APCC) under the aegis of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP).

Motto

To highlight the importance and uses of coconuts.

Note

This Day helps to create awareness for the importance of this fruit in poverty reduction.

About APCC

- Type: Inter-governmental organization
- Headquarters: Jakarta, Indonesia
- Membership: 18 countries

INTERNATIONAL DAY OF CHARITY



05
SEP

Importance

To commemorate the death anniversary of Mother Teresa.

Motto

To sensitise and mobilizing people, NGOs, and stakeholders all around the world, who help others through volunteer and philanthropic activities.

Mother Teresa

(26 August 1910 - 5 September 1997)

- An Albanian-Indian Roman Catholic nun and missionary
- Full name: Anjezë Gonxhe Bojaxhiu
- Nationality: Indian, Ottoman, Yugoslavian

Awards

Bharat Ratna, Nobel Peace Prize, Order of the Smile, Ramon Magsaysay Award, Presidential Medal of Freedom, Golden Honour of the Nation, etc.

राजतन्त्र एवं शासन

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का औपचारिक शुभारंभ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) का औपचारिक शुभारंभ किया है, जो जीएसटी विवाद समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न्यायाधिकरण दिसंबर 2025 से कार्य करना शुरू कर देगा और अपीलें चरणबद्ध तरीके से दायर की जाएंगी।

अपील के लिए प्रमुख समय-सीमा

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पुराने मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी और करदाता विस्तारित सीमा अवधि के तहत 30 जून 2026 तक अपील दायर कर सकते हैं। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि नए विवादों से पहले पुराने लंबित मामलों का निपटारा किया जाए।

जीएसटीएटी का महत्व

करदाताओं के लिए न्याय के प्रतीक के रूप में वर्णित, जीएसटीएटी से मुकदमेबाजी में देरी, नकदी प्रवाह में रुकावट और कानूनी अनिश्चितता को कम करने की उम्मीद है, जिससे विशेष रूप से एमएसएमई और निर्यातकों को लाभ होगा। एक एकल राष्ट्रव्यापी अपीलीय मंच प्रदान करके, यह न्यायाधिकरण सहकारी संघवाद को मजबूत करेगा और करदाताओं का विश्वास बढ़ाएगा।

संरचना और पैमाना

GSTAT भारत का सबसे बड़ा न्यायाधिकरण होगा, जिसमें 32 पीठों में 116 सदस्य होंगे और यह 45 स्थानों पर कार्यरत होगा। इसके संचालन के पहले दिन से ही 4 लाख से अधिक लंबित मामलों को निपटाने की उम्मीद है। पहले करदाताओं को उच्च न्यायालयों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब यह न्यायाधिकरण GST के अंतर्गत द्वितीय अपीलों के लिए मंच के रूप में कार्य करेगा।

नेतृत्व और नियुक्तियाँ

सरकार पहले ही वरिष्ठ सदस्यों को प्रमुख पदों पर नियुक्त कर चुकी है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा को प्रधान पीठ का अध्यक्ष (मई 2024) नियुक्त किया गया है। अन्य नियुक्तियों में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मयंक कुमार जैन को न्यायिक सदस्य, ए. वेणु प्रसाद (सेवानिवृत्त आईएएस) को तकनीकी सदस्य (राज्य) और अनिल कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त आईआरएस) को तकनीकी सदस्य (केंद्र) के रूप में नियुक्त किया गया है।

शासन प्रभाव

GSTAT के गठन से GST कानून की व्याख्या में एकरूपता आने, पूर्वानुमानित परिणाम सुनिश्चित होने और उच्च न्यायालयों पर बोझ कम होने की उम्मीद है। इसे करदाताओं और प्रशासन के बीच विश्वास निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, साथ ही यह भारत के कर प्रशासन ढांचे में भी सुधार लाएगा।

केरल मंत्रिमंडल ने पारंपरिक कृषि त्योहारों को पुनर्जीवित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी

केरल की ग्रामीण परंपराओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आयोजित विशेष मंत्रिमंडल बैठक में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन हेतु एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, जिससे कलापूत, कन्नुपूत, मरमादी और पोथोट्टम जैसे पारंपरिक कृषि त्योहारों के आयोजन का मार्ग प्रशस्त होगा।

विधायी प्रक्रिया

विधेयक अनुमोदन: केरल मंत्रिमंडल ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन हेतु एक विधेयक को मंजूरी दे दी है।

अगले चरण: स्वीकृत विधेयक अब केरल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि यह पारित हो जाता है, तो इसे भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह मामला समवर्ती सूची में आता है। तभी यह संशोधन लागू होगा, जिससे राज्य में इन त्योहारों को कानूनी रूप से आयोजित करने की अनुमति मिल जाएगी।

सांस्कृतिक उत्सवों का पुनरुद्धार

- पारंपरिक उत्सव: इस विधेयक का उद्देश्य कलापूत, कन्नुपूत, मरमादी और पोथोट्टम जैसे पारंपरिक कृषि उत्सवों को पुनर्जीवित करना है, जो कभी राज्य के कृषि जीवन और उत्सवों का अभिन्न अंग थे।
- सांस्कृतिक महत्व: इन सांस्कृतिक आयोजनों पर पशु क्रूरता के आधार पर केंद्रीय कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालाँकि, किसान और सांस्कृतिक समूह लंबे समय से इनके पुनरुद्धार की माँग कर रहे हैं, उनका तर्क है कि ये उत्सव केरल की कृषि विरासत में गहराई से निहित हैं और इन्हें क्रूरता के समान नहीं माना जाना चाहिए।

कानूनी मिसाल

तमिलनाडु का उदाहरण: यह कदम तमिलनाडु द्वारा अपनाए गए मॉडल का अनुसरण करता है, जिसने केंद्रीय अधिनियम में इसी तरह के एक संशोधन के माध्यम से जल्लीकट्टू—एक पारंपरिक बैल-वशीकरण खेल—को सफलतापूर्वक वैध कर दिया था। उस मिसाल को अब केरल के लिए अपने लंबे समय से मनाए जाने वाले कृषि रीति-रिवाजों को वापस लाने का मार्ग प्रशस्त करने के रूप में देखा जा रहा है।

परंपरा और कल्याण में संतुलन

- सांस्कृतिक गौरव: समर्थकों का तर्क है कि इन आयोजनों के पुनरुद्धार से न केवल ग्रामीण समुदायों में सांस्कृतिक गौरव की भावना बहाल होगी, बल्कि केरल की पारंपरिक पहचान को संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी।

- पशु कल्याण संबंधी चिंताएँ: पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा क्रूरता और शोषण की चिंताओं का हवाला देते हुए आपत्तियाँ उठाने की उम्मीद है।
- सरकार का रुख: सरकार ने संकेत दिया है कि कल्याणकारी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पुनरुद्धार के साथ सख्त दिशानिर्देश और नियामक तंत्र भी लागू होंगे।

केरल

- राजधानी: तिरुवनंतपुरम
- ज़िले: 14
- राज्यपाल: राजेंद्र आर्लेकर
- मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन (माकपा)
- राज्यसभा: 9 सीटें
- लोकसभा: 20 सीटें
- साक्षरता (2024): 95.3% (चौथा)
- लिंगानुपात (2025): 1084♀/1000♂ (17वां)

राजस्थान विधानसभा ने भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पारित किया

राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पारित किया, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और व्यापार सुगमता में सुधार लाना है।

मुख्य प्रावधान:

- यह संशोधन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को संशोधित करता है ताकि RIICO (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड) को आवंटित सभी भूमि भूखंडों को कानूनी मान्यता प्रदान की जा सके।
- ये परिवर्तन संशोधन के लागू होने से पहले और बाद में आवंटित भूखंडों पर लागू होंगे, सिवाय 18 सितंबर, 1979 से पहले आवंटित भूमियों के, जिनके पट्टे पहले ही रद्द कर दिए गए थे।
- यह संशोधन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि विनिमय, रूपांतरण, उपविभाजन, विलय, नियमितीकरण, लेआउट योजना, भूमि उपयोग परिवर्तन और विकास कार्य जैसी गतिविधियों को वैध बनाता है।
- यह संशोधन RIICO को औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अधिक नियामक और नियोजन अधिकार प्रदान करता है, जिससे सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ सुनिश्चित होती हैं।

प्रभाव:

इससे विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आने और भूमि प्रबंधन में सुचारू संचालन सुनिश्चित होने की उम्मीद है। स्पष्ट भूमि नियमों के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ने की संभावना है, जिससे नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। यह संशोधन राजस्थान की एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षा का समर्थन करता है।

सरकार का दृष्टिकोण:

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस विधेयक को उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और रीको के कामकाज के लिए एक मज़बूत कानूनी ढाँचा प्रदान करने हेतु एक "आवश्यक सुधार" बताया।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने विवादास्पद आतंकवाद विरोधी विधेयक पर हस्ताक्षर किए, आलोचकों ने राज्य की शक्ति के विस्तार की चेतावनी दी

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आतंकवाद विरोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है। यह विधेयक 1997 के आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) के प्रावधानों को पुनर्जीवित और विस्तारित करता है, जिससे सरकार और सेना को आतंकवाद और उससे संबंधित अपराधों से निपटने के लिए अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

विधायी पृष्ठभूमि

- पारित: इस विधेयक को इसी महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय सभा और सीनेट, दोनों ने मंजूरी दी थी।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति: राष्ट्रपति जरदारी की स्वीकृति से यह विधेयक औपचारिक रूप से कानून बन गया।

मुख्य प्रावधान

- निवारक निरोध: राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होने का संदेह होने पर बिना किसी आरोप के तीन महीने तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
- विस्तारित अधिकार: संघीय अधिकारियों और सशस्त्र बलों को नए प्रावधानों के तहत व्यक्तियों को हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान करता है।
- व्यापक परिभाषाएँ: आतंकवाद की परिभाषा में ऐसे कृत्य शामिल हैं जो "भय फैलाते हैं" या संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं, जिनमें संभावित रूप से कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं।

विवाद और आलोचना

- नागरिक स्वतंत्रता संबंधी चिंताएँ: आलोचकों का तर्क है कि इस कानून के कारण मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने और असहमति के दमन को बढ़ावा मिल सकता है।
- सैन्यीकरण: सेना को हिरासत में लेने की शक्तियों का विस्तार घरेलू मामलों में सशस्त्र बलों की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंताएँ पैदा करता है।
- ऐतिहासिक संदर्भ: पाकिस्तान के आतंकवाद-रोधी कानूनों का इस्तेमाल पहले भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ किया जा चुका है, जिससे इनके दुरुपयोग की आशंकाएँ बढ़ गई हैं।

सरकार का बचाव

- सुरक्षा संबंधी औचित्य: सरकार इस संशोधन का बचाव बढ़ते उग्रवाद, जबरन वसूली और फिरौती के लिए अपहरण की

घटनाओं का मुकाबला करने के लिए आवश्यक बताकर करती है।

- कानूनी निगरानी: अधिकारियों का दावा है कि इस कानून में निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

निहितार्थ

इस कानून का लागू होना पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो नागरिक स्वतंत्रता और शासन में सेना की भूमिका से जुड़ी चिंताओं के साथ सुरक्षा उपायों को संतुलित करता है।

पाकिस्तान

- राजधानी: इस्लामाबाद
- राष्ट्रपति: आसिफ अली जरदारी
- प्रधानमंत्री: शहबाज शरीफ़
- मुख्य न्यायाधीश: याह्या अफरीदी
- मुद्रा: पाकिस्तानी रुपया

लघु लेख

अधिकारों और दायित्वों में संतुलन: आरटीई अधिनियम एवं भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

परिचय

शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक विकास के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक माना जाता है। इसके महत्व को समझते हुए, भारत ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE अधिनियम) लागू किया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन ने महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है, खासकर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर इसकी प्रयोज्यता को लेकर।

RTE अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

RTE अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित।
- कक्षाओं, शिक्षक-छात्र अनुपात और स्वच्छता सहित बुनियादी ढाँचे के मानदंडों का रखरखाव।
- प्रवेश के लिए कैपिटेशन शुल्क, साक्षात्कार या स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध।
- आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से विद्यालयों की मान्यता और जवाबदेही।
- इन प्रावधानों का उद्देश्य भारत में सभी बच्चों के लिए शिक्षा को न्यायसंगत, समावेशी और सुलभ बनाना है।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और उनके अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषाई) को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने

और उनका संचालन करने का अधिकार दिया गया है। यह विशेष सुरक्षा शिक्षा के माध्यम से अल्पसंख्यक पहचान, संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए है।

अल्पसंख्यक संस्थान मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं:

- धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान - ईसाई, मुस्लिम, सिख आदि समुदायों द्वारा संचालित स्कूल और कॉलेज।
- भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान - क्षेत्रीय या भाषाई पहचान को संरक्षित करने वाले संस्थान, जैसे गैर-देशी राज्यों में मराठी, तमिल या तेलुगु स्कूल।
- संविधान यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए इन संस्थानों को प्रशासन, प्रवेश और पाठ्यक्रम के मामलों में स्वायत्तता प्राप्त हो।

आरटीई और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच टकराव

मुख्य बहस इस बात पर उठती है कि क्या आरटीई अधिनियम के प्रावधान—विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए 25% आरक्षण—अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2012, सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ):

न्यायालय ने आरटीई अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों को 25% आरक्षण से छूट दी, यह कहते हुए कि उन्हें इसका पालन करने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 30 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा।

बाद में स्पष्टीकरण (प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम भारत संघ, 2014):

न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों अल्पसंख्यक संस्थान आरटीई अधिनियम के दायित्वों के दायरे से बाहर हैं।

इस प्रकार, अल्पसंख्यक स्कूल कानूनी रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने के लिए बाध्य नहीं हैं, हालाँकि कुछ स्वेच्छा से उन्हें प्रवेश देते हैं।

समानता और अल्पसंख्यक स्वायत्तता में संतुलन

- अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट देने से एक दोहरी व्यवस्था बन गई है। एक ओर, सरकार सभी बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना चाहती है; दूसरी ओर, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की जाती है।
- आलोचकों का तर्क है कि इस छूट से गरीब बच्चों के लिए उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण सीटों की संख्या कम हो जाती है। हालाँकि, समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि समुदाय-आधारित शिक्षा में राज्य के हस्तक्षेप को रोकने के लिए अल्पसंख्यक स्वायत्तता आवश्यक है।

निष्कर्ष

शिक्षा का अधिकार अधिनियम सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए इसकी छूट सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के बीच नाजुक संतुलन को उजागर करती है। हालाँकि अल्पसंख्यक संस्थान अधिनियम के कुछ प्रावधानों से बाहर हैं, फिर भी वे भारत के शैक्षिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्माताओं

के लिए भविष्य की चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा में समानता और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण के लक्ष्य सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में बने रहें।

धनखड़ के इस्तीफे से लेकर राधाकृष्णन की जीत तक: उपराष्ट्रपति चुनाव की व्याख्या

एक दुर्लभ मध्यावधि चुनाव

भारत में सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति पद के लिए एक दुर्लभ मध्यावधि चुनाव हुआ। जुलाई में जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद, उनके कार्यकाल के तीन साल से भी कम समय बाद, यह चुनाव आवश्यक हो गया। इस चुनाव में वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में विजयी हुए। उनका चुनाव न केवल इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह एक अप्रत्याशित रिक्ति के बाद हुआ था, बल्कि इसलिए भी कि यह बढ़ते राजनीतिक संघर्ष के समय हुआ था।

चुनाव परिणाम

- सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने विपक्ष समर्थित उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को हराया। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को 300 वोट मिले। जीत का अंतर—152 वोट—हाल के वर्षों में सबसे कम अंतर में से एक था।
- यह चुनाव संसद में आयोजित किया गया था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों ने अपने वोट डाले। मतदान लगभग 98 प्रतिशत रहा, जो दर्शाता है कि सांसदों ने इस संवैधानिक ज़िम्मेदारी को कितनी गंभीरता से लिया। हालाँकि, कुछ दलों ने मतदान में भाग नहीं लिया, जिससे राजनीतिक रणनीति और आंतरिक असंतोष पर सवाल उठे।
- परिणाम घोषित होने के बाद, राधाकृष्णन ने अपनी जीत को "राष्ट्रवादी विचारधारा की विजय" बताया और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन के अनुरूप, भारत के विकास के लिए काम करने का वादा किया।

जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया

हालाँकि जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2025 में इस्तीफा देते समय स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला दिया था, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसके और भी गहरे कारणों की ओर इशारा किया। कई कारकों ने उनके और सरकार के बीच मतभेद पैदा किए।

एक न्यायाधीश के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करना

धनखड़ ने भ्रष्टाचार के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश को हटाने के लिए विपक्ष समर्थित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जबकि सरकार इस मामले को अलग तरीके से संभालना चाहती थी। इस स्वतंत्र निर्णय ने सत्तारूढ़ नेतृत्व को नाराज़ कर दिया।

महत्वपूर्ण बैठकों से अनुपस्थिति

धनखड़ ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई, लेकिन कई वरिष्ठ मंत्री अनुपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति ने समन्वय की कमी और

बढ़ते अविश्वास का संकेत दिया। धनखड़ कथित तौर पर नाराज़ थे और इस घटना से संबंधों में और तनाव पैदा हो गया।

न्यायपालिका की लगातार आलोचना

अपने पूरे करियर के दौरान, धनखड़ न्यायिक अतिक्रमण के बारे में मुखर रहे। उपराष्ट्रपति रहते हुए भी, उन्होंने न्यायपालिका पर तीखी टिप्पणियाँ जारी रखीं। जहाँ कुछ लोगों ने उनकी स्पष्टवादिता की सराहना की, वहीं सरकार में अन्य लोगों ने इसे एक अनावश्यक विवाद माना जिसने उनके कार्य संबंधों को कमज़ोर कर दिया।

अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बाद रुख में बदलाव

2024 के अंत में, धनखड़ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से बच गए। हालाँकि, इस प्रकरण के बाद, उन्होंने अधिक स्वतंत्र रुख अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने संवेदनशील विषयों पर बहस की अनुमति दी, कभी-कभी विपक्षी सदस्यों का पक्ष लिया और सरकारी नीतियों पर सवाल उठाए। इस बदलाव ने उन्हें सत्तारूढ़ गठबंधन से दूर कर दिया और यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि उनका इस्तीफा बढ़ते दबाव का नतीजा था।

हालाँकि धनखड़ ने पद छोड़ते समय सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का धन्यवाद किया, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि उनका इस्तीफा केवल स्वास्थ्य समस्याओं के बजाय बढ़ती राजनीतिक बेचैनी का नतीजा था।

उपराष्ट्रपति की भूमिका और चुनाव प्रक्रिया

- भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं और उच्च सदन में व्यवस्था बनाए रखने तथा सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभालते हैं।
- उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा पाँच वर्षों के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत, राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत गुप्त मतदान द्वारा होता है, जो सांसदों को वरीयता क्रम में उम्मीदवारों को रैंक करने की अनुमति देता है। नामांकन दाखिल करने के लिए एक उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, साथ ही एक सुरक्षा जमा भी होना चाहिए।
- संविधान में यह अनिवार्य है कि यदि त्यागपत्र, मृत्यु या पदच्युति के कारण कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो "यथाशीघ्र" नया चुनाव कराया जाना चाहिए। 2025 का चुनाव 1987 के बाद पहला मध्यावधि उपराष्ट्रपति चुनाव था, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि धनखड़ का इस्तीफा कितना असामान्य था।

आगे की राह

- सी.पी. राधाकृष्णन को अब ऐसे समय में राज्यसभा की अध्यक्षता का कार्यभार संभालना है जब राजनीतिक मतभेद तीव्र हैं और बहसें लगातार गर्म होती जा रही हैं। उनकी

भूमिका न केवल प्रशासनिक होगी, बल्कि प्रतीकात्मक भी होगी, क्योंकि उनसे सरकार और विपक्ष के हितों में संतुलन बनाए रखते हुए संसदीय मर्यादा बनाए रखने की अपेक्षा की जाएगी।

- यह प्रकरण संवैधानिक पदों और राजनीतिक सत्ता के बीच के नाजुक रिश्ते को भी उजागर करता है। हालाँकि उपराष्ट्रपति का पद तटस्थ होना चाहिए, लेकिन राजनीति की वास्तविकता अक्सर तनाव पैदा करती है जब उच्च पदस्थ व्यक्ति सत्ताधारी प्रतिष्ठान से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं।

निष्कर्ष

कार्यकाल के बीच में ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के संवैधानिक इतिहास में एक दुर्लभ घटना है। जगदीप धनखड़ के

इस्तीफे ने उन चुनौतियों को उजागर किया जो तब उत्पन्न होती हैं जब संवैधानिक सत्ता राजनीतिक अपेक्षाओं से टकराती है। इस बीच, सी.पी. राधाकृष्णन का चुनाव निरंतरता और परिवर्तन, दोनों को दर्शाता है। निरंतरता, क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन ने पद पर नियंत्रण बनाए रखा; और परिवर्तन, क्योंकि कांग्रेस के मुकाबले ने दिखाया कि विपक्षी गठबंधन अधिक प्रभावी होते जा रहे हैं। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, उपराष्ट्रपति का कार्यालय न केवल संसद के कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहेगा, बल्कि यह दशानि में भी महत्वपूर्ण रहेगा कि संवैधानिक भूमिकाओं को गरिमा, स्वतंत्रता और संतुलन के साथ कैसे निभाया जा सकता है।

"संघर्ष इंसान को मज़बूत बनाता है !
फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों न हो !!

"सफलता का मुख्य आधार !
सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है !!"

TEACHER'S DAY



Inception: 1967

05
SEP

Importance

To mark the birth anniversary of Bharat Ratna recipient Dr Sarvepalli Radhakrishnan who was the First Vice President and second President of India post-Independence.

Motto

To honour teachers for their contributions in shaping the lives of students.

Sarvepalli Radhakrishnan

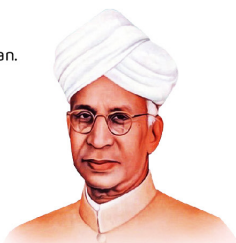
(5 September 1888 - 17 April 1975)
An Indian philosopher, academic, and statesman.

Awards

Bharat Ratna, Templeton Prize, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, Order of Merit.

Books

The philosophy of Rabindranath Tagore, Indian Philosophy, The Hindu View of Life, An Idealist View of Life, Recovery of Faith, The Brahma Sutra, etc.



INTERNATIONAL LITERACY DAY



1st Celebrated
1967

10
SEP

Importance

To remind the international community of the importance of literacy for individuals, communities and societies, and the need for intensified efforts towards more literate societies.

Organisation Involved

UNESCO.

Highlight

Role of educators and changing pedagogies.

Proclamation

26 October 1966.

2025 Theme

Promoting literacy in the digital era.

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाएँ

भारत इंटरपोल एशियाई समिति के लिए निर्वाचित

सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। बहु-चरणीय मतदान प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित इस चुनाव से संगठित अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी सुरक्षा चुनौतियों पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।

भारत का प्रतिनिधित्व और भूमिका:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सीबीआई इंटरपोल के लिए भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) के रूप में कार्य करता है, जो इंटरपोल से संबंधित सभी समन्वय और पहलों के लिए ज़िम्मेदार है। यह समिति क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर विचार-विमर्श करने, समन्वित कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने और क्षेत्र के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं की पहचान करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करेगी।

चुनाव का महत्व:

भारत का शामिल होना अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग और सुरक्षा मामलों में उसके बढ़ते नेतृत्व को दर्शाता है, और अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग पहलों में उसकी भागीदारी को मज़बूत करता है। यह वैश्विक पुलिसिंग लक्ष्यों और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़े हुए सुरक्षा सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करता है।

इंटरपोल एशियाई समिति के बारे में:

यह समिति एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन को सलाह देती है और सदस्य देशों को प्रभावित करने वाले रणनीतिक और परिचालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा को सुगम बनाती है। इसका उद्देश्य पुलिस सहयोग में सुधार, सूचना साझाकरण को बढ़ावा देना और सीमा पार अपराध से निपटने के लिए संयुक्त पहलों का समन्वय करना है।

इंटरपोल:

इंटरपोल, या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जो वैश्विक पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण को सुगम बनाता है।

- इंटरपोल मुख्यालय: ल्योन, फ्रांस।
- सदस्यता: 195 देश, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन बनाता है।

भारत यूपीयू की प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद में पुनः निर्वाचित

भारत को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की प्रशासन परिषद (सीए) और डाक संचालन परिषद (पीओसी) दोनों के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। यह पुनर्निर्वाचन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 28वीं यूपीयू कांग्रेस के दौरान हुआ।

यूपीयू निकायों की भूमिकाएँ

- प्रशासन परिषद (सीए): नीति, नियामक और शासन संबंधी मामलों के लिए उत्तरदायी।
- डाक संचालन परिषद (पीओसी): तकनीकी और परिचालन निकाय, जो दुनिया भर में डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है।

भारत के योगदान और उपलब्धियाँ

भारत 1876 से यूपीयू का सदस्य रहा है।

- डिजिटल परिवर्तन पहलों का समर्थन किया, जिनमें शामिल हैं: डिजीपिन (डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम), यूपीआई-सक्षम सीमा-पार प्रेषण
- डाक घर निर्यात केंद्रों के माध्यम से ई-कॉमर्स सुविधा
- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए विस्तारित समर्थन, एशिया, अफ्रीका और अन्य देशों के डाक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- सदस्यता योगदान और स्वैच्छिक निधि के माध्यम से यूपीयू की स्थिरता में वित्तीय योगदान दिया।

भविष्य का दृष्टिकोण

दुबई चक्र के दौरान भारत नवाचार, समावेशिता और वैश्विक सहयोग में अपने प्रयास जारी रखेगा। भारत ने आगामी चक्र में प्रशासन परिषद में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने में भी रुचि व्यक्त की है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू):

- 1874 में स्थापित (बर्न की संधि)।
- मुख्यालय: बर्न, स्विट्जरलैंड।
- 1948 से संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी।
- सदस्यता: 192 देश।
- प्राथमिक उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय डाक नीतियों और सेवाओं का समन्वय।
- महानिदेशक: मासाहिको मेटोकी

भारतीय डाक:

1.5 लाख से अधिक डाकघरों वाला विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क।

वित्तीय समावेशन, डिजिटल सेवाओं और ग्रामीण संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- सचिव, डाक विभाग: सुश्री वंदिता कौल
- डाक सेवाएँ महानिदेशक: श्री जितेंद्र गुप्ता

अमेरिका ने एंटीफा को घरेलू आतंकवादी संगठन घोषित किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वामपंथी एंटीफा आंदोलन को घरेलू आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह कदम यूटा विश्वविद्यालय में रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के बाद उठाया गया था।

परिभाषा और विवरण:

एंटीफा, "फासीवाद-विरोधी" का संक्षिप्त रूप है, जो फासीवाद और दक्षिणपंथी विचारधाराओं का विरोध करने वाले अति-वामपंथी समूहों को संदर्भित करता है। ट्रंप के आदेश में इसे एक सैन्यवादी, अराजकतावादी उद्यम बताया गया है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने और वैध राजनीतिक गतिविधियों में बाधा डालने के लिए हिंसा और आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। यह आदेश अमेरिकी अधिकारियों को एंटीफा की ओर से काम करने या उसे भौतिक सहायता प्रदान करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है।

पृष्ठभूमि और पिछली गतिविधियाँ:

कार्यकारी आदेश में एंटीफा के सविनय अवज्ञा और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के इतिहास का हवाला दिया गया है, जिसमें 2017 में ट्रंप के पहले उद्घाटन के दौरान की घटनाएँ, चार्लोट्सविले में नस्लवादी प्रदर्शनों के प्रति-विरोध और 6 जनवरी, 2021 को अमेरिकी कैपिटल दंगे में कथित संलिप्तता शामिल है। एंटीफा से जुड़े कार्यकर्ता अक्सर काले कपड़े और मुखौटे पहनते हैं और अति-दक्षिणपंथी समूहों के खिलाफ संघर्ष में शामिल होते हैं।

राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ:

आलोचकों का तर्क है कि इस पदनाम का इस्तेमाल असहमति को दबाने और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। यह कदम अमेरिका में दोनों प्रमुख दलों के सदस्यों के खिलाफ बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण और हिंसा के बीच उठाया गया है। ट्रंप पहले भी वामपंथी समूहों पर कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं और एंटीफा पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर हमला करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने का आरोप लगा चुके हैं।

एंटीफा और अमेरिकी संदर्भ:

- उत्पत्ति: एंटीफा की जड़ें 1930 के दशक के जर्मनी में हैं, जिसका गठन एडॉल्फ हिटलर और फासीवाद का विरोध करने वाले समाजवादी समूहों द्वारा किया गया था।
- प्रकृति: यह एक औपचारिक संगठन के बजाय एक शिथिल रूप से संगठित, विकेन्द्रीकृत आंदोलन है।
- रणनीति: कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा और कभी-कभी हिंसा का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर आत्मरक्षा का दावा करते हैं।
- अमेरिकी कानूनी संदर्भ: कार्यकारी आदेश अधिकारियों को घरेलू आतंकवाद के प्रावधानों के तहत समर्थकों या सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है।
- हालिया घटना: 10 सितंबर, 2025 को यूटा विश्वविद्यालय में चार्ली किर्क की हत्या।
- आलोचना: मानवाधिकार अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि इस कदम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक असहमति पर अंकुश लग सकता है।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्रों में बढ़ता तनाव

खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के खिलाफ आतंकवाद-रोधी अभियान की आड़ में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा (केपी) में पाकिस्तान के सैन्य अभियानों में नागरिक हताहत हुए हैं। केपी की तिराह घाटी में हाल ही में हुए हवाई हमलों में 30 लोग मारे गए, जिसमें पाकिस्तान ने चीन निर्मित जे-17 लड़ाकू विमानों और लेज़र-गाइडेड एल-6 बमों का इस्तेमाल किया। विश्लेषकों का सुझाव है कि ये अभियान आतंकवादी समूहों के साथ-साथ स्थानीय आबादी को भी निशाना बनाते हैं।

पृष्ठभूमि और कारण:

पाकिस्तान इन क्षेत्रों में रणनीतिक परियोजनाओं को सुरक्षित करने और आतंकवादी खतरों को खत्म करने के लिए चीन और अमेरिका के दबाव का सामना कर रहा है। जहाँ चीन अपने निवेश पर हमलों को लेकर चिंतित है, वहीं अमेरिका यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि खनिज और बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ें। हालाँकि, स्थानीय लोगों के प्रतिरोध, अफ़ग़ान समर्थन की कमी और पिछली सैन्य असफलताओं के कारण पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों से निपटने में संघर्ष करना पड़ा है।

स्थानीय समुदायों पर प्रभाव:

बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के स्थानीय लोग लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार द्वारा संसाधनों के दोहन की शिकायत करते रहे हैं, जिसका लाभ मुख्य भूमि पाकिस्तान को दिया जाता है जबकि उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सेना के अभियानों को नागरिकों को निशाना बनाने वाला माना जाता है, जिससे व्यापक शोक और आक्रोश फैल रहा है। 10 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले में 10 लोगों की मौत सहित पहले हुए हमलों में नागरिक हताहतों की एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने आलोचना की है।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

पाकिस्तान के भीतर भी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) जैसे विपक्षी दलों ने सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकाय नागरिक सुरक्षा के प्रति पाकिस्तान की उपेक्षा को उजागर करते रहते हैं, और कहते हैं कि आतंकवाद-रोधी अभियानों के परिणामस्वरूप अक्सर निर्दोष लोगों को नुकसान पहुँचता है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य

- बलूचिस्तान: क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, खनिजों और प्राकृतिक गैस सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध।
- खैबर पख्तूनख्वा (खैबर पख्तूनख्वा): पाकिस्तान का उत्तर-पश्चिमी प्रांत, अफ़ग़ानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है; ऐतिहासिक रूप से उग्रवाद और उग्रवाद से प्रभावित रहा है।
- तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी): पाकिस्तान में कई हमलों के लिए ज़िम्मेदार इस्लामी आतंकवादी समूह।
- चीन-पाकिस्तान सहयोग: चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के तहत रणनीतिक परियोजनाएँ अक्सर इन्हीं क्षेत्रों में स्थित होती हैं।

- अमेरिकी हित: यह सुनिश्चित करना कि बलूचिस्तान में आतंकवादी समूह खनिज और बुनियादी ढाँचे के सौदों में बाधा न डालें।
- अंतर्राष्ट्रीय आलोचना: मानवाधिकार संगठनों ने संघर्ष क्षेत्रों में नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए अभियानों की बार-बार निंदा की है।

दक्षिण कोरिया-अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाई सुंग-लाक ने कहा कि उत्तर कोरिया के रुख के बावजूद, परमाणु निरस्तीकरण ही अंतिम लक्ष्य है।

उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्तीकरण के लिए तीन-चरणीय योजना:

- उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर तत्काल रोक।
- मौजूदा सुविधाओं को बंद करना और उनकी निगरानी करना।
- परमाणु अवसंरचना को पूरी तरह से नष्ट करना।
- विश्वास-निर्माण के उपाय: दक्षिण कोरिया ने विश्वास-निर्माण के उपायों के माध्यम से तनाव कम करने पर ज़ोर दिया, साथ ही निरोध और सुरक्षा सुनिश्चित की।

APEC शिखर सम्मेलन 2025:

- स्थान: ग्योंगजू, दक्षिण कोरिया।
- उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के भाग लेने की उम्मीद नहीं है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भाग लेने का कार्यक्रम है।

कोरियाई प्रायद्वीप समस्या:

- द्वितीय विश्व युद्ध (1945) के बाद उत्तर कोरिया (DPRK) और दक्षिण कोरिया (ROK) में विभाजित।
- कोरियाई युद्ध (1950-1953): शांति संधि के बजाय युद्धविराम के साथ समाप्त हुआ; प्रायद्वीप तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में है।
- उत्तर कोरिया ने 2005 में खुद को परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र घोषित किया।

उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम:

2006 में पहला परमाणु परीक्षण किया। तब से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए कई परीक्षण किए हैं।

दक्षिण कोरिया-अमेरिका गठबंधन:

- अमेरिकी सैनिक 1953 से एक पारस्परिक रक्षा संधि के तहत दक्षिण कोरिया में तैनात हैं।
- मुख्य उद्देश्य: उत्तर कोरियाई आक्रमण को रोकना और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC):

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1989 में स्थापित।

सदस्य: अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि सहित 21 अर्थव्यवस्थाएँ। भारत APEC का सदस्य नहीं है।

मॉरीशस की संप्रभुता पुनः प्राप्त करने के साथ भारत ने चागोस में रणनीतिक पैर जमाया

भारत हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अपनी रणनीतिक स्थिति को मज़बूत करने के लिए तैयार है क्योंकि मॉरीशस ने चागोस द्वीप समूह पर औपचारिक रूप से संप्रभुता पुनः प्राप्त कर ली है। चागोस द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र है जहाँ डिएगो गार्सिया में अमेरिका-ब्रिटिश सैन्य अड्डा स्थित है। यह अड्डा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी सैन्य प्रतिष्ठानों में से एक है। इस विकास के एक भाग के रूप में, भारत ने मॉरीशस को उसकी निगरानी क्षमताओं का विस्तार करने, जल सर्वेक्षण मानचित्रण में सुधार करने और उसके नए विस्तारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के प्रबंधन में सहायता करने पर सहमति व्यक्त की है।

भारत की ओर से मॉरीशस को सहायता

यह घोषणा 12 सितंबर 2025 को मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम की वाराणसी यात्रा के दौरान की गई थी, जो 2024 में सत्ता में लौटने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपग्रह ट्रैकिंग अवसंरचना की स्थापना और समुद्री निगरानी प्रणालियों के विस्तार जैसे क्षेत्रों में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। भारत 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा, जिसका उपयोग स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढाँचे के विकास और समुद्री सुरक्षा पहलों के लिए किया जाएगा।

चागोस विवाद का समाधान

चागोस द्वीपसमूह पर संप्रभुता का मुद्दा मई 2025 में सुलझ गया, जब यूनाइटेड किंगडम ने मॉरीशस के दावे को मान्यता देते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जबकि अमेरिका-ब्रिटिश सैन्य अभियानों को जारी रखने के लिए डिएगो गार्सिया अड्डे पर 99 साल का पट्टा बरकरार रखा। इस समझौते ने 1960-70 के दशक में चागोस की आबादी को जबरन बेदखल करने से जुड़े दशकों पुराने विवाद को समाप्त कर दिया।

भारत के लिए भू-राजनीतिक महत्व

हालाँकि डिएगो गार्सिया अड्डे का संचालनात्मक नियंत्रण अभी भी अमेरिका और ब्रिटेन के पास है, लेकिन व्यापक चागोस समुद्री क्षेत्र पर मॉरीशस का संप्रभु नियंत्रण भारत के लिए नए अवसर खोलता है। अपनी बढ़ती साझेदारी के साथ, भारत समुद्री सुरक्षा, अवैध मछली पकड़ने का मुकाबला करने और निगरानी नेटवर्क को मज़बूत करने में अपने सहयोग का विस्तार कर सकता है। यह कदम हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव को संतुलित करने और छोटे द्वीपीय देशों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी बनाने के भारत के प्रयासों को दर्शाता है।

सामरिक संदर्भ और व्यापक पहल

चागोस द्वीप समूह में भारत की भागीदारी, अगले दशक में द्वीप परियोजना जैसे अन्य सामरिक प्रयासों के अनुरूप है, जहाँ भारत

अपनी परिचालन उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक रनवे और बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि "मॉरीशस पर अब कई ज़िम्मेदारियाँ हैं, और भारत उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में एक पसंदीदा साझेदार है।" यह विकास वैश्विक शक्ति प्रतिद्वंद्विता के बीच छोटे देशों के हितों की रक्षा करने वाले एक सुरक्षा गारंटर, क्षमता-निर्माता और प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की छवि को पुष्ट करता है।

दक्षिण कोरिया ने ली के 5 साल के कार्यकाल में अमेरिका से ओपीकॉन ट्रांसफर करने की योजना की पुष्टि की

दक्षिण कोरिया युद्ध के समय का ऑपरेशनल कंट्रोल (ओपीकॉन) अमेरिका से ले लेगा। यह ट्रांसफर राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के पांच साल के कार्यकाल के दौरान पूरा हो जाएगा। यह फैसला सरकार के प्रमुख रक्षा नीति कार्यों का हिस्सा है।

ओपीकॉन का मतलब

ओपीकॉन का मतलब है युद्ध के समय दक्षिण कोरियाई सेना को कमांड करने का अधिकार। दक्षिण कोरिया शांति काल में अपनी सेना को नियंत्रित करता है, लेकिन युद्ध के समय नहीं। यह ट्रांसफर पहले 2015 में होने वाला था, लेकिन उत्तर कोरिया से बढ़ते सुरक्षा खतरों के कारण इसमें देरी हुई।

ट्रांसफर के लिए शर्तें

दक्षिण कोरिया को यह साबित करना होगा कि वह अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त सेना का नेतृत्व कर सकता है। इसके पास मजबूत स्ट्राइक और एयर-डिफेंस क्षमता होनी चाहिए। क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति स्थिर रहनी चाहिए।

अन्य रक्षा योजनाएं

सरकार रक्षा काउंटरइंटेलिजेंस कमांड को पुनर्गठित और बाद में भंग करने की योजना बना रही है। यह उत्तर कोरिया से निपटने के लिए तीन-अक्षीय रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी। एक नई स्पेस स्टैटेजी कमांड चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाएगी।

दक्षिण कोरिया

- राजधानी: सियोल
- राष्ट्रपति: ली जे म्यूंग
- प्रधानमंत्री: किम मिन-सक
- मुद्रा: कोरियाई रिपब्लिकन वॉन

श्रीलंका ने पूर्व राष्ट्रपतियों के विशेषाधिकार समाप्त किए

श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति अधिकार (निरसन) विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य पूर्व राष्ट्रपतियों और उनकी विधवाओं को प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्त करना है। यह विधेयक राष्ट्रपति अधिकार अधिनियम, 1986 को निरस्त करता है, जो पूर्व राष्ट्रपतियों को राज्य द्वारा वित्त पोषित आवास, परिवहन, कर्मचारी और सचिवीय भत्ते प्रदान करता था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह विधेयक संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, और उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि यह निहित अधिकारों को सीमित करता है और

इसके लिए दो-तिहाई संसदीय बहुमत और जनमत संग्रह की आवश्यकता है।

अध्यक्ष जगत विक्रमरत्ने ने संसद में इस फैसले की घोषणा की, जिससे विधेयक पारित होने का रास्ता साफ हो गया। यह कदम राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की सरकार की अत्यधिक सरकारी खर्च को कम करने की योजना का हिस्सा है। पूर्व राष्ट्रपतियों को अभी भी पेंशन मिलती रहेगी, जो संविधान के तहत संरक्षित है और इस निरसन से प्रभावित नहीं होगी।

इस मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य:

- राष्ट्रपति अधिकार अधिनियम, 1986 - पूर्व राष्ट्रपतियों और उनके परिवारों को विलासितापूर्ण विशेषाधिकार प्रदान करता था, जिसकी अक्सर राज्य की वित्तीय स्थिति पर बोझ के रूप में आलोचना की जाती थी।
- जनता की धारणा - इस विधेयक का पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के बेहतर उपयोग की दिशा में एक कदम के रूप में स्वागत किया गया है।
- शासन पर प्रभाव - यह राजनीतिक नेताओं के विशेषाधिकारों को सीमित करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जिससे संसाधनों के समान आवंटन को बढ़ावा मिलेगा।

भारत को मलक्का जलडमरूमध्य गश्ती में शामिल होने के लिए सिंगापुर का समर्थन प्राप्त

भारत को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले एक प्रमुख समुद्री मार्ग, मलक्का जलडमरूमध्य में गश्त में भाग लेने के लिए सिंगापुर का समर्थन प्राप्त हुआ है। सिंगापुर के समर्थन से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समुद्री प्रभाव में वृद्धि और मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे अन्य तटीय देशों के साथ सहयोग गहरा होने की उम्मीद है।

मलक्का जलडमरूमध्य का महत्व

मलक्का जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है, जहाँ से:

टन भार के हिसाब से वैश्विक व्यापार का 40-50% भाग गुजरता है। एशिया का 70% तेल आयात इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। यह मध्य पूर्व और अफ्रीका से चीन के आयात के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग है। यह जलडमरूमध्य एक भू-रणनीतिक अवरोध बिंदु है, और संघर्ष के दौरान इसकी नाकाबंदी वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकती है।

भारत के सामरिक हित

भारत का लगभग 60% समुद्री व्यापार, और लगभग 100% LNG आयात मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहाँ भारत की नौसेना मौजूद है, केवल 600 किमी दूर स्थित है, जिससे नौसैनिक जहाजों की तेजी से तैनाती संभव हो पाती है। गश्ती दल में भारत का शामिल होना उसकी 'एक्ट ईस्ट' नीति और क्षेत्र में एक व्यापक सुरक्षा प्रदाता बनने की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है। यह ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक सहयोग

समुद्री सुरक्षा के अलावा, भारत और सिंगापुर ने निम्नलिखित क्षेत्रों में पाँच समझौतों पर हस्ताक्षर किए:

- विमानन और हवाई संपर्क,
- कौशल विकास,
- हरित और डिजिटल शिपिंग,
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और
- फ़िनटेक अवसंरचना।

UNSC लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना अभियान समाप्त करेगा

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जहाँ लगभग 1,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। यह निर्णय दो वर्षों में संचालन बंद करने के लिए मतदान के साथ लिया गया।

अधिकार विस्तार

UNIFIL का 47 साल पुराना अधिदेश, जो इस सप्ताहांत समाप्त होने वाला था, को अंतिम बार 2026 के अंत तक बढ़ा दिया गया है। शांति सेना की सुरक्षित और व्यवस्थित वापसी सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त वर्ष प्रदान किया गया है। यह प्रस्ताव फ्रांस द्वारा तैयार किया गया था, जिसे अमेरिकी वीटो से बचने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था, जो UNIFIL के प्रति इज़राइल के विरोध को दर्शाता है।

UNIFIL की पृष्ठभूमि

दक्षिणी लेबनान पर इज़राइल के आक्रमण के बाद UNSC द्वारा 1978 में स्थापित।

प्राथमिक अधिदेश:

- इज़राइली सैनिकों की वापसी की निगरानी करना।
- दक्षिणी लेबनान में सत्ता बहाल करने में लेबनानी सरकार की सहायता करना।
- वर्तमान क्षमता: विभिन्न देशों के 10,800 शांति सैनिक, जिनमें 903 भारतीय सैनिक शामिल हैं।
- 2000 के दशक की शुरुआत में ब्रिगेडियर गणेशन आत्मनाथन और मेजर जनरल ललित मोहन तिवारी के नेतृत्व में यूनिफिल की कमान संभालते हुए भारत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भू-राजनीतिक संदर्भ

इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष के कारण यूनिफिल को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कमज़ोर लेबनानी सेना बीच में फँसी हुई है। यह बंद होना मध्य पूर्व के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की उपस्थिति में बदलाव का संकेत देता है।

भारत को 15 वर्षीय गहरे समुद्र में खनन अन्वेषण अधिकार प्राप्त

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) के साथ 15 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत को हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग रिज के 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (पीएमएस) के अन्वेषण का विशेष अधिकार प्रदान करता है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा घोषित।

पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (पीएमएस) का महत्व

पीएमएस समुद्री क्रस्ट से निकलने वाले गर्म जलतापीय तरल पदार्थों से बनते हैं। तांबा, जस्ता, लोहा, चांदी, सोना और प्लैटिनम से भरपूर। उच्च आर्थिक और रणनीतिक क्षमता, वैश्विक रुचि को आकर्षित करती है। भारत के अन्वेषण अधिकार गहरे समुद्र अनुसंधान और नीली अर्थव्यवस्था पहलों में इसके नेतृत्व को बढ़ाते हैं।

भारत की रणनीतिक स्थिति

भारत पीएमएस अन्वेषण के लिए आईएसए के साथ दो अनुबंध करने वाला पहला देश बन गया है। दूसरा अनुबंध मध्य भारतीय रिज और दक्षिण-पश्चिम भारतीय रिज को कवर करता है। भारत अब आईएसए के अधिदेश के तहत आवंटित सबसे बड़ा पीएमएस अन्वेषण क्षेत्र रखता है। यह समुद्री संसाधन विकास में भारत की समुद्री उपस्थिति और क्षमता को मज़बूत करता है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए):

- संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) 1982 के तहत स्थापित।
- मुख्यालय: किंग्स्टन, जमैका।
- राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल क्षेत्र में खनिज संबंधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ज़िम्मेदार।

ऑयल इंडिया और हिंदुस्तान कॉपर ने रणनीतिक खनिज अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने तांबे और संबंधित खनिजों जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण और विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

समझौते का महत्व

खान मंत्रालय ने इस समझौता ज्ञापन को भारत की खनिज सुरक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। यह साझेदारी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अनुरूप है, जिसे आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और तकनीकी उन्नति के लिए आवश्यक खनिजों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तांबा और अन्य महत्वपूर्ण खनिज नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा अनुप्रयोगों और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु:

भारत की महत्वपूर्ण खनिजों की सूची (2023) में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व आदि जैसे 30 खनिज शामिल हैं। तांबा विद्युत संचरण, नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी

बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे घरेलू अन्वेषण महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य घरेलू स्रोतों का विकास करना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना है।

कनाडा ने ब्रैम्पटन में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची भगवान शिव प्रतिमा का अनावरण किया

एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में, कनाडा ने ब्रैम्पटन में भगवान शिव की 54 फुट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया, जिससे यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊँची भगवान शिव प्रतिमा बन गई। इस अनावरण समारोह ने शहर के क्षितिज में एक आध्यात्मिक मील का पत्थर जोड़ दिया और इसमें हजारों भारतीय प्रवासी भक्तों ने भाग लिया।

प्रतिमा विवरण:

ब्रैम्पटन, ऑंटारियो में भगवान शिव की 54 फुट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह अब उत्तरी अमेरिका में भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा है।

समारोह:

इस कार्यक्रम में एक भव्य रथ यात्रा (रथ जुलूस) शामिल थी, जिसमें भक्त मूर्ति को मंदिर परिसर तक ले गए। भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक "हर हर महादेव" के जयकारों के बीच प्रतिमा का अनावरण किया गया।

प्रतिमा के पीछे कलाकार:

इस प्रतिमा को नरेश ने बनाया था, जो कनाडा में अन्य प्रमुख आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मिसिसॉगा में 51 फुट ऊँची भगवान राम की मूर्ति और ब्रैम्पटन के सभा मंदिर में विशाल भगवान हनुमान की मूर्ति भी बनाई।

कनाडा में अन्य आध्यात्मिक स्थल:

मिसिसॉगा स्थित हिंदू हेरिटेज सेंटर में भगवान राम की 51 फुट ऊँची मूर्ति का उद्घाटन अगस्त 2025 में किया गया था। भारत के राम जन्मभूमि मंदिर से प्रेरित होकर, इस मूर्ति का निर्माण चार वर्षों में किया गया था और इसके कुछ हिस्से दिल्ली, भारत में निर्मित किए गए थे। राम की मूर्ति इतनी प्रमुख है कि यह टोरंटो पियर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उतरते समय दिखाई देती है।

लघु लेख

भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद: चुनौतियाँ और स्थायी समाधान

पाक जलडमरूमध्य और कच्चातीवु द्वीप के आसपास भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद एक मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो मछुआरों की आजीविका और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखे। यह मुद्दा संप्रभुता, समुद्री सीमाओं और स्थायी मत्स्य पालन प्रथाओं से जुड़ा है।

विवाद की पृष्ठभूमि

भौगोलिक संदर्भ:

- पाक जलडमरूमध्य तमिलनाडु (भारत) और उत्तरी प्रांत (श्रीलंका) को अलग करने वाला एक संकरा जलक्षेत्र है, जो पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है।
- पाक जलडमरूमध्य में 285 एकड़ का एक निर्जन टापू, कच्चातीवु, 1974 के समुद्री सीमा समझौते के तहत श्रीलंका को सौंप दिया गया था।

संप्रभुता और मत्स्य पालन अधिकार:

- कच्चातीवु पर संप्रभुता कानूनी रूप से श्रीलंका के पक्ष में है, लेकिन भारतीय मछुआरे जाल सुखाने और धार्मिक उद्देश्यों के लिए वहां जा सकते हैं।
- मछली पकड़ने के अधिकार ऐतिहासिक प्रथाओं, UNCLOS (1982) और द्विपक्षीय समझौतों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

शामिल समुदाय:

- तमिलनाडु के पारंपरिक मछुआरे और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मछुआरे सदियों से इन जल क्षेत्रों का उपयोग करते रहे हैं।
- जब मशीनीकृत भारतीय ट्रॉलर श्रीलंकाई जलक्षेत्र में प्रवेश करते हैं और बॉटम ट्रॉलिंग करते हैं, जो 2017 से श्रीलंका में प्रतिबंधित है, तो संघर्ष उत्पन्न होते हैं।

संघर्ष की प्रकृति:

- पर्यावरणीय क्षति में प्रवाल भित्तियों का विनाश, झींगों के आवास का नुकसान और मछली भंडार में कमी शामिल है।
- मशीनीकृत ट्रॉलरों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे पैमाने के कारीगर मछुआरों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- मछुआरे तेजी से उच्च समुद्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण मालदीव के जलक्षेत्र में और डिएगो गार्सिया के पास ब्रिटिश नौसेना द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है।

स्थायी मत्स्य पालन के लिए प्रस्तावित उपाय

पारंपरिक आजीविका को प्राथमिकता दें:

- स्थायी तरीकों का उपयोग करने वाले कारीगर मछुआरों का समर्थन करें।
- पारिस्थितिक तंत्र और साझा समुद्री संसाधनों की रक्षा के लिए मशीनीकृत तल-जाल (बॉटम ट्रॉलिंग) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करें।

सहकारी ढाँचों को मज़बूत करें:

- मछुआरों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों सहित एक भारत-श्रीलंका मत्स्य प्रबंधन परिषद की स्थापना करें।
- पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी जैसे अर्ध-संलग्न जलक्षेत्रों में सहयोग का मार्गदर्शन करने के लिए UNCLOS अनुच्छेद 123 का उपयोग करें।
- कारीगर मछुआरों के लिए संयुक्त कोटा, मौसमी मछली पकड़ने के अधिकार, या विनियमित मछली पकड़ने के दिनों पर विचार करें।

वैकल्पिक मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा दें:

- तटीय संसाधनों पर दबाव कम करने के लिए भारत के 200 समुद्री मील के EEZ में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करें।

- विनाशकारी प्रथाओं से दूर जाने के लिए प्रशिक्षण, आधुनिक जहाज और वित्तीय सहायता प्रदान करें।

कच्चातीवु का राजनीतिकरण न करें:

यह स्वीकार करें कि संप्रभुता कानूनी रूप से तय है; मछली पकड़ने का अधिकार एक अलग मुद्दा है जिस पर बातचीत की जा सकती है।

विवादों के बजाय, द्वीप का उपयोग संयुक्त समुद्री अनुसंधान और पारिस्थितिक सहयोग के लिए करें।

सामुदायिक समझ को बढ़ावा दें:

- तमिलनाडु में सद्भावना निर्माण हेतु श्रीलंकाई तमिल मछुआरों की कठिनाइयों को उजागर करें।
- श्रीलंका के गृहयुद्ध के दौरान तमिलनाडु द्वारा दिए गए मानवीय सहयोग को याद करते हुए, लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

पाक जलडमरूमध्य और कच्चातीवु मुद्दों को संघर्ष के बजाय सहयोग के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

कारिगरों की आजीविका की रक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और भारत-श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने के लिए एक निष्पक्ष और टिकाऊ मत्स्य पालन व्यवस्था आवश्यक है। छोटे-मोटे विवादों को दक्षिण एशिया में शांति, पारिस्थितिक संतुलन और आपसी सम्मान के व्यापक दृष्टिकोण पर हावी नहीं होने देना चाहिए।

नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता

वर्तमान स्थिति

नेपाल, जेनरेशन ज़ेड (Z) के युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच, प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद राजनीतिक अशांति के दौर से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, बेरोजगारी, बढ़ती असमानताएँ और सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों से असंतोष जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों ने इस अशांति को और हवा दी है। काठमांडू में पुलिस गोलीबारी के बाद तनाव बढ़ गया, जिसमें कई लोग हताहत हुए और जनता की शिकायतें और गहरी हो गईं।

भारत के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध

भारत और नेपाल के बीच मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं। रामायण में, अयोध्या के भगवान राम ने जनकपुर (नेपाल) की देवी सीता से विवाह किया था। राजकुमार सिद्धार्थ (बुद्ध) का जन्म लुम्बिनी (नेपाल) में हुआ था और उन्होंने बोधगया (भारत) में निर्वाण प्राप्त किया था। ऐतिहासिक रूप से, मगध और शाक्य गणराज्य दोनों देशों के क्षेत्रों में फैले हुए थे। स्वतंत्रता संग्राम ने भी दोनों देशों को जोड़ा; उदाहरण के लिए, वाराणसी में जन्मे के.पी. भट्टराई ने भारत छोड़ो आंदोलन और नेपाल में राणा-विरोधी गतिविधियों में भाग लिया। सुगौली संधि (1816) और शांति एवं मैत्री संधि (1950) के माध्यम से सैन्य और राजनयिक संबंधों

को औपचारिक रूप दिया गया, जिससे पारस्परिक आर्थिक, व्यापारिक, निवास और संपत्ति के अधिकार प्राप्त हुए।

भारत के लिए निहितार्थ

- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता शासन में अंतराल पैदा करती है, जिसका विद्रोहियों, अपराधियों और सीमा पार अवैध नेटवर्क द्वारा संभावित रूप से फायदा उठाया जा सकता है। नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा आंतरिक सुरक्षा को घुसपैठ, तस्करी और मानव तस्करी के प्रति संवेदनशील बनाती है।
 - आर्थिक निहितार्थ: भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो 7.32 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात करता है (वित्त वर्ष 2025)। राजनीतिक अशांति निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए खतरा पैदा करती है और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों, विशेष रूप से चीन, को रणनीतिक लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
 - विकास सहयोग: भारत के पास नेपाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण और स्वच्छता से संबंधित 573 से अधिक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (HICDP) हैं। अस्थिरता परियोजना कार्यान्वयन को बाधित कर सकती है और वैकल्पिक शक्तियों को नेपाल को प्रभावित करने का अवसर दे सकती है।
 - ऊर्जा और जलविद्युत परियोजनाएँ: राजनीतिक अस्थिरता सीमा पार बिजली व्यापार और अरुण-3, फुकोट करनाली और लोअर अरुण जैसी जलविद्युत परियोजनाओं को प्रभावित कर सकती है, जिससे भारत का क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र बनने का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।
 - रक्षा और सामरिक प्रभाव: सूर्य किरण जैसे संयुक्त अभ्यास प्रभावित हो सकते हैं, और चीन जैसे बाहरी तत्व कमज़ोर संस्थागत ढाँचे का फायदा उठा सकते हैं।
- ### व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव
- आंतरिक सुरक्षा खतरे: जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में छिद्रपूर्ण सीमाएँ आतंकवाद, उग्रवाद और तस्करी के जोखिम को बढ़ाती हैं।
 - भू-राजनीतिक परिणाम: पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता चीन और अमेरिका सहित प्रमुख शक्तियों को प्रभाव बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है। हंबनटोटा (श्रीलंका) और ग्वादर (पाकिस्तान) जैसी सामरिक संपत्तियाँ क्षेत्रीय कमज़ोरियों को बढ़ाती हैं।
 - आर्थिक और विकासात्मक प्रभाव: भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी सीमा पार बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में देरी हो सकती है, जिससे भारत की एकट ईस्ट नीति प्रभावित हो सकती है। तीस्ता जैसी साझा नदियों का प्रबंधन भी प्रभावित हो सकता है।
 - मानवीय चिंताएँ: नेपाल से शरणार्थियों का आगमन भारतीय सीमावर्ती राज्यों के संसाधनों पर दबाव डाल सकता है, जिससे सामाजिक-सांस्कृतिक तनाव पैदा हो सकता है।

- क्षेत्रीय प्रभाव: अस्थिरता सार्क और बिस्मटेक को कमजोर करती है, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और बहुपक्षीय पहलों को आगे बढ़ाने की भारत की क्षमता सीमित हो जाती है।

भारत के लिए रणनीतिक उपाय

- सीमा प्रबंधन: व्यापार को सुरक्षित करने और कमज़ोरियों को कम करने के लिए एकीकृत जाँच चौकियों और डिजिटल सीमा शुल्क प्रणालियों सहित बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करें।
- रक्षा और संकट सहयोग: नेपाल, मालदीव और म्यांमार के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों को मज़बूत करें और क्षेत्रीय संकट प्रबंधन ढाँचे विकसित करें।
- बुनियादी ढाँचा और संपर्क: बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट परियोजना जैसी परियोजनाओं के माध्यम से सड़क, रेल और बंदरगाह संपर्कों का विस्तार करें।
- आर्थिक कूटनीति: चीन की ऋण-जाल कूटनीति के विकल्प के रूप में आसान ऋण, अनुदान और विकास सहायता प्रदान करें, जिससे विश्वसनीय साझेदारी को बढ़ावा मिले।
- सॉफ्ट पावर जुड़ाव: भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसी पहलों के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

नेपाल की राजनीतिक अशांति भारत के पड़ोस की नाजुकता को रेखांकित करती है, जिससे सुरक्षा, व्यापार, विकास और रणनीतिक प्रभाव प्रभावित हो रहा है।

इशिबा का इस्तीफा: जापान की अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए उनके इस्तीफे का अभिप्राय

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने पदभार ग्रहण करने के एक साल से भी कम समय बाद अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उनका यह फैसला लगातार चुनावी हार, बढ़ती जीवन-यापन की लागत और अपनी ही पार्टी के बढ़ते दबाव के बाद आया है।

चुनावी हार और जनता का गुस्सा

फुमियो किशिदा के पद छोड़ने के बाद इशिबा अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके तुरंत बाद, उनकी पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP), चुनाव हारने लगी। निचले और ऊपरी सदन, दोनों के चुनावों में, सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपना बहुमत खो दिया। यह असामान्य था क्योंकि LDP दशकों से जापानी राजनीति पर हावी रही है। हार से पता चला कि कई मतदाता रोज़मर्रा की समस्याओं जैसे ऊँची खाद्य कीमतों, मुद्रास्फीति, स्थिर वेतन और कमज़ोर जापानी येन से नाराज़ थे।

व्यापारिक सफलता उन्हें नहीं बचा सकी

इस्तीफा देने से कुछ दिन पहले, इशिबा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक समझौता किया। अमेरिका जापानी कारों पर शुल्क 25% से घटाकर 15% करने पर सहमत हुआ।

इशिबा ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन यह जनता का विश्वास जीतने के लिए पर्याप्त नहीं था। कई लोग अब भी उनकी सरकार पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और जीवन-यापन की लागत, खासकर चावल की बढ़ती कीमतों को कम करने में विफल रहने का आरोप लगाते हैं, जिससे आम परिवारों पर भारी असर पड़ा है।

पार्टी के दबाव ने उन्हें मजबूर किया

अपनी ही पार्टी के अंदर इशिबा को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई एलडीपी सांसदों का मानना था कि उनका नेतृत्व पार्टी को कमज़ोर कर रहा है और उसके भविष्य को खतरे में डाल रहा है। कुछ रूढ़िवादियों ने तो पार्टी को टूटने से बचाने के लिए उन्हें हटाने की भी माँग की। इस्तीफा देकर, इशिबा ने एक उलझी हुई आंतरिक लड़ाई को टाल दिया और कहा कि वह "पार्टी की एकता की रक्षा" करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी होती कि वह पद छोड़ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का नेतृत्व करना मुश्किल होता।

उनकी जगह कौन लेगा?

एलडीपी ने 4 अक्टूबर, 2025 को आपातकालीन नेतृत्व चुनाव का आह्वान किया है। मुख्य दावेदार हैं:

- शिंजिरो कोइजुमी, कृषि मंत्री, जिन्हें खाद्य सुरक्षा और पीढ़ीगत बदलाव पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक युवा सुधारक के रूप में देखा जाता है।
- साने ताकाइची, एक रूढ़िवादी नेता जो मज़बूत सरकारी खर्च का समर्थन करती हैं। अगर वह जीत जाती हैं, तो वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं।
- जो भी सत्ता संभालेगा, उसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एलडीपी अब अल्पमत सरकार चला रही है, और विपक्षी दल मज़बूत होते जा रहे हैं। नए नेता को जनता का विश्वास बहाल करना होगा, मुद्रास्फीति से निपटना होगा और जापान की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को संभालना होगा।

अल्पकालिक नेताओं का एक पैटर्न

इशिबा का इस्तीफा जापानी राजनीति में एक लंबे समय से चली आ रही प्रवृत्ति को जारी रखता है। 1990 के बाद से, देश ने 18 प्रधानमंत्रियों को देखा है, जिनमें से कई ने बहुत कम समय तक ही सेवा की है। बार-बार नेतृत्व परिवर्तन ने अस्थिरता पैदा की है और इस बारे में संदेह पैदा किया है कि क्या सत्तारूढ़ दल दीर्घकालिक समाधान दे सकता है। इशिबा ने प्रधानमंत्री बनते समय "देश को फिर से मुस्कुराने" का वादा किया था। लेकिन उनका कार्यकाल छोटा रहा और आर्थिक संघर्षों, चुनावी हार और पार्टी विभाजन से भरा रहा।

निष्कर्ष

शिगेरु इशिबा का इस्तीफा दर्शाता है कि जापान की राजनीतिक और आर्थिक समस्याएँ कितनी गंभीर हो गई हैं। एलडीपी के सामने अब एक अहम परीक्षा है—क्या वह एक मज़बूत नेता के पीछे एकजुट होकर जापानी मतदाताओं का विश्वास फिर से जीत पाएगी, या विपक्षी दलों के आगे अपनी ज़मीन खोती रहेगी।

अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक प्रमाणन को पारस्परिक मान्यता दी

- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक-दूसरे के जैविक प्रमाणन को स्वीकार करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (MRA) को भारत के APEDA (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) और ऑस्ट्रेलिया के DAFF (कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी विभाग) द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।
- इस व्यवस्था का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, नियामक बाधाओं को कम करना और व्यापार को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों के लिए नए अवसर उपलब्ध होंगे।

समझौते का महत्व

- दोनों देशों के जैविक मानकों और प्रमाणन प्रणालियों में विश्वास और भरोसे को मज़बूत करता है।
- इससे भारतीय किसानों की आजीविका में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि जैविक उत्पादों की कीमत आमतौर पर 30-40% अधिक होती है।
- इसमें उचित लेबलिंग, जैविक और अजैविक उत्पादों के बीच सख्त पृथक्करण, दंड, क्षमता निर्माण और किसानों के लिए सलाहकार सहायता पर ज़ोर दिया गया है।

जैविक क्षेत्र का तीव्र विकास

- भारत जैविक कृषि भूमि के मामले में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा और कुल जैविक उत्पादकों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है।
- शीर्ष उत्पादक राज्य: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात।
- ऑस्ट्रेलिया में 53 मिलियन हेक्टेयर जैविक कृषि भूमि है, जो दुनिया में सबसे बड़ी है।

सरकारी पहल

- भारत 24 केंद्रीय और राज्य प्रयोगशालाओं में जैविक खाद्य परीक्षण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ₹105 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा है।
- राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) भारत के जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करता है।

जैविक उत्पादों के बारे में

पर्यावरण और सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार प्रथाओं का पालन करते हुए, रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों के बिना उगाया जाता है। इसमें खाद्य उत्पाद (फल, सब्ज़ियाँ, अनाज, दालें, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ) और अखाद्य वस्तुएँ (जैविक कपास रेशा, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ) शामिल हैं।

एनपीसीआई ने व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन के लिए यूपीआई सीमा को संशोधित कर ₹10 लाख कर दिया

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) भुगतानों के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) लेनदेन सीमा में संशोधन की घोषणा की है। नए नियम 15 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे और इनका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उच्च मूल्य के डिजिटल लेनदेन को सुगम बनाना है। संशोधित ढाँचे के तहत, उपयोगकर्ता अब चुनिंदा और सत्यापित व्यापारी श्रेणियों के लिए एक ही दिन में ₹10 लाख तक का यूपीआई भुगतान कर सकते हैं। इस कदम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने, सुविधा में वृद्धि होने और भारत के कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालाँकि, व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) हस्तांतरण की लेनदेन सीमा ₹1 लाख प्रति दिन पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

अतिरिक्त जानकारी:

यूपीआई एनपीसीआई द्वारा विकसित और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित एक त्वरित रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली है। दुरुपयोग और धोखाधड़ी को रोकने के लिए नई लेनदेन सीमा केवल सत्यापित व्यापारी श्रेणियों पर लागू होती है। हाल के महीनों में UPI ने 10 अरब से ज़्यादा लेनदेन संसाधित किए हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी रीयल-टाइम भुगतान प्रणालियों में से एक बन गई है। यह कदम डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, नकदी पर निर्भरता कम करने और डिजिटल इंडिया पहलों का समर्थन करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी और यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक प्रमुख संगठन है। बढ़ी हुई सीमा से रियल एस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और लग्जरी रिटेल जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा, जहाँ उच्च लेनदेन मूल्य आम हैं। UPI ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यूपीएस से एनपीएस में एकमुश्त बदलाव की शुरुआत की

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में एकमुश्त, एकतरफा बदलाव की सुविधा की घोषणा की है। यह सुविधा यूपीएस ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी:

- सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पहले तक, या
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले तक।
- बर्खास्तगी, निष्कासन या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे।

शर्तें और लाभ

इस सुविधा का लाभ उठाने के बाद, कर्मचारी यूपीएस लाभ (सुनिश्चित भुगतान सहित) खो देंगे। सरकार का 4% अंतर अंशदान ग्राहक के एनपीएस कोष में निकासी के समय जोड़ दिया जाएगा।

इस कदम का उद्देश्य लचीलापन प्रदान करना और एनपीएस को दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति समाधान के रूप में सुदृढ़ करना है।

यूपीएस की शुरुआत

1 अप्रैल, 2025 से, सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरुआत की। यूपीएस कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रदान करता है। 20 जुलाई, 2025 तक, लगभग 31,555 केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना है।

यूपीएस में नामांकन की अंतिम तिथि: 30 सितंबर, 2025।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस):

- प्रारंभ: 2004 (शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों के लिए, बाद में सभी नागरिकों के लिए विस्तारित)।
- नियामक: पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)।
- विशेषताएँ: बाजार से जुड़े रिटर्न, निवेश विकल्पों में लचीलापन, आंशिक निकासी विकल्प, सेवानिवृत्ति पर वार्षिकी।

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)

- शुरू: 1 अप्रैल, 2025।
- उद्देश्य: सुनिश्चित रिटर्न (पुरानी पेंशन योजना की तरह) और बाजार से जुड़े लाभों (एनपीएस की तरह) में संतुलन स्थापित करना।
- प्रस्ताव: सरकार के अंतर अंशदान के साथ सुनिश्चित मासिक भुगतान।

पीएफआरडीए

- स्थापना: 2003।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।
- अध्यक्ष: दीपक मोहंती।

सेमीकॉन इंडिया 2025: चिप डिज़ाइन में भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना

यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद उपस्थित थे। उन्होंने सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चिप डिज़ाइन में आत्मनिर्भरता लाने में भारतीय स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

विषय: सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर भारत को मज़बूत करना

मुख्य अंश

आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले स्टार्टअप्स:

डिज़ाइन लिंकड इंसेंटिव (DLI) योजना के तहत, 23 चिप डिज़ाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

72 कंपनियों को उद्योग-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन (EDA) टूल्स तक पहुँच प्राप्त हुई है।

स्टार्टअप्स ब्रॉडबैंड, निगरानी, स्मार्ट ऊर्जा मीटर, मोटर नियंत्रण और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) समाधान विकसित कर रहे हैं।

RISC-V तकनीक में अभूतपूर्व सफलता:

इनकोर सेमीकंडक्टर्स ने एक अभिनव SoC जेनरेटर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे डिज़ाइन का समय महीनों से घटकर मिनटों में रह गया है। TSMC के 40nm नोड पर छह विषम RISC-V कोर, कस्टम नेटवर्क-ऑन-चिप और संपूर्ण RTOS स्टैक का प्रदर्शन किया गया।

प्रोसेसर परिवार:

अजुराइट - अल्ट्रा-लो पावर, रीयल-टाइम (मोटर नियंत्रण, IoT)।
कैल्साइट - मध्यम-स्तरीय एम्बेडेड (POS, IP कैमरा, स्मार्ट IoT)।

डोलोमाइट - विकासाधीन, नेटवर्किंग और एज AI के लिए उच्च-प्रदर्शन वेक्टर प्रोसेसिंग।

मुख्य जानकारी:

- डीएलआई योजना: घरेलू सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और स्टार्टअप्स को वित्तीय और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में शुरू की गई।
- ईडीए टूल्स: चिप डिज़ाइन और सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर, जिस पर कैडेंस, सिनोप्सिस और सीमेंस का वैश्विक प्रभुत्व है।
- आरआईएससी-वी: ओपन-सोर्स आईएसए (यूसी बर्कले में विकसित) → रॉयल्टी-मुक्त, मॉड्यूलर, एआई, आईओटी और सुपरकंप्यूटर में नवाचार को बढ़ावा देता है।
- एसओसी (सिस्टम-ऑन-चिप): सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी, आई/ओ को एकीकृत करने वाला एकल सिलिकॉन → लागत, आकार और बिजली की खपत को कम करता है।
- एससीएल मोहाली: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला, चिप निर्माण के लिए भारत की नोडल सुविधा।
- वैश्विक संदर्भ: भारत का लक्ष्य 2026 तक 63 बिलियन डॉलर का सेमीकंडक्टर बाजार हासिल करना है।

विभिन्न संगठनों द्वारा FY25 के लिए भारत की GDP अनुमान

संगठन	रेटिंग
एसएंडपी ग्लोबल	6.5%
फिच रेटिंग्स	6.9%
मॉर्गन स्टेनली	6.7%

भारत और कनाडा द्विपक्षीय वार्ता तंत्र को पुनः सक्रिय करने पर सहमत

भारत और कनाडा ने हाल ही में हुई सुरक्षा-स्तरीय वार्ता के बाद द्विपक्षीय वार्ता तंत्र को पुनः सक्रिय करने के लिए कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की है। यह निर्णय नियमित द्विपक्षीय सुरक्षा परामर्श के तहत 18 सितंबर 2025 को दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया।

पृष्ठभूमि:

यह चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच कनानसकीस, अल्बर्टा (जून 2025) में जी7 शिखर सम्मेलन में हुई बैठक के बाद हुई। दोनों नेताओं ने अपनी वार्ता को "सकारात्मक और रचनात्मक" बताया। एक प्रारंभिक कदम के रूप में, भारत और कनाडा एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों की बहाली पर सहमत हुए।

वार्ता तंत्र को पुनर्जीवित करना

निम्नलिखित क्षेत्रों में वरिष्ठ और कार्यकारी स्तर के परामर्श फिर से शुरू करने के लिए समझौता:

- व्यापार और निवेश
- लोगों के बीच संपर्क
- संपर्क और प्रौद्योगिकी सहयोग

उद्देश्य: वर्षों के तनावपूर्ण संबंधों के बाद द्विपक्षीय संबंधों में गति लाना।

राजनयिक नियुक्तियाँ

भारत ने दिनेश के. पटनायक (स्पेन में पूर्व राजदूत) को कनाडा में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। यह नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार में तनाव के कारण अक्टूबर 2024 में भारत द्वारा अपने पूर्व उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को वापस बुलाने के 10 महीने बाद हुई है।

तनावपूर्ण संबंधों का संदर्भ

ट्रूडो द्वारा कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर (जून 2023) की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाने के बाद संबंधों में खटास आ गई। भारत ने इन आरोपों का कड़ा खंडन करते हुए इन्हें "राजनीति से प्रेरित और निराधार" बताया। कनाडा में हाल ही में हुए नेतृत्व परिवर्तन (मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने) ने संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का रास्ता खोल दिया है।

मुख्य अंश:

- भारत-कनाडा राजनयिक संबंध: 1947 में स्थापित।
- कनाडा में प्रवासी भारतीय: 16 लाख से ज़्यादा लोग (कनाडा की आबादी का लगभग 4%)।
- कनाडा के नए प्रधानमंत्री: मार्क कार्नी (2025 में जस्टिन ट्रूडो के बाद पदभार ग्रहण करेंगे)।
- प्रमुख सहयोग क्षेत्र: ऊर्जा (यूरेनियम आपूर्ति), शिक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार।
- भारत-कनाडा व्यापार: लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023-24)।

- खालिस्तानी मुद्दा: द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख अड़चन बना हुआ है।

ब्लू पोर्ट अवसंरचना के विकास हेतु भारत-एफएओ साझेदारी

मत्स्य पालन विभाग (मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन) ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (टीसीपी) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

उद्देश्य: सतत मत्स्य पालन, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट विकसित करना।

स्वीकृत पायलट बंदरगाह:

1. वनकबारा (दीव)
 2. कराईकल (पुदुचेरी)
 3. जखाऊ (गुजरात)
- कुल निवेश: ₹369.8 करोड़।
 - दृष्टिकोण: पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, सामाजिक रूप से समावेशी मत्स्य पालन प्रणालियों का निर्माण।
 - प्रौद्योगिकियाँ: दक्षता और सेवा वितरण में सुधार के लिए 5G, AI, स्वचालन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

ब्लू इकोनॉमी अवधारणा: पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोज़गार के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग।

भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र:

भारत विश्व स्तर पर मत्स्य उत्पादन में तीसरे और जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मत्स्य पालन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.07% और कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 7% से अधिक का योगदान देता है। यह भारत में 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है।

एफएओ (खाद्य एवं कृषि संगठन):

1945 में स्थापित, मुख्यालय रोम, इटली में।

सरकारी योजनाओं से जुड़ाव:

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) - इसका उद्देश्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 22 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना है।
- सागरमाला परियोजना - बंदरगाह आधुनिकीकरण और तटीय सामुदायिक विकास पर केंद्रित है।

भारत ने देश के युवाओं को ग्लोबल जॉब मार्केट तक आसान पहुँच के लिए ILO के साथ समझौता किया

भारत ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को ग्लोबल मार्केट में नौकरी पाने में मदद करना

है। यह समझौता जिनेवा में भारत के UN प्रतिनिधि और ILO के महानिदेशक ने किया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया।

यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है

कई देशों में बढ़ती आबादी और तेजी से हो रही डिजिटल ग्रोथ के कारण स्किल की कमी हो रही है। भारत अपने कुशल श्रमिकों को उन देशों से जोड़ना चाहता है, जिन्हें प्रतिभा की आवश्यकता है। यह कदम G20 समिट में अधिक नियमित, स्किल-आधारित माइग्रेशन के लिए किए गए वादे को भी पूरा करता है।

ILO

- स्थापना: 11 अप्रैल 1919
- प्रकार: संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
- महानिदेशक: गिलबर्ट होंगबो

अमेरिका और पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण खनिजों पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए

अमेरिका और पाकिस्तान ने पाकिस्तान में महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और पुनर्चक्रण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर इस्लामाबाद स्थित प्रधानमंत्री आवास में पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन (एफडब्ल्यूओ) और यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स (यूएसएसएम) के बीच हस्ताक्षर किए गए।

समझौते का उद्देश्य

इस साझेदारी का उद्देश्य पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र का विकास करना है, जिसमें कोबाल्ट, निकल, तांबा और लिथियम जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अमेरिकी ऊर्जा विभाग द्वारा इन खनिजों को उन्नत विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक माना गया है।

संबंधित घटनाक्रम

31 जुलाई को, अमेरिका और पाकिस्तान ने पारस्परिक शुल्कों, विशेष रूप से पाकिस्तानी निर्यात पर, को कम करने पर केंद्रित एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान में तेल अन्वेषण में सहयोग की घोषणा की। यह समझौता भारत-रूस द्वारा दुर्लभ मृदा खनिजों की खोज, कोयला गैसीकरण और औद्योगिक अवसंरचना के प्रयासों के बाद हुआ है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत ₹1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में पुनर्चक्रण और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- कोबाल्ट, निकल, तांबा और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं।
- यूएस. स्ट्रैटेजिक मेटल्स (USSM) का मुख्यालय मिसौरी, अमेरिका में है और यह महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन और पुनर्चक्रण में विशेषज्ञता रखता है।

- फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन (FWO) पाकिस्तान सरकार के अधीन एक सैन्य इंजीनियरिंग संगठन है, जो बुनियादी ढाँचे और रणनीतिक परियोजनाओं में शामिल है।
- अमेरिकी ऊर्जा विभाग महत्वपूर्ण खनिजों को तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता है।

भारत-इज़राइल द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर

भारत और इज़राइल ने नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते पर भारत की ओर से केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और इज़राइल का प्रतिनिधित्व करते हुए वित्त मंत्री बेज़ेलेल स्मोर्ट्रिच ने हस्ताक्षर किए।

समझौते के उद्देश्य

इस समझौते का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, निवेशकों के लिए अधिक निश्चितता और सुरक्षा प्रदान करना, और व्यापार एवं पारस्परिक निवेश के विकास को सुगम बनाना है। यह मध्यस्थता के माध्यम से एक स्वतंत्र विवाद समाधान तंत्र सुनिश्चित करता है, जिससे निवेशकों को विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझाने में मदद मिलती है। इस समझौते में ज़ब्ती के विरुद्ध सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, और सुचारू हस्तांतरण और किसी भी नुकसान की भरपाई को सक्षम बनाता है।

वर्तमान निवेश स्थिति

वर्तमान में, भारत और इज़राइल के बीच द्विपक्षीय निवेश 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। नए समझौते से व्यावसायिक संपर्क को प्रोत्साहित करके और सहयोग के नए रास्ते तलाशकर इन निवेश प्रवाहों को और बढ़ाने की उम्मीद है।

सहयोग के क्षेत्र

दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा, रक्षा, नवाचार, उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योग, फिनटेक नवाचार, बुनियादी ढाँचा विकास, वित्तीय विनियमन और डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस साझेदारी का उद्देश्य साझा विशेषज्ञता का लाभ उठाना और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना है।

अमेज़न ने एक्सियो का अधिग्रहण पूरा किया, भारत में प्रत्यक्ष ऋण लाइसेंस प्राप्त किया

अमेज़न ने बेंगलुरु स्थित गैर-बैंक ऋणदाता एक्सियो का अधिग्रहण पूरा कर लिया है और जून 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा इस सौदे को मंजूरी मिलने के बाद भारत में प्रत्यक्ष ऋण लाइसेंस प्राप्त कर लिया है।

- एक्सियो के बारे में: यह एक 12 साल पुरानी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो खुदरा उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों को डिजिटल ऋण और धन प्रबंधन समाधान प्रदान करती है। यह 2018 से अमेज़न के साथ जुड़ी हुई है और ऋण और बाद में भुगतान करने वाले उत्पाद प्रदान करती है।

- अमेज़न का वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान: एक्सियो के माध्यम से, अमेज़न अब अपने प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करेगा, जिसमें चेकआउट ऋण और अपने बाज़ार से परे अन्य वित्तीय उत्पाद शामिल हैं। यह कदम अमेज़न को फ्लिपकार्ट जैसे प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देता है, जो फ्लिपकार्ट फ़ाइनेंस एनबीएफसी (अप्रैल 2025 में लाइसेंस प्राप्त) के माध्यम से संचालित होता है।
- वित्तीय स्थिति: एक्सियो ने जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए लगभग ₹22 बिलियन (\$251.4 मिलियन) की ऋण पुस्तिका की सूचना दी।
- सहायक कंपनी का दर्जा: एक्सियो एक अलग व्यवसाय के रूप में जारी रहेगा, लेकिन अमेज़न इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगा।

अमेज़न का फिनटेक इकोसिस्टम:

भारत में भुगतान वॉलेट जारी करने और बीमा पॉलिसियाँ बेचने के लिए पहले से ही लाइसेंस प्राप्त है। जुलाई 2025 में यूपीआई पर वॉल्यूम के हिसाब से अमेज़न पे 9वीं सबसे बड़ी कंपनी थी (एनपीसीआई डेटा)।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- आरबीआई: 1935 में स्थापित; मुख्यालय - मुंबई; वर्तमान गवर्नर (2025) - शक्तिकांत दास।
- एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी): कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत, आरबीआई द्वारा विनियमित; ऋण और ऋण सुविधाएँ प्रदान करता है, लेकिन मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता।
- एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम): 2008 में स्थापित; मुख्यालय - मुंबई; यूपीआई, रुपये, भीम, फास्टैग, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस) का संचालन करता है।
- भारत का डिजिटल ऋण बाजार: 2030 तक 350 अरब डॉलर को पार करने का अनुमान (नीति आयोग की रिपोर्ट)।
- वैश्विक संदर्भ: ऐप्पल (ऐप्पल पे लेटर) और गूगल (गूगल पे ऋण साझेदारी) जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियाँ भी दुनिया भर में फिनटेक ऋण मॉडल में प्रवेश कर रही हैं।

भारत-यूई ऊर्जा साझेदारी

अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) ने अपनी कम कार्बन वाली रुवाइस LNG परियोजना से 10 लाख टन प्रति वर्ष (MTPA) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के साथ 15 साल का बिक्री और खरीद समझौता (SPA) किया है। इसकी आपूर्ति भारत भर के बंदरगाहों तक की जाएगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मज़बूत होगी और बढ़ती माँग पूरी होगी।

ADNOC ने इनके साथ भी LNG आपूर्ति समझौते किए हैं:

- हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) - 0.5 MTPA (10 वर्ष, 2025 में हस्ताक्षरित)।

- गेल (इंडिया) लिमिटेड - 0.52 एमटीपीए (10 वर्ष, हस्ताक्षरित 2024)।
- रुवाइस एलएनजी परियोजना
- स्थान: अल रुवाइस औद्योगिक शहर, अबू धाबी।
- संचालन प्रारंभ: 2028 में अपेक्षित।

महत्व:

- पश्चिम एशिया में पहली एलएनजी सुविधा जो पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा से संचालित है।
- वैश्विक स्तर पर सबसे कम कार्बन-तीव्रता वाले एलएनजी संयंत्रों में से एक।
- सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए एआई-आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
- क्षमता: 4.8 एमटीपीए की दो द्रवीकरण ट्रेनें, जिनकी संयुक्त क्षमता 9.6 एमटीपीए है।
- दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से 8 एमटीपीए से अधिक क्षमता पहले ही बुक की जा चुकी है।
- परियोजना का शिलान्यास नवंबर 2024 में होगा।

द्विपक्षीय व्यापार संदर्भ

यह समझौता 2022 में भारत और यूई के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर आधारित है, जिसने विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का एक प्रमुख ऊर्जा साझेदार है, जो भारत के कच्चे तेल और एलएनजी आयात में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- एडीएनओसी: 1971 में स्थापित, संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी तेल कंपनी, जिसका मुख्यालय अबू धाबी में है।
- आईओसी: 1959 में स्थापित, भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक तेल कंपनी और एक महारत्न सार्वजनिक उपक्रम।
- भारत का एलएनजी आयात: भारत अपनी प्राकृतिक गैस की ज़रूरतों का लगभग 50% आयात करता है, जिसमें कतर, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और रूस प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।
- ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्य: भारत का लक्ष्य अपने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% (2024) से बढ़ाकर 2030 तक 15% करना है।
- सीईपीए (भारत-यूई, 2022): एक दशक से भी अधिक समय में भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापक व्यापार समझौता; इसका उद्देश्य 5 वर्षों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को वस्तुओं में 100 बिलियन डॉलर और सेवाओं में 15 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है।

कृषि में भारत-भूटान सहयोग

भारत और भूटान ने थिम्पू में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर भारत के कृषि मंत्रालय के सचिव देवेश

चतुर्वेदी और भूतान के कृषि सचिव थिनले नामग्याल ने हस्ताक्षर किए।

एमओयू के मुख्य उद्देश्य

- खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना और सतत कृषि को बढ़ावा देना।
- कृषि विकास के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना।
- कृषि अनुसंधान एवं नवाचार, पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन, कटाई-पश्चात प्रबंधन और मूल्य श्रृंखला विकास में सहयोग।
- दोनों देशों के बीच ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान।

महत्व

भारत-भूतान साझेदारी में, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक और ग्रामीण विकास क्षेत्र में, एक मील का पत्थर है। ऐतिहासिक संबंधों और भूतान के विकास के लिए भारत के निरंतर समर्थन पर आधारित है। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

भारत-भूतान राजनयिक संबंध: 1949 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित; भूतान को अधिक संप्रभुता प्रदान करने के लिए 2007 में संशोधित।

आर्थिक सहयोग:

भारत भूतान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

- प्रमुख परियोजनाएँ: जलविद्युत सहयोग (भारत भूतान की जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली आयात करता है)।
- भौगोलिक तथ्य: भूतान की सीमा चार भारतीय राज्यों - सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है।
- हाल की पहल: भारत ने कृषि के अलावा, डिजिटल कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढाँचे के विकास में भूतान का समर्थन किया है।

सीसीआई ने अडानी समूह द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स के 100% तक अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) में 100% तक शेयरधारिता हासिल करने के अडानी समूह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अधिग्रहण अडानी एंटरप्राइजेज (आईएल), अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स (एआईडीपीएल) या अडानी समूह की किसी अन्य इकाई द्वारा किया जा सकता है।

जेएएल की दिवाला कार्यवाही

एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ (जून 2024) के आदेशों के अनुसार, जेएएल दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही है। लेनदारों ने ₹57,185 करोड़ के दावे दायर किए हैं। सबसे बड़ा दावेदार नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) है, जिसने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम से JAL के संकटग्रस्त ऋणों का अधिग्रहण किया था।

व्यापक महत्व

यह अधिग्रहण आईबीसी के तहत संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए बड़ी कंपनियों (अडानी, डालमिया, वेदांता, जिंदल) के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। बुनियादी ढाँचा, सीमेंट और रियल एस्टेट क्षेत्रों में इसके विस्तार और जोखिम को देखते हुए, जेएएल के ऋण संकट का समाधान महत्वपूर्ण है। अडानी के प्रवेश से समूह को उत्तर भारत में मूल्यवान रियल एस्टेट, सीमेंट संयंत्रों और रणनीतिक संपत्तियों तक पहुँच प्राप्त होगी।

सीसीआई (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग):

- स्थापना: 2003 (2009 में कार्यरत)
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- वर्तमान अध्यक्ष: रवनीत कौर (सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष, 2023 में नियुक्त)

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी):

- अधिनियमित: 2016
- उद्देश्य: कॉर्पोरेट, साझेदारियों और व्यक्तियों के दिवाला समाधान के लिए एकीकृत ढाँचा।
- न्यायिक प्राधिकरण: एनसीएलटी (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण)।

एनएआरसीएल (राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड):

- भारत के "बैड बैंक" के रूप में जाना जाता है।
- स्थापना: 2021 बैंकों से संकटग्रस्त ऋणों का अधिग्रहण करने के लिए।

वैश्विक भुखमरी से लड़ने के लिए भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की

भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति और वैश्विक भुखमरी से लड़ने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।

- समझौता: मानवीय सहायता के लिए भारत से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति हेतु एक आशय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए गए।
- उद्देश्य: वैश्विक भुखमरी और कुपोषण, विशेष रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रों में, का समाधान करना।
- दर्शन: भारत ने "वसुधैव कुटुम्बकम्" (विश्व एक परिवार है) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

महत्व: एक कृषि अधिशेष राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करता है, जिससे विश्वसनीय वैश्विक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

भारत-विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्य सहयोग

- फोर्टिफाइड चावल की शुरुआत
- आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन (वितरण और खरीद)
- अन्नपूर्ति उपकरण (अनाज एटीएम)
- जन पोषण केंद्र
- स्मार्ट वेयरहाउसिंग तकनीक
- फ्लोस्पैन (मोबाइल स्टोरेज यूनिट)

विश्व खाद्य कार्यक्रम (विश्व खाद्य कार्यक्रम):

- पूरा नाम: संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएन-विश्व खाद्य कार्यक्रम)
- स्थापना: 1961 (एफएओ और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा)
- मुख्यालय: रोम, इटली
- वर्तमान कार्यकारी निदेशक: सिंडी मैक्केन (अमेरिका)
- उप कार्यकारी निदेशक: कार्ल स्काउ
- मूल संगठन: संयुक्त राष्ट्र (यूएन)

भारत के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान स्टार्टअप (2025)

भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है, जहाँ कुल 73 यूनिकॉर्न हैं—जिनका मूल्य 1 अरब डॉलर या उससे अधिक है। हुरुन इंडिया यूनिकॉर्न रिपोर्ट 2025 ने देश के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान स्टार्टअप को सूचीबद्ध किया है, जिसमें फिनटेक, प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया है जो विकास को गति दे रहे हैं।

मुख्य अंश:**शीर्ष स्टार्टअप और उनका मूल्यांकन:**

- ज़ीरोधा - जिसका मूल्य 8.2 अरब डॉलर है, भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप है, जो डिस्काउंट ब्रोकरेज सेवाओं में विशेषज्ञता रखता है।
- रेज़रपे - जिसका मूल्य 7.5 अरब डॉलर है, व्यवसायों के लिए भुगतान समाधान प्रदान करने वाला एक अग्रणी फिनटेक प्लेटफॉर्म है।
- लेंसकार्ट - जिसका मूल्य 7.5 अरब डॉलर है, एक शीर्ष आईवियर ब्रांड है जो प्रिस्क्रिप्शन चश्मे और एक्सेसरीज़ प्रदान करता है।
- शीर्ष 10 में शामिल अन्य स्टार्ट-अप्स में ई-कॉमर्स, हेल्थ-टेक, एड-टेक, लॉजिस्टिक्स और SaaS (सॉफ्टवेयर ऐज़ अ सर्विस) जैसे क्षेत्रों की कंपनियाँ शामिल हैं।

भारत में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम:

यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। स्टार्ट-अप इकोसिस्टम डिजिटल अपनाने, उद्यम पूंजी निवेश और सरकारी समर्थन से संचालित होता है।

स्टार्ट-अप्स को समर्थन देने वाली प्रमुख सरकारी पहल:

नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरू किया गया स्टार्टअप इंडिया अभियान। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (FFS) शुरुआती चरण की कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। व्यापार में आसानी को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ और नए उद्यमों के लिए कर प्रोत्साहन।

यूनिकॉर्न का महत्व:

यूनिकॉर्न प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करते हैं और रोज़गार के अवसर पैदा करते हैं। ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय समावेशन और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देते हैं।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- यूनिकॉर्न की परिभाषा: एक स्टार्टअप जिसका मूल्य 1 बिलियन डॉलर या उससे अधिक हो।
- ज़ेरोधा का प्रभाव: इसने ब्रोकरेज लागत को कम करके और पहुँच बढ़ाकर शेयर ट्रेडिंग में क्रांति ला दी है।
- रेज़रपे की भूमिका: यह ऑनलाइन व्यवसायों का समर्थन करता है, उन्हें भुगतान स्वीकार करने, संसाधित करने और सुचारू रूप से प्रबंधित करने में मदद करता है।
- लेंसकार्ट का विकास: इसने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किफ़ायती और फैशनेबल आईवियर तक पहुँच का विस्तार किया है।

नारी रिपोर्ट 2025: महिलाओं के लिए शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित भारतीय शहर

महिलाओं की सुरक्षा के लिए लचीले बुनियादी ढाँचे का राष्ट्रीय मूल्यांकन (नारी) रिपोर्ट 2025 ने भारत के महिलाओं के लिए शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित शहरों की रैंकिंग की है, जिसमें लैंगिक-संवेदनशील शहरी नियोजन, कानून प्रवर्तन और सामुदायिक भागीदारी में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।

- रैंक 1 - कोहिमा (नागालैंड, सुरक्षा सूचकांक: 82.9%): मज़बूत सामुदायिक संरचनाएँ, नागरिक सहभागिता और सतर्क पुलिस व्यवस्था इसे सबसे सुरक्षित शहर बनाती है।
- रैंक 2 - विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश, 79.5%): बेहतर बुनियादी ढाँचा, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग, निगरानी और संवेदनशील पुलिस व्यवस्था।
- रैंक 3 - भुवनेश्वर (ओडिशा, 77.8%): प्रभावी संस्थान, आधुनिक नियोजन, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और नागरिक-पुलिस सहयोग।
- रैंक 4 - आइज़ोल (मिज़ोरम, 76.4%): उच्च सामाजिक विश्वास, सुगठित नियोजन, मज़बूत सामुदायिक पुलिस व्यवस्था और लैंगिक-संवेदनशील शासन।
- रैंक 5 - गंगटोक (सिक्किम, 74.2%): समुदाय-समर्थित पुलिसिंग और सहयोगात्मक शासन कम अपराध दर सुनिश्चित करते हैं।
- रैंक 6 - ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश, 72.6%): शासन और लिंग-केंद्रित बुनियादी ढाँचे के विकास में महिलाओं की सक्रिय भूमिका।
- रैंक 7 - मुंबई (महाराष्ट्र, 71.3%): सतर्क पुलिसिंग, मज़बूत सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा उपाय और समावेशी नागरिक संस्कृति।
- रैंक 8 - हैदराबाद (तेलंगाना, 69.9%): तकनीक-संचालित पुलिसिंग, परिवहन में केवल महिलाओं के लिए पहल और नागरिक समाज भागीदारी।
- रैंक 9 - बेंगलुरु (कर्नाटक, 69.7%): महिला हेल्पलाइन, सुरक्षित परिवहन प्रणाली और जागरूकता अभियान।

- रैंक 10 – अहमदाबाद (गुजरात, 67%): मज़बूत सांस्कृतिक ताना-बाना, सामुदायिक पहुँच, उन्नत निगरानी और शहरी सुरक्षा कार्यक्रम।

उल्लेखनीय तथ्य:

नारी रिपोर्ट 2025 महानगरों और छोटे शहरों में महिलाओं के सुरक्षा अनुभवों को दर्शाती है। यह महिलाओं के लिए डेटा-आधारित शहरी सुरक्षा नीतियों पर ज़ोर देती है। कोहिमा नागालैंड का पहला शहर बन गया जिसने राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। नारी जैसी रिपोर्टों का उपयोग नीति-निर्माण, शहरी नियोजन और महिला सशक्तिकरण पहलों में तेज़ी से बढ़ रहा है।

एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 जारी

शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2025 का 10वां संस्करण जारी किया, जिसका अनावरण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने किया। यह रैंकिंग 17 श्रेणियों को कवर करती है, जिसमें शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान, स्नातक परिणाम, समावेशिता और धारणा जैसे मानदंडों के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

- आईआईटी मद्रास ने समग्र रूप से (लगातार 7वें वर्ष: 2019-2025) और इंजीनियरिंग में (लगातार 10वें वर्ष: 2016-2025) प्रथम स्थान बरकरार रखा।
- आईआईएससी बेंगलुरु को समग्र रूप से दूसरा और विश्वविद्यालयों में पहला स्थान मिला।
- प्रबंधन में, आईआईएम अहमदाबाद शीर्ष पर रहा, उसके बाद आईआईएम बेंगलुरु और आईआईएम कोझीकोड का स्थान रहा।
- वास्तुकला और योजना में, आईआईटी रुड़की पहले स्थान पर रहा।
- जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष पर रहा।
- मेडिकल और डेंटल संस्थानों में एम्स दिल्ली सबसे आगे रहा।
- फार्मेसी में जामिया हमदर्द, नई दिल्ली को पहला स्थान मिला।
- ओपन यूनिवर्सिटी श्रेणी में इग्नू, नई दिल्ली शीर्ष पर रहा।
- सतत विकास लक्ष्य संस्थान और कौशल विश्वविद्यालय जैसी नई श्रेणियों को भी शामिल किया गया।

श्रेणी के अनुसार शीर्ष संस्थान

कुल मिलाकर (शीर्ष 5)

1. आईआईटी मद्रास
2. आईआईएससी बेंगलुरु
3. आईआईटी बॉम्बे
4. आईआईटी दिल्ली
5. आईआईटी कानपुर

प्रबंधन (शीर्ष 3)

1. आईआईएम अहमदाबाद
2. आईआईएम बेंगलुरु
3. आईआईएम कोझीकोड

वास्तुकला एवं योजना (शीर्ष 3)

1. आईआईटी रुड़की
2. एनआईटी कालीकट
3. आईआईटी खड़गपुर

विश्वविद्यालय (शीर्ष 3)

1. आईआईएससी बेंगलुरु
2. जेएनयू, नई दिल्ली
3. मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी

कॉलेज (शीर्ष 3)

- हिंदू कॉलेज, दिल्ली
- मिरांडा हाउस, दिल्ली
- हंस राज कॉलेज, दिल्ली

कानून (शीर्ष 3)

- एनएलएसआईयू बेंगलुरु
- एनएलयू दिल्ली
- एनएलएसएआर हैदराबाद

चिकित्सा (शीर्ष 3)

- एम्स दिल्ली
- पीजीआईएमईआर चंडीगढ़
- सीएमसी वेल्लोर

फार्मेसी (शीर्ष 3)

- जामिया हमदर्द, नई दिल्ली
- बिट्स पिलानी
- पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

कृषि एवं संबद्ध संस्थान (शीर्ष 3)

- आईएआरआई, नई दिल्ली
- आईसीएआर-एनडीआरआई, करनाल
- पीएयू, लुधियाना

नवाचार (शीर्ष 3)

- आईआईटी मद्रास
- आईआईटी बॉम्बे
- आईआईएससी बेंगलुरु

मुक्त विश्वविद्यालय

1. इग्नू, नई दिल्ली
2. केएसओयू, मैसूर
3. उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

एसडीजी संस्थान

1. आईआईटी मद्रास
2. आईएआरआई, नई दिल्ली
3. जामिया मिलिया इस्लामिया

कौशल विश्वविद्यालय

1. सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे
2. सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, इंदौर
3. श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, पलवल

उल्लेखनीय बिंदु:

- प्रारंभ: 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) द्वारा।
- संस्करण: 10वां (2025)।
- सम्मिलित श्रेणियाँ: 17.
- मूल्यांकन मानदंड: शिक्षण, अधिगम, संसाधन, अनुसंधान, स्नातक परिणाम, समावेशिता, धारणा।

वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) 2025 में सिंगापुर को एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया

अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान (IEP) द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक (GPI) 2025 में सिंगापुर को एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश और विश्व स्तर पर छठा सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है। सिंगापुर का स्कोर 1.339 (2024) से बढ़कर 1.357 (2025) हो गया, हालाँकि वैश्विक स्तर पर इसकी रैंकिंग एक स्थान नीचे खिसक गई (2024 में पाँचवें से 2025 में छठे स्थान पर)। GPI तीन श्रेणियों के अंतर्गत 23 संकेतकों का उपयोग करके 163 देशों का मूल्यांकन करता है:

- सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा
- चल रहे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष
- सैन्यीकरण
- वैश्विक स्तर पर, आइसलैंड शीर्ष स्थान पर बना रहा, उसके बाद आयरलैंड और न्यूज़ीलैंड का स्थान रहा।

जीपीआई 2025 में शीर्ष 10:

1. आइसलैंड – 1.095
2. आयरलैंड – 1.260
3. न्यूज़ीलैंड – 1.282
4. ऑस्ट्रिया – 1.294
5. स्विट्ज़रलैंड – 1.294
6. सिंगापुर – 1.357
7. पुर्तगाल – 1.371
8. डेनमार्क – 1.393
9. स्लोवेनिया – 1.409
10. फ़िनलैंड – 1.420

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- जीपीआई 2025 में भारत का स्थान: 163 में से 129वाँ (स्कोर: 2.314)।
- सबसे कम शांतिपूर्ण देश 2025: यमन (163वाँ)।
- क्षेत्रीय रूप से: सिंगापुर एशिया में शीर्ष पर है, जबकि आइसलैंड यूरोप और दुनिया में अग्रणी बना हुआ है।
- सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को 2025 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा भी दिया गया, जिससे सुरक्षा, दक्षता और जीवन की गुणवत्ता के मामले में देश की प्रतिष्ठा और मज़बूत हुई।
- पहली GPI रिपोर्ट 2007 में प्रकाशित हुई थी।
- प्रकाशक: इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP), जिसका मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है।

लघु लेख

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस): सुनिश्चित सेवानिवृत्ति लाभों की ओर एक कदम

भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अपनाने का विकल्प दिया है। हालाँकि, इसे अपनाने की गति धीमी रही है, और अब तक 23.94 लाख पात्र कर्मचारियों में से केवल 40,000 ने ही इस योजना को अपनाया है।

एकीकृत पेंशन योजना क्या है?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की समीक्षा के लिए टी.वी. सोमनाथन समिति (2023) द्वारा यूपीएस की सिफारिश की गई थी। इसकी घोषणा अगस्त 2024 में की गई थी और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई। यूपीएस, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत एक वैकल्पिक पेंशन योजना है।

यूपीएस की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- सुनिश्चित और मुद्रास्फीति-सूचकांकित पेंशन
- पूर्वानुमानित सेवानिवृत्ति लाभ
- सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों के लिए कवरेज, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित।

पात्रता मानदंड

यूपीएस चुनने के पात्र कर्मचारी और परिवार के सदस्य:

- 1 अप्रैल 2025 तक एनपीएस के तहत कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारी।
- 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारी।
- सेवानिवृत्त एनपीएस ग्राहक जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हों, जिनकी न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा हो, बशर्ते सेवानिवृत्ति एफआर 56(जे) (अनुशासनात्मक कारणों से समय से पहले सेवानिवृत्ति) के अंतर्गत न हुई हो।
- मृत एनपीएस ग्राहक का कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी जो यूपीएस चुनने से पहले सेवानिवृत्त हुआ हो।

यूपीएस के अंतर्गत अंशदान संरचना

- कर्मचारी अंशदान: मूल वेतन + महंगाई भत्ता (डीए) का 10%
- सरकारी अंशदान: मूल वेतन + महंगाई भत्ता (कर्मचारी अंशदान के बराबर) का 10%
- अतिरिक्त सरकारी अंशदान (पूल कॉर्पस): सुनिश्चित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मूल वेतन + महंगाई भत्ता का लगभग 8.5%
- PRAN खाता: सभी अंशदान और लेनदेन कर्मचारी के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) के अंतर्गत रखे जाते हैं

यूपीएस के अंतर्गत कॉर्पस

- व्यक्तिगत कॉर्पस (IC): कर्मचारी और सरकारी अंशदान से वास्तविक बचत

- बेंचमार्क कॉर्पस (BC): बिना किसी निकासी के नियमित अंशदान मानकर गणना की गई काल्पनिक राशि
- एनपीएस की तुलना में यूपीएस के प्रमुख लाभ

प्रकृति:

- एनपीएस: नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य (2004 के बाद)
- यूपीएस: पात्र कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक

अंशदान:

- एनपीएस: कर्मचारी द्वारा 10% + सरकार द्वारा 14%
- यूपीएस: कर्मचारी द्वारा 10% + सरकार द्वारा 10% + 8.5% पूल कॉर्पस

सुनिश्चित भुगतान:

- एनपीएस: नहीं
- यूपीएस: हाँ (शर्तों के अधीन)

न्यूनतम पेंशन:

- एनपीएस: नहीं
- यूपीएस: ₹10,000/माह

महंगाई राहत:

- एनपीएस: नहीं
- यूपीएस: हाँ

अंतिम निकासी:

- एनपीएस: 60% तक
- यूपीएस: 60% तक

पारिवारिक लाभ:

- एनपीएस: वार्षिकी पर निर्भर
- यूपीएस: ग्राहक के भुगतान का 60%

आंशिक निकासी:

- एनपीएस: हाँ
- यूपीएस: हाँ

अतिरिक्त जानकारी

- 2004 से पहले भर्ती हुए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत निश्चित पेंशन के साथ थे। 2004 के बाद के कर्मचारी बाजार से जुड़ी एनपीएस के अंतर्गत हैं।
- कई कर्मचारी अधिक सुरक्षा और बिना किसी अंशदान की आवश्यकता के ओपीएस में वापसी की मांग करते हैं।
- ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) देश भर के किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे भुगतान सुव्यवस्थित होता है और तत्काल ऋण सुनिश्चित होता है।
- 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का उद्देश्य विशेष रूप से गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

निष्कर्ष

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक आधुनिक, सुनिश्चित और मुद्रास्फीति-संरक्षित सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है, जो एनपीएस की सीमाओं को दूर करते हुए पूर्वानुमानित और समान लाभ प्रदान करती है। इसे

अपनाने से कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार होगा और साथ ही यह पेंशन क्षेत्र में सरकारी सुधारों के अनुरूप भी होगा।

नया यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडा: द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना

यूरोपीय संघ (ईयू) ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा का अनावरण किया है, जिसमें पारस्परिक हितों और पूरक शक्तियों के पाँच प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यूरोपीय संघ ने 2025 के अंत तक भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा एफटीए समझौता होगा।

रणनीतिक एजेंडे के पाँच स्तंभ

- आर्थिक विकास, स्थिरता और नवाचार
- व्यापार और निवेश में अप्रयुक्त क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यूरोपीय संघ-भारत एफटीए को प्राथमिकता देता है और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को मज़बूत करता है।
- यूरोपीय संघ-भारत स्टार्टअप साझेदारी और होराइज़न यूरोप के माध्यम से प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देता है।
- हरित परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु लचीलापन और आपदा प्रबंधन का समर्थन करता है।

सुरक्षा और रक्षा सहयोग

- समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, आतंकवाद-निरोध और संकट प्रबंधन को बढ़ावा देता है।
- उत्पादन, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सुधार के लिए रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

संपर्क और वैश्विक साझेदारियाँ

त्रिपक्षीय सहयोग के लिए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) और ग्लोबल गेटवे को समर्थन प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, वैश्विक शासन और बहुपक्षीय मूल्यों को मज़बूत करने के लिए बहुपक्षीय मंचों में सहभागिता को बढ़ावा देता है।

लोगों के बीच सहभागिता

- यूरोपीय लीगल गेटवे कार्यालय और अध्ययन, कार्य और अनुसंधान के ढाँचों के माध्यम से कौशल गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है।
- नागरिक समाज, युवाओं, थिंक टैंकों और व्यवसायों के साथ सहभागिता को गहरा करता है, जिसमें यूरोपीय संघ-भारत व्यापार मंच के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

समन्वय और रणनीतिक संरेखण

- कई स्तरों पर यूरोपीय संघ-भारत समन्वय को बढ़ावा देता है।
- साझा प्राथमिकताओं के आधार पर एक व्यापक रणनीतिक योजना बनाता है।
- विदेश मामलों की परिषद के माध्यम से यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को एकजुट करता है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का महत्व**पारस्परिक महत्व:**

- राजनयिक संबंध: भारत-यूरोपीय संघ संबंध 1962 में शुरू हुए और 2004 में रणनीतिक साझेदारी में उन्नत हुए।
- व्यापार संबंध: यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है (€120 बिलियन, व्यापार का 11.5%)।
- रणनीतिक संरक्षण: सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई और बहुपक्षवाद में सहयोग।
- अवसंरचना और प्रौद्योगिकी: टीटीसी सेमीकंडक्टर, एआई, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल वित्त सहयोग को बढ़ावा देता है।
- वैश्विक शासन: यूरोपीय संघ चीन पर निर्भरता कम करता है, भारत के व्यापार विविधीकरण का समर्थन करता है, और नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था (जी20, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र) की वकालत करता है।

भारत के लिए महत्व:

- आर्थिक विकास: यूरोपीय संघ भारत का नौवां सबसे बड़ा साझेदार है, जिसका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 107.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2000-2023) है।
- रक्षा एवं सुरक्षा: यूरोपीय कंपनियाँ भारत के रक्षा आधुनिकीकरण (जैसे, एयरबस सी-295) का समर्थन करती हैं।
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा और वित्तीय प्रौद्योगिकी में सहयोग।

यूरोपीय संघ के लिए महत्व:

- बाज़ार पहुँच: भारत एक विशाल, बढ़ता हुआ बाज़ार प्रदान करता है।
- मानव पूँजी: भारत का कुशल कार्यबल यूरोपीय शैक्षणिक और औद्योगिक सहयोग का समर्थन करता है।
- भू-राजनीतिक सहयोग: भारत वैश्विक दक्षिण में यूरोपीय संघ के प्रभाव को बढ़ाता है।
- सुरक्षा: हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यूरोप-एशिया व्यापार के 35% की सुरक्षा करता है।

यूरोपीय संघ-भारत संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ

- ठप पड़ी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वार्ता: ऑटोमोबाइल, स्पिरिट, डेयरी, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेवाओं पर शुल्क को लेकर विवाद।
- नियामक एवं निवेश बाधाएँ: यूरोपीय संघ के तकनीकी और स्वच्छता संबंधी नियम; पूर्वानुमानित निवेश नीतियों की आवश्यकता।
- डेटा गोपनीयता: यूरोपीय संघ के सख्त डेटा कानून भारतीय आईटी फर्मों के लिए अनुपालन लागत बढ़ाते हैं।
- विदेश नीति में भिन्नताएँ: रूस के प्रति भारत का तटस्थ रुख यूरोपीय संघ की अपेक्षाओं के विपरीत है।
- आपूर्ति श्रृंखला जोखिम: चीन पर निरंतर निर्भरता भू-राजनीतिक और व्यापारिक कमज़ोरियों को जन्म देती है।

संबंधों को मज़बूत करने के लिए नीतिगत सुझाव

- मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और व्यापार सुगमता में तेज़ी लाएँ: टैरिफ विवादों का समाधान करें और बातचीत को तेज़ करें।
- उच्च-तकनीकी निर्यात को बढ़ावा दें: भारत के विनिर्माण क्षेत्र में यूरोपीय निवेश को प्रोत्साहित करें।
- डेटा-साझाकरण ढाँचा: सीमा-पार डेटा प्रवाह के लिए गोपनीयता ढाँचे स्थापित करें।
- हरित प्रौद्योगिकी साझेदारी: नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों और कार्बन-तटस्थ तकनीक पर सहयोग करें।
- निवेश सुधार: बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा और व्यापार सुगमता को मज़बूत करें।
- सुरक्षा सहयोग बढ़ाएँ: संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, साइबर सुरक्षा और ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने का विस्तार करें।

भारत के जीएसटी में व्यापक बदलाव: जीएसटी 2.0 अगली पीढ़ी के कर सुधारों का प्रतीक**1. निर्णायक मोड़: क्या बदल रहा है और कब**

भारत की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था 2017 में लागू होने के बाद से अपने सबसे महत्वपूर्ण बदलाव से गुज़र रही है। जीएसटी 2.0 नामक यह सुधार चार-स्तरीय स्लैब संरचना (5%, 12%, 18%, 28%) को एक अधिक सरल प्रणाली में बदल देता है: **दो मुख्य स्लैब:** आवश्यक वस्तुओं के लिए 5% और अधिकांश अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए 18%।

पाप और विलासिता की वस्तुओं (जैसे तंबाकू, पान मसाला, उच्च-स्तरीय वस्तुएँ) के लिए एक विशेष 40% "डिमेरिट" स्लैब चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर पूर्ण जीएसटी छूट। ये बदलाव 22 सितंबर, 2025 से नवरात्रि के साथ लागू होंगे— त्योहारों की रौनक बढ़ाने और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम।

2. अभी क्यों? रणनीतिक और आर्थिक कारक

इस लंबित सुधार के पीछे कई कारक थे:

- सरलता और अनुपालन: कई स्लैबों ने भ्रम और अनुपालन संबंधी कठिनाइयाँ पैदा कीं। एक सुव्यवस्थित द्वि-स्तरीय प्रणाली करदाताओं और व्यवसायों, दोनों के लिए सरल बनाती है।
- मांग को प्रोत्साहित करना: वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, भारत उपभोग बढ़ाने के लिए घरेलू लागत में कमी पर दांव लगा रहा है। अमेरिका से टैरिफ के मंडराते खतरे को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
- चुनाव और त्योहारों का समय: त्योहारों के मौसम के करीब और प्रमुख राज्यों के चुनावों से पहले घोषित, यह राजकोषीय प्रोत्साहन राजनीतिक रूप से उपयुक्त है।
- संरचनात्मक सरलीकरण और आधुनिक शासन: इसे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक परिवर्तनकारी बदलाव के रूप

में देखा जा रहा है—जो जीएसटी के एक अधिक कुशल तंत्र की ओर विकास को दर्शाता है।

3. अब क्या सस्ता है? जीएसटी 2.0 से उपभोक्ता लाभ

आवश्यक वस्तुएं और दैनिक उपयोग की वस्तुएं (5% या शून्य जीएसटी)

- मुख्य किराना सामान, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ और बिस्कुट, चॉकलेट और कॉर्नफ्लेक्स जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 12-18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- यूएचटी दूध अब कर-मुक्त है (पहले 5%), जबकि पनीर, चीज़, मक्खन, घी और कंडेंस्ड मिल्क पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% या शून्य कर दिया गया है।
- डायपर, टूथब्रश, शैम्पू, हेयर ऑयल, साबुन, बिलिंग आइटम, दूध की बोतलें, रसोई के बर्तन और साइकिल जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुएं 5% कर के दायरे में आ गईं।
- पेंसिल, नोटबुक, नक्शे, ग्लोब आदि सहित स्टेशनरी पर जीएसटी 5-12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
- कृषि मशीनरी, उर्वरक, जैव-कीटनाशक और ट्रैक्टर के पुर्जों पर अब केवल 5% जीएसटी लागेगा।
- स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक वस्तुएं जैसे डायग्नोस्टिक किट, थर्मामीटर, चश्मा, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स, आदि। जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी दर घटकर 5% या शून्य हो गई है।
- व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर अब जीएसटी शून्य है।

मध्यम श्रेणी की वस्तुएं (18% GST)

टेलीविज़न, एसी, 350 सीसी से कम की बाइक, छोटी कारें, रसोई और सीमेंट पर अब 28% की बजाय 18% GST लागेगा—काफी कटौती

क्षेत्रवार उल्लेखनीय बदलाव:

ऑटोमोबाइल: 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और छोटी पेट्रोल/डीज़ल कारों पर अब 18% GST लागेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण: एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवाशर पर अब 28% से घटकर 18% GST लागेगा।

सीमेंट: निर्माण लागत कम करने के लिए 28% से घटाकर 18% कर दिया गया।

यात्रा और आतिथ्य:

₹7,500 से कम के होटल के कमरे: ITC के साथ GST 12% से घटकर ITC के बिना 5% हो गया।

इकोनॉमी क्लास के हवाई टिकट: 5% GST, जबकि प्रीमियम/बिज़नेस/प्रथम श्रेणी के टिकटों पर 18% GST लागेगा—बुकिंग तिथि के आधार पर।

4. क्या ज़्यादा महंगा है? उच्च जीएसटी दर

सरकार ने हानिकारक उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए उच्च कराधान दर बरकरार रखी है:

- गुटखा, तंबाकू, पान मसाला और कार्बोनेटेड पेय जैसे पाप और विलासिता के सामान अब 40% "डिमेरिट" स्लैब में आते हैं।

- गैर-अल्कोहलिक फ़िज़ी या कैफीनयुक्त पेय पर 40% की दर लागू होगी, जो पहले 18% या 28% थी, जो अब काफ़ी ज़्यादा है; यह स्वास्थ्य और राजस्व दोनों के लिए एक बड़ा कदम है।
- ₹2,500 से अधिक कीमत वाले परिधानों पर अब 12% से बढ़कर 18% कर लगेगा, जिसका असर उच्च-स्तरीय फैशन ब्रांडों पर पड़ेगा।
- कोयला और अन्य उच्च-प्रदूषण या विलासिता की वस्तुओं पर जीएसटी में वृद्धि होगी, जिससे कर नीति पर्यावरणीय और राजकोषीय उद्देश्यों के अनुरूप होगी।

5. वृहद-आर्थिक प्रभाव: घाटा, मुद्रास्फीति और विकास राजस्व प्रभाव:

₹48,000 करोड़ (लगभग 5.5 बिलियन डॉलर) का अनुमानित राजस्व नुकसान, जो पहले के अनुमानों से कम है। अनुपालन को बढ़ावा देने और कर आधार को व्यापक बनाने के लिए क्षतिपूर्ति उपकरण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र को सरल बनाने से नुकसान की भरपाई होगी।

मुद्रास्फीति:

अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति में 50-90 आधार अंकों की गिरावट आएगी, जो संभवतः 1% से भी अधिक होगी।

मांग-आधारित विकास:

आवश्यक वस्तुओं पर कम जीएसटी से खपत में वृद्धि होने की उम्मीद है, खासकर त्योहारों के मौसम में।

ऑटोमोटिव और उपकरण करों में कटौती से विवेकाधीन व्यय को पुनर्जीवित करना, मुद्रास्फीति और शुल्कों से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता करना।

सरलीकृत शासन:

जटिलता में कमी से राज्य और केंद्र कर संग्रह आसान होता है, डिजिटल-प्रथम नीतियों के अनुरूप है, और "विकसित भारत 2047" के विज़न के अनुरूप है।

इन कटौतियों में देरी क्यों हुई: राजनीतिक, प्रक्रियात्मक और राजकोषीय कारण

A. राजस्व हानि का डर

पहले राज्यों की अनिच्छा क्षतिपूर्ति उपकरण राजस्व पर निर्भर होने के कारण थी। बिना किसी विकल्प के जल्दबाज़ी में कर कम करने से उनके बजट पर दबाव पड़ता।

B. राजनीतिक सावधानी

जीएसटी में कटौती को लोकलुभावनवाद समझा जा सकता है। सरकार ने बिना किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया के बड़ी कटौती की घोषणा करने के लिए सही समय—त्योहारों का मौसम और चुनावी तैयारियाँ—का इंतज़ार किया।

C. संरचनात्मक रूप से जटिल प्रणाली

चार स्लैब, छूट, उपकरण और राज्यों के बीच भिन्नताओं के साथ, जीएसटी में सुधार करना तार्किक रूप से चुनौतीपूर्ण था। अब, जब डिजिटल बुनियादी ढाँचा परिपक्व हो गया है, तभी ऐसे बदलावों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

D. राजकोषीय संतुलन बिंदु ढूँढना

सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ से राज्य के राजस्व या जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुँचे। उच्च अवगुण स्लैब वाली दो-स्तरीय प्रणाली तैयार करना और उपकरणों को हटाना एक नाज़ुक संतुलनकारी कार्य था।

जीएसटी को समझना: सिद्धांत और पृष्ठभूमि

1. जीएसटी क्या है?

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक व्यापक, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है जिसने कई केंद्रीय और राज्य करों को एक एकीकृत कर में समाहित कर दिया है।

इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसे आज़ादी के बाद से भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माना गया।

मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन व्यापक प्रभावों से बचने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ।

2. जीएसटी की आवश्यकता

जीएसटी से पहले, भारत में एक जटिल कर संरचना थी जिसमें कई अतिव्यापी शुल्क थे:

1. केंद्रीय कर: उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिपूरक शुल्क।
2. राज्य कर: वैट, प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर, चुंगी, आदि।

इससे अक्षमताएँ, उच्च अनुपालन लागत और "कर पर कर" (व्यापक प्रभाव) उत्पन्न हुए।

जीएसटी का उद्देश्य:

भारत के संघीय ढांचे में कर प्रणाली को एकीकृत करना। अंतर-राज्यीय व्यापार बाधाओं को दूर करके व्यापार करने में आसानी बढ़ाना।

अधिक व्यवसायों को औपचारिक अनुपालन के अंतर्गत लाकर कर आधार का विस्तार करना।

एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार बनाना और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना।

3. संवैधानिक पृष्ठभूमि

जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से लागू किया गया था।

इसने एक अद्वितीय दोहरा जीएसटी मॉडल तैयार किया जिसमें केंद्र और राज्य दोनों एक साथ कर लगाते हैं:

1. सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) - केंद्र द्वारा संग्रहित।
 2. एसजीएसटी (राज्य जीएसटी) - राज्यों द्वारा संग्रहित।
- आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी) - अंतर-राज्यीय आपूर्ति और आयात पर लगाया जाता है।

4. संस्थागत तंत्र - जीएसटी परिषद

जीएसटी परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसके सदस्य राज्य के वित्त मंत्री होते हैं।

यह कर की दरें, छूट, सीमाएँ और संरचनात्मक सुधार तय करती है।

सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करते हुए, भारित मतदान (केंद्र 1/3, राज्य 2/3) द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।

5. जीएसटी स्लैब प्रणाली (मूल)

अपने शुभारंभ के समय, जीएसटी ने चार-स्तरीय स्लैब संरचना अपनाई:

1. 5% - आवश्यक वस्तुएँ (खाद्यान्न, दवाइयाँ, परिवहन)।
2. 12% और 18% - मानक वस्तुएँ और सेवाएँ।
3. 28% - विलासिता और अहितकर वस्तुएँ (कार, एयर कंडीशनर, तंबाकू)।
4. साथ ही, बुनियादी वस्तुओं के लिए 0%/छूट वाली सूची और कुछ वस्तुओं पर उपकरण।

6. जीएसटी की अब तक की उपलब्धियाँ

लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को कर के दायरे में लाकर अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण बढ़ा।

जीएसटीएन (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) के माध्यम से डिजिटल अनुपालन।

हाल के वर्षों में राजस्व में उछाल आया है, मासिक संग्रह अक्सर ₹1.5 लाख करोड़ को पार कर गया है।

एक राष्ट्र, एक कर का नारा काफी हद तक साकार हुआ है, जिससे रसद संबंधी बाधाएँ कम हुई हैं।

सारांश: जीएसटी 2.0 का परिवर्तनकारी वादा

- अपनी सरल संरचना, आकांक्षापूर्ण समय और व्यापक राहत के साथ, जीएसटी 2.0 को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है:
- कर अनुपालन को आसान बनाना और प्रशासनिक बोझ कम करना
- दिवाली से ठीक पहले उपभोग को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना
- कृषि से लेकर ऑटो तक प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन
- राजकोषीय स्थिरता बनाए रखना और एक स्थायी जीएसटी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना

अवलोकन तालिका

श्रेणी	विवरण
स्लैब संरचना	5% (आवश्यक वस्तुएँ), 18% (मानक), 40% (पाप/विलासिता)
प्रभावी तिथि	22 सितंबर, 2025 (नवरात्रि प्रारंभ)
प्रमुख लाभ	किराने का सामान, उपकरण, वाहनों पर कम जीएसटी; कर-मुक्त बीमा
प्रभावित क्षेत्र	खाद्य, स्वास्थ्य, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, आतिथ्य, कृषि
राजस्व प्रभाव	₹48,000 करोड़ का अनुमानित घाटा, संरचनात्मक डिज़ाइन द्वारा कम किया गया
मुद्रास्फीति राहत	0.5-1.0 प्रतिशत अंकों की अपेक्षित कमी
अभी क्यों?	चुनावी समय, त्योहारी मांग, परिपक्व डिजिटल बुनियादी ढांचा

रक्षा एवं सुरक्षा

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत किसी एक देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सुरक्षा और रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप देता है। पाकिस्तान दशकों से सऊदी अरब की सेनाओं को प्रशिक्षित करता रहा है और सऊदी अरब पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए सहायता सहित वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है।

रणनीतिक संदर्भ

यह समझौता कतर पर इजराइल के हमले के तुरंत बाद हुआ है, जो पश्चिम और दक्षिण एशिया में बदलती सुरक्षा गतिशीलता को दर्शाता है। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी राजतंत्र पारंपरिक रूप से अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का ध्यान इस क्षेत्र से हटा जा रहा है। यह समझौता ईरान, इजराइल और अन्य कारकों के बीच क्षेत्रीय तनाव के बीच सऊदी अरब के सुरक्षा गठबंधनों के विविधीकरण का संकेत देता है।

क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव

पाकिस्तान के लिए, यह समझौता खाड़ी में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में उसकी भूमिका को मजबूत करता है और सऊदी अरब से संभावित वित्तीय और रणनीतिक सहायता प्राप्त करता है। सऊदी अरब के लिए, यह पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंधों को संस्थागत बनाता है, सैन्य विशेषज्ञता तक पहुँच सुनिश्चित करता है और साथ ही अमेरिका के नेतृत्व वाले सुरक्षा ढाँचों से स्वतंत्रता का संकेत देता है। भारत, जिसने इजराइल समर्थक रुख अपनाया है, के लिए यह समझौता पश्चिम एशिया में उसकी गतिविधियों को जटिल बना सकता है। भारत को क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

प्रमुख चिंताएँ और जोखिम

यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान का परमाणु छत्र सऊदी अरब तक फैला है या नहीं। संभावित फँसने के जोखिम: पाकिस्तान खाड़ी संकटों में और सऊदी अरब दक्षिण या मध्य एशियाई तनावों में फँस सकता है। इजराइल-गाज़ा युद्ध सहित चल रहे संघर्षों के बीच फ़ारस की खाड़ी और व्यापक पश्चिम एशिया में गठबंधनों के पुनर्गठन पर प्रकाश डालता है।

भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा सहयोग

भारत और बांग्लादेश सीमा पार अपराध के विरुद्ध संयुक्त प्रयासों को तेज़ करने पर सहमत हुए हैं:

- समन्वित गश्त (सीओपी) बढ़ाना
- वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करना बढ़ाना
- सीमा पर सतर्कता को मजबूत करना

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

निम्नलिखित से निपटने के लिए समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीबीएमपी) का कार्यान्वयन:

- तस्करी
- मानव तस्करी
- अवैध घुसपैठ
- आतंकवाद और उग्रवाद
- सामुदायिक सहभागिता: सीमावर्ती आबादी को शिक्षित करना, संवेदनशील क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास।
- बुनियादी ढाँचा और सुरक्षा उपाय: बाड़ लगाने में तेज़ी लाना, सीमा चौकियों में सुधार करना और नदी तटों की सुरक्षा करना।
- शून्य सहनशीलता नीति: दोनों पक्षों ने आतंकवाद और उग्रवादी गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत-बांग्लादेश सीमा:

- लंबाई: 4,096 किमी (भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा)।
- 5 भारतीय राज्यों को छूता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम।

सीमा सुरक्षा बल:

- भारत: सीमा सुरक्षा बल (BSF), जिसकी स्थापना 1965 में भारत-पाक युद्ध के बाद हुई थी।
- बांग्लादेश: बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB), जिसे पहले बांग्लादेश राइफल्स (BDR) के नाम से जाना जाता था, का नाम 2010 में बदल दिया गया।

समझौते:

सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए 2011 में समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (CBMP) पर हस्ताक्षर किए गए। भूमि सीमा समझौते (LBA) पर 2015 में हस्ताक्षर किए गए, जिससे लंबे समय से लंबित सीमा विवादों और एन्क्लेव मुद्दों का समाधान हुआ।

द्विपक्षीय संबंध:

भारत, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद 1971 में उसे मान्यता देने वाला पहला देश था। व्यापार, संपर्क, आतंकवाद-रोधी और नदी जल बंटवारे में मजबूत सहयोग।

भारत-फ़िजी ने रक्षा कार्य योजना को अंतिम रूप दिया, सांस्कृतिक एवं खेल कूटनीति को बढ़ावा दिया

भारत और फ़िजी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिंगामामादा राबुका के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान एक रक्षा कार्य योजना को अंतिम रूप दिया। यह कार्य योजना रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, खेल और संस्कृति में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है, जिससे चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच वैश्विक दक्षिण और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत की भागीदारी मजबूत होगी।

यात्रा की मुख्य विशेषताएँ:**रक्षा एवं सुरक्षा:**

- भारत फ़िजी की समुद्री सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करेगा।
- रक्षा और आपदा प्रतिक्रिया में सहयोग को मज़बूत किया गया।

हस्ताक्षरित समझौते (7 समझौता ज्ञापन):

- रक्षा सहयोग
- आपदा प्रबंधन
- शिक्षा एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान
- खेल सहयोग (क्रिकेट विकास सहित)।

सांस्कृतिक कूटनीति:

भारतीय शिक्षक फ़िजी विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत पढ़ाएँगे।

फ़िजी के पंडित भारत में गीता महोत्सव में भाग लेंगे।

सामरिक महत्व:

फ़िजी को एक स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में एक प्रमुख साझेदार माना जाता है। मोदी ने वैश्विक दक्षिण सहयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए आपदा प्रबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

भारत-फ़िजी संबंध:

- 1970 में (फ़िजी की स्वतंत्रता के बाद) राजनयिक संबंध स्थापित हुए।
- भारत का सुवा में एक उच्चायोग है।
- विशाल भारतीय प्रवासी (फ़िजी की जनसंख्या का लगभग 37%), जिनमें से अधिकांश गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फ़िजी:

- दक्षिण प्रशांत महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित।
- जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील, जिससे आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है।

वैश्विक दक्षिण सहयोग:

भारत-प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच (FIPIC) के तहत भारत प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ संबंधों को मज़बूत कर रहा है। पहला FIPIC शिखर सम्मेलन 2014 में फ़िजी में आयोजित किया गया था।

खेल कूटनीति के उदाहरण:

भारत ने पहले अफ़ग़ानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और कैरिबियन में क्रिकेट के विकास का समर्थन किया है।

भारतीय नौसेना को स्वदेशी रॉकेट और सोनार से लैस INS एंड्रोथ प्राप्त हुआ

भारतीय नौसेना को औपचारिक रूप से INS एंड्रोथ प्राप्त हो गया है, जो आठ पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल यानों (ASW SWCs) की श्रृंखला का दूसरा जहाज है। इस जहाज का निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा किया गया था। इसे 13 सितंबर 2025 को सौंपा गया था।

डिज़ाइन और क्षमताएँ

INS एंड्रोथ लगभग 77 मीटर लंबा है और डीजल इंजन + वाटरजेट प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करने वाले सबसे बड़े भारतीय युद्धपोतों में से एक है। इसकी 80% से अधिक सामग्री स्वदेशी है, जो "आत्मनिर्भर भारत" के लक्ष्य के अनुरूप है।

हथियार प्रणालियाँ और सोनार

यह हल्के टॉरपीडो, स्वदेशी ASW रॉकेट और उन्नत उथले जल सोनार प्रणालियों से लैस है। ये विशेषताएँ तटीय या "तटीय" जल में पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उनसे निपटने की इसकी क्षमता को बढ़ाती हैं।

भूमिका और रणनीतिक महत्व

एंड्रोथ, पनडुब्बी रोधी युद्ध, तटीय निगरानी और बारूदी सुरंग बिछाने के अभियानों में नौसेना की क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप के नाम पर इस जहाज का नामकरण, अपने समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के प्रति भारत के समर्पण को दर्शाता है।

व्यापक प्रभाव

यह आपूर्ति 16 ASW उथले जल यानों के निर्माण की योजना का हिस्सा है, जिससे तट के पास भारत की नौसैनिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह प्रगति आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने में सहायक है।

भारतीय नौसेना ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए गुरुग्राम में INS अरावली का जलावतरण किया

भारतीय नौसेना ने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में गुरुग्राम में एक समारोह में INS अरावली का जलावतरण किया। इस नए अड्डे का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और सहयोग के केंद्र के रूप में कार्य करना है, जो महासागरों के पार स्थित नौसैनिक प्लेटफार्मों और साझेदारों को जोड़ेगा। यह पहल भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण, महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) का समर्थन करती है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। INS अरावली का जलावतरण हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में एक पसंदीदा सुरक्षा साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को और पुष्ट करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

- INS अरावली भारत के अपने नौसैनिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और समुद्री साझेदारी को मज़बूत करने के प्रयास का हिस्सा है।
- यह भारत की सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) नीति के अनुरूप है और व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति का पूरक है।
- यह बेस मित्र देशों के साथ अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाएगा और संयुक्त अभ्यास, आपदा प्रतिक्रिया और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को सक्षम बनाएगा।
- यह नीली अर्थव्यवस्था की पहलों में योगदान देगा और समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा करेगा।

- वैश्विक तेल शिपमेंट में 70% से अधिक का योगदान हिंद महासागर क्षेत्र का है, जिससे समुद्री सुरक्षा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन गई है।
- एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 2024 में नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे।

आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि: भारतीय नौसेना दो स्टील्थ फ्रिगेट्स को कमीशन करेगी

भारतीय नौसेना 26 अगस्त 2025 को विशाखापत्तनम में दो नीलगिरि श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स—आईएनएस उदयगिरि (मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई द्वारा निर्मित) और आईएनएस हिमगिरि (गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता द्वारा निर्मित)—को कमीशन करेगी।

दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17ए (पी-17ए) का हिस्सा हैं, जिसके तहत पहले आईएनएस नीलगिरि को कमीशन किया गया था।

यह पहली बार है जब दो अलग-अलग शिपयार्ड के दो प्रमुख सतही लड़ाकू जहाजों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है।

- विस्थापन: 6,700 टन (शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट्स से बड़ा और स्टील्थ)।
- प्रणोदन: डीजल इंजन और गैस टर्बाइनों के साथ CODOG (संयुक्त डीजल या गैस) प्रणाली।
- हथियार सूट: सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, मध्यम दूरी की एसएएम, 76 मिमी एमआर गन, 30 मिमी और 12.7 मिमी सीआईडब्ल्यूएस, पनडुब्बी रोधी प्रणालियाँ।
- औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र: 200 से अधिक एमएसएमई शामिल, 4,000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित।
- आईएनएस उदयगिरि भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया 100वाँ जहाज है।

सामरिक महत्व:

चीन की "स्टिंग ऑफ़ पर्स" रणनीति (ग्वादर, हंबनटोटा, चटगाँव, जिबूती) के विरुद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री उपस्थिति को मज़बूत करता है। मलक्का जलडमरूमध्य से अफ्रीका तक समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा बढ़ाता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का प्रतीक।

निर्माता:

- आईएनएस उदयगिरि - एमडीएल, मुंबई।
- आईएनएस हिमगिरि - जीआरएसई, कोलकाता।
- विस्थापन: लगभग 6,700 टन।
- प्रणोदन: CODOG (संयुक्त डीजल या गैस)।
- पहली बार: दो शिपयार्डों से दो युद्धपोतों का एक साथ जलावतरण।
- सामरिक भूमिका: चीन की मोतियों की माला का मुकाबला करना, हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना।

मोरक्को में भारत के पहले विदेशी रक्षा संयंत्र का उद्घाटन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान मोरक्को में भारत के पहले विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे।

यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की मोरक्को की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत-मोरक्को रक्षा संबंधों को मज़बूत करना और अफ्रीका में भारत के रक्षा निर्यात का विस्तार करना है।

रक्षा विनिर्माण संयंत्र

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) का संयंत्र कैसाब्लांका के बेरेचिड में स्थित है। मोरक्को के शाही सशस्त्र बलों के साथ साझेदारी में स्थापित। यह व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफ़ॉर्म (WhAP) 8x8, एक उभयचर पैदल सेना लड़ाकू वाहन, जो सभी इलाकों में संचालन करने में सक्षम है, को असेंबल करेगा।

रणनीतिक महत्व

अफ्रीका को भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक लॉन्चपैड के रूप में कार्य करता है। मोरक्को के साथ राजनयिक और सुरक्षा संबंधों को मज़बूत करता है। मोरक्को को भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए अफ्रीका और यूरोप का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन से पहले भारत-अफ्रीका रक्षा सहयोग को बढ़ाता है।

भारत-मोरक्को रक्षा संबंधों में वृद्धि

2023 में, मोरक्को के शाही सशस्त्र बलों को TASL से 92 छह-पहिया सैन्य ट्रक प्राप्त हुए। पिछले वर्ष, मोरक्को ने टाटा समूह से LPTA 2445 रक्षा डंप ट्रक खरीदे। मोरक्को का लक्ष्य: आधुनिक और सुसज्जित सेना; अन्य आपूर्तिकर्ताओं में अमेरिका, इज़राइल और चीन शामिल हैं।

उल्लेखनीय तथ्य:

- टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL): DRDO के साथ सहयोग करने वाली प्रमुख भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी।
- व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफ़ॉर्म (WhAP) 8x8: विभिन्न भूभागों के लिए उपयुक्त उभयचर पैदल सेना लड़ाकू वाहन।
- आत्मनिर्भर भारत पहल: रक्षा, विनिर्माण और अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 2020 में शुरू की गई।
- भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन: भारत और अफ्रीकी देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए हर 3 साल में आयोजित किया जाता है।
- कैसाब्लांका: मोरक्को का सबसे बड़ा शहर, प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्र।
- मोरक्को की राजधानी: रबात
- मोरक्को के प्रधानमंत्री: अज़ीज़ अख़त्रौच
- मोरक्को की मुद्रा: मोरक्कन दिरहम

माह के रक्षा/सैन्य अभ्यास

जैपड-2025

भारत ने रूस के साथ अपनी दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी के तहत, रूस के निज़नी नोवगोरोड में आयोजित जैपड-2025 सैन्य अभ्यास में भाग लिया। थल सेना, वायु सेना और नौसेना के 65 भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों की एक टुकड़ी ने इस अभ्यास में भाग लिया। भारतीय सेना समूह का नेतृत्व कुमाऊँ रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया। यह अभ्यास रूस और बेलारूस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 1,00,000 सैनिक शामिल थे। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सैन्य सहयोग, अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना और पारंपरिक युद्ध तथा आतंकवाद-रोधी अभियानों से संबंधित रणनीतियों को साझा करना था। यह अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिससे भाग लेने वाले बलों को परिचालन तत्परता में सुधार करने, उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने और एक बहुराष्ट्रीय वातावरण में मिलकर काम करने का अवसर मिला। भारत की भागीदारी ने रूस के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत किया, आपसी विश्वास को बढ़ावा दिया और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा दिया। अभ्यास के 2025 संस्करण में रूस और बेलारूस के अलावा, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो, माली, भारत, ईरान, नाइजर और ताजिकिस्तान सहित बीस से अधिक देश भाग लेंगे। पर्यवेक्षकों में कंबोडिया, चीन, क्यूबा, कजाकिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, निकारागुआ, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सर्बिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और उज्बेकिस्तान शामिल होंगे।

भारत और रूस के बीच अन्य सैन्य अभ्यास

इंद्रा अभ्यास श्रृंखला

भारत और रूस के बीच एक प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसमें थल, वायु और जल सेनाएँ शामिल हैं। यह पहली बार 2003 में आयोजित किया गया था और दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया गया था।

रूसइंड अभ्यास

- रूसी और भारतीय सेनाओं के बीच विशेष बल अभ्यास।
- आतंकवाद-निरोध, विशेष अभियानों और अपरंपरागत युद्ध पर केंद्रित।

अभ्यास केंद्र-2019 / वोस्तोक श्रृंखला (रूस के साथ)

- रूस के वोस्तोक और केंद्र अभ्यास जैसे बड़े पैमाने के सैन्य अभ्यासों में भारतीय सेनाओं की भागीदारी।
- विभिन्न सेनाओं के बीच रणनीतिक अभियानों और समन्वय पर केंद्रित।

पैसिफिक रीच 2025

भारतीय नौसेना का आईएनएस निस्तार सिंगापुर में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में भाग ले रहा है। आईएनएस निस्तार एक गोताखोरी सहायता पोत (डीएसवी) है, जिसे भारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया

है। यह अभ्यास एक द्विवार्षिक आयोजन है, जिसमें इस वर्ष 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। आईएनएस निस्तार गहरे जलमग्न बचाव वाहनों (डीएसआरवी) के लिए मुख्य पोत के रूप में कार्य करता है और अन्य नौसेनाओं के साथ पनडुब्बी बचाव अभ्यास और विषय विशेषज्ञ आदान-प्रदान (एसएमईई) में भाग लेगा।

अभ्यास चरण:

बंदरगाह चरण (सप्ताह भर):

- पनडुब्बी बचाव प्रणालियों पर चर्चा
- SMEE सत्र
- चिकित्सा संगोष्ठियाँ
- भाग लेने वाले देशों के बीच क्रॉस-डेक दौरे

समुद्री चरण:

- दक्षिण चीन सागर में बचाव और हस्तक्षेप अभ्यास आयोजित
- अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के साथ INS निस्तार और पनडुब्बी बचाव इकाई (E) की भागीदारी

INS निस्तार:

- प्रकार: गोताखोरी सहायता पोत (DSV)
- डिज़ाइन और निर्माण: भारत द्वारा स्वदेशी रूप से
- प्राथमिक भूमिका: गहरे जलमग्न बचाव वाहनों (DSRV) के लिए मुख्य पोत के रूप में कार्य करता है
- उद्देश्य: हस्तक्षेप, बचाव अभ्यास और पानी के भीतर आपात स्थितियों सहित पनडुब्बी बचाव कार्यों में सहायता प्रदान करना
- क्षमताएँ: गहरे समुद्र में बचाव, चिकित्सा सहायता और विशेषज्ञ समन्वय के लिए उन्नत प्रणालियों से सुसज्जित
- संबद्ध इकाई: अभियानों के दौरान पनडुब्बी बचाव इकाई (E) के साथ कार्य करती है
- रणनीतिक महत्व: भारत की पनडुब्बी बचाव क्षमता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाता है

फ्रीडम एज अभ्यास

संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने फ्रीडम एज नामक पाँच दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों के जवाब में अपनी सामूहिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है।

अभ्यास विवरण

- अवधि: 15-19 सितंबर, 2025
- स्थान: दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू के अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में
- उद्देश्य: उत्तर कोरिया के उभरते परमाणु और मिसाइल खतरों के विरुद्ध मिसाइल रक्षा और संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना

भाग लेने वाले देश

- संयुक्त राज्य अमेरिका
- दक्षिण कोरिया
- जापान

- यह अभ्यास पिछले वर्ष जून और नवंबर में हुए पिछले सत्रों के बाद त्रिपक्षीय अभ्यासों के तीसरे दौर का प्रतीक है।

प्रशिक्षण के मुख्य क्षेत्र

- बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा: मिसाइल खतरों को रोकने और बेअसर करने की क्षमता बढ़ाना
- वायु रक्षा अभ्यास: हवाई खतरों के विरुद्ध समन्वय और प्रतिक्रिया समय में सुधार
- चिकित्सा निकासी प्रशिक्षण: त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया और निकासी प्रक्रियाओं का अनुकरण
- समुद्री अवरोधन अभियान: अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में जहाजों के अवरोधन और निरीक्षण का अभ्यास

समवर्ती अभ्यास

आयरन मेस अभ्यास: दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक टेबलटॉप सैन्य अभ्यास, जो उत्तर कोरियाई खतरों को रोकने के लिए परमाणु और पारंपरिक सैन्य संसाधनों को एकीकृत करने पर केंद्रित है।

उत्तर कोरिया की प्रतिक्रिया

- निंदा: उत्तर कोरिया ने संयुक्त अभ्यास की निंदा की है, और नेता किम जोंग-उन की बहन किम यो-जोंग ने चेतावनी दी है कि इस तरह के "लापरवाहीपूर्ण बल-प्रदर्शन" के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।
- परमाणु स्थिति घोषणा: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के एक सत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की हालिया आलोचना के बाद, उत्तर कोरिया ने घोषणा की कि उसके परमाणु हथियार की स्थिति कानून में "स्थायी रूप से निहित" है और इसे "अपरिवर्तनीय" माना जाता है।

अभ्यास दिबांग शक्ति

पूर्वी हिमालय में एक साहसिक अभ्यास

अरुणाचल प्रदेश की सुदूर दिबांग घाटी में, भारतीय सेना ने 'अभ्यास दिबांग शक्ति' नामक एक गहन प्रशिक्षण अभ्यास किया। हिमालय का ऊबड़-खाबड़ इलाका—घने जंगल, बर्फीली नदियाँ और खड़ी ढलानें—सेना की तैयारी का परीक्षण स्थल बन गया।

वास्तविक परिस्थितियों में सैनिकों का परीक्षण

कई दिनों तक, सैनिकों ने 1,000 से 4,000 मीटर की ऊँचाई पर, अचानक मौसम परिवर्तन और कठिन जंगल के रास्तों का सामना करते हुए, युद्ध किया। लक्ष्य सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण था: यह साबित करना कि वे भारत की पूर्वी सीमा के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में लड़ सकते हैं और जीवित रह सकते हैं।

प्रदर्शन कौशल

यह अभ्यास जंगल युद्ध की रणनीति, ऊँचाई पर जीवित रहने और तीव्र युद्ध प्रतिक्रिया का प्रदर्शन था। टीमों ने घने जंगल में चुपके से आगे बढ़ने का अभ्यास किया। विशेष बलों ने लड़ाकू फ्री-फॉल ड्रॉप्स का प्रदर्शन किया। इकाइयों ने उग्रवाद-रोधी और अपरंपरागत खतरे की परिस्थितियों का पूर्वाभ्यास किया।

तकनीक और रणनीति का संगम

आधुनिक निगरानी उपकरणों और उन्नत हथियारों का इस्तेमाल वास्तविक युद्धक्षेत्र की परिस्थितियों का अनुकरण करने के लिए किया गया। पैदल सेना, विशेष बलों और सहायक इकाइयों के बीच समन्वय ने प्रदर्शित किया कि सेना कितनी जल्दी नए युग के युद्ध के अनुकूल ढल सकती है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

दिबांग शक्ति अभ्यास एक स्पष्ट संदेश देता है: भारत अपनी पूर्वी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है। यह सेना की युद्ध तैयारियों को मज़बूत करता है, टीम वर्क को प्रखर बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि सैनिक विषम परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास से भरे रहें।

मैत्री-XIV

भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री-XIV मेघालय के री-भोई जिले के उमरोई छावनी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह अभ्यास लगभग 14 दिनों तक चला।

मुख्य गतिविधियाँ

- संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत आयोजित।
- इसमें सामरिक अभ्यास, परिचालन योजना और युद्ध प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण शामिल था।

अंतिम 48 घंटे के सत्यापन चरण में शामिल थे:

- एक अस्थायी संचालन अड्डा (TOB) स्थापित करना
- खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) कार्य
- गांवों को अलग करने के अभियान
- हेलीबोर्न अभियान
- छापे और बंधक-बचाव अभियान
- दोनों सेनाओं ने नई पीढ़ी के सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया।

सांस्कृतिक और टीम-निर्माण कार्यक्रम

- समापन समारोह में दोनों देशों के उत्कृष्ट सैनिकों को सम्मानित किया गया।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत और थाईलैंड की परंपराओं पर प्रकाश डाला गया।
- वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और रस्साकशी जैसे मैत्रीपूर्ण खेल आयोजनों ने मित्रता को और मज़बूत किया।

उद्देश्य और परिणाम

- भारतीय और थाई सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता में सुधार।
- संचालन रणनीति और युद्ध अभ्यासों का ज्ञान साझा करना।
- द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मज़बूत करना और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देना।

भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा अभ्यासों की सूची

1. अभ्यास मैत्री (सेना)

- प्रकार: संयुक्त सैन्य अभ्यास
- प्रारंभ: 2006
- आवृत्ति: द्विवार्षिक (प्रत्येक दो वर्ष में)

- उद्देश्य: जंगल और शहरी वातावरण में उग्रवाद-रोधी और आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण।
- हाल के संस्करण:
- मैत्री-XIII – 2019 (उमरोई, मेघालय)
- मैत्री-XIV – 2025 (उमरोई, मेघालय)

2. अभ्यास इंडो-थाई कॉर्पेट (नौसेना)

- प्रकार: समन्वित गश्ती
- प्रारंभ: 2005
- आवृत्ति: वर्ष में दो बार
- उद्देश्य: समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और अंडमान सागर तथा आसपास के क्षेत्रों को समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और तस्करी से सुरक्षित रखना।
- विशेषताएँ: संयुक्त निगरानी, समुद्री गश्त और खोज एवं बचाव अभ्यास।

3. अभ्यास सियाम भारत (वायु सेना)

- प्रकार: वायु सेना सहयोग
- फोकस: मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) और संयुक्त हवाई अभियान।
- स्थिति: छोटे पैमाने के हवाई अभ्यास और आदान-प्रदान कार्यक्रमों के रूप में आयोजित।

4. तटरक्षक संयुक्त गश्ती / एचएडीआर अभ्यास

- प्रकार: रॉयल थाई नौसेना/तटरक्षक बल के साथ भारतीय तटरक्षक बल
- उद्देश्य: अंडमान सागर में समुद्री सुरक्षा, समुद्री डकैती विरोधी गश्त और खोज एवं बचाव अभियान।

एक्सरसाइज अलेक्जेंडर

भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस त्रिकंद, एक स्टील्थ फ्रिगेट, हेलीनिक (यूनानी) नौसेना के साथ पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, "एक्सरसाइज अलेक्जेंडर" में भाग लेने के लिए ग्रीस के सलामिस खाड़ी पहुँचा। यह यात्रा भूमध्य सागर में जहाज की चल रही तैनाती का हिस्सा है।

एक्सरसाइज अलेक्जेंडर में प्रमुख गतिविधियाँ

बंदरगाह चरण:

- बैठकों और ब्रीफिंग की योजना बनाना।
- भारतीय और यूनानी नौसेना अधिकारियों के बीच क्रॉस-डेक दौरा।
- समझ बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक और व्यावसायिक आदान-प्रदान।

समुद्री चरण:

- संयुक्त अभ्यास और सामरिक युद्धाभ्यास।
- अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए संचार और गठन अभ्यास।

संबद्ध तैनाती

इससे पहले, INS त्रिकंद ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास में भाग लेने के लिए (1 सितंबर को) मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में डॉक किया गया था। ब्राइट स्टार 2025 एक बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास था जिसमें भारतीय सेना, वायु सेना और सऊदी अरब, कतर, ग्रीस, साइप्रस, इटली और अमेरिका जैसे देशों की सेनाएँ शामिल थीं। मिस्र में भी इसी तरह की सहयोगी गतिविधियाँ हुईं: सैन्य चर्चाएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल।

उद्देश्य और महत्व

- भारत और ग्रीस के बीच नौसैनिक सहयोग को मज़बूत करना।
- भूमध्यसागरीय क्षेत्र में परिचालन समन्वय और समुद्री सुरक्षा में सुधार करना।
- सांस्कृतिक और व्यावसायिक आदान-प्रदान के माध्यम से सद्भावना और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना।

युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास

भारतीय सेना ने पूर्वी हिमालय के कामेंग क्षेत्र में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जो अत्यधिक मौसम की स्थिति वाला एक उच्च-ऊँचाई वाला क्षेत्र है। इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण इलाकों में युद्ध की तैयारी, अनुकूलनशीलता और अगली पीढ़ी की तकनीकों के एकीकरण को प्रमाणित करना था।

मुख्य प्रदर्शन

इस अभ्यास में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शामिल थे, जिनमें शामिल थे:

- ड्रोन निगरानी
- वास्तविक समय में लक्ष्य प्राप्ति और सटीक हमले
- हवाई-तटीय प्रभुत्व
- समन्वित युद्धक्षेत्र संचालन

तकनीकी प्रगति

इसका एक प्रमुख आकर्षण ASHNI प्लाटूनों का परिचालन पदार्पण था, जिन्हें अगली पीढ़ी की तकनीक को सामरिक युद्धक्षेत्र के अनुभव के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह मानवरहित प्रणालियों और सटीक हथियारों के उपयोग सहित बहु-क्षेत्रीय युद्ध की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम था।

रणनीतिक महत्व

युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास के सफल समापन ने उच्च-ऊँचाई और कठोर जलवायु परिस्थितियों में संचालन के लिए सेना की तत्परता की पुष्टि की। इसने तकनीकी प्रगति, अनुकूलनशीलता और भविष्य की युद्ध तैयारियों पर भारत के फोकस को भी प्रदर्शित किया, जिससे मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

"जीतने का असली मज़ा तो तब है !
जब सब आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो !!

"यदि मज़िल न मिले तो रास्ते बदलो !
क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियाँ बदलते हैं जड़े नहीं !!"

सामाजिक मुद्दे एवं योजनाएँ

तमिलनाडु ने अनाथ बच्चों के लिए 'अंबू करंगल' योजना शुरू की

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अनाथ और वंचित बच्चों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अंबू करंगल (प्यार के हाथ) योजना शुरू की। इस कल्याणकारी पहल के तहत, प्रत्येक पात्र बच्चे को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ₹2,000 की मासिक सहायता मिलेगी।

अन्य चल रही कल्याणकारी योजनाएँ:

- कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगाई योजना - 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को ₹1,000 मासिक सहायता।
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को वित्तीय सहायता।

त्वरित तथ्य:

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री: एम.के. स्टालिन
- तमिलनाडु के राज्यपाल: आर.एन. रवि।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015: अनाथ/परित्यक्त बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और गोद लेने का प्रावधान करता है।
- तमिलनाडु ई-गवर्नेंस एजेंसी (TNeGA): राज्य में ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी।

केंद्र सरकार की एक समान पहल:

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (2021) - कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वित्तीय और शैक्षिक सहायता।

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया, जो बिहार में जीविका कार्यक्रम के सदस्यों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने की एक पहल है।

जीविका निधि की मुख्य विशेषताएँ

- यह समुदाय के सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर धन उपलब्ध कराती है।
- जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर-स्तरीय संघ इस संस्था के सदस्य होंगे।
- केंद्र और बिहार सरकार दोनों के योगदान से वित्त पोषित।
- प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ के दौरान संस्था के बैंक खाते में ₹105 करोड़ हस्तांतरित किए।
- वित्त तक आसान पहुँच प्रदान करके ग्रामीण महिला उद्यमियों का समर्थन करने पर केंद्रित।

- इसका उद्देश्य अनौपचारिक उधार पर निर्भरता कम करना और महिलाओं के नेतृत्व वाले आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

महिला सशक्तिकरण पर सरकार का ध्यान

- लखपति दीदी योजना - ग्रामीण महिलाओं को सालाना ₹1 लाख+ कमाने में सक्षम बनाना।
- ड्रोन दीदी योजना - महिलाओं को कृषि के लिए ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण।
- बैंक सखी योजना - ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के वितरण में महिलाओं को शामिल करना।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य

- जीविका परियोजना: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत विश्व बैंक के सहयोग से 2006 में बिहार में शुरू की गई।
- उद्देश्य: स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को बढ़ावा देना और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- कार्यक्षेत्र: जीविका ने बिहार भर में 1.4 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है।
- एनआरएलएम: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत 2011 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना।
- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी): महिलाओं को सूक्ष्म वित्त, आजीविका सहायता और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- बिहार: एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक।

सरकार आदिवासी भाषाओं के लिए भारत के पहले एआई अनुवादक, आदि वाणी का बीटा संस्करण लॉन्च करेगी

भारत सरकार आदिवासी भाषाओं के लिए देश के पहले एआई-संचालित अनुवादक, आदि वाणी का बीटा संस्करण लॉन्च करने के लिए तैयार है। जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस पहल का नेतृत्व किया जा रहा है।

उद्देश्य

- आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों के बीच संवाद की खाई को पाटना।
- भारत की आदिवासी संस्कृति और भाषाई विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना।
- डिजिटल और एआई-आधारित समाधानों के माध्यम से समावेशी आदिवासी सशक्तिकरण सुनिश्चित करना।
- लुप्तप्राय भाषाओं के एआई-संचालित संरक्षण में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना।

मुख्य विशेषताएँ

- विशेष रूप से आदिवासी और स्वदेशी भाषाओं के लिए एआई-संचालित अनुवाद उपकरण।
- भारत के सांस्कृतिक बहुलवाद के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप भाषाई विविधता का समर्थन करता है।
- वास्तविक समय और सटीक अनुवाद के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों के साथ विकसित।

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने महिलाओं के स्वरोज़गार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना को मंजूरी दे दी है।

योजना की विशेषताएँ:

बिहार में प्रत्येक परिवार की एक महिला को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक वित्तीय सहायता के रूप में ₹10,000 मिलेंगे। 6 महीने के मूल्यांकन के बाद, महिला उद्यमियों को ₹2 लाख तक का अतिरिक्त अनुदान मिल सकता है। धनराशि का हस्तांतरण सितंबर 2025 से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में शुरू होगा। ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग के सहयोग से नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन के लिए गाँवों और कस्बों में हाट बाज़ार/स्थानीय बाज़ार विकसित किए जाएंगे। सहायता एक अनुदान है, ऋण नहीं, इसलिए किसी पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

अपेक्षित प्रभाव:

- बिहार में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।
- श्रमिकों के पलायन पर अंकुश।
- स्थानीय बाज़ारों और उद्यमिता को बढ़ावा।

संबंधित मुख्य तथ्य:

बिहार के मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार | राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान।

सिक्किम सरकार घर-घर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'कानूनी सहयोग अभियान' शुरू करेगी

सिक्किम सरकार 'कानूनी सहयोग अभियान' नामक एक राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी, ताकि लोगों को उनके घर-घर कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यह पहल मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) के मार्गदर्शन में शुरू की जाएगी और रेनॉक निर्वाचन क्षेत्र के रोरथांग से शुरू होकर बाद में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विस्तारित की जाएगी। यह अभियान सप्ताह में एक बार चलाया जाएगा, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से घोषित किए जाएंगे।

पहल के उद्देश्य

नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, को निःशुल्क कानूनी परामर्श, शपथ-पत्र सेवाएँ और कानूनी जागरूकता प्रदान करना।

बुनियादी कानूनी अधिकारों और प्रमुख कानूनों के बारे में जागरूकता फैलाना, जैसे:

- POCSO अधिनियम (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण)
- घरेलू हिंसा अधिनियम
- नशा-विरोधी कानून
- महिला एवं बाल संरक्षण अधिनियम
- मानसिक स्वास्थ्य अधिकार (आत्महत्या दर कम करने के उद्देश्य से)

सामाजिक प्रभाव और सशक्तिकरण

- मुख्यमंत्री के "स्वर्णिम, समृद्ध और सक्षम सिक्किम" के दृष्टिकोण के अनुरूप।
- राज्य के नशामुक्ति मिशन और महिला सशक्तिकरण एजेंडे का समर्थन करता है।
- उन समुदायों को लक्षित करता है जो अक्सर कानूनी मंचों से संपर्क करने में झिझकते हैं, इस प्रकार नागरिकों और न्याय के बीच की खाई को पाटता है।
- युवाओं, महिलाओं, किसानों और ग्रामीण समुदायों को कानूनी अधिकारों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाकर और उन्हें अपने अधिकारों का दावा करने का आत्मविश्वास देकर उन्हें सशक्त बनाता है।

व्यापक महत्व

यह अभियान न केवल जागरूकता पर आधारित है, बल्कि व्यावहारिक कानूनी सहायता भी प्रदान करता है। जागरूकता, सशक्तिकरण और न्याय को बढ़ावा देकर मज़बूत और अधिक लचीले ज़मीनी स्तर के समुदायों के निर्माण की उम्मीद है। इसे भारत के पूर्वोत्तर हिमालयी राज्य में समावेशी न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

सिक्किम:

- मुख्यमंत्री: प्रेम सिंह तमांग (गोले) - सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के नेता।
- राज्यपाल: लक्ष्मण प्रसाद आचार्य।
- राजधानी: गंगटोक।
- संविधान में सिक्किम: 1975 (36वाँ संशोधन) में भारत का 22वाँ राज्य बना।
- विशिष्ट विशेषता: भारत का पहला 100% जैविक राज्य (2016)।
- पूर्वोत्तर में न्यायिक पहुँच: पूर्वोत्तर राज्यों को अक्सर न्यायिक बुनियादी ढाँचे की कमी का सामना करना पड़ता है; सिक्किम की पहल ज़मीनी स्तर पर कानूनी सशक्तिकरण का एक आदर्श उदाहरण है।

कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और 2030 तक विस्तार को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹7,332 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के पुनर्गठन और 31 मार्च 2030 तक विस्तार को मंजूरी दे दी है।

ऋण में वृद्धि और नए प्रावधान

- पहली किश्त की ऋण सीमा: ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई है।
- दूसरी किश्त की ऋण सीमा: ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है।
- तीसरी किश्त की ऋण सीमा: ₹50,000 पर जारी रहेगी।
- दूसरा ऋण समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर व्यावसायिक और व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए यूपीआई-लिंकड रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे।
- खुदरा और थोक बाजारों में डिजिटल लेनदेन अपनाने पर ₹1,600 तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

कार्यान्वयन तंत्र

इस योजना का संयुक्त रूप से कार्यान्वयन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा:

- आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA): योजना कार्यान्वयन के लिए प्रमुख मंत्रालय।
- वित्तीय सेवा विभाग (DFS): बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण और क्रेडिट कार्ड तक पहुँच को सुगम बनाना।
- पुनर्गठित योजना डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन, विस्तारित भौगोलिक कवरेज और बढ़ी हुई ऋण राशि प्रदान करेगी।

कौशल निर्माण और सुरक्षा पर ध्यान

यह योजना रेहड़ी-पटरी वालों के लिए उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और विपणन सहायता पर भी ज़ोर देगी। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण FSSAI के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि और उपलब्धियाँ

1 जून, 2020 को शुरू किया गया, COVID-19 महामारी के दौरान प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों की सहायता के लिए। वित्तीय सहायता के अलावा, इस योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के लिए पहचान और औपचारिक मान्यता प्रदान की है।

प्रधानमंत्री स्वनिधि (प्रधानमंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्मनिर्भर निधि)।

- 31 मार्च, 2030 तक विस्तारित।
- वित्तीय परिणाम: ₹7,332 करोड़।
- आरंभ: 1 जून, 2020।
- ऋण सीमा: ₹15,000 (पहला), ₹25,000 (दूसरा), ₹50,000 (तीसरा)।

- नई सुविधाएँ: UPI-लिंकड RuPay क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन (₹1,600)।
- कार्यान्वयन मंत्रालय: MoHUA और DFS।
- खाद्य सुरक्षा के लिए सहयोगी निकाय: FSSAI।
- वितरित ऋण (जुलाई 2025 तक): ₹13,797 करोड़ मूल्य के 9.6 मिलियन ऋण।
- डिजिटल लेनदेन: ₹6.09 ट्रिलियन मूल्य के 5.57 बिलियन लेनदेन।

एनएचएआई ने परियोजना आरोहण शुरू की

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए परियोजना आरोहण शुरू की है। इस पहल की घोषणा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई थी।

परियोजना का उद्देश्य

इस परियोजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करना है। एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव के अनुसार, यह योजना टोल प्लाजा कर्मचारियों के परिवारों की प्रतिभा को निखारने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कक्षा 11 से स्नातक तक के 500 छात्रों को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ₹12,000 की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त, स्नातकोत्तर और उच्च शिक्षा के इच्छुक 50 मेधावी छात्रों को ₹50,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। छात्रों को सत्यापन के लिए शैक्षणिक रिकॉर्ड, आय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जैसे प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने होंगे।

एनएचएआई

- स्थापना: 1995 (एनएचएआई अधिनियम, 1988 के अंतर्गत)
- मुख्य मंत्रालय: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- वर्तमान अध्यक्ष: संतोष कुमार यादव
- प्रमुख पहल: इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए फास्टैग का प्रबंधन

"जीवन में ऊँचे उठते समय लोगो से अच्छा व्यवहार करें !
क्योंकि यदि आप फिर निचे आये तो सामना इन्हीं
लोगो से करना होगा !!"

"जब तक किसी काम को किया नहीं जाता !
तब तक वह असंभव ही लगता है !!"

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

कृषि-खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारती पहल

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने भारत के कृषि-खाद्य निर्यात को मजबूत करने के लिए एक नई पहल, भारती (भारत का कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र) शुरू की है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में हुआ, जिसमें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी भी शामिल हुए।

भारती की मुख्य विशेषताएँ

- 100 कृषि-खाद्य स्टार्टअप को समर्थन।
- 2030 तक 50 अरब डॉलर के कृषि-खाद्य निर्यात का लक्ष्य।
- खाद्य क्षेत्र में नवाचार, लचीलापन और इनक्यूबेशन को बढ़ावा।
- आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया मिशनों के साथ संरेखित।
- भारत की वैश्विक कृषि-खाद्य व्यापार उपस्थिति को मजबूत करता है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य

एपीडा की स्थापना 1985 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कृषि-खाद्य निर्यात लगभग 53 अरब डॉलर (चावल, गेहूँ, समुद्री उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य सहित) रहा।

- प्रमुख निर्यात गंतव्य: अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ के देश और आसियान देश।
- भारत बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है और मसालों, भैंस के मांस और समुद्री उत्पादों के शीर्ष निर्यातकों में से एक है।
- यह पहल भारत-यूई व्यापार संबंधों को भी मजबूत करती है, क्योंकि यूई भारतीय कृषि-खाद्य उत्पादों के शीर्ष आयातकों में से एक है।

प्रधानमंत्री मोदी ने असम में भारत के पहले बांस-आधारित बायो-एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गोलाघाट जिले में भारत के पहले बांस-आधारित बायो-एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। उद्देश्य: यह पहल विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम करके और सतत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) प्राप्त करने के भारत के मिशन का हिस्सा है।

ऊर्जा लक्ष्य:

भारत का लक्ष्य गहरे पानी के ऊर्जा संसाधनों का दोहन करना और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत शीर्ष पाँच देशों में शामिल है।

बाँस-आधारित जैव-इथेनॉल:

बाँस एक तेज़ी से बढ़ने वाला, नवीकरणीय पौधा है जिसे जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है, जो जीवाश्म ईंधन का एक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। उत्सर्जन कम करने और ऊर्जा स्थिरता बढ़ाने के लिए जैव-इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

ऊर्जा सुरक्षा:

जैव ईंधन, सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों में भारत के प्रयास, जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ-साथ बढ़ती ऊर्जा माँगों को पूरा करने की उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

ब्रह्मपुत्र नदी परियोजनाएँ:

नए पुल और रिंग रोड का उद्देश्य परिवहन अवसंरचना को बढ़ाना, क्षेत्रीय संपर्क में सुधार करना और असम में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

लघु लेख

भारत में फसल अवशेषों में आग लगाने की समस्या से निपटना

वायु प्रदूषण पर न्यायालय का हस्तक्षेप

दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में तीन महीने के भीतर रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है। साथ ही, न्यायालय ने केंद्र सरकार से धुएँ और प्रदूषण को कम करने के लिए पराली जलाने पर जुर्माना लगाने का भी आग्रह किया है।

फसल अवशेष जलाने को समझना

फसल अवशेष जलाने का अर्थ है धान और गेहूँ जैसी फसलों की कटाई के बाद बचे हुए भूसे में आग लगाना। किसान मुख्य रूप से अगले बुवाई के मौसम से पहले खेतों को जल्दी से साफ करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। यह प्रथा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सितंबर के अंत से नवंबर की शुरुआत तक व्यापक रूप से प्रचलित है।

किसानों को पराली जलाने के लिए प्रेरित करने वाले कारक

- एकल कृषि: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीतियाँ गेहूँ और चावल के पक्ष में हैं, जो एकल-फसल पैटर्न को बढ़ावा देती हैं।
- लागत लाभ: श्रेडर या मिट्टी में मिलावट जैसे मशीनरी-आधारित विकल्पों की तुलना में सस्ता।
- खरपतवार और कीट नियंत्रण: आग खरपतवार और बीजों को नष्ट करती है, जिससे रसायनों पर निर्भरता कम होती है।

- विकल्पों का अभाव: खाद बनाने या जैव ऊर्जा के उपयोग के बारे में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा या जानकारी।
- जलवायु दबाव: अनियमित मानसून और गर्मी के कारण कटाई में देरी के कारण खेतों की कटाई जल्दी करनी पड़ती है।

फसल की आग के परिणाम

- वायु गुणवत्ता में गिरावट: PM10, PM2.5, NO_x, CO, CH₄ और VOCs उत्सर्जित होते हैं, जिससे धुंध पैदा होती है और श्वसन संबंधी बीमारियाँ बढ़ती हैं।
- ग्लोबल वार्मिंग में योगदान: ग्रीनहाउस गैसों का महत्वपूर्ण उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन को तेज़ करता है।
- मृदा क्षरण: आवश्यक पोषक तत्वों को जलाता है, सूक्ष्मजीवों को मारता है और मृदा की नमी को कम करता है।

अवशेष आग से निपटने में बाधाएँ

- प्रौद्योगिकी और उपकरणों की कमी: मानक हार्वेस्टर 10-15 सेमी पराली छोड़ देते हैं; सीएचसी में अक्सर मशीनरी की कमी होती है। पराली में उच्च सिलिका उपकरणों को नुकसान पहुँचा सकता है, और संग्रहण प्रणालियाँ अक्षम होती हैं।
- नीतिगत जटिलताएँ: अस्पष्ट नियम, भ्रामक अनुपालन चिह्न और दंड-केंद्रित नियम पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को हतोत्साहित करते हैं।
- वित्तीय बाधाएँ: कम सब्सिडी और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए सीमित धनराशि आधुनिक तकनीक को अपनाने में बाधा डालती है।
- जागरूकता का अभाव: कई किसान वैकल्पिक उपायों पर अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण पारंपरिक तरीके से पराली जलाना जारी रखते हैं।

भारत द्वारा उठाए गए कदम सीएक्यूएम की कार्य योजना:

- खेत प्रबंधन: मशीनरी का उपयोग, क्रमिक कटाई, तेजी से बढ़ने वाला धान और जैव-अपघटक।
- खेत से बाहर उपयोग: बायोमास ऊर्जा, 2जी इथेनॉल, बायोगैस और पैकेजिंग सामग्री में रूपांतरण।
- वित्तीय सहायता: कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के माध्यम से, छोटे और सीमांत किसानों को मशीनरी के लिए सहायता मिलती है।

तकनीकी समाधान:

- हैप्पी सीडर: पराली जलाए बिना गेहूँ बोता है।
- पूसा डीकंपोजर: पराली को खाद में बदलता है।
- पेलेट और बायोचार: ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं और उर्वरता में सुधार करते हैं।

स्थानीय नवाचार:

- छत्तीसगढ़: गौठान पराली को जैविक खाद में परिवर्तित करते हैं, जिससे ग्रामीण रोजगार सृजित होते हैं।
- पंजाब: आई-खेत और सहकारी मशीनरी ट्रेकर जैसे ऐप्स अवशेष प्रबंधन उपकरणों तक पहुँचने में मदद करते हैं।

भविष्य में नियंत्रण के लिए प्रस्तावित उपाय

- कानूनी और नीतिगत बदलाव: धान के अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करें।
- बुनियादी ढाँचे का विकास: वास्तविक समय में फसल मानचित्रण, अस्थायी भंडारण और बेहतर आपूर्ति श्रृंखलाएँ।
- स्मार्ट खेती को अपनाना: खाद बनाने के लिए माइक्रोब पूसा, सीधी बुवाई के लिए हैप्पी सीडर, कम अवधि वाली धान की किस्मों और अवशेषों के पुनर्चक्रण का उपयोग करें।
- आर्थिक प्रोत्साहन: पराली की कीमतों की गारंटी, श्रम सहायता, सब्सिडी और पर्यावरण के अनुकूल किसानों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम।

पंजाब में बाढ़ क्यों आती रहती है — 2025 की बाढ़ को जाने विस्तार से

पंजाब का भूगोल: नदियों और जोखिमों का प्रदेश

पंजाब को "पाँच नदियों की भूमि" कहा जाता है। ये नदियाँ—सतलुज, व्यास, रावी और घग्गर जैसी छोटी नदियाँ—इस राज्य को भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक बनाती हैं। ये नदियाँ इसकी कृषि अर्थव्यवस्था को सहारा देती हैं और पंजाब को "भारत का अन्न भंडार" का खिताब देती हैं।

लेकिन इस वरदान में एक जोखिम भी छिपा है। जब मानसून बहुत भारी बारिश लाता है, खासकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, तो नदियाँ जल्दी भर जाती हैं। जब ये अपने सुरक्षित स्तर को पार कर जाती हैं, तो बाढ़ आ जाती है। गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर और पठानकोट जैसे जिले अक्सर सबसे पहले नुकसान का सामना करते हैं।

भारी बारिश और उफान पर नदियाँ

- 2025 में, मानसून की बारिश सामान्य से कहीं ज़्यादा रही। बारिश सामान्य औसत से लगभग आधी ज़्यादा रही। इस अचानक हुई अधिक बारिश ने नदियों को उनकी सीमा से बाहर तक भर दिया।
- रावी नदी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। एक समय तो, इसमें से बहने वाला पानी इसकी सुरक्षित क्षमता से लगभग दोगुना था। सतलुज और व्यास नदियाँ भी भारी मात्रा में पानी लाती थीं, हालाँकि इनसे रावी जितनी तबाही नहीं हुई। जैसे-जैसे नदियाँ उफान पर आईं, आस-पास के गाँव, खेत और कस्बे तेज़ी से जलमग्न हो गए।

मानवीय भूलों ने इसे और बदतर बना दिया

- सिर्फ प्राकृतिक बारिश से ही सारा नुकसान नहीं हुआ। मानवीय गतिविधियों ने इस आपदा में और घी डालने का काम किया।
- वर्षों से, लोगों ने प्राकृतिक बाढ़ के मैदानों और जल निकासी क्षेत्रों पर घर, सड़कें और बाज़ार बनाए हैं। इससे पानी का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो गया।
- बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए नदी तटबंध, खराब रखरखाव के कारण कमज़ोर हो गए थे।

- नदी के किनारों पर अवैध खनन ने मिट्टी और सुरक्षात्मक तटबंधों को और कमज़ोर कर दिया।
- समतल क्षेत्रों में तेज़ी से हो रहे निर्माण ने अतिरिक्त वर्षा जल के निकास के लिए बहुत कम जगह छोड़ी।
- इन सभी समस्याओं ने मिलकर बाढ़ को और भी विनाशकारी बना दिया।

मानसून के दौरान बाँध कैसे काम करते हैं

पंजाब और उसके आसपास के प्रमुख बाँध—भाखड़ा बाँध (सतलज), पौग बाँध (ब्यास), और रंजीत सागर/थीन बाँध (रावी)—मानसून के दौरान पानी का भंडारण करते हैं।

ये बाँध एक "नियम वक्र" का पालन करते हैं, जो यह तय करता है कि वर्ष के अलग-अलग समय में कितना पानी संग्रहित किया जाना चाहिए और कितना छोड़ा जाना चाहिए।

आदर्श रूप से, इन्हें भारी बारिश के दौरान अचानक आने वाले पानी को सोखने के लिए कुछ बफर स्पेस बनाए रखना चाहिए।

बाँधों के बावजूद बाढ़ क्यों आती है

- भारी मानसून के दौरान, बाँध जल्दी ही अपने अधिकतम स्तर तक भर जाते हैं।
- यदि जलाशय अपने "खतरे के स्तर" को पार कर जाते हैं, तो बाँध की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। बाँध के टूटने से बचने के लिए, अधिकारियों को नीचे की ओर बड़ी मात्रा में पानी छोड़ना पड़ता है।
- जब ये पानी अचानक छोड़ा जाता है, और नदियाँ पहले से ही बारिश से उफान पर होती हैं, तो इससे नीचे के इलाकों में अचानक बाढ़ आ जाती है।

पंजाब की विशेष समस्या

- पंजाब तीनों बड़े बाँधों के नीचे स्थित है, इसलिए जब भी अतिरिक्त पानी छोड़ा जाता है, तो उसके जिले—खासकर गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, होशियारपुर, फिरोजपुर—सबसे पहले प्रभावित होते हैं।
- किसान और ग्रामीण अक्सर शिकायत करते हैं कि बाँधों से पानी छोड़ने में समन्वय या संचार ठीक से नहीं होता, जिससे उन्हें तैयारी के लिए बहुत कम समय मिलता है।
- पंजाब के राजनीतिक नेताओं ने यह भी तर्क दिया है कि हरियाणा और राजस्थान के साथ जल-बँटवारे के विवाद कभी-कभी पंजाब को जलाशयों में आवश्यकता से अधिक पानी रखने के लिए मजबूर करते हैं। जब बारिश तेज़ हो जाती है, तो अचानक आपातकालीन पानी छोड़ने से बाढ़ और भी बदतर हो जाती है।

आपदा का पैमाना

- 2025 की बाढ़, 1988 के बाद से पंजाब में आई सबसे भीषण बाढ़ों में से एक थी। सभी जिलों के 1,900 से ज़्यादा गाँव प्रभावित हुए। लगभग चार लाख लोग विस्थापित हुए और लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो गई।
- जान-माल का नुकसान बहुत दर्दनाक था, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। खड़ी फसलें नष्ट हो जाने

और खेतों में पानी भर जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। पशुधन और स्थानीय बुनियादी ढाँचे को भी नुकसान हुआ।

मानवीय क्षति

- कई ग्रामीणों के लिए, बाढ़ ने सब कुछ नष्ट कर दिया—घर, फसलें और बचत। बुवाई के मौसम की तैयारी कर रहे किसानों के खेत बर्बाद हो गए। स्कूल और अस्पताल प्रभावित हुए और कई क्षेत्रों में परिवहन ठप हो गया।
- इस आपदा ने खाद्य आपूर्ति को लेकर भी चिंताएँ पैदा कर दीं, क्योंकि पंजाब भारत के खाद्यान्न भंडार का एक बड़ा हिस्सा है।

गुस्सा और माँगें

- बाढ़ ने जनता के गुस्से को भी तीव्र रूप से भड़काया। ग्रामीणों ने नहरों और तटबंधों का विरोध किया, खासकर हांसी-बुटाना नहर के खिलाफ, क्योंकि उनका मानना था कि इससे बाढ़ और भी बदतर हो गई है। लोगों ने अस्थायी राहत के बजाय मज़बूत बाढ़ नियंत्रण प्रणालियों, बेहतर तटबंधों और दीर्घकालिक योजना की माँग की।
- राजनीतिक स्तर पर, पुनर्निर्माण के लिए बड़ी वित्तीय सहायता की माँग की गई। कई लोगों ने इस राहत की आलोचना करते हुए कहा कि यह बड़े पैमाने पर हुए विनाश की तुलना में बहुत कम है।

क्या किया जाना चाहिए

विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई और दीर्घकालिक योजना दोनों की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख कदमों में शामिल हैं:

- तटबंधों को मज़बूत और ऊँचा करना, खासकर संवेदनशील नदियों के किनारे।
- नदियों और नहरों की नियमित रूप से गाद निकालना ताकि उनकी जल वहन क्षमता बढ़े।
- बांधों से छोड़े जाने वाले पानी का बेहतर प्रबंधन, और निचले इलाकों के लोगों को पहले से चेतावनी देना।
- प्राकृतिक आर्द्रभूमि और जंगलों की रक्षा करना जो अतिरिक्त पानी सोख सकते हैं।
- बाढ़ के मैदानों पर निर्माण से बचना और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सख्त भवन निर्माण नियमों को लागू करना।

निष्कर्ष

पंजाब में 2025 की बाढ़ ने दिखाया कि कैसे प्राकृतिक शक्तियाँ और मानवीय त्रुटियाँ मिलकर भारी तबाही मचा सकती हैं। हालाँकि भारी बारिश इसकी वजह थी, लेकिन कमज़ोर बुनियादी ढाँचे, खराब योजना और प्राकृतिक प्रणालियों की उपेक्षा ने स्थिति को और बदतर बना दिया। अगर पंजाब और पूरा भारत ऐसी त्रासदियों को दोहराना नहीं चाहता, तो उसे मज़बूत बाढ़ सुरक्षा, बेहतर योजना और पर्यावरण के प्रति सम्मान में निवेश करना होगा। तभी राज्य अपनी नदियों को बार-बार आने वाली आपदा के बजाय एक वरदान में बदल सकता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत ने रेल-आधारित प्रक्षेपक से अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया

भारत ने रेल-आधारित मोबाइल प्रक्षेपक से उन्नत मध्यम-दूरी बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अभ्यास को "अपनी तरह का पहला" बताया, जिसमें सामरिक रक्षा क्षमताओं में भारत के स्वदेशी नवाचार का प्रदर्शन किया गया।

मुख्य विशेषताएँ:

- मिसाइल प्रकार: अग्नि-प्राइम, एक मध्यम-दूरी बैलिस्टिक मिसाइल।
- मारक क्षमता: 2,000 किलोमीटर तक।
- प्रक्षेपण मंच: रेल-आधारित मोबाइल प्रक्षेपक, गतिशीलता और रणनीतिक लचीलेपन को बढ़ाता है।
- संचालनकर्ता: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), सामरिक बल कमान (SFC) और सशस्त्र बलों के समन्वय में।
- महत्व: भारत दुनिया भर के उन गिने-चुने देशों में से एक बन गया है जिन्होंने चलते-फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्ट्राइज्ड प्रक्षेपण प्रणाली विकसित की है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- अग्नि मिसाइल श्रृंखला: अग्नि श्रृंखला भारत के परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार का हिस्सा है, जिसमें छोटी, मध्यम और अंतरमहाद्वीपीय दूरी की मिसाइलें शामिल हैं।
- कैनिस्ट्राइज्ड सिस्टम का लाभ: यह मिसाइल को अधिक कुशलता से संग्रहीत, परिवहन और प्रक्षेपित करने की अनुमति देता है, जिससे परिचालन तत्परता बढ़ती है।
- रणनीतिक महत्व: यह भारत की द्वितीय-आक्रमण क्षमता और समग्र परमाणु निवारक स्थिति को बढ़ाता है।

अग्रिकुल कॉसमॉस ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा शुरू की

चेन्नई स्थित स्पेसटेक स्टार्टअप अग्रिकुल कॉसमॉस ने भारत की पहली समर्पित रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा शुरू की है। यह अत्याधुनिक एडिटिव मैनुफैक्चरिंग इकाई एयरोस्पेस 3D प्रिंटिंग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करती है - डिज़ाइन और सिमुलेशन से लेकर प्रिंटिंग, पोस्ट-प्रोसेसिंग और फ़िनिशिंग तक, एक ही छत के नीचे।

महत्व

- इसका उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष निर्माण क्षमताओं को गति देना है।
- उत्पादन लागत में 50% तक की कमी आने की उम्मीद है।

- यह एयरोस्पेस और रॉकेट के पुर्जों को 1 मीटर ऊँचाई तक 3D प्रिंट कर सकता है, जिससे एडिटिव तकनीक के माध्यम से पहले असंभव जटिल पुर्जों का निर्माण संभव हो सकेगा।
- जिन पुर्जों के लिए पहले हफ़्तों/महीनों का समय लगता था, अब उन्हें उड़ान के लिए तैयार कुछ ही दिनों में तैयार किया जा सकता है, जिससे विकास चक्र में काफी कमी आती है।

तकनीकी प्रगति

- स्वदेशी डी-पाउडरिंग मशीन: दोषरहित सतह फ़िनिश और अंतरिक्ष-स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।
- एकल-टुकड़ा 3D-मुद्रित रॉकेट इंजन: अग्रिकुल के पास इस नवाचार के लिए पहले से ही अमेरिकी पेटेंट है।
- नई सुविधा 1 मीटर ऊँचे इंजनों के उत्पादन को सक्षम बनाती है जो पहले के डिज़ाइनों की तुलना में 7 गुना अधिक थ्रस्ट प्रदान करते हैं।
- इंजनों का निर्माण अब कुछ ही दिनों में पूरी तरह से घरेलू स्तर पर किया जा सकता है, जिससे प्रक्षेपण की तैयारी में तेज़ी आती है।

कंपनी प्रोफ़ाइल और भविष्य की संभावनाएँ

- स्थापना: 2017 में श्रीनाथ रविचंद्रन (सीईओ) और मोइन एसपीएम (सीटीओ) द्वारा।
- उल्लेखनीय प्रक्षेपण यान: अग्निबाण - 3D-मुद्रित इंजनों द्वारा संचालित एक मॉड्यूलर छोटा-उठाने वाला रॉकेट।
- यह सुविधा लागत-प्रभावी और विश्वसनीय अंतरिक्ष पहुँच में वैश्विक अग्रणी बनने की भारत की कोशिशों को मज़बूत करती है।
- नीतिगत संदर्भ: भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों (2020) से बढ़ावा मिला, जिसने निजी कंपनियों को IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) के तहत अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी।
- वैश्विक संदर्भ: स्पेसएक्स (यूएसए) और रिलेटिविटी स्पेस (यूएसए) जैसी कंपनियों द्वारा एयरोस्पेस में एडिटिव मैनुफैक्चरिंग (3डी प्रिंटिंग) को तेज़ी से अपनाया जा रहा है।

सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण हेतु बैटरी अपशिष्ट के पुनर्चक्रण हेतु ₹1,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत लिथियम, कोबाल्ट, निकल, नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और समैरियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण हेतु बैटरी और ई-कचरे के पुनर्चक्रण हेतु ₹1,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 31 तक छह वर्षों तक चलेगी।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

उद्देश्य: आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता का निर्माण करना, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्थिरता को बढ़ावा देना।

कार्यान्वयन:

प्रोत्साहनों में संयंत्र और मशीनरी पर 20% पूंजीगत सब्सिडी शामिल है। परिचालन सब्सिडी वृद्धिशील बिक्री से जुड़ी है (दूसरे वर्ष में 40%, पाँचवें वर्ष में 60%)।

सब्सिडी सीमा:

- बड़ी फर्मों के लिए ₹50 करोड़।
- छोटी फर्मों और स्टार्ट-अप के लिए ₹25 करोड़ (उनके लिए एक-तिहाई परिव्यय आरक्षित)।
- लक्षित क्षमता: 270 किलो टन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता जोड़ना → प्रति वर्ष लगभग 40 किलो टन महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन करना।
- अपेक्षित परिणाम: ₹8,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और लगभग 70,000 रोजगार (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष) सृजित करना।

सामरिक महत्व

चीन वर्तमान में वैश्विक दुर्लभ मृदा उत्पादन के 60% से अधिक और शोधन के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है।

चीन द्वारा दुर्लभ मृदा चुंबक की आपूर्ति में हाल ही में व्यवधान ने अति-निर्भरता के जोखिमों को उजागर किया है। लंबी अवधि की खनन परियोजनाओं की तुलना में पुनर्चक्रण को एक तेज़ और लागत-कुशल मार्ग माना जाता है।

दक्षिण कोरिया-अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाई सुंग-लाक ने पुष्टि की है कि उत्तर कोरिया की स्थिति चाहे जो भी हो, परमाणु निरस्त्रीकरण अंतिम और अपरिवर्तित लक्ष्य बना रहेगा।

दक्षिण कोरिया की त्रि-चरणीय योजना

- उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों पर तत्काल रोक।
- सुरक्षा और निवारक क्षमता से समझौता किए बिना तनाव कम करने के उपाय।
- दीर्घकालिक शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्वास-निर्माण के प्रयास।

APEC शिखर सम्मेलन संदर्भ

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित किया जाएगा। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के इसमें शामिल होने की उम्मीद नहीं है। शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दक्षिण कोरिया आने की उम्मीद है।

व्यापक संदर्भ

उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम के कारण कोरियाई प्रायद्वीप एक प्रमुख सुरक्षा केंद्र बना हुआ है।

क्षेत्रीय स्थिरता में अमेरिका और दक्षिण कोरिया का गठबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता एक दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा रहा है जिसमें छह-पक्षीय वार्ता ढाँचे (2003-2009) के तहत चीन, जापान, रूस और अमेरिका शामिल हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

- उत्तर कोरिया का पहला परमाणु परीक्षण: 2006 में किया गया।
- परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी): उत्तर कोरिया ने 2003 में वापसी कर ली।
- दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति: लगभग 28,500 सैनिक।
- APEC: 1989 में स्थापित, इसमें अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएँ हैं।

ईरान और IAEA परमाणु निरीक्षण फिर से शुरू करने पर सहमत

ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने ईरान की संप्रभुता का सम्मान करते हुए और उसके लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए परमाणु निरीक्षण पर सहयोग फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान अपनी परमाणु नीति या अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। यह घोषणा मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती और IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। मिस्र यूरोपीय देशों और ईरान के बीच मध्यस्थता करने के लिए काम कर रहा है ताकि उन्हें करीब लाया जा सके और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। जून में ईरानी परमाणु स्थलों पर इज़राइली-अमेरिकी हमलों और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के बाद सहयोग रोक दिया गया था। ईरान ने अपने सहयोग को निलंबित कर दिया था, यह मांग करते हुए कि सभी निरीक्षणों को उसकी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाए, और परमाणु सुविधाओं और कर्मियों की सुरक्षा की गारंटी पर ज़ोर दिया।

सहायक तथ्य:

- IAEA संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार है।
- परमाणु हथियारों के विकास की आशंकाओं के कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक चिंता का विषय रहा है, जिसके कारण उस पर प्रतिबंध और कूटनीतिक वार्ताएँ हुई हैं।
- 2015 में हस्ताक्षरित संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA), प्रतिबंधों में राहत के बदले ईरान की परमाणु गतिविधियों को सीमित करने के उद्देश्य से किया गया एक पूर्व समझौता था।

- इज़राइली हवाई हमलों और लक्षित हत्याओं सहित हाल की वृद्धि ने तनाव को और बढ़ा दिया है और मध्य पूर्व में परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- मध्यस्थ के रूप में मिस्र की भूमिका क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा संघर्षों को रोकने और परमाणु मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देने के प्रयासों को दर्शाती है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए परमाणु निरीक्षण महत्वपूर्ण है कि परमाणु सामग्री का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए न किया जाए और सुविधाएँ सुरक्षित रूप से संचालित हों।
- वैश्विक परमाणु अप्रसार प्रयासों को बनाए रखने के लिए IAEA जैसी अंतराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ ईरान का सहयोग महत्वपूर्ण है।

ईरान:

- राजधानी: तेहरान
- राष्ट्रपति: मसूद पेज़ेशकियन
- मुद्रा: ईरानी रियाल

आईईईए:

- स्थापना: 29 जुलाई 1957
- मुख्यालय: वियना, ऑस्ट्रिया
- प्रमुख: राफेल ग्रॉसी

इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उद्देश्य: इस समझौते का उद्देश्य SSLV प्रौद्योगिकी का व्यावसायिक प्रचार करना, अंतरिक्ष अभियानों में उद्योग की भागीदारी को सक्षम बनाना और वैश्विक मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादन का विस्तार करना है।

SSLV के बारे में:

SSLV को इसरो द्वारा एक त्वरित, ऑन-डिमांड प्रक्षेपण यान के रूप में विकसित किया गया है। यह कम लागत और तेज़ तैनाती के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए उपयुक्त है। इसे उद्योगों द्वारा कुशलतापूर्वक निर्मित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रक्षेपण स्थल:

झुकी हुई कक्षाओं के लिए SSLV को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसे ध्रुवीय कक्षाओं के लिए कुलशेखरपट्टिनम के आगामी स्थल से भी प्रक्षेपित किया जाएगा।

महत्व:

यह समझौता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देता है, भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

घरेलू और अंतराष्ट्रीय लघु उपग्रह प्रक्षेपण सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है।

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):

- स्थापना: 2019
- उद्देश्य: इसरो की वाणिज्यिक शाखा
- कार्य: प्रक्षेपण सेवाएँ, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उपग्रह पट्टे पर देना
- अध्यक्ष: राधाकृष्णन डी (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO):

- स्थापना: 1969
- मुख्यालय: बेंगलुरु
- कार्य: अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह प्रक्षेपण, मिशन (चंद्रयान, मंगलयान)
- अध्यक्ष: एस. सोमनाथ (अध्यक्ष)

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और मर्क ने भारत में सेमीकंडक्टर सामग्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हाथ मिलाया

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) और जर्मन प्रौद्योगिकी दिग्गज मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर सामग्री, निर्माण अवसंरचना और विशिष्ट रसायन/गैस वितरण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

मर्क की भूमिका:

- उच्च शुद्धता वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों की आपूर्ति।
- उन्नत गैस और रासायनिक वितरण प्रणालियाँ।
- टर्नकी फैब अवसंरचना सेवाएँ।
- एआई-संचालित "मटेरियल इंटेलिजेंस" समाधान।
- एथिनिया (सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए सुरक्षित डेटा विश्लेषण प्लेटफ़ॉर्म) तक पहुँच।

गुजरात के धोलेरा में टाटा का फैब:

- भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई (फैब)।
- निवेश: ₹91,000 करोड़ (~\$11 बिलियन)।
- अनुप्रयोग: ऑटोमोटिव, मोबाइल उपकरण, एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियाँ।

पारिस्थितिकी तंत्र विकास योजनाएँ:

- स्थानीयकृत भंडारण और कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला।
- कुशल सेमीकंडक्टर प्रतिभाओं का संवर्धन।
- भारत में वैश्विक सुरक्षा एवं विनिर्माण मानकों की स्थापना।

अतिरिक्त जानकारी:

- भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM): दिसंबर 2021 में MeitY के तहत लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- धोलेरा में फैब: भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र; चिप आयात पर निर्भरता कम करने की सरकार की योजना का एक हिस्सा।

- वैश्विक महत्व: भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स: जर्मनी में मुख्यालय, सेमीकंडक्टर सामग्री, सब-फैब सेवाओं और रासायनिक प्रक्रिया अनुकूलन में वैश्विक अग्रणी।
- टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स: सरकार के "मेक इन इंडिया" विजन के अनुरूप, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी के रूप में उभर रही है।

ल्यूपिन को जेनेरिक कैंसर दवा लेनालिडोमाइड के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी मिली

भारतीय दवा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से कई शक्तियों (2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम) में लेनालिडोमाइड कैप्सूल के संक्षिप्त नए दवा आवेदन (एएनडीए) के लिए मंजूरी मिल गई है।

दवा विवरण:

लेनालिडोमाइड, ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब द्वारा निर्मित रेवलिमिड कैप्सूल का जेनेरिक संस्करण है। यह मल्टीपल मायलोमा, एक प्रकार के रक्त कैंसर के उपचार के लिए संकेतित है।

- विनिर्माण इकाई: इस उत्पाद का निर्माण ल्यूपिन के पीथमपुर संयंत्र (मध्य प्रदेश, भारत) में किया जाएगा।
- बाजार का आकार: जुलाई 2025 तक अनुमानित वार्षिक अमेरिकी बिक्री \$7,511 मिलियन (USD) (IQVIA MAT डेटा)।

नियामक अद्यतन - नागपुर संयंत्र:

ल्यूपिन की नागपुर इंजेक्टेबल सुविधा अमेरिकी FDA निरीक्षण (8-16 सितंबर, 2025) के अंतर्गत आ गई है। निरीक्षण के परिणामस्वरूप छह टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। ल्यूपिन ने आश्वासन दिया है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर USFDA को जवाब देगा।

उल्लेखनीय बिंदु:

- USFDA: अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन - अमेरिका में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और खाद्य सुरक्षा को नियंत्रित करता है।
- ANDA (संक्षिप्त नई दवा आवेदन): ब्रांडेड संस्करणों के लिए जैव-समतुल्यता साबित करने वाली जेनेरिक दवाओं के अनुमोदन का मार्ग।
- ल्यूपिन लिमिटेड: मुंबई, भारत में मुख्यालय, जेनेरिक और फार्मूलेशन में विशेषज्ञता वाली शीर्ष दवा कंपनियों में से एक।
- ल्यूपिन संस्थापक: देश बंधु गुप्ता
- ल्यूपिन सीईओ: विनीता डी. गुप्ता
- ल्यूपिन एमडी: नीलेश गुप्ता

प्राइमा एयरोस्पेस को कृषि में अर्जुन ड्रोन के लिए डीजीसीए की मंजूरी मिली

शहर स्थित ड्रोन निर्माता, प्राइमा एयरोस्पेस को अपने अर्जुन ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जिससे इसे कृषि संबंधी गतिविधियों जैसे सटीक छिड़काव, फसल निगरानी और मृदा-जल प्रबंधन में तैनात करने की अनुमति मिल गई है। यह प्रमाणन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्राइमा समूह की संस्थापक और सीईओ धनश्री मंधानी को प्रदान किया।

प्राइम समूह की पहल

हाल ही में, डीजीसीए ने समूह के ड्रोन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन (आरपीटीओ) के रूप में मंजूरी दी है। इससे प्राइमा समूह भारत का पहला संपूर्ण मार्ग बन गया है:

- ड्रोन निर्माण,
- पायलट प्रशिक्षण, और
- बड़े पैमाने पर तैनाती (सलाम किसान के राष्ट्रव्यापी मंच के माध्यम से)।

इससे पहले 2025 में, PRYM समूह ने ड्रोन अपनाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व आर्थिक मंच (WEF), दावोस में महाराष्ट्र सरकार के साथ ₹300 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

भारत में ड्रोन नीति:

ड्रोन नियम, 2021 ने लाइसेंसिंग और अनुमतियों को सरल बनाया।

ड्रोन के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 2021 में ₹120 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई। ऑनलाइन अनुमोदन और उड़ान अनुमति के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म विकसित किया गया।

भारत में ड्रोन के अनुप्रयोग:

- कृषि (सटीक खेती, कीटनाशक छिड़काव)।
- आपदा प्रबंधन।
- बुनियादी ढाँचा सर्वेक्षण।
- ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स।
- रक्षा और निगरानी।

लघु लेख

भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026: वैश्विक एआई नेतृत्व के लिए एक मील का पत्थर

भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026, 19-20 फरवरी, 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि यह पहली बार है जब कोई वैश्विक दक्षिण देश इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को नैतिक, समावेशी और सतत एआई विकास में अग्रणी बनाना है।

मार्गदर्शक सिद्धांत: लोग, ग्रह और प्रगति

यह शिखर सम्मेलन तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है:

- लोग: यह सुनिश्चित करना कि एआई मानवता की समावेशी सेवा करे, सांस्कृतिक विविधता और सुगम्यता का सम्मान करे।
- ग्रह: ऐसे एआई को बढ़ावा देना जो संसाधन-कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और सततता लक्ष्यों के अनुरूप हो।
- प्रगति: प्रमुख क्षेत्रों में डेटा, कंप्यूटिंग संसाधनों और अनुप्रयोगों तक खुली पहुँच के साथ, एआई लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना।

सात चक्र: शिखर सम्मेलन के विषयगत स्तंभ

इन सिद्धांतों को कार्यान्वयन योग्य परिणामों में बदलने के लिए, शिखर सम्मेलन सात विषयगत चक्रों पर केंद्रित होगा, जिनमें से प्रत्येक एआई विकास और अनुप्रयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है:

- मानव पूंजी: एआई प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रबंधन में सक्षम कुशल कार्यबल को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ हों।
- समावेशन: यह सुनिश्चित करना कि एआई प्रणालियाँ समावेशी होने के लिए डिज़ाइन और कार्यान्वित की जाएँ, विविध आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करें और सामाजिक समानता को बढ़ावा दें।
- सुरक्षित और विश्वसनीय एआई: ऐसी एआई प्रणालियाँ विकसित करना जो सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह हों, जनता का विश्वास बनाएँ और एआई अनुप्रयोगों में सुरक्षा सुनिश्चित करें।
- लचीलापन: चुनौतियों और व्यवधानों के अनुकूल होने के लिए एआई प्रणालियों की क्षमता को बढ़ाना, विभिन्न संदर्भों में उनकी मजबूती और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना।
- विज्ञान: एआई में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, ज्ञान और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाली नई पद्धतियों और अनुप्रयोगों के विकास को प्रोत्साहित करना।
- एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण: डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए डेटा, कंप्यूटिंग अवसंरचना और विशेषज्ञता सहित एआई संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
- सामाजिक भलाई के लिए एआई: सभी के लाभ के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एआई का लाभ उठाना।

शिखर सम्मेलन की प्रमुख पहल

शिखर सम्मेलन में एआई नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों को शामिल किया जाएगा:

- एआई पिच फेस्ट (उड़ान): टियर 2 और टियर 3 शहरों के एआई स्टार्टअप्स को प्रदर्शित करना, उन्हें वैश्विक दर्शकों के सामने अपने नवाचार प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
- वैश्विक नवाचार चुनौतियाँ: सार्वजनिक मुद्दों के लिए एआई समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करना, सरकारों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- एआई एक्सपो: विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम एआई तकनीकों, अनुप्रयोगों और नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली एक व्यापक प्रदर्शनी।
- युवाएआई नवाचार चुनौती: युवाओं को एआई नवाचार में शामिल करना, उन्हें सामाजिक चुनौतियों के समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- HER द्वारा AI: AI में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में लैंगिक विविधता को प्रोत्साहित करना।
- शोध संगोष्ठी: शोधकर्ताओं के लिए अपना कार्य प्रस्तुत करने और AI अनुसंधान के भविष्य पर चर्चा करने का एक मंच।

स्वदेशी AI पहल

स्वदेशी AI विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, MeitY ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुप्रयोगों को लक्षित करते हुए आठ आधारभूत AI मॉडल परियोजनाएँ शुरू की हैं:

- बहुभाषी संचार
- स्वास्थ्य सेवा समाधान
- वैज्ञानिक अनुसंधान
- औद्योगिक स्वचालन
- शासन और सार्वजनिक सेवाएँ
- कृषि प्रौद्योगिकियाँ

इन पहलों का उद्देश्य AI में भारत की आत्मनिर्भरता को मज़बूत करना, स्थानीय भाषाओं में नवाचार को बढ़ावा देना और AI प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना है।

निष्कर्ष

भारत-AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026, ज़िम्मेदार और समावेशी AI विकास में भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सात चक्रों पर ध्यान केंद्रित करके, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि AI प्रौद्योगिकियों का विकास और उपयोग इस तरह से किया जाए जिससे सभी मानवता को लाभ हो, स्थिरता को बढ़ावा मिले और समान प्रगति को बढ़ावा मिले।

"जितने वाले कुछ अलग चीज़ें नहीं करते !
बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं !!

"इंतेज़ार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है !
जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं !!"

संस्कृति एवं इतिहास

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को 2025 ग्लोबल एजुकेशन फॉर पीस अवार्ड मिला

ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (JGU) को STAR स्कॉलर्स नेटवर्क द्वारा 2025 ग्लोबल एजुकेशन फॉर पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस (21 सितंबर 2025) पर की गई, जिसमें वैश्विक शांति, न्याय और स्थिरता को बढ़ावा देने में उच्च शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

पुरस्कार का महत्व

ग्लोबल एजुकेशन फॉर पीस अवार्ड दुनिया भर के उन उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) को मान्यता देता है जो:

- शिक्षा के माध्यम से शांति को बढ़ावा देते हैं।
- पाठ्यक्रम में वैश्विक दृष्टिकोणों को शामिल करते हैं।
- वैश्विक नागरिकता और अंतर-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देते हैं।
- संवाद, सहानुभूति और नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं।

वैश्विक संदर्भ

- जेजीयू ने 2025 का पुरस्कार अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन द एमिरेट्स (यूएई) के साथ साझा किया है।
- चयन एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय समिति द्वारा किया गया, जिसने संस्थानों के शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभाव, नवाचार और वैश्विक पहुँच का मूल्यांकन किया।
- पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष, प्रोफेसर जॉन सी. वीडमैन ने उच्च शिक्षा में शांति, न्याय और स्थिरता को एकीकृत करने के एक आदर्श के रूप में जेजीयू की प्रशंसा की।

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 - मोहनलाल दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (2023) प्रदान किए। वरिष्ठ मलयालम अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को भारतीय फिल्मों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च सिनेमा सम्मान, प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रमुख पुरस्कार - राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023

- सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म: 12वीं फ़ेल (हिंदी)।
- सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म: कथाल: अ जैकफ्रूट मिस्ट्री।
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12वीं फ़ेल)।
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: रानी मुखर्जी (मिसेज़ चटर्जी वर्सेस नॉर्वे)।
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: सुदीप्तो सेन (द केरल स्टोरी)।
- सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी।
- सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्वगायक: पीवीएनएस रोहित (बेबी - तेलुगु)।

- सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगायिका: शिल्पा राव (जवान - हिंदी)।
- सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म: मऊ: द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराव (मिज़ो)।

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार:

- 1969 में स्थापित, "भारतीय सिनेमा के जनक" धुंडिराज गोविंद फाल्के के नाम पर।
- सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार:

- 1954 में स्थापित; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित।
- उद्देश्य: पूरे भारत में फिल्म निर्माण, कहानी कहने और अभिनय में उत्कृष्टता को सम्मानित करना।

बैलन डी'ओर 2025: प्रमुख पुरस्कार विजेता

69वां बैलन डी'ओर समारोह पेरिस, फ्रांस के थिएटर डू चैटलेट में आयोजित किया गया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) का सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरना रहा, जिसने पुरुषों के बैलन डी'ओर और पुरुषों के क्लब ऑफ द ईयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते, जो इस फ्रांसीसी क्लब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था।

प्रमुख व्यक्तिगत पुरस्कार

- पुरुष बैलन डी'ओर: ओस्मान डेम्बेले (फ्रांस, PSG) - पहला प्रमुख व्यक्तिगत पुरस्कार, PSG को UEFA चैंपियंस लीग, लीग 1 और कूप डी फ्रांस तक पहुँचाने के बाद।
- महिला बैलन डी'ओर: ऐताना बोनमाटी (स्पेन, बार्सिलोना) - लगातार तीन बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी।

युवा पुरस्कार (कोपा ट्रॉफी)

- पुरुषों की कोपा ट्रॉफी: लामिन यामल (स्पेन, बार्सिलोना) - सबसे कम उम्र के दोहरे विजेता, पुरुषों के बैलन डी'ओर के उपविजेता भी।
- महिलाओं की कोपा ट्रॉफी (उद्घाटन): विकी लोपेज़ (स्पेन, बार्सिलोना)।

गोलकीपिंग पुरस्कार (याशिन ट्रॉफी)

- पुरुषों की याशिन ट्रॉफी: जियानलुइगी डोनारुम्मा (इटली, पीएसजी)।
- महिलाओं की याशिन ट्रॉफी (उद्घाटन): हन्ना हैम्पटन (इंग्लैंड, चेल्सी)।

कोचिंग पुरस्कार (जोहान क्रूफ ट्रॉफी)

- पुरुषों के कोच: लुइस एनरिक (स्पेन, पीएसजी) - यूईएफए चैंपियंस लीग जीतने के लिए।
- महिलाओं के कोच: सरीना विगमैन (नीदरलैंड, इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम) - लगातार दो महिला यूरो खिताब जीतने के लिए।

गोल स्कोरिंग पुरस्कार (गर्ड मुलर ट्रॉफी)

- पुरुष: विक्टर ग्योकेरेस (स्वीडन, स्पोर्टिंग सीपी/आर्सेनल) – 52 खेलों में 54 गोल।
- महिला: इवा पाजोर (पोलैंड, बार्सिलोना) – 46 खेलों में 43 गोल।

क्लब और मानवतावादी पुरस्कार

- वर्ष का पुरुष क्लब: पेरिस सेंट-जर्मेन (फ्रांस)।
- वर्ष का महिला क्लब: आर्सेनल (इंग्लैंड)।

सोक्रेट्स पुरस्कार: ज्ञाना फाउंडेशन (स्पेन) – लुइस एनरिक द्वारा अपनी बेटी की स्मृति में स्थापित, जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की सहायता के लिए।

उल्लेखनीय तथ्य:

- बैलोन डी'ओर: फ्रांस फुटबॉल द्वारा वार्षिक पुरस्कार, पहली बार 1956 में प्रदान किया गया।
- 69वां संस्करण (2025): तीन नई महिला श्रेणियां (कोपा, याशिन, गर्ड मुलर ट्रॉफी) शुरू की गईं।

ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया

ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीईजी) 2025 विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया, जहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने किया और पुरस्कार राज्य मंत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किए गए।

विषय: "विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन"।

नई श्रेणी शुरू की गई

- श्रेणी: सेवा वितरण को गहन बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में जमीनी स्तर की पहल।
- मूल्यांकन की गई प्रविष्टियाँ: देश भर में 1.45 लाख से अधिक।

पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतें

- स्वर्ण पुरस्कार (₹10 लाख): रोहिणी ग्राम पंचायत, धुले, महाराष्ट्र - सरपंच डॉ. आनंदराव पवारा।
- रजत पुरस्कार (₹5 लाख): पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत, पश्चिम त्रिपुरा - सरपंच श्रीमती। अनीता देब दास।
- जूरी पुरस्कार: पलसाना ग्राम पंचायत, सूरत, गुजरात - सरपंच श्री प्रवीणभाई पुरुषोत्तमभाई अहीर।
- जूरी पुरस्कार: सुआकाटी ग्राम पंचायत, केंदुझार, ओडिशा - सरपंच श्रीमती कौतुका नाइक।

उल्लेखनीय डिजिटल नवाचार**रोहिणी ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र:**

- महाराष्ट्र की पहली ग्राम पंचायत जिसने पूरी तरह से कागज़ रहित ई-ऑफिस अपनाया।
- 1,027 ऑनलाइन सेवाएँ, 100% घरेलू डिजिटल साक्षरता।
- रीयल-टाइम शिकायत निवारण, ब्लक एसएमएस आउटरीच।

पश्चिम मजलिसपुर ग्राम पंचायत, त्रिपुरा:

- नागरिक चार्टर-संचालित शासन मॉडल।
- प्रमाण पत्र (जन्म, मृत्यु, विवाह), व्यापार लाइसेंस, संपत्ति रिकॉर्ड, मनरेगा जॉब कार्ड का ऑनलाइन वितरण।
- जवाबदेही के लिए प्रत्येक अनुरोध की डिजिटल निगरानी।

पलसाना ग्राम पंचायत, गुजरात:

- एकिकृत डिजिटल गुजरात और ग्राम सुविधा पोर्टल।
- ऑनलाइन शिकायत निवारण, क्यूआर/यूपीआई-आधारित संपत्ति कर भुगतान।
- 10,000 से ज्यादा नागरिक सालाना ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हैं।

सुआकाटी, ग्राम पंचायत, ओडिशा:

- ओडिशावन और सेवा ओडिशा प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएँ।
- रीयल-टाइम ट्रेकिंग के साथ 24/7 नागरिकों की पहुँच।
- महिला नेतृत्व और समावेशी शासन को बढ़ावा देता है।

संस्थागत ढाँचा

- पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) के सहयोग से DARPG (प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग) द्वारा स्थापित पुरस्कार।
- MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा समर्थित।
- ज्ञान भागीदार: IIM विशाखापत्तनम।

बाबा कल्याणी को ASME द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया

भारत फोर्ज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (ASME) द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया है। ASME एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठन है जो जनहित के लिए इंजीनियरिंग नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। 1924 में स्थापित होली मेडल, उत्कृष्ट और अद्वितीय इंजीनियरिंग योगदान के लिए प्रदान किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति या टीम द्वारा किसी एक उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण और समयबद्ध जनहित प्राप्त होता है। बाबा कल्याणी को यह सम्मान अमेरिकी टैरिफ जैसी ऊँची व्यापार बाधाओं के बीच उन्नत विनिर्माण, उत्पादन के स्थानीयकरण और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए मिला है। उनके प्रयासों ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों को कम करने और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में योगदान दिया है। यह पुरस्कार अमेरिका के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में भारतीय मूल के इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के योगदान को भी मान्यता देता है। यह भारत फोर्ज के अमेरिका के साथ दीर्घकालिक सहयोग और आर्थिक एवं व्यापार संबंधी चुनौतियों पर काबू पाने में सीमा पार सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है।

मध्य प्रदेश को विरासत पर्यटन नेतृत्व के लिए गोल्डन बनयान पुरस्कार मिला

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (एमपीटीबी) को सर्वश्रेष्ठ राज्य - विरासत पर्यटन श्रेणी में गोल्डन बनयान पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार दिल्ली में आयोजित हेरिटेज वीक अवार्ड्स 2025 में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा प्रदान किया गया। यह राज्य द्वारा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को मान्यता देता है।

समृद्ध विरासत संपत्तियाँ

- मध्य प्रदेश में तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं:
- खजुराहो मंदिर समूह
- भीमबेटका शैलाश्रय
- सांची स्तूप

विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 15 अन्य विरासत स्थल इसकी सांस्कृतिक संपदा में वृद्धि करते हैं। सक्रिय संरक्षण और संवर्धन के अंतर्गत प्रमुख शहर: ओरछा, मांडू, चंदेरी और खजुराहो। ग्वालियर को हाल ही में यूनेस्को "संगीत नगरी" का नाम दिया गया है, जिससे राज्य की वैश्विक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।

गोल्डन बनयान पुरस्कार क्या है?

यह हेरिटेज अवार्ड्स या हेरिटेज वीक कार्यक्रमों के तहत दिया जाने वाला एक पुरस्कार है - ये भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों का जश्न मनाते हैं। यह पुरस्कार कई श्रेणियों में प्रदान किया जाता है जैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य - विरासत पर्यटन, सर्वश्रेष्ठ शहर/स्थल आदि।

मध्य प्रदेश

- राजधानी: भोपाल (कार्यकारी शाखा)
- राज्यपाल: मंगूभाई सी. पटेल
- मुख्यमंत्री: मोहन यादव (भाजपा)
- उपमुख्यमंत्री: जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल (भाजपा)
- ज़िले: 55 (10 संभाग)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दीवान एस. रावत को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (FNA) द्वारा सम्मानित किया गया

कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दीवान एस. रावत को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (FNA) का फेलो चुना गया है। FNA को भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान माना जाता है।

प्रो. रावत की उपलब्धियाँ:

- दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के वरिष्ठ प्रोफेसर और वर्तमान में कुमाऊँ विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्यरत।
- 175 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित और 9 पेटेंट धारक।
- औषधीय रसायन विज्ञान, विशेष रूप से पार्किंसंस रोग के लिए दवा विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित।

- उनके शोध से एक ऐसे अणु का विकास हुआ जिसने पार्किंसंस रोग के उपचार के लिए चरण I मानव नैदानिक परीक्षणों को पारित कर दिया, और यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान से US FDA अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला अणु बन गया।
- उनके शोध से दो और अणु ऑटोइम्यून रोगों और मनोभ्रंश को लक्षित करने वाले प्रीक्लिनिकल चरण में हैं।

व्यावसायिक पृष्ठभूमि:

- 2003 में दिल्ली विश्वविद्यालय में शामिल होने से पहले नाइपर, मोहाली में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत।
- 2010 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत।
- 28 पीएचडी छात्रों का पर्यवेक्षण किया; उनके शोध को 7750 से अधिक बार उद्धृत किया गया है, जिसमें एच-इंडेक्स 52 और आई10-इंडेक्स 139 है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA): 1935 में स्थापित, यह भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाली प्रमुख विज्ञान अकादमियों में से एक है।
- अमेरिकी FDA अनुमोदन: अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अनुमोदन प्राप्त करना दवा विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करता है।
- MERU योजना: बहु-विषयक अनुसंधान और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देकर उच्च शिक्षा को मजबूत करने की एक सरकारी पहल।
- पार्किंसंस रोग: एक न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार जो गति और समन्वय को प्रभावित करता है, जिससे दवा चिकित्सा में प्रगति उपचार के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।

टाइम पत्रिका की 2025 की सर्वश्रेष्ठ किड: भारतीय-अमेरिकी किशोरी तेजस्वी मनोज

टेक्सास की सत्रह वर्षीय भारतीय-अमेरिकी किशोरी तेजस्वी मनोज को टाइम पत्रिका की 2025 की सर्वश्रेष्ठ किड चुना गया है। कैलिफ़ोर्निया में जन्मी और आठ साल की उम्र से डलास में पली-बढ़ी, वह ऐसे परिवार में पली-बढ़ी जहाँ माता-पिता दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तेजस्वी को मिडिल स्कूल में गर्ल्स हू कोड कार्यक्रम के माध्यम से कोडिंग के प्रति अपने जुनून का पता चला, जिसने उन्हें तकनीक और समाज पर इसके प्रभाव को समझने के लिए प्रेरित किया।

नवाचार के लिए प्रेरणा:

फरवरी 2024 में, तेजस्वी के दादा एक ऑनलाइन घोटाले में लगभग ठगे गए थे, जिससे वृद्धों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी का पता चला। इस अनुभव से प्रेरित होकर, उन्होंने शोध किया और पाया कि इस तरह के घोटाले व्यापक थे, जिससे उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया।

शील्ड सीनियर्स पहल:

तेजस्वी ने शील्ड सीनियर्स नामक एक वेबसाइट विकसित की, जिसका उद्देश्य वृद्धों को ऑनलाइन धोखाधड़ी की पहचान करने और उससे बचने में मदद करना है। प्लेटफॉर्म:

- उपयोगकर्ताओं को साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातों के बारे में शिक्षित करता है
- त्वरित प्रश्नों के लिए एक AI-संचालित चैटबॉट प्रदान करता है
- संदिग्ध संदेशों का विश्लेषण करता है
- पीड़ितों को रिपोर्टिंग एजेंसियों के पास भेजता है
- यह पहल वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल दुनिया में स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में सक्षम बनाती है।

यूनुस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया

केरल के पलक्कड़ निवासी प्रवासी भारतीय व्यवसायी और मिडिल ईस्ट डॉटस्पेस कोवर्किंग के कार्यकारी निदेशक यूनुस अहमद को अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार व्यवसाय में उनके उल्लेखनीय योगदान और नेतृत्व को मान्यता देता है। यह पुरस्कार दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एक समारोह के दौरान शारजाह कैमल रेसिंग क्लब के अध्यक्ष शेख मटर बिन हुवैदेन अल केतबी द्वारा प्रदान किया गया। श्री अहमद के साथ, दुनिया के विभिन्न हिस्सों के 14 अन्य उपलब्धि प्राप्त व्यक्तियों को साहित्य, कला, ललित कला, व्यवसाय और सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन व्यक्तियों को उजागर करना है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक पहल है, जो विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करता है।

भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता

भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म समारोह के ओरिज़ोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। ओरिज़ोंटी खंड नई और स्वतंत्र फिल्मों पर केंद्रित है। उनकी फिल्म "सॉन्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज़", जो मुंबई में दो प्रवासी महिलाओं की कहानी कहती है, इस खंड में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि थी। इस पुरस्कार की घोषणा ओरिज़ोंटी निर्णायक मंडल की अध्यक्ष जूलिया डुकोर्नी ने की।

82वें वेनिस फिल्म समारोह में अन्य प्रमुख पुरस्कार:

- गोल्डन लायन (सर्वश्रेष्ठ फिल्म): जिम जार्मुश (अमेरिका) को "फादर मदर सिस्टर ब्रदर" के लिए।
- सिल्वर लायन (उपविजेता): कौथर बेन हानिया (ट्यूनीशिया) द्वारा "द वॉयस ऑफ हिंद रजब"।
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: टोनी सर्विलो (इटली) को "ला ग्राज़िया" के लिए।

- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: शिन ज़िलेई (चीन) को "द सन राइज़ ऑन अस ऑल" के लिए।
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (मुख्य प्रतियोगिता): बेनी सफ़्डी (द स्मैशिंग मशीन)।
- विशेष जूरी पुरस्कार: जियानफ्रेंको रोसी (इटली) (बिलो द क्लाउड्स)।

आनंद वी. पाटिल को बेंगलुरु में प्रो. वी.के. गोकक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा

प्रो. वी.के. गोकक पुरस्कार समारोह 7 सितंबर 2025 को के.आर.जी. हॉल, भारतीय विद्या भवन, रेसकोर्स रोड, बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय विद्या भवन और विनायक गोकक वांग्मय ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक और केंद्रीय साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार विजेता आनंद वी. पाटिल हैं।

पुरस्कार के बारे में

यह पुरस्कार प्रसिद्ध भारतीय लेखक, कवि और आलोचक प्रो. विनायक कृष्ण गोकक (1909-1992) के नाम पर रखा गया है। प्रो. गोकक को उनकी महान कृति "भारत सिंधु रश्मि" (कन्नड़ महाकाव्य) के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार (1990) से सम्मानित किया गया था। उन्होंने गोकक समिति की अध्यक्षता की, जिसने कर्नाटक के स्कूलों में कन्नड़ को पहली भाषा के रूप में प्राथमिकता देने की सिफ़ारिश की (जिसके परिणामस्वरूप 1980 के दशक में गोकक आंदोलन शुरू हुआ)। यह पुरस्कार कन्नड़ साहित्य और भाषा नीति में उनके योगदान को याद करता है।

आनंद वी. पाटिल के बारे में

प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक, बाल साहित्य और लघु कथाओं के विशेषज्ञ। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित। कन्नड़ भाषा और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने वाले उनके कार्यों के लिए सम्मानित।

भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार - उद्घाटन संस्करण

असम ओलंपिक संघ ने गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव अंतर्राष्ट्रीय सभागार में पहली बार भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों का नाम असम के पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता (1966, एथलेटिक्स) और एक खेल दिग्गज भोगेश्वर बरुआ के नाम पर रखा गया है।

राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार

- सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: मनु भाकर (निशानेबाज, ओलंपिक पदक विजेता)
- लाइफटाइम अचीवमेंट: सुनील छेत्री (पूर्व कप्तान, भारतीय फुटबॉल टीम)
- उभरते खिलाड़ी: बेदब्रत भराली (भारोत्तोलक, असम)

राज्य स्तरीय पुरस्कार

- सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी: लवलीना बोरगोहेन (मुक्केबाजी, ओलंपिक पदक विजेता)
 - लाइफटाइम अचीवमेंट: दीपांकर भट्टाचार्य (पूर्व ओलंपियन शटलर)
 - उभरते खिलाड़ी: प्रियानुज भट्टाचार्य (टेबल टेनिस)
- प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी और नकद पुरस्कार शामिल है।

विशेष सम्मान पुरस्कार

प्रेमा धर सरमा, स्वाधीन डेका राजा, बालेंद्र मोहन चक्रवर्ती, रिम्पी बुरागोहेन और अन्य सहित 10 खिलाड़ियों/आयोजकों को सम्मानित किया गया।

- भोगेश्वर बरुआ के बारे में: 1966 के एशियाई खेलों (बैंकॉक) में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता; अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स पदक जीतने वाले पहले असमिया।
- पुरस्कार आवृत्ति: छह श्रेणियों (सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, उभरते खिलाड़ी, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर आजीवन उपलब्धि) में हर दो साल में एक बार प्रदान किया जाता है।

एजुकेट गर्ल्स एनजीओ ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता

भारतीय गैर-लाभकारी संगठन 'फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली', जिसे एजुकेट गर्ल्स के नाम से जाना जाता है, को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय संगठन को यह पुरस्कार मिला है, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है।

एजुकेट गर्ल्स के बारे में

राजस्थान में सफीना हुसैन द्वारा 2007 में स्थापित, एजुकेट गर्ल्स ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक और सरकारी संसाधनों को जुटाने का काम करती है। यह संगठन स्कूल न जाने वाली लड़कियों की पहचान करता है, उन्हें कक्षाओं में लाता है, और उच्च शिक्षा या रोजगार योग्यता प्राप्त करने तक उनकी पढ़ाई जारी रखने को सुनिश्चित करता है। उनका आदर्श वाक्य है "एक समय में एक लड़की।"

2025 के अन्य पुरस्कार विजेता

एजुकेट गर्ल्स के अलावा, 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं:

- शाहिना अली (मालदीव) - पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए।
- फ्लेवियानो एंटोनियो एल. विलानुएवा (फिलीपींस) - उनकी सामाजिक सेवा पहलों के लिए।

पुरस्कार समारोह

67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 7 नवंबर, 2025 को मेट्रोपॉलिटन थिएटर, मनीला (फिलीपींस) में प्रदान किया जाएगा। विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में

फिलीपींस के सातवें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1957 में स्थापित। सरकारी सेवा, जनसेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक कलाओं और शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन (आरएमएएफ), फिलीपींस द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

भारत और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार

वर्गीस कुरियन, सत्यजीत रे, महाश्वेता देवी, अरुणा रॉय और अंशु गुप्ता सहित कई भारतीयों ने अतीत में व्यक्तिगत रूप से यह पुरस्कार जीता है, लेकिन एजुकेट गर्ल्स यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन है।

प्रधानमंत्री मोदी ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली (विज्ञान भवन) में ज्ञान भारतम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल केंद्रीय बजट 2025 के दौरान घोषित ज्ञान भारतम मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रह है - लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियाँ।

ज्ञान भारतम मिशन के उद्देश्य:

- भारत और विदेशों में पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और सूचीकरण।
- सार्वजनिक पहुँच के लिए एक केंद्रीय मंच का निर्माण।
- संरक्षण और अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग।
- बौद्धिक चोरी को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि पारंपरिक ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत विश्व स्तर पर सुलभ हों।

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रेखांकित महत्व:

80 से अधिक भाषाओं (संस्कृत, प्राकृत, असमिया, बंगाली, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, आदि) में पांडुलिपियाँ मौजूद हैं।

- उदाहरण: गिलगित पांडुलिपियाँ (कश्मीर का इतिहास), कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सारनाथ की बौद्ध पांडुलिपियाँ, चरक और सुश्रुत संहिताएँ (आयुर्वेद), शुल्व सूत्र, नाट्य शास्त्र और बख्शाली पांडुलिपि (शून्य के प्रारंभिक प्रयोग के प्रमाण)।
- पांडुलिपियों में दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, वास्तुकला, धातु विज्ञान, कला और तत्वमीमांसा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- भारत की ज्ञान परंपरा चार स्तंभों पर टिकी है: संरक्षण, नवाचार, परिवर्धन और अनुकूलन।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण: ज्ञान को क्षति, हानि और दुरुपयोग से बचाने में मदद करता है।
- ज्ञान भारतम मिशन: डिजिटल ज्ञान भंडार बनाकर मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पहलों का समर्थन करता है।

- गिलगित पांडुलिपियाँ: भारत की सबसे पुरानी बौद्ध पांडुलिपियों में से एक (5वीं-6ठी शताब्दी ई.)।
- बख्शाली पांडुलिपि: प्राचीन भारतीय ग्रंथ (तीसरी-चौथी शताब्दी ई.) जिसमें शून्य का सबसे पहला अभिलिखित प्रयोग है।

भारत ने दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय 'आदि संस्कृति' का शुभारंभ किया

जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय - आदि संस्कृति का शुभारंभ किया।

उद्देश्य: आदि संस्कृति एक डिजिटल अकादमी और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प और ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देना है।

विशेषताएँ:

आदिवासी उत्पादों और सेवाओं के लिए एक ऑनलाइन बाज़ार प्रदान करता है। राष्ट्रीय और वैश्विक दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सांस्कृतिक संरक्षण, आजीविका सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देता है।

महत्व:

- जमीनी स्तर पर आदिवासी सशक्तिकरण, सम्मान और अवसरों को बढ़ाता है।
- जनजातीय विरासत के संवर्धन और संरक्षण को प्रोत्साहित करता है।
- संबंधित पहल: यह शुभारंभ आदि कर्मयोगी अभियान राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई चर्चाओं का हिस्सा था, जिसमें एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए) के परियोजना अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री मोदी को जापान की प्रसिद्ध दारुमा गुड़िया से सम्मानित किया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुनमा प्रान्त के ताकासाकी स्थित शोरिनज़ान दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी सेशी हिरोसे ने जापान के सबसे प्रतिष्ठित स्मृति चिन्हों में से एक, दारुमा गुड़िया से सम्मानित किया।

दारुमा गुड़िया के बारे में

- प्रतीकात्मकता: सौभाग्य, दृढ़ता और समृद्धि का प्रतीक।
- उत्पत्ति: 17वीं शताब्दी, ताकासाकी, गुनमा प्रान्त।
- प्रेरणा: बोधिधर्म पर आधारित, जो पाँचवीं शताब्दी के भिक्षु थे जिन्होंने जैन बौद्ध धर्म की स्थापना की थी।
- डिज़ाइन: गोल, अंगहीन आकृति "नानाकोरोबी याओकी" (सात बार गिरना, आठ बार उठना) का प्रतीक है।
- परंपरा: खरीदार एक आँख पर इच्छा करते समय और दूसरी आँख पूरी होने पर रंग लगाते हैं।

सांस्कृतिक महत्व

विभिन्न रंगों में रंगी गई, प्रत्येक का अर्थ:

- लाल - पारंपरिक, बीमारियों से सुरक्षा से जुड़ा।
- सफेद - प्रेम और सद्भाव।
- पीला - सुरक्षा और संरक्षण।
- सुनहरे कांजी ("फुकु-इरी") से रंगा हुआ, जिसका अर्थ है सौभाग्य लाना।
- विशेषताएँ सारस (दीर्घायु) और कछुआ (सुरक्षा, लंबी आयु) का प्रतीक हैं।
- जापानी घरों, दुकानों, रेस्टोरेंट, एनीमे, मंगा और सांस्कृतिक परंपराओं में व्यापक रूप से देखा जाता है।

अतिरिक्त तथ्य:

80% दारुमा गुड़िया ताकासाकी में बनाई जाती हैं। जापान में नए साल के दौरान लक्ष्य-निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। पुरानी गुड़ियों को पारंपरिक रूप से दारुमा कुयो समारोह में जलाया जाता है। जापान ने पहले भी सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करते हुए वैश्विक नेताओं को प्रतीकात्मक सांस्कृतिक वस्तुएं भेंट की हैं।

"सफलता के लिए किसी भी ख़ास समय का
इंतज़ार मत करो !
बल्कि अपने हर समय को ख़ास बनालो !!"

"निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े !
क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय
बदल जाती है !!

खेल-कूद

ICC ने यूएसए क्रिकेट की सदस्यता निलंबित की

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने यूएसए क्रिकेट की सदस्यता निलंबित कर दी है।

कारण: ICC संविधान के तहत दायित्वों का बार-बार और निरंतर उल्लंघन।

प्रमुख कमियों में शामिल हैं:

- कार्यात्मक शासन संरचना को लागू करने में विफलता।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (USOPC) के साथ राष्ट्रीय शासी निकाय (NGB) का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का अभाव।
- ICC ने स्पष्ट किया कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन वैश्विक क्रिकेट के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक निर्णय था।

ICC (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) के बारे में

- स्थापना: 1909 (इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में), 1989 में इसका नाम बदलकर ICC कर दिया गया।
- मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात।
- वर्तमान अध्यक्ष: जय शाह
- सीईओ: संजोग गुप्ता
- महाप्रबंधक: वसीम खान

भारत ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय फुटसल जीत दर्ज की

भारत ने एएफसी फुटसल एशियन कप 2026 कालीफायर में मंगोलिया को 3-0 से हराकर अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय फुटसल जीत दर्ज की। यह मैच कुवैत के अर्दिया में खेला गया, जिसने भारत के फुटसल सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। फुटसल फुटबॉल का एक फाइव-ए-साइड इनडोर संस्करण है, जो एक छोटे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यह खेल, जिसका संचालन विश्व स्तर पर फीफा और एशिया में एशियाई फुटबॉल परिषद (एएफसी) द्वारा किया जाता है, 1930 के दशक में उरुग्वे में शुरू हुआ था।

फीफा (फ़ेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन)

- स्थापना: 21 मई 1904, पेरिस, फ्रांस
- मुख्यालय: ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड
- वर्तमान अध्यक्ष: जियानी इन्फ़ेन्टिनो (2016 से)
- सदस्य: 211 राष्ट्रीय संघ (संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से ज्यादा)

एएफसी (एशियाई फुटबॉल परिषद)

- स्थापना: 1954
- मुख्यालय: कुआलालंपुर, मलेशिया
- वर्तमान अध्यक्ष: शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफ़ा (बहरीन)
- सदस्य: 47 देश (एशिया और ऑस्ट्रेलिया)

- भूमिका: एशिया में फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर का शासी निकाय।

आनंदकुमार वेलकुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में रचा इतिहास

भारत के आनंदकुमार वेलकुमार ने चीन में आयोजित 2025 विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 42 किमी मैराथन में स्वर्ण पदक जीता और भारत के पहले स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियन बने।

कई पदक विजेता

- 22 वर्षीय एथलीट ने इस प्रतियोगिता में कुल तीन पदक जीते:
- 42 किमी मैराथन में स्वर्ण
- 1000 मीटर में स्वर्ण (1:24.92 के रिकॉर्ड समय के साथ)
- 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य

अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य

स्पीड स्केटिंग का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग संघ (ISU) द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1892 में नीदरलैंड में हुई थी। 2025 की विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप चीन में आयोजित की गई थी। मैराथन स्केटिंग स्पर्धाएँ आमतौर पर 42 किमी (मैराथन दौड़ की दूरी के समान) की होती हैं। भारत ने पारंपरिक रूप से क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है - वेलकुमार की जीत भारत की खेल उपलब्धियों में विविधता लाती है। विश्व खेल, ओलंपिक में शामिल नहीं होने वाले खेलों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है, जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ (IWGA) द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ:

- स्थापना: 21 मई 1980
- मुख्यालय: लॉज़ेन, स्विट्ज़रलैंड
- अध्यक्ष: जोस पेरुरेना लोपेज़

अर्शदीप सिंह 100 टी20I विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज़ बने

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय (टी20I) में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज़ बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 2025 एशिया कप के भारत के अंतिम ग्रुप मैच के दौरान ओमान के विनायक शुक्ला को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की।

ऐतिहासिक संदर्भ

- टेस्ट क्रिकेट: वीनू मांकड़ 100 विकेट तक पहुँचने वाले पहले भारतीय थे।

- एकदिवसीय क्रिकेट: कपिल देव 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय थे (1986)।
- टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: अर्शदीप सिंह पहले बने।

विश्व कप रिकॉर्ड

- 2022 टी20 विश्व कप: 10 विकेट (टूर्नामेंट में भारत का सर्वोच्च)।
- 2024 टी20 विश्व कप: 8 पारियों में 17 विकेट (भारत की खिताबी जीत में अहम भूमिका)।

बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर: मरियम फातिमा

बिहार के मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा शतरंज में राज्य की पहली महिला FIDE मास्टर (WFM) बन गई हैं। मान्यता: अंतराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) द्वारा प्रदत्त उपाधि।

WFM के लिए पात्रता मानदंड:

- न्यूनतम FIDE रेटिंग 2100।
- FIDE-रेटेड टूर्नामेंटों में निरंतर प्रदर्शन।

FIDE (अंतराष्ट्रीय शतरंज महासंघ):

- स्थापना: 1924 में पेरिस, फ्रांस में।
- मुख्यालय: लुसाने, स्विट्जरलैंड।
- अध्यक्ष: अर्काडी ड्वोर्कोविच
- उपाध्यक्ष: विश्वनाथन आनंद

भारत में शतरंज:

- भारत ने 75 शतरंज ग्रैंडमास्टर (2025 तक) दिए हैं।
- विश्वनाथन आनंद - भारत के पहले ग्रैंडमास्टर (1988) और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन।
- भारत तमिलनाडु के मामल्लपुरम में शतरंज ओलंपियाड (2022) की मेज़बानी कर रहा है।

रजत पाटीदार के सेंट्रल ज़ोन ने 11 साल बाद दलीप ट्रॉफी जीती

बीसीसीआई के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में आयोजित दलीप ट्रॉफी के फाइनल में सेंट्रल ज़ोन ने साउथ ज़ोन को छह विकेट से हरा दिया। सेंट्रल ज़ोन ने अंतिम दिन 65 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना सातवाँ दलीप ट्रॉफी खिताब हासिल किया और 11 साल के खिताबी सूखे को समाप्त किया। यह जीत रजत पाटीदार के लिए 2025 में दूसरा खिताब है, जो उन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अपनी सफलता के बाद जीता था।

मुख्य तथ्य:

- टूर्नामेंट: दलीप ट्रॉफी
- प्रकार: भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट
- स्थापना: 1961-62 सीज़न
- आयोजक संस्था: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)
- नाम: कुमार श्री दलीपसिंहजी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर।

- प्रतिभागी: क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों या चयनकर्ताओं द्वारा चुनी गई टीमों (संस्करण के अनुसार भिन्न हो सकती हैं)
- नवीनतम विजेता: मध्य क्षेत्र
- मध्य क्षेत्र के खिताब: 7 (इस जीत सहित)
- प्लेयर ऑफ़ द मैच: यश राठौड़
- प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़: सारांश जैन (दक्षिण क्षेत्र)

स्मृति मंधाना ने ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान फिर से हासिल किया

टीम इंडिया की उप-कप्तान और ओपनर स्मृति मंधाना ने ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान फिर से हासिल कर लिया है। उन्होंने इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर-ब्रंट को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। मंधाना ने न्यू चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 63 गेंदों में 58 रन की पारी खेली। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सात रेटिंग पॉइंट मिले, जिससे वह साइवर-ब्रंट से चार पॉइंट आगे हो गईं।

टॉप महिला वनडे बल्लेबाज

रैंक	खिलाड़ी	टीम	रेटिंग पॉइंट
1	स्मृति मंधाना	भारत	735
2	नेट साइवर-ब्रंट	इंग्लैंड	731
3	लौरा वोल्वार्ट	दक्षिण अफ्रीका	725
4	एलीसे पेरी	ऑस्ट्रेलिया	689
5	बेथ मूनी	ऑस्ट्रेलिया	685

भारतीय ग्रैंडमास्टर वैशाली ने FIDE ग्रैंड स्विस् जीता, 2026 कैडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया

भारत की ग्रैंडमास्टर (जीएम) वैशाली रमेशबाबू ने लगातार दूसरे संस्करण में FIDE ग्रैंड स्विस् टूर्नामेंट जीता। यह टूर्नामेंट उज़्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था, जहाँ वैशाली ने पूर्व महिला विश्व चैंपियन टैन झोंगयी के खिलाफ अंतिम दौर में ड्रा खेलकर अपनी जीत सुनिश्चित की। 24 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने 11 राउंड में 8 अंक हासिल कर खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ, उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शतरंज आयोजनों में से एक, 2026 कैडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया। वैशाली कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के साथ 2026 कैडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गईं। पिछले संस्करण में, भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते थे, जिसमें विदित गुजराती ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता था।

FIDE:

- स्थापना: 1924
- मुख्यालय: लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड
- अध्यक्ष: अर्काडी ड्वोर्कोविच
- उपाध्यक्ष: विश्वनाथन आनंद

मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता

मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम वर्ग में नाज़िम काइजेबे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। जैस्मीन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को हराकर स्वर्ण पदक जीता।

ऐतिहासिक उपलब्धि:

अपनी जीत के साथ, दोनों मुक्केबाज़ भारतीय विश्व चैंपियनों के एक प्रतिष्ठित समूह में शामिल हो गईं, जिनमें शामिल हैं:

- मैरी कॉम (6 बार की विश्व चैंपियन)
- निकहत ज़रीन (2 बार की विश्व चैंपियन)
- सरिता देवी
- जेनी आरएल
- लेखा केसी
- नीतू घनघस
- लवल्लिना बोरगोहेन
- स्वीटी बूरा

महिला हॉकी एशिया कप में भारत उपविजेता रहा

चीन के हांगजो में आयोजित फाइनल मैच में चीन से 1-4 से हारने के बाद, भारत महिला हॉकी एशिया कप में उपविजेता रहा।

स्कोर:

नवनीत कौर ने भारत का एकमात्र गोल किया। चीन के स्कोरर ज़िक्सिया ओउ, होंग ली, मीरॉन्ग जू और जियाकी झोंग थे।

क्वालीफिकेशन प्रभाव:

चीन ने बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले 2026 एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है।

भारत को विश्व कप में जगह बनाने के लिए क्वालीफायर में भाग लेना होगा।

महिला हॉकी एशिया कप:

एशियाई हॉकी महासंघ (एचएफ) द्वारा आयोजित एक प्रमुख महाद्वीपीय टूर्नामेंट। यह टूर्नामेंट एफआईएच हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफिकेशन के रास्ते प्रदान करता है और एशिया में प्रतिस्पर्धा के स्तर को बढ़ाता है।

एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2026:

बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाना है। यह महिला हॉकी के शीर्ष अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में से एक है, जिसमें दुनिया भर की टीमों में भाग लेती हैं।

मैक्स वेरस्टैपेन ने 2025 में इटैलियन ग्रां प्री जीती

रेड बुल रेसिंग के मैक्स वेरस्टैपेन ने इटली के ऑटोड्रोमो नाज़ियोनेल मोज़ा में आयोजित इटैलियन ग्रां प्री में शानदार जीत हासिल की। वेरस्टैपेन की यह जीत मई 2025 के बाद उनकी पहली और सीज़न की तीसरी जीत थी, जो चार बार के फ़ॉर्मूला 1

विश्व चैंपियन के लिए एक मज़बूत प्रदर्शन का प्रतीक है। लैंडो नॉरिस (मैकलारेन) दूसरे स्थान पर रहे, जिससे उनके साथी और खिताब के दावेदार ऑस्कर पियास्ती से अंकों का अंतर 34 अंकों से घटकर 31 अंक रह गया। चार्ल्स लेक्लर (फेरारी) चौथे स्थान पर रहे, जिनका फेरारी के घरेलू ग्रां प्री में उत्साही प्रशंसकों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया, जबकि लुईस हैमिल्टन (मर्सिडीज) ने शानदार शुरुआत के बाद छठा स्थान हासिल किया। इटैलियन ग्रां प्री फ़ॉर्मूला 1 कैलेंडर की सबसे पुरानी रेसों में से एक है, जिसका पहला आयोजन 1921 में मोज़ा में हुआ था। रेड बुल रेसिंग, मिल्टन कीन्स, यूके में स्थित है और हाल के F1 सीज़न में एक प्रभावशाली टीम रही है।

भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता

भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने ताजिकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित CAFA नेशंस कप 2025 में ओमान को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। निर्धारित समय में मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा, जिसमें उदंत सिंह ने भारत के लिए बराबरी का गोल दागा। पेनल्टी शूटआउट में, भारत ने 3-2 से जीत हासिल की: ओमान ने अपने पहले दो पेनल्टी गंवा दिए, और गुरप्रीत सिंह संधू ने अंतिम पेनल्टी बचा ली। यह जीत अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में ओमान पर भारत की पहली जीत थी। यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एशियाई फुटबॉल में, विशेष रूप से मध्य एशियाई फुटबॉल संघ (CAFA) द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों में, भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

CAFA नेशंस कप का आयोजन मध्य एशियाई फुटबॉल संघ द्वारा किया जाता है, जो AFC (एशियाई फुटबॉल परिषद) के अंतर्गत एक क्षेत्रीय निकाय है। भारत की फुटबॉल टीम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) द्वारा शासित है। गुरप्रीत सिंह संधू भारत के पसंदीदा गोलकीपर और अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक प्रमुख खिलाड़ी हैं।

मध्य एशियाई फुटबॉल संघ (CAFA):

- स्थापना: 2014
- मुख्यालय: दुशांबे, ताजिकिस्तान
- अध्यक्ष: रुस्तम इमोमाली (ताजिकिस्तान)
- महासचिव: उलुगबेक करीमोव (ताजिकिस्तान)

102 वर्षीय कोकिची अकुज़ावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज़ व्यक्ति बने

जापान के 102 वर्षीय कोकिची अकुज़ावा, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्राप्त माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज़ व्यक्ति बन गए। वह जापान की सबसे ऊँची चोटी, 12,388 फीट (3,776 मीटर) माउंट फूजी के शिखर पर पहुँचे। अकुज़ावा ने स्वीकार किया कि चढ़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण थी और उन्होंने बीच में ही हार मान ली थी, लेकिन परिवार और दोस्तों के प्रोत्साहन से वे

शिखर तक पहुँचने में सफल रहे। इस चढ़ाई में उनकी 70 वर्षीय बेटी मोटो, उनकी पोती और उसके पति, और एक स्थानीय पर्वतारोहण क्लब के चार दोस्तों ने उनका साथ दिया। समूह ने अपनी अंतिम चढ़ाई से पहले दो रातों के लिए डेरा डाला।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

माउंट फूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी और जापान का एक सांस्कृतिक प्रतीक है, जो हर साल हज़ारों पर्वतारोहियों को आकर्षित करता है। माउंट फूजी के शिखर तक चढ़ाई आमतौर पर चुने गए मार्ग के आधार पर एक से दो दिनों में पूरी हो जाती है। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स विभिन्न श्रेणियों में असाधारण मानवीय उपलब्धियों को मान्यता देता है, जिसमें आयु-संबंधी रिकॉर्ड भी शामिल हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि, जैसे पर्वतारोहण, वृद्ध व्यक्तियों के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़ी है। स्वस्थ जीवनशैली और उन्नत स्वास्थ्य सेवा के कारण, जापान दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाले देशों में से एक है। मनोरंजक पर्वतारोहण जापान में एक लोकप्रिय गतिविधि है, जो अक्सर सामुदायिक बंधन और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है।

विश्व चैंपियनशिप में भारत ने पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता

दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत ने रोमांचक फाइनल में फ्रांस को 235-233 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले, ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव की मिश्रित टीम ने नीदरलैंड से 155-157 से हारने के बाद रजत पदक जीता था। ऋषभ यादव (23 वर्षीय) ने मिश्रित टीम फाइनल से वापसी की और अपने साथियों अमन सैनी और प्रथमेश फुगे के साथ मिलकर भारत के लिए पुरुषों की कंपाउंड टीम का स्वर्ण पदक जीता।

भारत ने चौथा एशिया कप हॉकी खिताब जीता; 2026 एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया

भारत ने बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2024 जीत ली। इस जीत ने भारत के चौथे एशिया कप खिताब को चिह्नित किया और एशियाई हॉकी में प्रभुत्व हासिल करने के आठ साल के इंतजार को समाप्त किया। इस जीत के साथ, भारत ने एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया, जो नीदरलैंड और बेलजियम में आयोजित किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी के लिए ₹3 लाख और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ सदस्य के लिए ₹1.5 लाख की पुरस्कार राशि की घोषणा की।

अतिरिक्त तथ्य:

- एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप एशियाई हॉकी महासंघ (एएचएफ) द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है।

- एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) द्वारा किया जाता है और यह फील्ड हॉकी की शीर्ष वैश्विक प्रतियोगिताओं में से एक है।
- भारत ने इससे पहले 1982, 2003 और 2007 में एशिया कप खिताब जीते थे।
- राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, जिसे एक खेल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- अगला एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 नीदरलैंड और बेलजियम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, जो हॉकी में यूरोप की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

कार्लोस अल्काराज़ ने दूसरा यूएस ओपन खिताब जीता और विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की

स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज़ ने जैनिन सिनर को हराकर अपना दूसरा यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। इस जीत के साथ, अल्काराज़ ने पुरुष टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर ली। 22 साल की उम्र में, अब उनके नाम छह ग्रैंड स्लैम खिताब हैं और 1978 के बाद से 23 साल की उम्र से पहले तीनों सतहों (हार्ड, क्ले, ग्रास) पर कई मेजर जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

2025 के चैंपियन:

- पुरुष एकल: कार्लोस अल्काराज़ (स्पेन)
- महिला एकल: अरीना सबालेन्का (बेलारूस)
- पुरुष डबल्स: मार्सेल ग्रैनोलर्स (स्पेन) / होरासियो सेबालोस (अर्जेंटीना)
- महिला डबल्स: गैब्रिएला डाब्रोस्की (कनाडा) / एरिन रॉटलिफ़ (न्यूज़ीलैंड)
- मिक्सड डबल्स: सारा एरानी (इटली) / एंड्रिया ववासाओरी (इटली)

अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लिया

अनुभवी भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने आधिकारिक तौर पर पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इस तरह उनके 25 साल से ज़्यादा लंबे करियर का अंत हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय करियर की मुख्य बातें:

- भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 156 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए।
- अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण: 2003 (बांग्लादेश में वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला)।
- टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण: 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहली में - पहले ही मैच में 5 विकेट लिए।
- 2013: द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने के जवागल श्रीनाथ के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की - जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों में 18 विकेट लिए।

- 2014 टी20 विश्व कप (बांग्लादेश): 10 विकेट लिए और भारत के फाइनल तक पहुँचने में अहम भूमिका निभाई।
- अंतिम अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति: 2017.

आईपीएल करियर:

- 162 मैच खेले, 23.82 की औसत से 174 विकेट लिए।
- आईपीएल इतिहास में सातवें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़।
- आईपीएल इतिहास में तीन अलग-अलग फ्रैंचाइज़ियों - दिल्ली डेयरडेविल्स, डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद - के लिए 3 हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज़।
- आईपीएल में अंतिम उपस्थिति: आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के लिए।

प्रणव वेंकटेश ने फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स शतरंज का खिताब जीता

भारतीय विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव वेंकटेश ने अंतिम दौर में स्पेनिश ग्रैंडमास्टर एलन पिचोट को हराकर संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीत लिया। प्रणव ने 9 में से 7 अंक बनाए और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों से एक अंक आगे रहे। प्रणव को अंतिम दौर में केवल ड्रा की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने सफ़ेद मोहरों से आक्रामक खेल खेला और जीत हासिल की।

सहायक तथ्य:

- प्रणव वेंकटेश (जन्म 2006, चेन्नई) 2022 में भारत के 75वें ग्रैंडमास्टर बने।
- वे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन (2024) हैं।
- विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंडमास्टर (1988) थे।
- भारत में वर्तमान में 84 ग्रैंडमास्टर हैं (2025 तक)।
- फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स टूर्नामेंट एक आमंत्रण आयोजन है जो दुनिया भर के शीर्ष युवा शतरंज खिलाड़ियों को आकर्षित करता है।
- भारतीय शतरंज महासंघ (सीएफआई): भारत में शतरंज का संचालन करता है और विश्व शतरंज महासंघ (एफआईडीई) से संबद्ध है।

भारतीय शतरंज महासंघ (सीएफआई)

- स्थापना: 1951
- मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु
- अध्यक्ष: नितिन नारंग

एफआईडीई (विश्व शतरंज महासंघ)

- स्थापना: 1924, पेरिस, फ्रांस
- मुख्यालय: लुसाने, स्विट्जरलैंड
- अध्यक्ष: अर्काडी ड्वोर्कोविच

महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ICC-Google साझेदारी

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने वैश्विक स्तर पर महिला क्रिकेट में प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए Google के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी Google की उन्नत तकनीक (Android, Google Gemini, Google Pay, Google Pixel) का उपयोग करके प्रशंसकों के अनुभव को और अधिक गतिशील, सुलभ और इंटरैक्टिव बनाएगी।

यह साझेदारी दो प्रमुख टूर्नामेंटों से पहले हुई है:

- ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 - जिसका आयोजन भारत और श्रीलंका में किया जाएगा।
- ICC महिला T20 विश्व कप 2026 - जिसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

- ICC का पहला वैश्विक महिला भागीदार (2025): यूनीलीवर।
- ICC मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात।
- ICC अध्यक्ष: जय शाह (2024 में नियुक्त)।
- ICC CEO: संजोग गुप्ता
- पिछला ICC महिला विश्व कप (2022): ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जिसकी मेजबानी न्यूजीलैंड में हुई।
- पिछला आईसीसी महिला टी20 विश्व कप (2023): ऑस्ट्रेलिया ने जीता, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित।
- गूगल मुख्यालय: माउंटेन व्यू, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका।
- गूगल के सीईओ: सुंदर पिचाई।

25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर

भारत ने अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कुल 13 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया:

- 4 स्वर्ण
- 6 रजत
- 3 कांस्य

इस उपलब्धि ने कॉमनवेल्थ स्तर पर भारोत्तोलन में भारत के प्रभुत्व की पुष्टि की।

चैंपियनशिप के बारे में

कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग फेडरेशन (CWF) द्वारा आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है।

यह कॉमनवेल्थ देशों के एथलीटों के लिए एक प्रतिस्पर्धी मंच प्रदान करती है और विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए कालीफायर के रूप में कार्य करती है।

भारत और भारोत्तोलन:

राष्ट्रमंडल प्रतियोगिताओं, विशेषकर भारोत्तोलन में भारत का रिकॉर्ड मज़बूत रहा है। दिग्गज भारतीय भारोत्तोलकों में कर्णम मल्लेश्वरी (भारोत्तोलन में पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता, सिडनी 2000) और मीराबाई चानू (टोक्यो 2020)

ओलंपिक रजत पदक विजेता) शामिल हैं। 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में, भारत ने भारोत्तोलन में 10 पदक जीते।

भारत ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025, श्यामकेंट (कज़ाखस्तान) में इतिहास रचा

भारत ने कज़ाखस्तान के श्यामकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में 50 स्वर्ण पदक हासिल करके और चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके एक रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि हासिल की।

- भारत की पदक तालिका: 99 (50 स्वर्ण, 26 रजत, 23 कांस्य)
- कज़ाखस्तान: दूसरा स्थान
- चीन: तीसरा स्थान

यह भारत का सबसे सफल अभियान रहा, जिसने 15वीं एशियाई चैंपियनशिप (चांगवोन, दक्षिण कोरिया) को 35 पदकों से पीछे छोड़ दिया।

प्रमुख भारतीय प्रदर्शन

- अंकुर मित्तल - विश्व रिकॉर्ड प्रदर्शन, पुरुषों की डबल ट्रैप में स्वर्ण पदक।
- एलावेनिल वालारिवन - महिलाओं की एयर राइफल में एशियाई रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपना दूसरा एशियाई खिताब जीता + मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक (अर्जुन बाबूता के साथ)।
- नीरू ढांडा - महिला ट्रैप में भारत का पहला एशियाई स्वर्ण पदक।
- शिफ्रत कौर समरा - महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री-पोज़िशन में पहला एशियाई खिताब।
- ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर - 50 मीटर राइफल थ्री-पोज़िशन में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया।
- मनु भाकर - महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल (व्यक्तिगत) सहित तीन कांस्य पदक जीते।

औकीब नबी ने दलीप ट्रॉफी 2025 में दोहरी हैट्रिक के साथ इतिहास रचा

जम्मू और कश्मीर के तेज़ गेंदबाज़ औकीब नबी ने बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस, बेंगलुरु में दलीप ट्रॉफी 2025 के पहले कार्टर फ़ाइनल में (29 अगस्त, 2025) उत्तर क्षेत्र के लिए पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ़ दोहरी हैट्रिक (चार गेंदों में चार विकेट) लेकर इतिहास रच दिया।

मैच के मुख्य अंश

नबी ने 10.1 ओवर में 28 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसमें 1 मेडन शामिल है। उन्होंने विराट सिंह, मनीषी, मुख्तार हुसैन, सूरज सिंधु जायसवाल और मोहम्मद शमी को आउट किया। उनके इस स्पेल ने पूर्वी क्षेत्र को 230 रनों पर समेट दिया, जिससे उत्तर क्षेत्र को 175 रनों की बढ़त मिल गई। नबी इससे पहले

रणजी ट्रॉफी 2024-25 में 8 मैचों में 44 विकेट लेकर शीर्ष तेज़ गेंदबाज़ रहे थे।

भारतीय क्रिकेट में दुर्लभ उपलब्धि

औकीब नबी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले केवल चौथे भारतीय गेंदबाज़ बने।

4 गेंदों में 4 विकेट लेने वाले भारतीय (प्रथम श्रेणी क्रिकेट):

- शंकर सैनी - दिल्ली बनाम हिमाचल प्रदेश (1988)
- मोहम्मद मुधासिर - जम्मू और कश्मीर बनाम राजस्थान (2018)
- कुलवंत खेजरोलिया - मध्य प्रदेश बनाम बड़ौदा (2024)
- औकीब नबी - उत्तर क्षेत्र बनाम पूर्व क्षेत्र (2025)

भारत ने 2025 SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता

यंग टाइग्रेस के नाम से मशहूर भारतीय अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम ने थिम्पू (भूटान) के चांगलिमथांग स्टेडियम में नेपाल को हराकर 2025 SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया।

महत्व

यह जीत युवा स्तर पर दक्षिण एशियाई महिला फुटबॉल में भारत की प्रमुख ताकत के रूप में स्थिति को और मजबूत करती है। क्लीन शीट रिकॉर्ड टीम की रक्षात्मक और आक्रामक ताकत को दर्शाता है।

ध्यान देने योग्य बिंदु:

SAFF (दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ): दक्षिण एशिया में फुटबॉल का शासी निकाय, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है।

- सदस्य राष्ट्र: भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका।
- भारत ने ऐतिहासिक रूप से SAFF चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अपना दबदबा कायम रखा है।
- चांगलिमथांग स्टेडियम (थिम्पू, भूटान): भूटान का राष्ट्रीय स्टेडियम, क्षेत्रीय टूर्नामेंटों की भी मेजबानी करता है।
- भारत की महिला फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग (2025 तक वरिष्ठ महिला टीम) में 65वें स्थान पर है।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत को मिला पहला मोंडो ट्रैक

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त 2024) के अवसर पर भारत को अपना पहला मोंडो ट्रैक मिल गया है। इसके साथ ही, भारत यह सुविधा प्राप्त करने वाला दुनिया का 25वाँ देश बन गया है।

मोंडो ट्रैक का महत्व

मोंडो ट्रैक इटली में निर्मित विश्वस्तरीय सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक हैं।

इनका उपयोग ओलंपिक और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों में किया जाता है। यह ट्रैक

भारतीय एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण और प्रतियोगिता सुविधाएँ प्रदान करने में मदद करेगा।

अन्य घोषणाएँ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत के आशय पत्र को मंजूरी दे दी है। भारत ने 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भी अपनी बोली प्रस्तुत की है।

मोंडो ट्रैक:

पहली बार 1968 के मेक्सिको ओलंपिक में पेश किया गया। यह एथलीटों को आघात अवशोषण, गति और स्थायित्व प्रदान करता है। मोंडो एस.पी.ए., इटली द्वारा निर्मित।

भारत के युवा फुटबॉलरों ने यूरोपियन ट्रिपल के साथ रचा इतिहास

मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब, मोहाली की अंडर-14/15 टीम ने जुलाई-अगस्त 2025 में यूरोपियन ट्रिपल पूरा करके इतिहास रच दिया - गोथिया कप (स्वीडन), दाना कप (डेनमार्क) और नॉर्वे कप (नॉर्वे) जीतकर। ये दुनिया के तीन सबसे प्रतिष्ठित युवा फुटबॉल टूर्नामेंट माने जाते हैं। टीम 26 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपराजित रही, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अन्य क्षेत्रों के युवा क्लबों के खिलाफ 295 गोल दागे, और केवल कुछ ही गोल खाए।

अतिरिक्त मुख्य तथ्य:

मिनर्वा अकादमी फुटबॉल क्लब (2005 में स्थापित, मोहाली, पंजाब में स्थित) युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए जाना जाता है; इसने इससे पहले 2017-18 आई-लीग जीता था। गोथिया कप (स्वीडन) दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसे अक्सर "विश्व युवा कप" कहा जाता है।

दाना कप (डेनमार्क) यूरोप के सबसे प्रतिस्पर्धी युवा फुटबॉल आयोजनों में से एक है। नॉर्वे कप टीमों की संख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। भारत का फुटबॉल प्रशासन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) द्वारा संचालित होता है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी और यह 1948 में फीफा और 1954 में एएफसी से संबद्ध हो गया। भारत सरकार ने फुटबॉल सहित जमीनी स्तर के खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम (2018) शुरू किया है।

राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में भारत का जलवा

भारत के अजय बाबू वल्लूरी ने अहमदाबाद में आयोजित 30वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 79 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कुल 335 किग्रा भार उठाकर मलेशिया के मुहम्मद एरी (333 किग्रा) और नाइजीरिया के एडेडापो एडेलके (306 किग्रा) को मामूली अंतर से हराया। इस जीत के साथ, अजय बाबू ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालीफाई कर लिया।

राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन महासंघ (CWF) द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रमंडल देशों में भारोत्तोलन का नियामक निकाय है। इस वर्ष (2025) का आयोजन भारत के अहमदाबाद में हुआ था, जहाँ भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (IWLF) ने CWF के सहयोग से इसका आयोजन किया था।

अन्य भारतीय पदक विजेता

महिलाओं के 69 किग्रा वर्ग में, हरजिंदर कौर ने कुल 222 किग्रा भार उठाकर कांस्य पदक जीता। इससे पहले, टोक्यो 2020 ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की, जिससे उन्होंने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अपना स्थान भी पक्का कर लिया।

चैंपियनशिप विवरण

राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 30वें संस्करण में 31 देशों के 300 से अधिक भारोत्तोलकों ने भाग लिया। यह आयोजन न केवल भारोत्तोलन में भारत की ताकत को दर्शाता है, बल्कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण क्वालीफाईंग मंच के रूप में भी कार्य करता है।

राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन महासंघ (CWF)

- स्थापना: 1947 (स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रमंडल देशों में भारोत्तोलन को बढ़ावा देने के लिए)
- मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम

भारतीय भारोत्तोलन महासंघ (IWLF)

- स्थापना: 1935
- मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत

रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने आखिरी बार 2025 सीज़न में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) का प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले, अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

संन्यास का कारण

बीसीसीआई की नीति के अनुसार, भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग में तभी भाग ले सकते हैं जब वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल दोनों से संन्यास ले लें। अश्विन का यह फैसला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने में उनकी रुचि से जुड़ा है।

आईपीएल करियर आँकड़े

- डेब्यू: 2009
- मैच: 221
- विकेट: 187 (औसत: 30.22, इकॉनमी: 7.20, सर्वश्रेष्ठ: 4/34)
- बल्लेबाजी आँकड़े: 92 पारियों में 833 रन, सर्वोच्च स्कोर 50, स्ट्राइक रेट 118.15

अतिरिक्त:

- रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं।
- आईपीएल शासी निकाय: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)।
- सबसे सफल आईपीएल टीम: मुंबई इंडियंस (5 खिताब), चेन्नई सुपर किंग्स (5 खिताब)।
- आईपीएल 2025 विजेता: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

स्टार भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।

महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए, उन्होंने कुल 193 किग्रा भार उठाया:

- स्नेच: 84 किग्रा (रिकॉर्ड)
- क्लीन एंड जर्क: 109 किग्रा (रिकॉर्ड)
- कुल: 193 किग्रा (रिकॉर्ड)

महत्व

तीनों भारोत्तोलकों ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में नए रिकॉर्ड बनाए। इस जीत के साथ, चानू ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में चौथे स्थान पर रहने के बाद यह उनका पहला प्रतिस्पर्धी आयोजन था। वह 49 किग्रा भार वर्ग (ओलंपिक से हटा दिया गया) से 48 किग्रा वर्ग में आ गईं।

मीराबाई चानू:

- पूरा नाम: सैखोम मीराबाई चानू
- जन्म: 8 अगस्त 1994, मणिपुर

प्रमुख उपलब्धियाँ:

- टोक्यो ओलंपिक 2020 (2021 में आयोजित): महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक।
- विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 (अमेरिका): 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण।
- राष्ट्रमंडल खेल: 2018 (गोल्ड कोस्ट) में स्वर्ण, 2014 (ग्लासगो) में रजत।
- पद्म श्री (2018) और राजीव गांधी खेल रत्न (मेजर ध्यानचंद खेल रत्न) पुरस्कार विजेता।

BCCI ने टीम इंडिया के नए मुख्य प्रायोजक के रूप में अपोलो टायर्स का ऐलान किया

अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य प्रायोजक है।

"जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की !
उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की !!"

यह ड्रीम11 की जगह लेगा, जो पहले का प्रायोजक था और जिसने अपना करार पहले ही खत्म कर दिया था।

डील की अवधि और शर्तें

यह प्रायोजन समझौता ढाई साल के लिए है, जो मार्च 2028 में खत्म होगा। अपोलो टायर्स का लोगो भारत की पुरुष और महिला टीमों की जर्सी पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में दिखेगा।

यह कैसे हुआ

यह डील एक प्रतिस्पर्धी बिडिंग प्रक्रिया के बाद हुई। BCCI ने ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, क्रिप्टो और तंबाकू जैसे सेक्टर के ब्रांड को बिडिंग से बाहर कर दिया था। कई बड़े ब्रांडों ने रुचि दिखाई, लेकिन अपोलो टायर्स की बोली चुनी गई।

फाइनेंशियल और प्रति मैच कीमत

इस डील की कीमत रिकॉर्ड है, जो पिछले प्रायोजक की तुलना में ज्यादा है। अपोलो टायर्स कुल लगभग ₹579 करोड़ देगा।

प्रति मैच कीमत (ICC टूर्नामेंट के बाहर के मैचों के लिए): लगभग ₹4.5 करोड़।

BCCI

- स्थापना: 1 दिसंबर, 1928
- संबंध: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एशियन क्रिकेट काउंसिल
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
- अध्यक्ष: राजीव शुक्ला (कार्यवाहक)
- CEO: हेमंग अमीन
- सचिव: देवजीत सैकिया
- पुरुष टीम के कोच: गौतम गंभीर
- महिला टीम के कोच: अमोल मुजुमदार

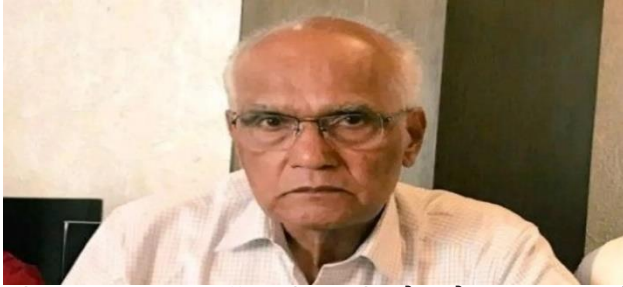
स्केचर्स ने भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद सिराज के साथ करार किया

वैश्विक एथलेटिक ब्रांड स्केचर्स ने भारतीय क्रिकेट में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारत के प्रमुख तेज़ गेंदबाज़ों में से एक मोहम्मद सिराज के साथ करार किया है। सिराज मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले हैं और भारत के सबसे प्रेरक और सफल क्रिकेटरों में से एक बनकर उभरे हैं। वह 2023 में ICC के शीर्ष क्रम के एकदिवसीय गेंदबाज़ थे और उन्होंने विश्व स्तर पर टेस्ट क्रिकेट में महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड के खिलाफ 2025 की टेस्ट सीरीज़ में, सिराज ने 23 विकेट लिए, जिसमें द ओवल में एक पाँच विकेट हॉल भी शामिल है, जिससे भारत को सीरीज़ बराबर करने और एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी बरकरार रखने में मदद मिली। वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुजरात टाइटन्स (GT) के लिए भी एक प्रमुख खिलाड़ी हैं।

"यह ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है !
ज़रूरी यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो !!"

निधन

प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक डॉ. एस. एल. भैरप्पा का निधन



प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक डॉ. संतशिवरा लिंगन्नैया भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया। भैरप्पा ने 25 से अधिक उपन्यास लिखे, जिनमें से कई ने सार्वजनिक बहस और बौद्धिक चर्चा उत्पन्न की।

- उल्लेखनीय कार्य: वंशवृक्ष, दातु, पर्व, गृहभंगा, आवरण, नई नेरालु और सार्थ।
- उनके कई उपन्यासों को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में रूपांतरित किया गया।
- उनकी रचनाओं का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

पुरस्कार एवं सम्मान

- पद्म भूषण - 2023
- सरस्वती सम्मान - 2010
- साहित्य अकादमी फ़ेलोशिप - 2015

महान अंग्रेजी अंपायर डिकी बर्ड का 91 वर्ष की आयु में निधन



महान अंग्रेजी क्रिकेट अंपायर हेरोल्ड "डिकी" बर्ड का 91 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के साउथ यॉर्कशायर के बार्न्सली में निधन हो गया। उनके घरेलू क्लब यॉर्कशायर ने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि उनका निधन घर पर शांतिपूर्वक हुआ। वे अपने पीछे खेल भावना, विनम्रता और पीढ़ियों के लिए प्रशंसा की विरासत छोड़ गए हैं।

प्रारंभिक जीवन और खेल करियर

19 अप्रैल 1933 को बार्न्सली, यॉर्कशायर में जन्मे डिकी बर्ड एक दाएँ हाथ के बल्लेबाज और दाएँ हाथ के ऑफ-ब्रेक गेंदबाज थे। उन्होंने यॉर्कशायर और लीसेस्टरशायर के लिए 93 प्रथम श्रेणी

मैच खेले, जिसमें 2 शतक और 14 अर्धशतक सहित 3,314 रन बनाए। सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने प्लायमाउथ कॉलेज (1966-68) और बाद में जोहान्सबर्ग (1968-69) में कोचिंग की।

अंपायरिंग करियर

बर्ड ने 1973 में अपने अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग करियर की शुरुआत की और 1996 तक अंपायरिंग की। उन्होंने 66 टेस्ट मैचों, 69 एकदिवसीय मैचों और 7 महिला एकदिवसीय मैचों में अंपायरिंग की। अपने तीक्ष्ण निर्णय और संयम के लिए जाने जाने वाले, वे क्रिकेट इतिहास के सबसे सम्मानित अंपायरों में से एक बन गए।

विरासत और पहचान

खेल के सबसे प्रिय अंपायर माने जाने वाले डिकी बर्ड को उनकी निष्पक्षता और विनम्रता के लिए दुनिया भर के क्रिकेटरों द्वारा सराहा जाता था। वे अक्सर एलबीडब्ल्यू के फैसले देने से हिचकिचाते थे, एक ऐसा गुण जिसे आधुनिक निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) के युग में चुनौती दी जा सकती थी। क्रिकेट में उनके योगदान ने उन्हें वैश्विक सम्मान और क्रिकेट इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दिलाया।

ग्रैमी पुरस्कार विजेता गीतकार ब्रेट जेम्स का उत्तरी कैरोलिना विमान दुर्घटना में निधन



ब्रेट जेम्स, जिनका पूरा नाम ब्रेट जेम्स कॉर्निलियस था, 57 वर्ष के थे, का उत्तरी कैरोलिना के फ्रैंकलिन में इओटला वैली एलीमेंट्री स्कूल के पास एक छोटे इंजन वाले विमान दुर्घटना में दुःखद निधन हो गया। यह विमान, संगीतकार के नाम पर पंजीकृत एक सिरस SR22T, नैशविले, टेनेसी से उड़ान भरकर स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 3 बजे उत्तरी कैरोलिना के मैकॉन काउंटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी तीन लोगों की मृत्यु हो गई, और इस घटना की जाँच संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) द्वारा राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) के समन्वय से की जा रही है।

ब्रेट जेम्स के बारे में

- करियर: ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायक और गीतकार; "जीसस टेक द व्हील" और "व्हेन द सन गोज़ डाउन" जैसे हिट गानों के लिए जाने जाते हैं।

- हॉल ऑफ़ फ़ेम: 2020 में नैशविले सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल।
- प्रारंभिक जीवन: संगीत सीखने के लिए मेडिकल स्कूल छोड़ दिया; 1995 में अपना पहला एकल एल्बम रिलीज़ किया।

उपलब्धियाँ:

- प्रमुख लेबलों के लिए 300 से ज्यादा गाने लिखे।
- 26 नंबर-वन सिंगल्स हासिल किए, पहला जेसिका एंड्रयूज़ का "हू आई एम" (2001) के साथ।
- "जीसस टेक द व्हील" ने ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ कंट्री सॉन्ग का पुरस्कार जीता।
- हालिया कार्य: 20 से ज्यादा वर्षों में अपना पहला स्व-लिखित एल्बम, "आई एम नाउ" रिलीज़ किया; महामारी के कारण स्थगन के कारण आधिकारिक हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल होने का कार्यक्रम 2021 में हुआ।

हॉलीवुड आइकॉन रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन



प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1936 में सांता मोनिका, कैलिफ़ोर्निया में जन्म।

करियर और उपलब्धियाँ

- अभिनय में पदार्पण: 1967 में जेन फोंडा के साथ बेयरफुट इन द पार्क से फ़िल्मी करियर की शुरुआत की।
- उल्लेखनीय भूमिकाएँ: बुच कैसिडी एंड द सनडांस किड (1969) में सनडांस किड की भूमिका निभाई, और द स्टिंग (1973) में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें अपना पहला ऑस्कर नामांकन मिला।
- करियर अवधि: छह दशकों से अधिक समय तक, रेडफोर्ड ने लगभग 50 फ़िल्मों का निर्माण किया।
- पुरस्कार: एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में योगदान और स्वतंत्र सिनेमा को प्रेरित करने के लिए 2002 में अकादमी मानद पुरस्कार प्राप्त किया।

स्वतंत्र सिनेमा में योगदान

- सनडांस फ़िल्म महोत्सव: सनडांस, यूटा में स्थापित, जिसका नाम उनके फ़िल्मी पात्र, द सनडांस किड के नाम पर रखा गया।
- अन्य पहल: स्वतंत्र फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सनडांस इंस्टीट्यूट, सनडांस सिनेमा, सनडांस कैटलॉग और सनडांस चैनल की स्थापना की।

- सेवानिवृत्ति: अपनी आखिरी फिल्म द ओल्ड मैन एंड द गन के बाद 2018 में अभिनय से संन्यास की घोषणा की।

बांग्लादेशी लोक गायिका फ़रीदा परवीन का 70 वर्ष की आयु में निधन



बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका और सांस्कृतिक हस्ती फ़रीदा परवीन का 70 वर्ष की आयु में गुर्दे की जटिलताओं से जूझते हुए निधन हो गया। उन्हें "लालन गीती की रानी" के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था, यह उपाधि बंगाली लोक संगीत की एक विधा, लालन गीतों के प्रचार में उनके अपार योगदान को दर्शाती है। योगदान: फ़रीदा परवीन बांग्लादेश की सबसे प्रमुख गायिकाओं में से एक थीं और उन्होंने लालन शाह के आध्यात्मिक और दार्शनिक गीतों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- लालन शाह: एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता, लालन शाह धार्मिक सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता और जाति-पाँति के भेदभाव को नकारने के अपने संदेशों के लिए जाने जाते हैं। उनके गीत पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।
- लालन गीती: लालन फ़कीर की शिक्षाओं और दर्शन पर आधारित लोक संगीत की एक शैली, जो मानवतावाद, समानता और आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण पर ज़ोर देती है।
- सांस्कृतिक महत्व: फ़रीदा परवीन के योगदान ने बांग्लादेश की लोक विरासत को संरक्षित और संवर्धित किया, जिससे लालन के गीत व्यापक श्रोताओं तक पहुँच सके।
- बांग्लादेश का संगीत परिदृश्य: लोक संगीत बांग्लादेश की सांस्कृतिक पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परवीन जैसे कलाकार परंपराओं की रक्षा में योगदान देते हैं।
- धार्मिक सद्भाव: लालन शाह का दर्शन विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों में एकता की वकालत करता है, शांति और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देता है।
- विरासत: फ़रीदा परवीन के कार्यों ने न केवल बांग्लादेश के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध किया, बल्कि बंगाली लोक संगीत की ओर वैश्विक ध्यान भी आकर्षित किया।

प्रतिष्ठित इतालवी फैशन डिज़ाइनर जियोर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन

विश्व प्रसिद्ध इतालवी फैशन डिज़ाइनर और अरबपति जियोर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अरमानी को मिलान के रेडी-टू-वियर फैशन के दिग्गज के रूप में जाना जाता

था, जिन्हें असंरचित, सुरुचिपूर्ण डिज़ाइनों के साथ वैश्विक फ़ैशन में क्रांति लाने के लिए जाना जाता था। उनकी कंपनी, अरमानी ग्रुप, कपड़ों के अलावा सौंदर्य, सुगंध, संगीत, खेल और लक़्ज़री होटलों के क्षेत्र में भी फैली, जिससे सालाना €2 बिलियन से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।



योगदान और उपलब्धियाँ

- फ़ैशन प्रभाव: न्यूनतम लेकिन परिष्कृत शैलियों को लोकप्रिय बनाकर वैश्विक फ़ैशन उद्योग को नया रूप देने का श्रेय।
- व्यावसायिक साम्राज्य: अरमानी ब्रांड इतालवी विलासिता का प्रतीक बन गया, और कई क्षेत्रों में विविधता आई।
- सांस्कृतिक प्रभाव: उनके डिज़ाइनों ने आधुनिक कॉपेरिट लुक को परिभाषित किया, खासकर हॉलीवुड और उच्च फ़ैशन जगत में।

जियोर्जियो अरमानी:

- जन्म: 11 जुलाई 1934, पियासेज़ा, इटली।
- 1975 में अपना लेबल अरमानी स्थापित किया।
- कुल संपत्ति: 6 अरब डॉलर से अधिक (2024 तक)।

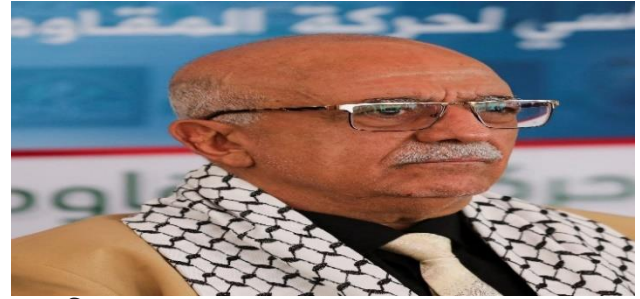
इतालवी फ़ैशन उद्योग:

इटली वर्साचे, प्रादा, गुच्ची, वेलेंटिनो जैसे लक़्ज़री फ़ैशन हाउस का घर है। मिलान, पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन के साथ-साथ वैश्विक फ़ैशन राजधानियों में से एक है।

हूती के प्रधानमंत्री अहमद अल-रहवी का निधन

ईरान समर्थित हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहवी यमन के सना में इज़राइली हवाई हमलों में मारे गए। इन हमलों में रक्षा मंत्री मोहम्मद अल-अतीफी और चीफ ऑफ़ स्टाफ़ मुहम्मद अब्द अल-करीम अल-गमारी सहित शीर्ष हूती सैन्य अधिकारियों को

भी निशाना बनाया गया। इज़राइली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने पुष्टि की है कि हूती-नियंत्रित क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया।



पृष्ठभूमि

गाज़ा संघर्ष के दौरान, हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीनियों के समर्थन में इज़राइल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इज़राइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सना स्थित राष्ट्रपति भवन सहित हूती सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अधिकारियों ने बताया कि नवीनतम हवाई हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत और 90 घायल हुए हैं।

क्षेत्रीय संदर्भ

ईरान के प्रतिरोध अक्ष का हिस्सा, हूती, 2014 में शुरू हुए गृहयुद्ध के बाद से यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। उन्होंने लाल सागर और अदन की खाड़ी में इज़राइली क्षेत्र और जहाजों को बार-बार निशाना बनाया है। मई 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए एक समझौते (ट्रम्प प्रशासन) का उद्देश्य नौवहन मार्गों पर हूती हमलों को रोकना था।

- यमन की राजधानी: सना
- हूती: ईरान समर्थित शिया विद्रोही समूह
- प्रतिरोध अक्ष: ईरान, हिज़्बुल्लाह (लेबनान), हूती (यमन), और इज़राइल/अमेरिकी प्रभाव का विरोध करने वाले अन्य समूह
- यमन गृहयुद्ध: 2014 में हूती और यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के प्रति वफादार बलों के बीच शुरू हुआ
- निकटवर्ती सामरिक जल: लाल सागर, अदन की खाड़ी, बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य - वैश्विक तेल नौवहन के लिए महत्वपूर्ण

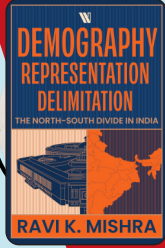
"सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है !
आप जो कर रहे हैं, उससे अगर आप प्यार करते हैं, तो आप ज़रूर सफल होंगे !!"

"किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए !
क्योंकि नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण बनती है !!

परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण दिन

दिवस	मनाया जाता है	थीम/महत्व
1 अक्टूबर	वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	बुजुर्ग लोग स्थानीय और वैश्विक स्तर पर कार्यवाई को आगे बढ़ा रहे हैं: हमारी आकांक्षाएं, हमारा कल्याण, हमारे अधिकार
2 अक्टूबर	अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस	भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता महात्मा गांधी की जयंती मनाने हेतु
4 अक्टूबर	विश्व पशु कल्याण दिवस	इस दिन की शुरुआत 1931 में लुप्तप्राय प्रजातियों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए की गई थी।
5 अक्टूबर	विश्व शिक्षक दिवस	शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना: शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर
8 अक्टूबर	भारतीय वायु सेना दिवस	8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायु सेना की स्थापना को चिह्नित करने हेतु
9 अक्टूबर	विश्व डाक दिवस	1874 में स्विट्स राजधानी, बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना को चिह्नित करने हेतु
10 अक्टूबर	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस	दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना
11 अक्टूबर	अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस	लड़कियों की जरूरतों और चुनौतियों को उजागर करना एवं उनके समाधान करने हेतु
12 अक्टूबर	विश्व गठिया दिवस	गठिया के बढ़ते प्रसार के प्रति जागरूकता लाना
13 अक्टूबर	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस	इस बारे में जागरूकता बढ़ाना कि लोग आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए कैसे कार्यवाई कर सकते हैं
14 अक्टूबर	विश्व मानक दिवस	बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण
15 अक्टूबर	विश्व विद्यार्थी दिवस	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती मनाने हेतु
16 अक्टूबर	विश्व खाद्य दिवस	बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ-से-हाथ मिलाना
17 अक्टूबर	अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस	गरीबी में रहने वाले लोगों के प्रयास और संघर्ष की सराहना करना
20 अक्टूबर	विश्व सांख्यिकी दिवस	सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण आँकड़ों और डेटा के माध्यम से बदलाव लाना
24 अक्टूबर	संयुक्त राष्ट्र दिवस	संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को चिह्नित करने के लिए जो आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया।
31 अक्टूबर	राष्ट्रीय एकता दिवस	सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने के लिए जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है।

पुस्तकें एवं लेखक



पुस्तक: डेमोग्राफी, रिप्रजेंटेशन, डीलिटमिंटेशन: द नार्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया

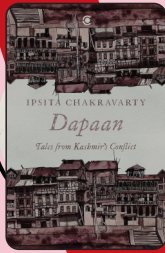
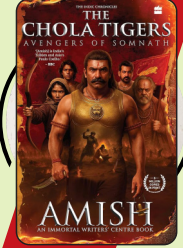
लेखक: रवि के मिश्रा

बारे में: यह पुस्तक लोकसभा क्षेत्र के परिसीमन से जुड़े विवादों पर चर्चा करती है, जिसमें उत्तर और दक्षिण भारत के बीच क्षेत्रीय पहचान, प्रतिनिधित्व संबंधी विवाद और जनसंख्या नियंत्रण पर बहस जैसे मुद्दे शामिल हैं।

पुस्तक: द चोला टाइगर्स: अवेंजर्स ऑफ़ सोमनाथ

लेखक: अमिष त्रिपाठी

बारे में: यह पुस्तक चोल राजवंश की दुनिया में एक झलक दिखाती है, जिसमें सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले का ऐतिहासिक बदला लेने की कहानी मुख्य रूप से है, यह घटना भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी।



पुस्तक: दापान: टेलस फ्रॉम कश्मीर कनफ्लिक्ट

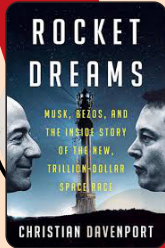
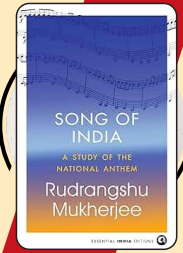
लेखक: इप्सिता चक्रवर्ती

बारे में: यह पुस्तक दशकों तक चले संघर्ष, सरकारी निगरानी और चुपचाप विरोध के कारण कश्मीर की ज़िंदगी में आए बदलावों का चित्रण करती है।

पुस्तक: सॉन्ग ऑफ़ इंडिया: अ स्टडी ऑफ़ द नेशनल एथम

लेखक: रुद्रानशु मुखर्जी

बारे में: यह पुस्तक भारत के राष्ट्रगान का विश्लेषण करती है। इसमें राष्ट्रगान का इतिहास, टैगोर का दृष्टिकोण, सांस्कृतिक महत्व और देशभक्ति, एकता तथा पहचान जैसे विषयों पर बहस शामिल है, जो राष्ट्र की सामूहिक भावना और गर्व को आकार देते हैं।



पुस्तक: रॉकेट ड्रीम्स

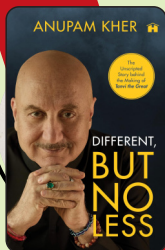
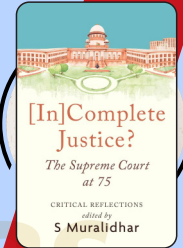
लेखक: क्रिश्चियन डेवेनपोर्ट

बारे में: यह पुस्तक बताती है कि आज की अंतरिक्ष दौड़ अहंकार, महत्वाकांक्षा और अरबपतियों के बीच प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित है, न कि खोज की भावना से, जो कभी नासा के स्वर्ण युग की पहचान थी।

पुस्तक: [इन] कम्पलीट जस्टिस? द सुप्रीम कोर्ट ऐट 75, क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस

लेखक: जस्टिस एस मुरलीधर

बारे में: यह पुस्तक सुप्रीम कोर्ट के 75 साल के इतिहास की आलोचना करती है, जिसमें भारत के लोकतंत्र में न्याय के लिए महत्वपूर्ण फैसलों, संविधान की व्याख्या और लगातार सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान दिया गया है।



पुस्तक: डिफरेंट बट नो लेस

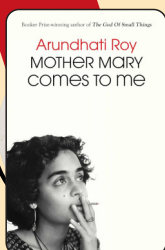
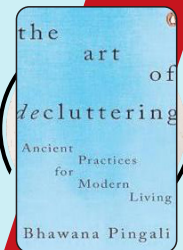
लेखक: अनुपम खेर

बारे में: यह पुस्तक लेखक के जीवन के अनुभवों और उनकी रचनात्मक यात्रा से जुड़ी एक भावपूर्ण कहानी होने का वादा करती है।

पुस्तक: द आर्ट ऑफ़ डीक्लटरिंग, इंडियन स्टाइल

लेखक: भावना पिंगली

बारे में: यह पुस्तक उन पुरानी प्रथाओं पर प्रकाश डालती है जो बताती हैं कि भारतीय घर कभी कैसे स्थिरता और संतुलन का प्रतीक थे।



पुस्तक: मदर मेरी कम टू मी

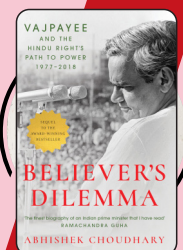
लेखक: अरुंधति रॉय

बारे में: यह पुस्तक लेखिका और उनकी माँ मेरी रॉय के बीच आजीवन चले मधुर रिश्ते की एक निजी कहानी है। मेरी रॉय एक महान शिक्षिका और महिलाओं के अधिकारों की प्रबल समर्थक थीं।

पुस्तक: बिलीवर'स डिलेमा

लेखक: अमिषेक चौधरी

बारे में: यह पुस्तक आस्था और तर्क के बीच के टकराव को दर्शाती है, और इसमें आधुनिक भारत में आस्था, संदेह और पहचान से जुड़ी व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों को दिखाया गया है।



अभ्यास हेतु प्रश्न बैंक

1. एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया का सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी, वाकिटा पॉरपाइज़, मेक्सिको के कैलिफ़ोर्निया की खाड़ी (कोर्टेज़ सागर) में केवल लगभग 10 ही बचे हैं। समुद्री स्तनधारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

- (1) डॉल्फ़िन डेल्फ़िनिडे परिवार और सीटेशिया गण से संबंधित हैं।
(2) ब्लू व्हेल बालेनोप्टेरिडे परिवार से संबंधित हैं और पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवर हैं।
(3) डुगोंग मस्टेलिडे परिवार और कार्निवोरा गण से संबंधित हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1 सही है -

डॉल्फ़िन डेल्फ़िनिडे परिवार से संबंधित हैं, जिसमें समुद्री डॉल्फ़िन शामिल हैं, और सीटेशिया गण का हिस्सा हैं, जिसमें सभी व्हेल, डॉल्फ़िन और पॉरपाइज़ शामिल हैं। गर्म रक्त वाले स्तनधारी होने के कारण, वे जीवित जन्म देते हैं और अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं।

कथन 2 सही है -

ब्लू व्हेल बालेनोप्टेरिडे परिवार से संबंधित हैं, जिन्हें रॉकल भी कहा जाता है, और ये पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवर हैं, जिनकी लंबाई 30 मीटर से अधिक और वजन 150 टन से अधिक होता है। ये फ़िल्टर फ़ीडर हैं, मुख्य रूप से क्रिल खाते हैं।

कथन 3 गलत है -

डुगोंग डुगोंगिडे परिवार और सिरिनिया गण से संबंधित हैं, न कि मस्टेलिडे (जिसमें नेवले और ऊदबिलाव शामिल हैं) या कार्निवोरा से। डुगोंग शाकाहारी समुद्री स्तनधारी हैं जो समुद्री घास खाते हैं, जो उन्हें तटीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख प्रजाति बनाता है।

2. संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में आधिकारिक तौर पर अकाल की घोषणा की है, जो पश्चिम एशिया में पहला अकाल है। गाजा पट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

- (1) गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे एक संकरा तटीय क्षेत्र है।
(2) इसकी सीमा पूर्व में इज़राइल और दक्षिण-पश्चिम में मिस्र से लगती है।
(3) गाजा पट्टी का प्रशासन हमास द्वारा किया जाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे फिलिस्तीनी क्षेत्रों का हिस्सा माना जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1 सही है -

गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे एक घनी आबादी वाला, संकरा क्षेत्र (लगभग 41 किमी लंबा और 6-12 किमी चौड़ा) है, जो इसे व्यापार, पहुँच और समुद्री संसाधनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।

कथन 2 सही है -

इसकी सीमा पूर्व और उत्तर में इज़राइल और दक्षिण-पश्चिम में मिस्र से लगती है, जिसका सुरक्षा, प्रवास और क्षेत्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ता है।

कथन 3 गलत है -

हालाँकि हमास का वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण है, गाजा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है; यह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत फिलिस्तीनी क्षेत्रों का हिस्सा बना हुआ है, जो जटिल शासन और विवादित संप्रभुता के मुद्दों को उजागर करता है।

3. वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में दुर्लभ चतुर्भुज तारा प्रणाली की खोज की है।

आकाशगंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- (1) आकाशगंगा एक अवरुद्ध सर्पिल आकाशगंगा है जिसमें एक केंद्रीय उभार और कई सर्पिल भुजाएँ हैं।
(2) सौरमंडल, आकाशगंगा के गांगेय केंद्र के पास स्थित है।
(3) आकाशगंगा स्थानीय आकाशगंगा समूह का हिस्सा है, जिसमें एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम आकाशगंगाएँ शामिल हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1 सही है - आकाशगंगा को एक पट्टीदार सर्पिल आकाशगंगा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि इसके केंद्र में तारों की एक केंद्रीय पट्टी फैली हुई है। इस पट्टी के चारों ओर तारों, गैस और धूल से बनी सर्पिल भुजाएँ हैं, जो सक्रिय तारा निर्माण के स्थल हैं। केंद्रीय उभार में पुराने तारे हैं, जबकि डिस्क और भुजाओं में युवा और वृद्ध तारों का मिश्रण है।

कथन 2 गलत है - सौरमंडल ओरियन आर्म (या ओरियन स्पिर) में स्थित है, जो आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर, केंद्रीय उभार से दूर है। यह स्थान इसे अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र में रखता है, जो केंद्र के पास उच्च विकिरण और घनी तारा गतिविधि से सुरक्षित है।

कथन 3 सही है - आकाशगंगा स्थानीय समूह से संबंधित है, जो 50 से अधिक आकाशगंगाओं का एक समूह है। इसके दो सबसे बड़े पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा (M31) और त्रिकोणीय आकाशगंगा (M33) हैं। इस समूह के भीतर गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाएँ इन आकाशगंगाओं की गति और विकास को प्रभावित करती हैं।

4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने परियोजना आरोहण शुरू की है। NHAI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- (1) NHAI का गठन NHAI अधिनियम, 1988 के तहत किया गया था और यह 1995 में चालू हुआ।
 - (2) इसका कार्य राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, दोनों का विकास और प्रबंधन करना है।
 - (3) NHAI, NHDP और भारतमाला परियोजना जैसी योजनाओं के तहत राजमार्ग परियोजनाओं का क्रियान्वयन करता है।
- उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1: सही

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की स्थापना संसद के एक अधिनियम, NHAI अधिनियम, 1988 द्वारा की गई थी।

हालाँकि, यह अधिनियम 1988 में पारित होने के बावजूद, NHAI फरवरी 1995 में ही चालू हुआ।

यह अंतराल इसके संचालन शुरू करने से पहले आवश्यक प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं के कारण था।

परीक्षा की तरकीब: छात्र अक्सर 1988 (अधिनियम पारित) और 1995 (कार्य प्रारंभ) के बीच भ्रमित हो जाते हैं।

कथन 2: गलत

NHAI केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ज़िम्मेदार है, राज्य राजमार्गों के लिए नहीं।

राज्य राजमार्ग संबंधित राज्य सरकारों/लोक निर्माण विभागों (PWD) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

यह कथन भ्रमित करने के लिए बनाया गया है क्योंकि छात्र सोच सकते हैं कि "राजमार्ग" में आम तौर पर दोनों शामिल होते हैं, लेकिन अधिदेश पूरी तरह से राष्ट्रीय राजमार्गों का है।

कथन 3: सही

एनएचआई निम्नलिखित के लिए मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी रही है:

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी): 1998 में शुरू की गई, स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारों पर केंद्रित।

भारतमाला परियोजना (2017 से): सीमावर्ती सड़कों, तटीय सड़कों, आर्थिक गलियारों, फीडर मार्गों आदि को कवर करने वाला एक अधिक व्यापक कार्यक्रम।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सशस्त्र बलों के लिए 3 संयुक्त सिद्धांत जारी किए।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- (1) सीडीएस का पद 2019 में कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था।
- (2) सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
- (3) सीडीएस तीनों सशस्त्र बलों का समग्र परिचालन कमांडर होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1: सही

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद दिसंबर 2019 में सृजित किया गया था।

यह कारगिल समीक्षा समिति (1999) और बाद में नरेश चंद्र समिति (2012) की सिफारिशों पर आधारित था।

कारगिल युद्ध के बाद तीनों सेनाओं (थलसेना, नौसेना, वायुसेना) के बीच बेहतर एकजुटता और समन्वय की आवश्यकता महसूस की गई।

कथन 2: सही

सीडीएस, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीओएससी) के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

पहले, सीओएससी की अध्यक्षता तीनों सेना प्रमुखों के बीच घूमती रहती थी, जिससे असंगति होती थी।

अब, सीडीएस निरंतरता और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना सुनिश्चित करता है।

कथन 3: गलत

सीडीएस सशस्त्र बलों का समग्र परिचालन कमांडर नहीं है।

प्रत्येक सेवा प्रमुख (थलसेना, नौसेना, वायुसेना) अपने-अपने बलों पर परिचालन कमान का प्रयोग जारी रखते हैं।

सीडीएस की भूमिका मुख्य रूप से निम्नलिखित है:

रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करना, प्रशिक्षण, रसद, खरीद में संयुक्तता को बढ़ावा देना, रक्षा मंत्रालय में नवगठित सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) का नेतृत्व करना।

यह एक आम परीक्षा जाल है, क्योंकि कई छात्र मानते हैं कि सीडीएस एक "सर्वोच्च कमांडर" की तरह है, जो गलत है।

6. समुद्रयान परियोजना की तैयारियों के तहत दो भारतीय जलयानों ने फ्रांस के पनडुब्बी नॉटाइल पर सवार होकर अटलांटिक महासागर में गोता लगाया। अटलांटिक महासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(1) मध्य-अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर की लगभग पूरी लंबाई में फैली एक अपसारी प्लेट सीमा है।

(2) अमेज़न नदी, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है, जल-निकासी मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है।

(3) सार्गासो सागर, जो अपने तैरते समुद्री शैवाल के लिए विशिष्ट है, चारों ओर से भूभागों से घिरा है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)

(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1: सही

मध्य-अटलांटिक कटक एक अपसारी प्लेट सीमा है जहाँ यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेटें (उत्तर में) और अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी प्लेटें (दक्षिण में) अलग हो रही हैं।

यह अटलांटिक महासागर से होकर उत्तर-दक्षिण दिशा में लगभग अपनी पूरी लंबाई तक बहती है।

कथन 2: सही

अमेज़न नदी अटलांटिक महासागर में बहती है।

यह जल की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, हालाँकि नील नदी लंबाई में इससे बड़ी है।

कथन 3: गलत

सार्गासो सागर अद्वितीय है क्योंकि यह भूभागों से घिरा नहीं है।

इसके बजाय, यह महासागरीय धाराओं (उत्तरी अटलांटिक चक्र: गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा, कैनरी धारा और उत्तरी अटलांटिक भूमध्यरेखीय धारा) द्वारा परिभाषित है।

इसकी सीमाएँ पूरी तरह से महासागरीय हैं, जो इसे भूमध्य सागर या बाल्टिक जैसे समुद्रों से अलग बनाती हैं।

7. हाल ही में, मंगा अनुकूलन 'ड्रॉप्स ऑफ गॉड' ने अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीत लिया

एमी पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

(1) 1948 में कल्पना की गई, उद्घाटन एमी पुरस्कार समारोह 25 जनवरी, 1949 को हुआ।

(2) प्राची देसाई अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता बनीं।

(3) पुरस्कारों का चयन टेलीविजन कला एवं विज्ञान अकादमी द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)

उत्तर:

व्याख्या: 1948 में कल्पना की गई, उद्घाटन एमी पुरस्कार समारोह 25 जनवरी, 1949 को हुआ।

सर्वाधिक उत्कृष्ट टेलीविजन व्यक्तित्व और सर्वाधिक लोकप्रिय टेलीविजन कार्यक्रम की मान्यता सहित छह पुरस्कार प्रदान किए गए।

निर्माता और फिल्म निर्माता एकता कपूर अंतर्राष्ट्रीय एमी निदेशालय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता बनीं, जो अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है।

एमी पुरस्कार अमेरिकी प्राइम टाइम टीवी कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ का सम्मान करने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है।

पुरस्कारों का चयन टेलीविजन कला एवं विज्ञान अकादमी द्वारा किया जाता है।

8.

हाल ही में, यूआईडीआई ने खुलासा किया है कि आधार प्रमाणीकरण सेवाओं में महत्वपूर्ण रुकावट आई थी।

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

(1) यूआईडीआई गृह मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।

(2) यूआईडीआई आधार नामांकन और प्रमाणीकरण और पहचान जानकारी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

(3) आधार नंबर पहचान का प्रमाण है जो किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार नहीं देता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)

(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर:

व्याख्या: वैधानिक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पहले, यूआईडीआई तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था।

आधार अधिनियम 2016 के तहत, यूआईडीआई आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार है, जिसमें आधार जीवन चक्र के सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन, व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने और प्रमाणीकरण करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है।

व्यक्तियों की पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड। नामांकन के लिए सामान्य प्रक्रिया रजिस्ट्रारों की ओर से काम करने वाली नामांकन एजेंसियों द्वारा संचालित की जाती है। किसी निवासी का नामांकन करने के लिए ईए द्वारा नामांकन के निम्नलिखित तीन तरीकों में से एक को अपनाया जा सकता है।

परिचयकर्ता आधारित नामांकन वैध पहचान प्रमाण (पीओआई) और पते का वैध प्रमाण (पीओए) के अभाव में, परिचयकर्ता की सेवा का लाभ उठाया जा सकता है।

परिचयकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसे रजिस्ट्रार या

प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पहचाना और अधिसूचित किया जाता है और उसके पास वैध आधार संख्या होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र और लिंग का हो, जो भारत का निवासी है, आधार संख्या प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से नामांकन कर सकता है। यहां निवासी का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के बारह महीनों में एक सौ बयासी दिन या उससे अधिक की अवधि या अवधि के लिए भारत में रहा हो। आधार संख्या पहचान का प्रमाण है, हालाँकि, यह आधार संख्या धारक के संबंध में नागरिकता या अधिवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

9. हाल ही में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एयर इंडिया की धमकी पर एक खालिस्तानी आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के संस्थापक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

(1) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भारत में आतंक से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय एजेंसी है।

(2) एजेंसी को राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने का अधिकार है।

(3) कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार से किसी मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध कर सकती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)

(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से सभी

उत्तर: (D)

व्याख्या: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भारत में आतंक से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक केंद्रीय एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी को राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने का अधिकार है।

एजेंसी को एनआईए अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच और अभियोजन चलाने का अधिकार दिया गया है। कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार से किसी मामले की जांच एनआईए को सौंपने का अनुरोध कर सकती है, बशर्ते मामला एनआईए अधिनियम की अनुसूची में शामिल अपराधों के लिए दर्ज किया गया हो।

केंद्र सरकार एनआईए को भारत में कहीं भी किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश भी दे सकती है। एनआईए के अधिकारी जो भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राज्य पुलिस, आयकर के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों

से लिए जाते हैं, उनके पास सभी शक्तियां, विशेषाधिकार और देनदारियां होती हैं जो पुलिस अधिकारियों के पास जांच के संबंध में होती हैं।

10.

भारतीय सशस्त्र बल के जवान मिस्र में आयोजित हो रहे अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 के 19वें संस्करण में भाग ले रहे हैं।

बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में भारत की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(1) मालाबार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है।

(2) मिलान इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और भारत द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।

(3) आईबीएसएएमएआर भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)

(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर:

व्याख्या: कथन 1: सही। मालाबार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख नौसैनिक अभ्यास है। यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक अंतर-संचालन और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित है।

कथन 2: गलत। मिलान भारत द्वारा (पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में) आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, न कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका या थाईलैंड द्वारा। ये देश भाग लेने वाले राष्ट्र हैं, लेकिन भारत प्रमुख मेजबान है। मिलान क्षेत्रीय सहयोग और नौसैनिक सहभागिता को बढ़ावा देता है।

कथन 3: सही। आईबीएसएएमएआर भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में आपसी समझ, परिचालन समन्वय और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है।

11.

आईआईटी इंदौर और आईसीआईएमओडी (नेपाल) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर में जलवायु परिवर्तन के कारण 1980-2020 तक 10% बर्फ पिघल गई है।

गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) गंगोत्री ग्लेशियर एक मिश्रित घाटी ग्लेशियर है जो रक्तवर्ण, चतुरंगी और स्वच्छंद जैसी सहायक नदियों से पोषित होता है।

(2) यह ग्लेशियर चौखंबा पर्वतमाला के दक्षिणी ढलानों से निकलता है।

(3) भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है और बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनाती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1: सही। गंगोत्री ग्लेशियर एक मिश्रित घाटी ग्लेशियर है, जिसका अर्थ है कि यह कई छोटी सहायक नदियों के मिलने से बना है। प्रमुख सहायक नदियों में रक्तवर्ण, चतुरंगी और स्वच्छंद शामिल हैं, जो ग्लेशियर के द्रव्यमान और प्रवाह में योगदान करती हैं।

कथन 2: गलत। यह ग्लेशियर चौखंबा पर्वतमाला के उत्तरी ढलानों से निकलता है, दक्षिणी ढलानों से नहीं। यह एक सामान्य भ्रम की स्थिति है, क्योंकि कई हिमालयी ग्लेशियरों के दोनों ओर ढलान होते हैं, लेकिन गंगोत्री का संचयन क्षेत्र उत्तरी दिशा में है।

कथन 3: सही। भागीरथी नदी गौमुख नामक ग्लेशियर से निकलती है, जो ग्लेशियर का एक प्रमुख अग्रभाग है। यह बाद में देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर भारत की प्रमुख नदी गंगा का निर्माण करती है। यह गंगोत्री ग्लेशियर को गंगा नदी बेसिन के जल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण बनाता है।

अतिरिक्त संदर्भ:

गंगोत्री ग्लेशियर लगभग 30 किमी लंबा है और भारतीय हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है।

इसका जलवायु और पर्यावरणीय महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह बारहमासी नदियों को पोषण प्रदान करता है जो उत्तर भारत में कृषि, जलविद्युत और पेयजल का समर्थन करती हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पीछे हटने (1980-2020 तक 10% हिम पिघलने से हुई हानि) ने गंगा बेसिन में भविष्य की जल सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

12. नोबेल पुरस्कार विजेता एडम रीस द्वारा सह-लिखित IUCAA का एक नया अध्ययन, ऑक्सीजन-समृद्ध मीरा परिवर्तनशील तारों का उपयोग करके हबल स्थिरांक को 3.7% सटीकता से मापता है।

हबल स्थिरांक (H_0) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) इसे एडविन हबल ने 1929 में ब्रह्मांड के विस्तार की दर मापने के लिए तैयार किया था।

(2) H_0 को किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक (km/s/Mpc) में व्यक्त किया जाता है।

(3) यह दर्शाता है कि हमारे निकट की आकाशगंगाएँ दूर की आकाशगंगाओं की तुलना में तेज़ गति से चलती हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1: सही। एडविन हबल (1929) ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और उन्होंने आकाशगंगाओं के

अलग होने की दर को मापने के लिए हबल स्थिरांक (H_0) का सूत्रीकरण किया।

कथन 2: सही। हबल स्थिरांक को किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक (km/s/Mpc) में व्यक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक मेगापार्सेक (लगभग 3.26 मिलियन प्रकाश वर्ष) की दूरी पर, एक आकाशगंगा हमसे एक निश्चित वेग (km/s) से दूर जाती है।

कथन 3: गलत। हबल का नियम कहता है कि दूर स्थित आकाशगंगाएँ तेज़ी से चलती हैं, न कि पास स्थित आकाशगंगाएँ। यह संबंध रेडशिफ्ट के माध्यम से देखा जाता है, जो अंतरिक्ष के विस्तार के कारण स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर प्रकाश का विस्थापन है।

अफ़गानिस्तान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया।

अफ़गानिस्तान और उसके आसपास भूकंपीय गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) हिंदू कुश क्षेत्र अल्पाइड बेल्ट का हिस्सा है, जो प्रशांत महासागरीय बेल्ट के बाद दूसरा सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है।

(2) सुलेमान पर्वतमाला भारतीय प्लेट के अवतलन के कारण बार-बार आने वाले गहरे केंद्र वाले भूकंपों के लिए जानी जाती है।

(3) चमन फॉल्ट और मेन पामीर थ्रस्ट जैसे भ्रंश अफ़गानिस्तान में भूकंपीय गतिविधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)

- (C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1 सही:

हिंदू कुश क्षेत्र अल्पाइड बेल्ट का एक हिस्सा है, जो दक्षिणी यूरोप से मध्य पूर्व होते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के परिक्षेत्र बेल्ट ("रिंग ऑफ़ फायर") के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय बेल्ट है। इस क्षेत्र में उथले और गहरे-केंद्रित दोनों प्रकार के भूकंप आते हैं, जो मुख्यतः यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के स्थलमंडल के अवतलन और तीव्र धंसाव के कारण होता है। ऐतिहासिक रूप से, 1900 से, हिंदू कुश ने 7 या उससे अधिक तीव्रता के 12 भूकंप देखे हैं, जो इसके उच्च भूकंपीय खतरे को दर्शाते हैं।

कथन 2 गलत:

दक्षिण-पूर्वी अफ़गानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित सुलेमान पर्वतमाला मुख्य रूप से उथले, विनाशकारी भूकंपों, विशेष रूप से अभिसारी सीमाओं पर थ्रस्ट-फॉल्ट प्रकार की घटनाओं, के लिए प्रवण है। हिंदू कुश के विपरीत, जहाँ उथले और गहरे दोनों प्रकार के भूकंप आते हैं, यहाँ गहरे-केंद्रित भूकंप आम नहीं हैं।

कथन 3 सही:

अफ़गानिस्तान में प्रमुख सक्रिय भ्रंश प्रणालियाँ, जिनमें चमन भ्रंश (एक प्रमुख स्ट्राइक-स्लिप भ्रंश) और मुख्य पामीर थ्रस्ट (या पामीर फ्रंटल थ्रस्ट) शामिल हैं, भूकंपीय गतिविधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। चमन भ्रंश भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर गति को समायोजित करता है, जबकि पामीर थ्रस्ट अभिसारी सीमा के साथ संपीडन बलों से जुड़ा है। ये भ्रंश इस क्षेत्र को विनाशकारी भूकंपों के लिए प्रवण बनाते हैं।

14. भारत के प्रधानमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं बैठक में भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- (1) भारत 2017 में पाकिस्तान के साथ SCO का पूर्ण सदस्य बना।
 - (2) SCO सचिवालय शंघाई, चीन में स्थित है।
 - (3) SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे (RATS) का मुख्यालय ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में है।
- उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1 – सही:

भारत और पाकिस्तान को 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन (कज़ाकिस्तान) में SCO की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी। इससे पहले, दोनों "पर्यवेक्षक" थे।

कथन 2 – गलत:

SCO सचिवालय बीजिंग, चीन में है, शंघाई में नहीं। "शंघाई सहयोग संगठन" नाम अक्सर भ्रम पैदा करता है, लेकिन इसका मुख्यालय बीजिंग में है।

कथन 3 – सही:

क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) SCO का एक स्थायी अंग है, जिसकी स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए की गई है। इसका मुख्यालय ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में है।

15. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन ट्रेडिंग को लागू करने के लिए एनडीए की स्थापना की है। भारत और पेरिस समझौते के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- (1) भारत ने पेरिस समझौते के अपने वादों के तहत 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है।
 - (2) भारत ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस समझौते का अनुसमर्थन किया।

(3) अपने एनडीसी के तहत, भारत ने 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33-35% तक कम करने का संकल्प लिया।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: कथन 1 – सही:

भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस समझौते का अनुसमर्थन किया, जो महात्मा गांधी की जयंती के साथ मेल खाने के लिए चुनी गई एक प्रतीकात्मक तिथि थी, जो सतत जीवन के सिद्धांत पर प्रकाश डालती है।

कथन 2 – गलत:

भारत की 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की घोषणा COP26 (ग्लासगो, 2021) में की गई थी, न कि उसके मूल पेरिस समझौते के वादों (2015-2016) के हिस्से के रूप में। पेरिस समझौते के तहत देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) जमा करने की आवश्यकता थी, लेकिन "शुद्ध शून्य" भारत के प्रारंभिक NDC का हिस्सा नहीं था।

कथन 3 – सही:

अपने पहले NDC (2015) में, भारत ने प्रतिज्ञा की थी:

2005 के स्तर से 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33-35% तक कम करना।

2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से लगभग 40% संचयी विद्युत ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना (बाद में 2030 तक 50% तक अद्यतन किया गया)।

परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें:

अनुमोदन तिथि: 2 अक्टूबर 2016 (महात्मा गांधी जयंती)। मूल एनडीसी (2015): उत्सर्जन तीव्रता में 33-35% की कमी, गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता में 40% की वृद्धि, वन क्षेत्र में वृद्धि।

नेट जीरो 2070: बाद में COP26 में घोषित, पेरिस समझौते के वादों के अंतर्गत नहीं।

16. कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई। कॉलेजियम प्रणाली के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- (1) प्रथम न्यायाधीश मामले (1981) में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका पर न्यायपालिका को प्राथमिकता दी।
 - (2) द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) में, न्यायालय ने "परामर्श" की व्याख्या "सहमति" के रूप में की और मुख्य न्यायाधीश की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया।

(3) तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) में, कॉलेजियम का विस्तार करके इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल किया गया।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: कथन 1: प्रथम न्यायाधीश वाद (1981)

वाद: एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981)।

न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 124 और 217 में "परामर्श" शब्द का अर्थ सहमति नहीं है।

इसका अर्थ था कि न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका (राष्ट्रपति/सरकार) को प्राथमिकता प्राप्त है, न्यायपालिका को नहीं।

कथन 2: द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993)

वाद: सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993)।

न्यायालय ने 1981 के फैसले को खारिज कर दिया और न्यायपालिका को प्राथमिकता दी।

न्यायालय ने माना कि "परामर्श" का वास्तव में अर्थ सहमति है, अर्थात्, मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है।

हालाँकि, मुख्य न्यायाधीश को सलाह देने से पहले अपने दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए।

कथन 3: तृतीय न्यायाधीश वाद (1998)

वाद: अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति का संदर्भ (1998)। न्यायालय ने कॉलेजियम का विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित को शामिल किया:

मुख्य न्यायाधीश + सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश।

इसने इस प्रणाली को और मज़बूत किया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों के लिए 5 न्यायाधीशों का कॉलेजियम बन गया।

17. 56वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ जीएसटी 2.0 का अनावरण किया। जीएसटी के लाभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- (1) जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है, जो वस्तुओं/सेवाओं के उपभोग के स्थान पर वसूला जाता है।
(2) जीएसटी के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को निर्यात और आपूर्ति को शून्य-रेटेड माना जाता है।
(3) जीएसटी ने कर प्रणाली में पारदर्शिता को कम किया है और सरकारी राजस्व में कमी की है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1: जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है

इसका अर्थ है कि कर राजस्व उस राज्य को जाता है जहाँ वस्तुओं/सेवाओं का उपभोग किया जाता है, न कि जहाँ उनका उत्पादन होता है।

उदाहरण: यदि गुजरात की कोई कंपनी महाराष्ट्र को माल बेचती है, तो जीएसटी राजस्व महाराष्ट्र (उपभोक्ता राज्य) को जाता है, न कि गुजरात (उत्पादक राज्य) को।

इससे कर का व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता और राज्यों के बीच जीएसटी अधिक न्यायसंगत हो जाता है।

कथन 2: निर्यात और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की आपूर्ति शून्य-दर वाली है

जीएसटी के तहत, निर्यात और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की आपूर्ति पर 0% (शून्य-दर वाली) कर लगता है।

निर्यातक भुगतान किए गए इनपुट करों की वापसी का दावा कर सकते हैं, जिससे भारतीय वस्तुएँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाती हैं।

उदाहरण: यदि कोई कपड़ा निर्यातक कच्चे माल पर जीएसटी का भुगतान करता है, तो वह अंतिम उत्पाद के निर्यात पर पूर्ण वापसी का दावा कर सकता है।

कथन 3: जीएसटी ने पारदर्शिता को कम किया है और राजस्व को कम किया है

वास्तव में, ऑनलाइन फाइलिंग, जीएसटीएन पोर्टल और इनवॉइस-मिलान के कारण जीएसटी ने पारदर्शिता बढ़ाई है।

इसने कर आधार का विस्तार किया है, कर चोरी को कम किया है और सरकारी राजस्व में वृद्धि की है।

उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 में, जीएसटी ने ₹22.08 लाख करोड़ का अपना अब तक का उच्चतम संग्रह दर्ज किया, जो दर्शाता है कि राजस्व वास्तव में बढ़ा है।

18.

अन्नामलाई टाइगर रिजर्व (एटीआर) में तमिलनाडु वन विभाग के एक अध्ययन में आठ जुगनू प्रजातियों की पहचान की गई है, जो पारिस्थितिक संकेतक के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करती हैं।

अन्नामलाई टाइगर रिजर्व (एटीआर) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- (1) एटीआर पश्चिमी घाट में स्थित है, जो तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है।
(2) इसे मूल रूप से इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था।
(3) यह रिजर्व पश्चिमी घाट के अंतर्गत एक अधिसूचित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1: एटीआर पश्चिमी घाट में स्थित है, जो तमिलनाडु और केरल में फैला है।

एटीआर पश्चिमी घाट में स्थित है, जो एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है।

यह पूरी तरह से तमिलनाडु (कोयंबटूर और तिरुनेलवेली जिले) में स्थित है, लेकिन इसके जंगल केरल के परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व से सटे हुए हैं।

इसलिए, एटीआर केरल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि पारिस्थितिक रूप से जुड़ा हुआ है।

उदाहरण के लिए: ध्यान से देखें - एटीआर तमिलनाडु में स्थित है, जो केरल के रिजर्व से सटा हुआ है।

कथन 2: इसे मूल रूप से इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था।

एटीआर को पहले इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान (आईजीडब्ल्यूएलएस और एनपी) कहा जाता था।

2008 में, इसे एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और इसका नाम बदलकर अनामलाई टाइगर रिजर्व कर दिया गया।

परीक्षा के लिए: दोनों नाम एक साथ आ सकते हैं, इसलिए छात्रों को याद रखना चाहिए कि आईजीडब्ल्यूएलएस और एनपी = एटीआर।

कथन 3: यह अभयारण्य पश्चिमी घाट के अंतर्गत एक अधिसूचित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

पश्चिमी घाट (साइलेंट वैली, पेरियार और अन्य जैसे कुछ संरक्षित क्षेत्रों सहित) यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।

एटीआर को व्यक्तिगत रूप से यूनेस्को स्थल के रूप में नामित नहीं किया गया है।

19. पहला प्रशिक्षण स्काड्रन (आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस सारथी) प्रशिक्षण तैनाती के लिए सेशेल्स (पोर्ट विक्टोरिया) पहुँच गया।

सेशेल्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(1) सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित 155 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है।

(2) यह भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है।

(3) माहे सेशेल्स द्वीपसमूह का सबसे बड़ा और सबसे विविध द्वीप है।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)

(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1 सही है -

सेशेल्स वास्तव में 155 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है जो पश्चिमी हिंद महासागर में, मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व में और अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है।

कथन 2 गलत है -

सेशेल्स भूमि क्षेत्रफल (459 वर्ग किमी) और जनसंख्या (लगभग 1 लाख) दोनों के संदर्भ में सबसे बड़ा नहीं बल्कि वास्तव में सबसे छोटा अफ्रीकी राष्ट्र है।

कथन 3 सही है -

माहे सबसे बड़ा और सबसे विविध द्वीप है, जहाँ लगभग 90% आबादी रहती है और राजधानी विक्टोरिया, साथ ही मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है।

आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025, 1 सितंबर 2025 को लागू हुआ।

विभिन्न देशों में आव्रजन और सुरक्षा उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

(1) संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवादी समूहों से जुड़े व्यक्तियों की पहचान करने और उनके वीजा रद्द करने के लिए एआई उपकरणों का उपयोग करते हुए "कैच एंड रिवोक" पहल शुरू की।

(2) ऑस्ट्रेलिया निर्वासन की व्यवहार्यता की परवाह किए बिना सभी राज्यविहीन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

(3) सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत जैसे खाड़ी देशों ने सुरक्षा कारणों से प्रवासी श्रमिकों को निर्वासित किया है, अक्सर अपील के सीमित रास्ते के साथ।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)

(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: कथन 1 सही है -

संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में "कैच एंड रिवोक" पहल शुरू की है, जो एक उन्नत एआई-संचालित प्रणाली है जो आतंकवादी समूहों से जुड़े वीजा धारकों की पहचान करने के लिए खुफिया डेटाबेस और यात्रा रिकॉर्ड को स्कैन करती है। एक बार चिह्नित होने के बाद, उनके वीजा को वास्तविक समय में रद्द किया जा सकता है, जिससे सीमा और मातृभूमि की सुरक्षा मजबूत होती है।

कथन 2 गलत है -

ऑस्ट्रेलिया में, सुरक्षा जोखिम माने जाने वाले गैर-नागरिकों को हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन राज्यविहीन व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं है, जब तक कि कोई व्यवहार्य निर्वासन योजना न हो। यह राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को मानवाधिकार दायित्वों के साथ संतुलित करता है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी सम्मेलनों के तहत।

कथन 3 सही है -

कुई खाड़ी देशों (विशेषकर सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत) ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए हजारों प्रवासी श्रमिकों को निर्वासित किया है। हालाँकि, ऐसे निर्वासन अक्सर न्यूनतम कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ किए जाते हैं, जिससे प्रवासियों को अपील या समीक्षा के

सीमित अवसर मिलते हैं। इसने क्षेत्र में मानवाधिकारों के अनुपालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

21. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट पर प्रकाश डालती है: 1 अरब से ज्यादा लोग प्रभावित, 100 में से 1 मौत आत्महत्या के कारण। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए डिजिटल पहलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- (1) iGOT-दीक्षा (2020) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण देता है।
- (2) 2022 में शुरू किया गया राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (टेली-मानस), 20 से ज्यादा भाषाओं में 24/7 मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करता है।
- (3) टेली-मानस केवल निजी क्षेत्र के सहयोग से सशुल्क परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है।
- उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1 सही है -

iGOT-दीक्षा (2020) भारत सरकार के एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म (iGOT) का एक हिस्सा है। यह स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और सामुदायिक स्तर के स्वयंसेवकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करता है, जिससे उन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने, रोगियों को उचित देखभाल के लिए मार्गदर्शन करने और कलंक को कम करने में मदद मिलती है। आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों के तहत जमीनी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

कथन 2 सही है -

राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (टेली-मानस) 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह समावेशिता सुनिश्चित करते हुए 20 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में एक टोल-फ्री नंबर के माध्यम से चौबीसों घंटे मुफ्त परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है। यह पहल परामर्शदाताओं, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और NIMH के लिए रेफरल लिंकेज के एक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होती है।

कथन 3 गलत है -

टेली-मानस एक सशुल्क सेवा नहीं है और यह पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। यह एक सरकारी वित्त पोषित पहल है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हो। यह मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 के अनुरूप, मानसिक

स्वास्थ्य सेवा को अधिकार-आधारित और सुलभ सेवा बनाने की दिशा में भारत के कदम को दर्शाता है।

22. नासा और हबबल ने IRAS 04302, बटरप्लॉय स्टार का खुलासा किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -
- (1) 1929 में, जॉर्जिस हबल ने हबल का नियम तैयार किया।
- (2) हबल के नियम ने ब्रह्मांड के विस्तार का पहला गणितीय विवरण प्रदान किया।
- (3) इस विस्तार की सटीक दर को हबल स्थिरांक कहा जाता है।
- उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?
- (A) केवल (1) और (3) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) और (3) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: 1929 में, एडविन हबल ने हबल का नियम तैयार किया, जिसने ब्रह्मांड के विस्तार का पहला गणितीय विवरण प्रदान किया।

इस विस्तार की सटीक दर, जिसे हबल स्थिरांक कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान में एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई है। हबल स्थिरांक के मान की गणना के लिए दो विवरणों की आवश्यकता होती है:

प्रेक्षक और खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, ब्रह्मांड के विस्तार के परिणामस्वरूप ये वस्तुएँ जिस वेग से पर्यवेक्षक से दूर जा रही हैं।

23. केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राएं हमारे युग के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय प्रयोगों में से एक हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

(1) अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है।

(2) एक डिजिटल मुद्रा को इसमें प्रोग्राम की गई शर्तों के साथ वितरित किया जा सकता है जैसे कि इसे खर्च करने की समय-सीमा।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) (B) केवल (1) और (2)
(C) केवल (2) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (B)

व्याख्या: सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) में स्विफ्ट और अमेरिकी डॉलर प्रणाली जैसे मध्यस्थों को खत्म करने की क्षमता है, जिससे अधिक प्रत्यक्ष और कुशल लेनदेन की अनुमति मिलती है।

डिजिटल मुद्राओं को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या टाइम-लॉकिंग तंत्र का उपयोग करके समय-आधारित स्थितियों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे नियमों और प्रतिबंधों के स्वचालित प्रवर्तन की अनुमति मिलती है।

ये स्थितियाँ खर्च को नियंत्रित कर सकती हैं, सुविधाओं को सक्रिय/निष्क्रिय कर सकती हैं, समय-सीमित प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं, या यहां तक कि एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपयोग नहीं किए जाने पर मुद्रा की समाप्ति या विनाश का परिणाम भी दे सकती हैं।

24. विश्व धरोहर दिवस 2025: आपदाओं और संघर्षों के बीच सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा।

अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद (ICOMOS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

(1) यह विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विश्व धरोहर समिति के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।

(2) इसकी स्थापना सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा की गई थी।

उपरोक्त में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल (1) (B) (1) और (2)
(C) केवल (2) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (A)

व्याख्या: ICOMOS यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए विश्व धरोहर समिति का एक सलाहकार निकाय है। इस प्रकार, यह सांस्कृतिक विश्व विरासत के नामांकन की समीक्षा करता है और संपत्तियों की संरक्षण स्थिति सुनिश्चित करता है।

ICOMOS सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम करता है। यह इस तरह का एकमात्र वैश्विक गैर-सरकारी संगठन है, जो वास्तुकला और पुरातात्विक विरासत के संरक्षण के लिए सिद्धांत, पद्धति और वैज्ञानिक तकनीकों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

25. अमेरिका ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए व्हाइट हाउस टास्क फोर्स की स्थापना की।

32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

(1) इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य 'एक नई दुनिया' है।

(2) खेल चढ़ाई, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे और बेसबॉल इस ओलंपिक में शामिल हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है / हैं?

- (A) केवल (1) (B) (2) और (1)
(C) केवल (2) (D) इनमें से कोई भी नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन था जो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो शहर में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मूल रूप से 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक आयोजित होने का

इरादा था, लेकिन चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण, टोक्यो 2020 ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया था।

मार्केटिंग और ब्रांडिंग कारणों से "टोक्यो 2020" का नाम बदलकर "टोक्यो 2021" नहीं किया गया है।

ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य तेज, उच्चतर, मजबूत-साथ-साथ है। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में छह नए खेल जोड़े गए हैं- बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइम्बिंग और सर्फिंग। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शुभंकर का नाम मिराईटोवा है। यह जापानी शब्द मिराई (भविष्य) और टोवा (अनंत काल) से लिया गया है। शुभंकर पुराने और नए दोनों का प्रतीक है, "सद्भाव से नवाचार" की अवधारणा को प्रतिध्वनित करता है। शुभंकर रियो तानिगुची द्वारा बनाया गया था। टोक्यो ने 1964 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की, जिससे दो बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर बन गया।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

I. कई इतिहासकारों द्वारा लाला लाजपत राय को "भारतीय पुनर्जागरण का जनक" माना जाता है।

II. लाला लाजपत राय को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी।

सही विकल्प का चयन करें

- (A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न I और न ही II

उत्तर: (D)

व्याख्या: राजा राम मोहन राय (22 मई 1772 - 27 सितंबर 1833)

ब्रह्म सभा के संस्थापकों में से एक थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज के अग्रदूत थे। उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। उनका प्रभाव राजनीति, लोक प्रशासन, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में स्पष्ट था। उन्हें सती और बाल विवाह की प्रथाओं को खत्म करने के प्रयासों के लिए जाना जाता था। राजा राम मोहन राय को कई इतिहासकारों द्वारा "भारतीय पुनर्जागरण का पिता" माना जाता है

निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

I. तुजुक-ए-बबुरी (बाबरनुमा) भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर की आत्मकथा है।

II. बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था; मुगल साम्राज्य के अधिकारी, बैरम खान खान-ए-खानन के पुत्र, अब्दुर रहीम खान-ए-खानन ने फ़ारसी में इसका अनुवाद किया। अच्छी तरह से यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्राप्त, इस पुस्तक का विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

सही विकल्प का चयन करें

- (A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न I और न ही II

उत्तर: (C)

व्याख्या: तुजुक-ए-बबुरी (बाबरनुमा) भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था; मुगल साम्राज्य के अधिकारी, बैरम खान खान-ए-खानन के पुत्र, अब्दुर रहीम खान-ए-खानन ने फ़ारसी में इसका अनुवाद किया। अच्छी तरह से यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्राप्त, इस पुस्तक का विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

28. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

- I. लॉर्ड लिटन को स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है।
II. रिपन का जन्म लंदन में प्रधानमंत्री एफ जे रॉबिन्सन के दूसरे पुत्र के रूप में हुआ था।
सही विकल्प का चयन करें

- (A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न I और न ही II

उत्तर: (B)

व्याख्या: लॉर्ड रिपन प्रधानमंत्री एफ.जे. रॉबिन्सन के दूसरे पुत्र थे, जिनका जन्म 24 अक्टूबर, 1827 को हुआ था और 9 जुलाई, 1909 को उनका निधन हो गया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है।

29. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

- I. बौद्ध धर्म विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है।
II. बौद्ध धर्म एक विश्वास है जिसे भारत में 2,500 साल से भी पहले सिद्धार्थ गौतम ("बुद्ध") द्वारा स्थापित किया गया था।
सही विकल्प का चयन करें

- (A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न I और न ही II

उत्तर: (B)

व्याख्या: बौद्ध धर्म एक आस्था है जिसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम ("बुद्ध") ने 2,500 साल पहले भारत में की थी। लगभग 470 मिलियन अनुयायियों के साथ, विद्वान बौद्ध धर्म को प्रमुख विश्व धर्मों में से एक मानते हैं। इसका अभ्यास ऐतिहासिक रूप से पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रमुख रहा है, लेकिन पश्चिम में इसका प्रभाव बढ़ रहा है। बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म के संस्थापक, बुद्ध को एक असाधारण व्यक्ति माना जाता है, लेकिन भगवान नहीं है। बुद्ध शब्द का अर्थ है।

30. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

- I. इलायची पहाड़ियाँ या येला माला उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं।

II. अनामीलाई या अनामला हिल्स, जिसे हाथी पर्वत भी कहा जाता है।

सही विकल्प का चयन करें

- (A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न तो I और न ही II

उत्तर: (B)

व्याख्या: अनामीलाई या अनामला हिल्स, जिसे हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, वे पर्वत हैं जो पश्चिमी घाट के दक्षिणी हिस्से का निर्माण करते हैं और दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित हैं। एनिमला नाम तमिल / मलयालम शब्द ऐ या अना से लिया गया है, जिसका अर्थ है हाथी, और मलाई या माला, जिसका अर्थ है पहाड़ी - इस प्रकार हाथी हिल। अनामुड़ी चोटी की सीमा के दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित है और दक्षिणी भारत की सबसे ऊँची चोटी है। पलक्कड़ गैप उत्तर में पश्चिमी घाट को विभाजित करता है।

इलायची हिल्स या यला माला दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला और दक्षिण-पूर्व केरल और भारत में दक्षिण-पश्चिम तमिलनाडु में स्थित दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। उनका नाम इलायची के मसाले से आता है जो कि पहाड़ियों की ठंडी ऊँचाई में उगाया जाता है, जो मिर्च और कॉफी का समर्थन करता है। पश्चिमी घाट और पेरियार उप-क्लस्टर इलायची पहाड़ियों सहित, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं।

31. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

- I. लोहे के अयस्कों में चट्टानें और खनिज होते हैं जिनसे धातु का लोहा आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है
II. बॉक्साइट एक बहुलक है जो मोनोमर्स फिनोल और फॉर्मलाडिहाइड से बना है।
सही विकल्प का चयन करें

- (A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न तो I और न ही II

उत्तर: (A)

व्याख्या: लोहे के अयस्कों में चट्टानें और खनिज होते हैं जिनसे धातु का लोहा आर्थिक रूप से निकाला जा सकता है। अयस्कों आमतौर पर लोहे के आक्साइड में समृद्ध होते हैं और गहरे भूरे, चमकीले पीले या गहरे बैंगनी रंग से लाल रंग के होते हैं। हेमटाइट या मैग्नेटाइट (लगभग 60% से अधिक लौह) की बहुत अधिक मात्रा वाले अयस्क को "प्राकृतिक अयस्क" या "प्रत्यक्ष शिपिंग अयस्क" के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें सीधे लोहा बनाने वाले ब्लास्ट फर्नेस में दिया जा सकता है। लौह अयस्क वह कच्चा माल है जिसका उपयोग पिग आयरन बनाने के लिए किया जाता है, जो कि स्टील बनाने के लिए मुख्य कच्चे माल में से एक है- 98% खनन लौह अयस्क का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है।

बॉक्साइट एक लाल रंग की मिट्टी से बनी एक चट्टान है जिसे लेटराइट मिट्टी कहा जाता है और यह उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है। बॉक्साइट मुख्य रूप से एल्यूमीनियम ऑक्साइड यौगिकों (एल्यूमिना), सिलिका, लौह आक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड से बना है। बैक्साइट एक बहुलक है जो मोनोमर्स फिनोल और फॉर्मलाडिहाइड से बना है। यह फिनोल-फॉर्मेलीहाइड राल एक थर्मोसेटिंग बहुलक है।

32. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

I. वनों की कटाई से खेतों तक वन भूमि का रूपांतरण हो सकता है।

II. गहन खेती एक प्रकार की कृषि है जिसमें पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे और श्रम का उपयोग किया जाता है।

सही विकल्प का चयन करें

- (A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न तो I और न ही II

उत्तर: (C)

व्याख्या: वनों की कटाई से खेत, खेत, या शहरी उपयोग के लिए वन भूमि का रूपांतरण शामिल हो सकता है। गहन कृषि या सघन कृषि एक प्रकार की कृषि है, जिसमें भूमि के प्रति क्षेत्र में प्राप्त होने वाली उपज को बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा और श्रम लगाया जाता है। फसलों के लिए बड़ी मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग, और पशु स्टॉक के लिए दवा का उपयोग आम है। यह पारंपरिक कृषि के विपरीत है, जिसमें प्रति क्षेत्र उतना उत्पादन नहीं मिलता है। जब कृषि तेज होती है, तो इसका मतलब है कि काम की मात्रा तब तक बढ़ जाती है, जब तक कि श्रमिक को मशीन द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। उस समय, मशीनों को संचालित करने के लिए केवल कुछ श्रमिकों की आवश्यकता होगी।

33. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

I. हिमालय धौलाधार और जास्कर श्रेणियों की ओर एक क्रमिक ऊँचाई दिखाता है।

II. उत्तराखंड छत की खेती के लिए प्रसिद्ध है।

सही विकल्प का चयन करें

- (A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न तो I और न ही II

उत्तर: (B)

व्याख्या: छतों पर चावल और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। पहाड़ी इलाके खेती के इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। खेती करने का अभ्यास करने वाले राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर-पूर्व के राज्य हैं। इसकी खेती, ढलान में निर्मित स्नातक छतों पर पहाड़ियों या पहाड़ों के किनारे उगने वाली फसलों की विधि। यद्यपि श्रम-गहन, विधि को

प्रभावी ढंग से नियोजित किया गया है ताकि चर क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि क्षेत्र को अधिकतम किया जा सके और मिट्टी के कटाव और पानी के नुकसान को कम किया जा सके।

पीर पंजाल रेंज (कश्मीरी: पीर पैटसाल), हिंदू शास्त्रों में भी पांचालदेव, इनर हिमालयी क्षेत्र में पहाड़ों का एक समूह है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में पूर्व-दक्षिण-पूर्व (ईएसई) से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम (डब्ल्यूएनडब्ल्यू) तक चलता है। और जम्मू और कश्मीर के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तानी क्षेत्र जहां औसत ऊंचाई 1,400 मीटर (4,600 फीट) से 4,100 मीटर (13,500 फीट) तक होती है। हिमालय धौलाधार और पीर पंजाल पर्वतमाला की ओर एक क्रमिक ऊँचाई को दर्शाता है। पीर पंजाल कम हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है। कश्मीर या झेलम घाटी पीर पंजाल रेंज और ज़ास्कर रेंज के बीच स्थित है और इसका क्षेत्रफल 15220 वर्ग किलोमीटर है।

34. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

I. दो बार किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है

II. अनुच्छेद 32 को डॉ बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा गया

सही विकल्प का चयन करें

- (A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न तो I और न ही II

उत्तर: (C)

व्याख्या: इस बात पर कोई रोक नहीं है कि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का उच्च पद धारण कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, हालांकि, एक व्यक्ति केवल दो बार (4 साल प्रत्येक) राष्ट्रपति बन सकता है, वह भी केवल लगातार। डॉ बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' अर्थात् संवैधानिक उपचारों को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा है। इसे स्वीकार किया गया क्योंकि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी मशीनरी के बिना मौलिक अधिकार की घोषणा निरर्थक होती

35. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

I. पंजाब में कुल 7 संसदीय सीटें (राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र) हैं।

II. भारत की संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी।

सही विकल्प का चयन करें

- (A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न तो I और न ही II

उत्तर: (C)

व्याख्या: राज्य सभा राज्यों की परिषद है और इसे भारत की संसद के ऊपरी सदन के रूप में भी जाना जाता है। इसके सभी

सदस्य संसद के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। राज्यसभा में पंजाब के सात सदस्य हैं।

भारत का संविधान लिखने के लिए भारत की संविधान सभा का चुनाव किया गया था। 1947 में ब्रिटिश सरकार से भारत की स्वतंत्रता के बाद, इसके सदस्यों ने देश की पहली संसद के रूप में कार्य किया।

एक संविधान सभा के लिए एक विचार 1934 में M. N. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी और कट्टरपंथी लोकतंत्र के पैरोकार थे। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक आधिकारिक मांग बन गई, (C) राजगोपालाचारी ने 15 नवंबर 1939 को वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा की मांग उठाई, और अगस्त 1940 में अंग्रेजों द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

36. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

I. पंचायत के सदस्य संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक होते हैं।

II. नागालैंड को अलग राज्य के रूप में वर्ष 1963 में बनाया गया था

सही विकल्प का चयन करें

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) न तो I और न ही II

उत्तर: (C)

व्याख्या: ग्राम पंचायतों के सदस्य, ग्राम कुटुंबाचार्य के पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य संबंधित क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से सीधे चुने जाते हैं।

पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड एक राज्य है। यह पश्चिम में असम राज्य, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर में असम, पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में मणिपुर की सीमा में आता है। नागालैंड भारत के उन तीन राज्यों में से एक है जहाँ की आबादी ज्यादातर ईसाई है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16 वां राज्य बना।

37. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

I. सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक चौथाई को अनुच्छेद 100(3) के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है।

II. अध्यक्ष अपने निर्वाचन की तिथि से जिस संसद में वह निर्वाचित हुआ था उसके विघटन के पश्चात अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक पद धारण करता है।

सही विकल्प का चयन करें।

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) न तो I और न ही II

उत्तर: (B)

व्याख्या: सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई को अनुच्छेद 100(3) के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना

जाता है। अध्यक्ष अपने निर्वाचन की तिथि से जिस संसद में वह निर्वाचित हुआ था उसके विघटन के पश्चात अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक पद धारण करता है।

38. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

I. पूंजीगत लाभ से तात्पर्य उस लाभ से है जो पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त होता है।

II. उपहार कर प्रत्यक्ष कर है।

सही विकल्प का चयन करें

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) न तो I और न ही II

उत्तर: (A)

व्याख्या: एक पूंजीगत लाभ से तात्पर्य उस लाभ से है जो पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से होता है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड या अचल संपत्ति, जहाँ बिक्री मूल्य खरीद मूल्य से अधिक होता है। लाभ उच्च बिक्री मूल्य और कम खरीद मूल्य के बीच का अंतर है। इसके विपरीत, यदि पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय खरीद मूल्य से कम है, तो पूंजीगत नुकसान होता है।

पूंजीगत लाभ एक परिसंपत्ति से प्राप्त लाभ के एक अलग रूप को भी संदर्भित कर सकता है जो नकदी प्रवाह या निष्क्रिय आय के रूप में "निवेश आय" को संदर्भित करता है जो वास्तविक संपत्ति, जैसे संपत्ति; वित्तीय संपत्ति, जैसे शेयर / स्टॉक या बॉन्ड और अमूर्त संपत्ति। प्रत्यक्ष कर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सीधे निकाय को भुगतान किया जाता है। एक करदाता, उदाहरण के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है, जिसमें वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर, आयकर या संपत्ति पर कर शामिल हैं।

39. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

I. मुद्रास्फीति एक धीमी गति से आर्थिक विकास द्वारा वर्णित विरोधाभासी स्थिति है।

II. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

सही विकल्प का चयन करें

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) न तो I और न ही II

उत्तर: (B)

व्याख्या: व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) 1964 में स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

UNCTAD व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है। संगठन के लक्ष्य हैं: "विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को अधिकतम करना

और उन्हें समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के उनके प्रयासों में सहायता करना" स्टैगफ्लेशन एक धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी, या आर्थिक ठहराव द्वारा वर्णित एक विरोधाभासी स्थिति है, जो एक ही समय में बढ़ती कीमतों (यानी मुद्रास्फीति) के साथ है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट के साथ संयुक्त मुद्रास्फीति को वैकल्पिक रूप से मुद्रास्फीति की अवधि के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

40. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
I. NHB Residex को 2007 में लॉन्च किया गया था।
II. आयकर एक प्रगतिशील कर है।
सही विकल्प का चयन करें।
(A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न तो I और न ही II

उत्तर: (C)

व्याख्या: एक प्रगतिशील कर एक ऐसा कर है जो उच्च आय वाले लोगों की तुलना में कम आय वाले लोगों पर कर की कम दर लगाता है, जो करदाता की भुगतान करनेकी क्षमता के आधार पर बनाता है। इसका मतलब है कि कम आय वाले व्यक्तियों की तुलना में यह उच्च आय वाले आय का बड़ा प्रतिशत लेता है। एक प्रगतिशील कर वह है जो उच्च आय अर्जित करने वाले लोगों के लिए उच्च कर दर वसूल करता है। तर्क यह है कि कम आय वाले लोग आमतौर पर अपनी आय का अधिक प्रतिशत अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए खर्च करेंगे। आयकर प्रणाली को एक प्रगतिशील प्रणाली माना जाता है।

भारत का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक NHB RESIDEX, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के इशारे पर किए गए राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) की एक पहल थी। सूचकांक एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था जिसमें आवास बाजार से हितधारकों को शामिल किया गया था। यह जुलाई, 2007 में लॉन्च किया गया था और मार्च 2015 तक समय-समय पर अद्यतन किया गया, 2007 को आधार वर्ष के रूप में लिया गया। इस अवधि के दौरान, NHB RESIDEX का विस्तार धीरे-धीरे 26 शहरों तक हो गया।

41. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
I. मर्केटर प्रक्षेपण एक बेलनाकार नक्शा प्रक्षेपण है।
II. मुद्रा बाजार अर्थव्यवस्था का एक घटक है जो अल्पकालिक निधि प्रदान करता है।
सही विकल्प का चयन करें।
(A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न तो I और न ही II

उत्तर: (C)

व्याख्या: मर्केटर प्रोजेक्शन फ्लेमिश जियोग्राफर और कार्टोग्राफर जेर्हार्डस मर्केटर द्वारा 1569 में प्रस्तुत किया गया एक बेलनाकार नक्शा प्रक्षेपण है। यह सीधे खंड के रूप में निरंतर असर वाले किसी भी पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने की अपनी अनूठी संपत्ति के कारण नेविगेशन के लिए मानक मानचित्र प्रक्षेपण बन गया।

मुद्रा बाजार अर्थव्यवस्था का एक घटक है जो अल्पकालिक निधि प्रदान करता है। मुद्रा बाजार अल्पकालिक ऋणों में, आमतौर पर 365 दिनों से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए सौदा करता है। पैसा कमोडिटी बन गया, मुद्रा बाजार अल्पकालिक उधार, उधार में शामिल संपत्ति के लिए वित्तीय बाजार का एक घटक बन गया। एक वर्ष या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ खरीद और बिक्री। मुद्रा बाजारों में व्यापार काउंटर पर किया जाता है और थोक होता है।

42. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
I. साबुन का बुलबुला सतह के तनाव के कारण गोलाकार आकार प्राप्त करता है।
II. एक तरल पदार्थ की चिपचिपाहट इसके प्रतिरोध का एक उपाय है।
सही विकल्प का चयन करें।
(A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न तो I और न ही II

उत्तर: (C)

व्याख्या: बुलबुले गोलाकार होते हैं क्योंकि सतह पर तनाव नामक एक आकर्षक बल होता है जो पानी के अणुओं को सबसे अधिक संभव समूह में खींचता है। और कणों के किसी भी संग्रह को प्राप्त करने वाले सबसे अधिक संभव समूह को एक साथ एक गोले में मिलता है। चिपचिपाहट को आंतरिक घर्षण बल को परिमाणित करने के रूप में माना जा सकता है जो तरल पदार्थ के आसन्न परतों के बीच उत्पन्न होता है जो सापेक्ष गति में होते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक ट्यूब के माध्यम से एक तरल पदार्थ को मजबूर किया जाता है, तो यह अपनी दीवारों की तुलना में ट्यूब के अक्ष के पास अधिक तेज़ी से बहती है।

43. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
I. रेड और ग्रीन को मिलाने पर ग्रे बनता है।
II. इलेक्ट्रिक मोटर ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
सही विकल्प का चयन करें।
(A) केवल I (B) केवल II
(C) I और II दोनों (D) न तो I और न ही II

उत्तर: (D)

व्याख्या: लाल, नीला और हरा तीन प्राथमिक रंग हैं, इन प्राथमिक रंगों को मिलाने पर, हमें विभिन्न रंग मिलते हैं जैसे पीला,

मैजेंटा और सियान इत्यादि। जब लाल और हरे रंग का संयोजन होता है, तो परिणाम पीला होता है। जब लाल और नीले रंग का संयोजन होता है, तो परिणाम मजेंटा है। जब नीले और हरे रंग का संयोजन होता है, तो परिणाम सियान होता है।

विद्युत मोटर एक विद्युत मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अधिकांश विद्युत मोटर मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और मोटर के शाफ्ट पर लगाए गए टोर्क के रूप में बल उत्पन्न करने के लिए एक तार घुमावदार में विद्युत प्रवाह के बीच संबंध के माध्यम से काम करते हैं।

44. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

I. डॉ होमी जे. भाभा ने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक विकसित की।

II. दोलन के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है।

सही विकल्प का चयन करें।

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) न तो I और न ही II

उत्तर: (A)

व्याख्या: होमी जहांगीर भाभा (30 अक्टूबर 1909 - 24 जनवरी 1966) एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी, संस्थापक निदेशक और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) में भौतिकी के प्रोफेसर थे। बोलचाल की भाषा में "भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक" के रूप में जाना जाता है, भाभा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, ट्रॉम्बे (AEET) के संस्थापक निदेशक भी थे, जिसे अब उनके सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम दिया गया है। TIFR और AEET परमाणु हथियारों के भारतीय विकास की आधारशिला थी जिसे भाभा ने निदेशक के रूप में भी पर्यवेक्षण किया।

डायोड का सबसे सामान्य कार्य एक विद्युत धारा को एक दिशा (जिसे डायोड की आगे की दिशा कहा जाता है) में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जबकि विपरीत दिशा (रिवर्स दिशा) में विद्युत धारा को अवरुद्ध करता है। इस यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर को रेक्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन कहा जाता है और इसका इस्तेमाल ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किया जाता है, जिसमें रेडियो रिसीवर में रेडियो सिग्नल्स से मॉड्यूलेशन का निष्कर्षण शामिल है - ये डायोड रेक्टिफायर्स के रूप में डायोड एक असममित ट्रांसफर विशेषता के साथ एक दो थर्मल इलेक्ट्रॉनिक घटक है, जिसके साथ कम (आदर्श रूप से शून्य) एक दिशा में वर्तमान प्रवाह का प्रतिरोध, और अन्य में उच्च (आदर्श रूप से अनंत) प्रतिरोध।

45. निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?

I. चार्ज कुछ प्राथमिक कणों द्वारा किए गए पदार्थ की मूल गुण है।

II. कैपेसिटेंस, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर की गुण, या कंडक्टर का सेट, जो अलग-अलग इलेक्ट्रिक चार्ज की मात्रा से मापा जाता है।

सही विकल्प का चयन करें।

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) न तो I और न ही II

उत्तर: (B)

व्याख्या: कैपेसिटेंस, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर की गुण, या कंडक्टरों का सेट, जो कि अलग-अलग इलेक्ट्रिक चार्ज की मात्रा से मापा जाता है, जिसे विद्युत क्षमता में प्रति यूनिट परिवर्तन पर इसे संग्रहीत किया जा सकता है। कैपेसिटेंस का तात्पर्य विद्युत ऊर्जा से जुड़े भंडारण से भी है। यदि विद्युत आवेश को दो आरंभिक संवाहकों के बीच स्थानांतरित किया जाता है, तो दोनों समान रूप से आवेशित हो जाते हैं, एक सकारात्मक रूप से, दूसरा नकारात्मक रूप से, और उनके बीच एक संभावित अंतर स्थापित हो जाता है। कैपेसिटेंस C, कंडक्टरों के बीच संभावित अंतर V के लिए या तो कंडक्टर पर चार्ज q की मात्रा का अनुपात है, $C = q / V$ है।

इलेक्ट्रिक चार्ज, कुछ प्राथमिक कणों द्वारा किए गए पदार्थ की मूल गुण इलेक्ट्रिक चार्ज, जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, असतत प्राकृतिक इकाइयों में होता है और इसे न तो बनाया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो सामान्य प्रकार के होते हैं: सकारात्मक और नकारात्मक। दो वस्तुएं जिनमें एक प्रकार के आवेश की अधिकता होती है, अपेक्षाकृत एक साथ बंद होने पर एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाती हैं।

46. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

I. पॉलिएस्टर कोयले से बना एक सिंथेटिक फाइबर है।

II. सिरका एसिटिक एसिड का एक जलीय घोल है।

सही विकल्प का चयन करें ?

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) न तो I और न ही II

उत्तर: (C)

व्याख्या: पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है जो कोयले, हवा, पानी और पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। 20 वीं सदी की प्रयोगशाला में विकसित, एसिड और अल्कोहल के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से पॉलिएस्टर फाइबर बनते हैं। इस प्रतिक्रिया में, दो या दो से अधिक अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, जिसकी संरचना इसकी पूरी लंबाई में दोहराती है। पॉलिएस्टर फाइबर अणुओं का निर्माण कर सकते हैं जो बहुत स्थिर और मजबूत होते हैं। सिरका एसिटिक एसिड और ट्रेस रसायनों का एक जलीय घोल है जिसमें स्वाद शामिल हो सकते हैं।

सिरका में आमतौर पर मात्रा के हिसाब से 5 से 8% एसिटिक एसिड होता है। आमतौर पर एसिटिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल या शर्करा के किण्वन द्वारा निर्मित होता है।

47. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

I. लोहे का शुद्ध रूप पिटवा लोहा है।

II. विलायक के 1 किलो में मौजूद विलेय के मोल्स की संख्या को इसकी साधारण अवस्था कहा जाता है।

सही विकल्प का चयन करें

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) न तो I और न ही II

उत्तर: (A)

व्याख्या: लोहा, दो रूपों में से एक है जिसमें लोहा गलाने से प्राप्त होता है; अन्य कच्चा लोहा है। पिटवा लोहा एक नरम, नमनीय, रेशेदार किस्म है जो कि आंशिक रूप से स्लैग से घिरे अपेक्षाकृत शुद्ध लोहे के ग्लोब्यूलस के अर्धनिर्मित द्रव्यमान से उत्पन्न होता है। इसमें आमतौर पर 0.1 प्रतिशत से कम कार्बन और 1 या 2 प्रतिशत स्लैग होता है। यह लोहे को कास्ट करने के अधिकांश उद्देश्यों के लिए बेहतर है, जो कि उच्च कार्बन सामग्री के कारण अत्यधिक कठोर और भंगुर है। मोलिटी एक समाधान की संपत्ति है और इसे विलायक के प्रति किलोग्राम मोल की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। मोलिटी के लिए एसआई यूनिट मोल / किग्रा है। 3 मोल / किग्रा की मात्रा के साथ एक विलय को अक्सर "3 मोल" या "3 मी" के रूप में वर्णित किया जाता है। हालांकि, एसआई प्रणाली की इकाइयों के बाद, मोल / किग्रा या संबंधित एसआई इकाई को प्राथमिकता दी जाती है।

48. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

I. सबसे अधिक विद्युतीय तत्व ब्रोमीन है।

II. सेलेनियम गैर धातु बिजली का एक खराब कंडक्टर नहीं है।

सही विकल्प का चयन करें?

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) न तो I और न ही II

उत्तर: (B)

व्याख्या: सेलेनियम प्रतीक Se और परमाणु संख्या 34 के साथ एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी, सल्फर और टेल्यूरियम में ऊपर और नीचे के तत्वों के बीच मध्यवर्ती है, गुणों के साथ एक अधातु (अधिक शायद ही कभी एक मेटालॉइड माना जाता है) है, और यह आर्सेनिक से भी समानता है यह शायद ही कभी अपनी प्राथमिक अवस्था में या पृथ्वी की पपड़ी में शुद्ध अयस्क यौगिकों के रूप में होता है। सेलेनियम धातु सल्फाइड अयस्कों में पाया जाता है, जहां यह आंशिक रूप से सल्फर की जगह लेता है।

आवर्त सारणी के दौरान वैद्युतीयक्राणत्मकता अनुमानित रूप से भिन्न होती है। इलेक्ट्रोनगेटिविटी समूहों में नीचे से ऊपर तक बढ़ती है, और बाएं से दाएं तक बढ़ती है। इस प्रकार, फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनगेटिव तत्व है, जबकि फ्रेंशियम कम से कम इलेक्ट्रोनगेटिव में से एक है।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

I. तांबा सल्फेट के घोल से तांबा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त धातु Fe है।

II. धातु की प्रक्रिया जिसमें धातु को एक फ्यूज अवस्था में प्राप्त किया जाता है, को कैल्सीनेशन कहा जाता है।

सही विकल्प का चयन करें।

(A) केवल I

(B) केवल II

(C) I और II दोनों

(D) न तो I और न ही II

उत्तर: (C)

व्याख्या: तांबा सल्फेट से तांबा को ठीक करने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। आयरन एक रासायनिक तत्व है जिसमें प्रतीक Fe और परमाणु संख्या 26 है। यह एक धातु है जो पहली संक्रमण श्रृंखला और आवर्त सारणी के समूह 8 से संबंधित है। यह पृथ्वी पर सबसे आम तत्व है, जो पृथ्वी के बाहरी और आंतरिक कोर का अधिकांश हिस्सा है। यह पृथ्वी की पपड़ी में चौथा सबसे आम तत्व है।

50. निम्नलिखित सही कथनों पर विचार करें।

1. टेटनस, मनुष्यों और अन्य जानवरों के तीव्र संक्रामक रोग, जो बेसिलस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के कारण होता है।

2. हेपेटाइटिस: यह एक वायरल बीमारी है, यकृत एनोरेक्सिया का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप यकृत क्षति (यकृत कैंसर) या पीलिया होता है।

(A) केवल 1

(B) केवल 2

(C) 1 और 2 दोनों

(D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (C)

व्याख्या: टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रमण है। यह जीवाणु एक विष का उत्पादन करता है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों में कठोरता होती है। यदि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बीजाणु एक घाव में जमा हो जाते हैं, तो न्यूरोटॉक्सिन मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने वाली नसों के साथ हस्तक्षेप करता है।

हेपेटाइटिस यकृत की एक उत्तेजक स्थिति को संदर्भित करता है। यह आमतौर पर एक वायरल संक्रमण के कारण होता है, लेकिन हेपेटाइटिस के अन्य संभावित कारण हैं। इनमें ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस शामिल हैं जो दवाओं, विषाक्त पदार्थों और शराब के माध्यमिक परिणाम के रूप में होते हैं।

सही मिलान प्रश्नावली

1. निम्नलिखित पोषक तत्वों और उनकी कमी से होने वाले रोगों का मिलान करें -

(a) पोटेशियम	1- उच्च रक्तचाप
(b) कैल्शियम	2- हाइपोकेल्सीमिया
(c) मैग्नीशियम	3- इलेक्ट्रोलाइटिक असंतुलन
(d) सोडियम	4- इंसुलिन प्रतिरोध

विकल्प

(A) a-1, b-4, c-3, d-2

(B) a-2, b-3, c-1, d-4

(C) a-1, b-2, c-4, d-3

(D) a-1, b-3, c-2, d-4

Ans: (C)

Exp: पोटेशियम - उच्च रक्तचाप
कैल्शियम - हाइपोकेल्सीमिया
मैग्नीशियम - इंसुलिन प्रतिरोध
सोडियम - इलेक्ट्रोलाइटिक असंतुलन

2. निम्नलिखित क्रांति क्षेत्र/उत्पाद और उनके जनक का मिलान करें -

(a) स्वर्णिम क्रांति	1- श्री निरपख टुटेज
(b) रजत क्रांति	2- श्री सैम पित्रोदा
(c) पीली क्रांति	3- श्रीमती इंदिरा गांधी

विकल्प

(A) a-1, b-2, c-3

(B) a-2, b-3, c-1

(C) a-3, b-2, c-1

(D) a-1, b-3, c-2

Ans: (D)

Exp: स्वर्णिम क्रांति - श्री निरपख टुटेज
रजत क्रांति - श्रीमती इंदिरा गांधी
पीली क्रांति - श्री सैम पित्रोदा

3. निम्नलिखित नदियों और उनके उद्गम का मिलान करें -

(a) पेनगंगा	1- अजंता श्रेणी
(b) इंद्रायणी	2- पश्चिमी घाट
(c) पावना	3- सह्याद्रि पर्वतमाला
(d) घटप्रभा	4- लोनावाला

विकल्प

(A) a-1, b-4, c-3, d-2

(B) a-2, b-3, c-1, d-4

(C) a-1, b-2, c-4, d-3

(D) a-1, b-3, c-2, d-4

Ans: (A)

पेनगंगा - अजंता श्रेणी
इंद्रायणी - लोनावाला
पावना - सह्याद्रि पर्वतमाला

घटप्रभा - पश्चिमी घाट

4. निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों का मिलान करें 2023 -

(a) अम्बेडकर: अ लाइफ	1- श्रीमंत कोकाटे
(b) कम! लेट्स रन	2- मा सुब्रमण्यम
(c) छत्रपति शिवाजी महाराज	3- शशि थरूर

विकल्प

(A) a-1, b-2, c-3

(B) a-2, b-3, c-1

(C) a-3, b-2, c-1

(D) a-1, b-3, c-2

Ans: (C)

Exp: अम्बेडकर: अ लाइफ - शशि थरूर
कम! लेट्स रन - मा सुब्रमण्यम
छत्रपति शिवाजी महाराज - श्रीमंत कोकाटे

5. नदी तट पर स्थित निम्नलिखित शहरों का मिलान करें -

(a) कुरनूल	1- तुंगभद्रा
(b) कटक	2- महानदी
(c) डिब्रूगढ़	3- सतलुज
(d) फिरोजपुर	4- ब्रह्मपुत्र

विकल्प

(A) a-1, b-4, c-3, d-2

(B) a-2, b-3, c-1, d-4

(C) a-1, b-2, c-4, d-3

(D) a-1, b-3, c-2, d-4

Ans: (C)

Exp: कुरनूल - तुंगभद्रा
कटक - महानदी
डिब्रूगढ़ - ब्रह्मपुत्र
फिरोजपुर - सतलुज

6. भारत में निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का मिलान करें -

(a) सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व	1- ओडिशा
(b) अचानकमार - अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व	2- छत्तीसगढ़
(c) अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व	3- केरल और तमिलनाडु

विकल्प

(A) a-1, b-2, c-3

(B) a-2, b-3, c-1

(C) a-3, b-2, c-1

(D) a-1, b-3, c-2

Ans: (A)

Exp: सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व - ओडिशा

अचानकमार - अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व - छत्तीसगढ़
अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व - केरल और तमिलनाडु

7. निम्नलिखित का मिलान करें -

स्थिरांक	मान / महत्त्व
(a) प्लैंक स्थिरांक	1- 1.38×10^{-23} J/K
(b) बोल्ज़मान स्थिरांक	2- 6.626×10^{-34} Js
(c) इलेक्ट्रॉन आवेश	3- 1.602×10^{-19} C
(d) रिडबर्ग स्थिरांक	4- 2.18×10^{-18} J
(e) आवोगाद्रो स्थिरांक	5- 6.022×10^{23} mol ⁻¹

विकल्प:

- (A) a-2, b-1, c-3, d-4, e-5
(B) a-1, b-2, c-5, d-3, e-4
(C) a-2, b-5, c-1, d-4, e-3
(D) a-4, b-1, c-3, d-2, e-5

Ans:

Exp:

प्लैंक स्थिरांक (h) = 6.626×10^{-34} Js → a-2
बोल्ज़मान स्थिरांक (k) = 1.38×10^{-23} J/K → b-1
इलेक्ट्रॉन आवेश (e) = 1.602×10^{-19} C → c-3
रिडबर्ग स्थिरांक (R_∞) = 2.18×10^{-18} J → d-4
आवोगाद्रो स्थिरांक (NA) = 6.022×10^{23} mol⁻¹ → e-5

8. निम्नलिखित का मिलान करें -

मिशन/परियोजना	उद्देश्य/विवरण
(a) डीप ओशन मिशन	1- मानव महासागर अन्वेषण हेतु डीप-सी सबमर्सिबल विकसित करना
(b) समुद्रयान	2- तटीय और समुद्री जैव विविधता का मानचित्रण और निगरानी
(c) सागर संपदा	3- डीप-सी खनिजों, हाइड्रोकार्बन और जैव विविधता का अन्वेषण
(d) सागर मंथन	4- सतत मत्स्य प्रबंधन और जलीय कृषि विकास

विकल्प:

- (A) a-3, b-1, c-4, d-2
(B) a-1, b-2, c-3, d-4
(C) a-4, b-3, c-2, d-1
(D) a-2, b-4, c-1, d-3

Ans:

Exp:

गहरे समुद्र मिशन (a) → गहरे समुद्र में खनिजों, हाइड्रोकार्बन और जैव विविधता की खोज पर केंद्रित → a-3

समुद्रयान (b) → मानवयुक्त गहरे समुद्र में पनडुब्बी विकसित करना → b-1
सागर संपदा (c) → सतत मत्स्य प्रबंधन, जलीय कृषि और तटीय आजीविका पर केंद्रित → c-4
सागर मंथन (d) → तटीय और समुद्री जैव विविधता का मानचित्रण और निगरानी → d-2

9. निम्नलिखित को मिलाएं -

पोषक तत्व -	घटक
(a) विटामिन बी9	1- फोलिक एसिड
(b) विटामिन सी	2- कैल्सिफेरॉल (D2)
(c) विटामिन डी	3- एल-एस्कोर्बिक एसिड
(d) विटामिन ई	4- टोकोफेरॉल

विकल्प

- (A) a-1, b-4, c-3, d-2
(B) a-2, b-3, c-1, d-4
(C) a-1, b-2, c-4, d-3
(D) a-1, b-3, c-2, d-4

Ans:

Exp:

पोषक तत्व - घटक
विटामिन बी9 - फोलिक एसिड
विटामिन सी - एल-एस्कोर्बिक एसिड
विटामिन डी - कैल्सिफेरॉल (D2)
विटामिन ई - टोकोफेरॉल

10. आधुनिक भारत के निम्नलिखित प्रमुख निचली जाति के आंदोलनों का मिलान करें -

(a) अरुविप्पुरम आंदोलन	1- श्री नारायण गुरु
(b) दलित वर्ग मिशन सोसायटी	2- महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे
(c) जस्टिस पार्टी	3- टी एम नायर और पी थेगराय चेट्टी

विकल्प

- (A) a-1, b-2, c-3
(B) a-2, b-3, c-1
(C) a-3, b-2, c-1
(D) a-1, b-3, c-2

Ans:

Exp:

अरुविप्पुरम आंदोलन - श्री नारायण गुरु
दलित वर्ग मिशन सोसायटी - महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे
जस्टिस पार्टी - टी एम नायर और पी थेगराय चेट्टी

11. निम्नलिखित प्राकृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का उनके समावेशन वर्ष से मिलान कीजिए:

यूनेस्को स्थल	समावेशन वर्ष
(a) मानस वन्यजीव अभयारण्य	1 - 1985

(b) नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान	2 – 1988
(c) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	3 – 1985
(d) ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान	4 – 2014

विकल्प:

(A) a-1, b-2, c-3, d-4

(B) a-3, b-2, c-1, d-4

(C) a-1, b-4, c-2, d-3

(D) a-2, b-1, c-3, d-4

Ans:

(B)

Exp:

मानस वन्यजीव अभयारण्य → 1985 में सूचीबद्ध, लेकिन बाद में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध (2011 में पुनर्स्थापित)।

नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान → 1988।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान → 1985 (पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य)।

ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान → 2014 (इनमें से नवीनतम)।

12. निम्नलिखित शरीर द्रवों का उनके प्राथमिक कार्यों से मिलान कीजिए:

द्रव	कार्य
(a) श्लेष द्रव	1 - मस्तिष्क और मेरुमज्जा की सुरक्षा करता है।
(b) जलीय द्रव	2 - जोड़ों को चिकनाई प्रदान करता है और घर्षण कम करता है।
(c) मस्तिष्कमेरु द्रव	3 - आँख में अंतःनेत्र दाब बनाए रखता है।
(d) लसीका	4 - वसा और प्रतिरक्षा कोशिकाओं का परिवहन करता है।

विकल्प:

(A) a-2, b-3, c-1, d-4

(B) a-1, b-2, c-4, d-3

(C) a-3, b-4, c-1, d-2

(D) a-2, b-1, c-3, d-4

Ans:

(A)

Exp:

सिनोवियल द्रव → (2) जोड़ों को चिकनाई प्रदान करता है।

जलीय द्रव → (3) आँख में अंतःनेत्र दाब बनाए रखता है।

मस्तिष्कमेरु द्रव → (1) मस्तिष्क और मेरुमज्जा को सहारा देता है।

लसीका → (4) वसा और प्रतिरक्षा कोशिकाओं का परिवहन करता है।

13. निम्नलिखित समितियों का उनके संबंधित क्षेत्रों/वर्षों से मिलान करें:

समिति	विवरण
-------	-------

(a) शाह आयोग (1977-78)	1 – माध्यमिक शिक्षा सुधार
(b) वांचू समिति (1971)	2 – शिक्षा नीति एवं रूपरेखा 1968
(c) मुदालियर समिति (1952-53)	3 – प्रत्यक्ष कर जाँच एवं सुधार
(d) कोठारी आयोग (1964-66)	4 – आपातकाल के दौरान ज्यादातियाँ (1975-77)

विकल्प:

(A) a-4, b-3, c-1, d-2

(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(C) a-3, b-4, c-2, d-1

(D) a-2, b-1, c-4, d-3

(A)

शाह आयोग (1977-78): आपातकाल (1975-77) के दौरान हुई ज्यादातियों की जाँच की।

वांचू समिति (1971): प्रत्यक्ष करों का अध्ययन किया और कर चोरी कम करने के उपाय सुझाए।

मुदालियर समिति (1952-53): स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा सुधारों पर काम किया।

कोठारी आयोग (1964-66): शिक्षा के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान किया, जो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार बना।

14.

निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों का उनके प्रकाशन संगठनों से मिलान करें:

रिपोर्ट	संगठन
(a) उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट	1 - संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
(b) वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ	2 - विश्व बैंक
(c) विश्व आर्थिक परिदृश्य	3 - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
(d) वैश्विक जोखिम रिपोर्ट	4 - विश्व आर्थिक मंच (WEF)

विकल्प:

(A) a-1, b-2, c-3, d-4

(B) a-2, b-3, c-1, d-4

(C) a-3, b-4, c-2, d-1

(D) a-4, b-2, c-1, d-3

(A)

उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट - यूएनईपी द्वारा जारी, यह रिपोर्ट ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की दिशा और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए आवश्यक लक्ष्यों की तुलना करती है।

वैश्विक आर्थिक संभावनाएँ - विश्व बैंक की एक रिपोर्ट जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की अल्पकालिक और मध्यम अवधि की संभावनाओं का विश्लेषण करती है।

Ans:

Exp:

विश्व आर्थिक परिदृश्य - आईएमएफ द्वारा प्रकाशित, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, व्यापार और राजकोषीय मुद्दों का विश्लेषण करती है।

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट - विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) द्वारा जारी, यह रिपोर्ट विशेषज्ञ सर्वेक्षणों के आधार पर वैश्विक जोखिमों (जलवायु परिवर्तन, साइबर खतरे, भू-राजनीतिक तनाव, आदि) की पहचान करती है।

15. निम्नलिखित प्रकार के कांच और उनके उपयोग का मिलान करें -

(a) क्रक्स ग्लास	1- महंगा ग्लास पॉट
(b) क्राउन ग्लास	2- धूप का चश्मा लेंस
(c) लेड क्रिस्टल ग्लास	3- चश्मों के लेंस
(d) फ़िल्टर ग्लास	4- एलईडी इलेक्ट्रिक बल्ब

विकल्प

- (A) a-1, b-4, c-3, d-2
(B) a-2, b-3, c-1, d-4
(C) a-1, b-2, c-4, d-3
(D) a-1, b-3, c-2, d-4

Ans: (B)

Exp: क्रक्स ग्लास - धूप का चश्मा लेंस
क्राउन ग्लास - चश्मों के लेंस
लेड क्रिस्टल ग्लास - महंगा ग्लास पॉट
फ़िल्टर ग्लास - एलईडी इलेक्ट्रिक बल्ब

16. निम्नलिखित रिपोर्टों का मिलान करें -

(a) यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स	1- विश्व बैंक
(b) वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	2- आईएमएफ
(c) विश्व शक्ति भाषा सूचकांक	3- विश्व आर्थिक मंच

विकल्प

- (A) a-1, b-2, c-3
(B) a-2, b-3, c-1
(C) a-3, b-2, c-1
(D) a-1, b-3, c-2

Ans: (A)

Exp: यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स - विश्व बैंक
वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - आईएमएफ
विश्व शक्ति भाषा सूचकांक - विश्व आर्थिक मंच

17. भारत में बैंकिंग एवं वित्त से संबंधित निम्नलिखित समितियों का मिलान करें -

(a) हजारी समिति (1967)	1- औद्योगिक नीति
(b) आईटी वाज़ समिति	2- बीमा क्षेत्र में सुधार
(c) जे रेड्डी समिति	3- बैंकों में कार्यशील पूंजी वित्त

(d) जेम्स राज समिति	4- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली
---------------------	--

विकल्प

- (A) a-1, b-4, c-3, d-2
(B) a-2, b-3, c-1, d-4
(C) a-1, b-2, c-4, d-3
(D) a-1, b-3, c-2, d-4

Ans: (D)

Exp: हजारी समिति (1967) - औद्योगिक नीति
आईटी वाज़ समिति - बैंकों में कार्यशील पूंजी वित्त
जे रेड्डी समिति - बीमा क्षेत्र में सुधार
जेम्स राज समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली

18. निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों का मिलान करें -

(a) नयनतारा सहगल	1- द डे इन शैडो
(b) निकिता सिंह	2- राइट हियर राइट नाउ
(c) प्रेमेश मित्रा	3- धूलि धूसोर

विकल्प

- (A) a-1, b-2, c-3
(B) a-2, b-3, c-1
(C) a-3, b-2, c-1
(D) a-1, b-3, c-2

Ans: (A)

Exp: नयनतारा सहगल - द डे इन शैडो
निकिता सिंह - राइट हियर राइट नाउ
प्रेमेश मित्रा - धूलि धूसोर

19. निम्नलिखित का मिलान करें -

राष्ट्रीय आंदोलन	नेता/ प्रमुख विशेषता
(A) असहयोग आंदोलन	1- महात्मा गांधी
(B) सविनय अवज्ञा आंदोलन	2- चंपारण सत्याग्रह
(C) इंडिगो विद्रोह	3- नमक मार्च
(D) बारडोली सत्याग्रह	4- सरदार वल्लभभाई पटेल
(E) होम रूल आंदोलन	5- बाल गंगाधर तिलक

विकल्प:

- (A) a-1, b-3, c-2, d-4, e-5
(B) a-5, b-3, c-2, d-4, e-1
(C) a-1, b-2, c-3, d-4, e-5
(D) a-4, b-1, c-2, d-5, e-3

Ans: (B)

Exp: (a) असहयोग आंदोलन - (5) बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन के पीछे उग्र राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया।
(b) सविनय अवज्ञा आंदोलन - (3) नमक मार्च गांधीजी के नेतृत्व वाले इस आंदोलन की पहचान थी।
(c) नील विद्रोह - (2) चंपारण सत्याग्रह ने नील की खेती से संबंधित किसानों की शिकायतों को संबोधित किया।

- (d) बारदोली सत्याग्रह - (4) सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा बढ़े हुए भूमि करों के खिलाफ नेतृत्व किया गया।
 (e) स्वशासन आंदोलन - (1) स्वशासन की मांग के लिए शुरू किया गया, जिसमें गांधीजी जैसे शुरुआती नेता शामिल थे।

20. निम्नलिखित का मिलान करें -

आरबीआई समिति	उद्देश्य / प्रमुख अनुशंसाएँ
(a) नचिकेत मोर समिति (2014)	1- बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और विवेकपूर्ण मानदंड
(b) नरसिंहम समिति (1991)	2- जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखापरीक्षा
(c) तारापोर समिति (1997)	3- मौद्रिक नीति ढाँचे की समीक्षा
(d) श्यामला गोपीनाथ समिति (2015)	4- वित्तीय समावेशन और बैंकिंग पहुँच
(e) उर्जित पटेल समिति (2013)	5- पूँजी खाता परिवर्तनीयता

विकल्प:

- (A) a-4, b-1, c-5, d-2, e-3
 (B) a-2, b-1, c-4, d-3, e-5
 (C) a-4, b-2, c-5, d-1, e-3
 (D) a-1, b-2, c-3, d-4, e-5

Ans:

Exp:

- (a) नचिकेत मोर समिति (2014) — (4) वित्तीय समावेशन और समाज के बैंकिंग सुविधा से वंचित वर्गों तक बैंकिंग पहुँच के विस्तार पर केंद्रित थी।
 (b) नरसिंहम समिति (1991) — (1) ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों और बैंकों को मज़बूत बनाने के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की शुरुआत की सिफ़ारिश की।
 (c) तारापोर समिति (1997) — (5) ने भारत की विदेशी मुद्रा व्यवस्था के लिए पूँजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया।
 (d) श्यामला गोपीनाथ समिति (2015) — (2) ने बैंकों में जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणालियों में सुधार की सिफ़ारिश की।
 (e) उर्जित पटेल समिति (2013) — (3) ने मौद्रिक नीति ढाँचे की समीक्षा की और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को एक प्रमुख लक्ष्य बताया।

21. निम्नलिखित का मिलान करें -

रेडियोधर्मी तत्व	सामान्य उपयोग / विशेषता
(a) प्लूटोनियम	1- रिएक्टरों में परमाणु ईंधन
(b) टेक्नेटियम-99m	2- कैंसर रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त
(c) यूरेनियम	3- चिकित्सा इमेजिंग में प्रयुक्त
(d) आयोडीन-131	4- थायरॉइड निदान और उपचार में प्रयुक्त

(e) रेडियम	5- परमाणु हथियारों और रिएक्टरों में प्रयुक्त
------------	--

विकल्प:

- (A) a-5, b-3, c-1, d-4, e-2
 (B) a-1, b-2, c-3, d-4, e-5
 (C) a-5, b-2, c-1, d-4, e-3
 (D) a-3, b-5, c-4, d-1, e-2

Ans:

Exp:

- (a) प्लूटोनियम - परमाणु हथियारों और रिएक्टरों में प्रयुक्त:
 प्लूटोनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका उपयोग मुख्यतः परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में और अपने विखंडनीय गुणों के कारण परमाणु हथियारों के निर्माण में किया जाता है।
 (b) टेक्नेटियम-99m - चिकित्सा इमेजिंग में प्रयुक्त:
 टेक्नेटियम-99m अपने आदर्श अर्धायु और गामा उत्सर्जन के कारण विभिन्न अंगों की इमेजिंग के लिए नैदानिक परमाणु चिकित्सा में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी अनुरेखक है।
 (c) यूरेनियम - रिएक्टरों में परमाणु ईंधन:
 यूरेनियम समस्थानिक, विशेष रूप से U-235, नियंत्रित विखंडन अभिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु रिएक्टरों में प्राथमिक ईंधन के रूप में कार्य करते हैं।
 (d) आयोडीन-131 - थायरॉइड निदान और उपचार में प्रयुक्त:
 आयोडीन-131 का उपयोग थायरॉइड ग्रंथि द्वारा इसके अवशोषण और रेडियोधर्मी गुणों के कारण थायरॉइड रोगों के लिए नैदानिक और चिकित्सीय दोनों रूप से किया जाता है।
 (e) रेडियम - कैंसर रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त:
 रेडियम अल्फा कण और गामा किरणें उत्सर्जित करता है, जिनका उपयोग ऐतिहासिक रूप से रेडियोथेरेपी में घातक कोशिकाओं को नष्ट करके कुछ कैंसर के इलाज के लिए किया जाता रहा है।

निम्नलिखित को मिलाएँ:

देश	प्राकृतिक संसाधन भंडार
(a) ऑस्ट्रेलिया	1- प्लैटिनम
(b) रूस	2- लोह अयस्क
(c) दक्षिण अफ्रीका	3- प्राकृतिक गैस
(d) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	4- बॉक्साइट
(e) ब्राज़ील	5- कोबाल्ट

विकल्प:

- (A) a-5, b-4, c-2, d-1, e-3
 (B) a-1, b-2, c-3, d-4, e-5
 (C) a-4, b-3, c-1, d-5, e-2

(D) a-3, b-1, c-4, d-2, e-5

Ans: (C)

Exp:

(a) ऑस्ट्रेलिया - बॉक्साइट:

ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार है, जो एल्युमीनियम उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख अयस्क है।

(b) रूस - प्राकृतिक गैस:

रूस प्राकृतिक गैस भंडारों के मामले में अग्रणी देश है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

(c) दक्षिण अफ्रीका - प्लैटिनम:

दक्षिण अफ्रीका में दुनिया भर में सबसे बड़ा प्लैटिनम भंडार है, जो औद्योगिक और उत्प्रेरक अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है।

(d) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य - कोबाल्ट:

डीआरसी में कोबाल्ट भंडार का प्रभुत्व है, जो बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाली एक महत्वपूर्ण धातु है।

(e) ब्राज़ील - लौह अयस्क:

ब्राज़ील लौह अयस्क भंडार के अग्रणी धारकों में से एक है, जो इस्पात उत्पादन में एक प्रमुख कच्चा माल है।

23. निम्नलिखित का मिलान करें -

वेदों का विवरण	विशेषता
(a) ऋग्वेद	1- धुनों और मंत्रों का संग्रह
(b) सामवेद	2- इसमें मंत्र, मन्त्र और दैनिक जीवन का ज्ञान समाहित है
(c) यजुर्वेद	3- विभिन्न देवताओं के भजन और स्तुति
(d) अथर्ववेद	4- अनुष्ठानों और यज्ञों के लिए गद्य मंत्र

विकल्प:

(A) a-1, b-2, c-3, d-4

(B) a-3, b-1, c-4, d-2

(C) a-2, b-3, c-1, d-4

(D) a-1, b-3, c-2, d-4

Ans: (B)

Exp:

ऋग्वेद (a): इसमें मुख्यतः विभिन्न देवताओं के भजन और स्तुतियाँ हैं और इसे चारों वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन भजनों की रचना अनुष्ठानों के दौरान पाठ के लिए की गई थी।

सामवेद (b): मुख्यतः धुनों और मंत्रों का संग्रह, सामवेद ऋग्वेद के भजनों को संगीतमय स्वरों में ढालता है और यज्ञों के दौरान पवित्र मंत्रों के प्रदर्शन में इसका उपयोग किया जाता है।

यजुर्वेद (c): इस वेद में अनुष्ठानों और यज्ञों में प्रयुक्त गद्य मंत्र और सूत्र हैं, जो अनुष्ठान करने वाले पुजारियों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं।

अथर्ववेद (d): अन्य तीन वेदों के विपरीत, अथर्ववेद में मंत्र, तावीज़ और दैनिक जीवन, उपचार और सुरक्षा से संबंधित

व्यावहारिक ज्ञान शामिल है, जो विषय-वस्तु के अधिक विविध स्वरूप को दर्शाता है।

निम्नलिखित का मिलान करें -

प्राचीन गाँव/स्थल	प्रमुख पुरातात्विक महत्व
(a) चंद्रकेतुगढ़	1- कपास की खेती और उन्नत शिल्प के प्रारंभिक साक्ष्य
(b) कौशांबी	2- प्राचीन गोदी और समुद्री व्यापार के साक्ष्य
(c) मेहरगढ़	3- मौर्यकालीन कलाकृतियों के साथ किलेबंद शहरी बस्ती
(d) लोथल	4- टेराकोटा कलाकृतियाँ और प्राचीन व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य

विकल्प:

(A) a-3, b-4, c-2, d-1

(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(C) a-4, b-3, c-1, d-2

(D) a-2, b-1, c-4, d-3

Ans: (C)

Exp:

चंद्रकेतुगढ़ (क-4):

पश्चिम बंगाल में स्थित, चंद्रकेतुगढ़ अपनी टेराकोटा कलाकृतियों और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंधों के साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था।

कौशांबी (ख-3):

मौर्य काल में कौशांबी एक महत्वपूर्ण किलेबंद शहरी बस्ती थी। उत्खनन से मौर्य काल की कलाकृतियाँ और संरचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जो प्राचीन भारत में इसके राजनीतिक और सामरिक महत्व को दर्शाती हैं।

मेहरगढ़ (ग-1):

वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़, नवपाषाण काल के दौरान कपास की खेती और मनके बनाने व मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे उन्नत शिल्पों के साक्ष्यों वाला सबसे प्रारंभिक स्थल है, जो शिकारी-संग्राहक समाजों से कृषि समाजों में संक्रमण का प्रतीक है।

लोथल (घ-2):

गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा, लोथल, अपने प्राचीन गोदी के लिए प्रसिद्ध है, जो समुद्री व्यापार और शहरी नियोजन के परिष्कृत ज्ञान को दर्शाता है।

निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों को उनकी प्रमुख उपलब्धियों से मिलाएं:

मिशन	प्रमुख उपलब्धियाँ
1. वॉयेजर 1	A. चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग

2. हबल स्पेस टेलीस्कोप	B. सौर मंडल छोड़ने वाला पहला अंतरिक्ष यान
3. अपोलो 11	C. दूर की आकाशगंगाओं की विस्तृत छवियां प्रदान कीं
4. मार्स रोवर क्यूरियोसिटी	D. मंगल की विस्तृत सतह की खोज
5. स्पुतनिक 1	E. अंतरिक्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह

विकल्प:

(A) 1-B, 2-C, 3-A, 4-D, 5-E

(B) 1-C, 2-B, 3-A, 4-E, 5-D

(C) 1-B, 2-D, 3-E, 4-C, 5-A

(D) 1-E, 2-A, 3-C, 4-B, 5-D

Ans: (A)

Exp:

वायेजर 1: वायेजर 1 सौर मंडल से बाहर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, जिसने अंतरतारकीय अंतरिक्ष के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान किया।

हबल स्पेस टेलीस्कोप: हबल स्पेस टेलीस्कोप ने दूर की आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय घटनाओं के बारे में विस्तृत चित्र और डेटा प्रदान किया है।

अपोलो 11: अपोलो 11 वह मिशन था जिसने चंद्रमा पर पहली बार मानव लैंडिंग की थी।

मंगल रोवर क्यूरियोसिटी: क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर व्यापक सतह अन्वेषण और अनुसंधान किया है।

स्पुतनिक 1: स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था, जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत को चिह्नित किया।

26. निम्नलिखित ऐतिहासिक हस्तियों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों से मिलाएं:

ऐतिहासिक हस्तियां	उपलब्धियां
1. मैरी क्यूरी	A. सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया
2. अल्बर्ट आइंस्टीन	B. रेडियोधर्मिता की खोज की
3. लियोनार्डो दा विंची	C. मोना लिसा को चित्रित किया
4. आइजैक न्यूटन	D. गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तैयार किया
5. गैलीलियो गैलीली	E. दूरबीन का आविष्कार किया और सूर्यकेंद्रवाद का समर्थन किया

विकल्प:

(A) 1-A, 2-B, 3-E, 4-D, 5-C

(B) 1-B, 2-C, 3-E, 4-D, 5-A

(C) 1-B, 2-A, 3-C, 4-D, 5-E

(D) 1-E, 2-D, 3-A, 4-C, 5-B

Ans:

Exp:

(C)

मैरी क्यूरी: मैरी क्यूरी रेडियोधर्मिता पर अपने अग्रणी शोध के लिए जानी जाती हैं, जिसके लिए उन्हें दो नोबेल पुरस्कार मिले।

अल्बर्ट आइंस्टीन: अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया, जो आधुनिक भौतिकी की आधारशिला है।

लियोनार्डो दा विंची: लियोनार्डो दा विंची मोना लिसा सहित अपनी उत्कृष्ट कृतियों के लिए प्रसिद्ध हैं।

आइजैक न्यूटन: आइजैक न्यूटन ने गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तैयार किया, जिसने शास्त्रीय भौतिकी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।

गैलीलियो गैलीली: गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और सौर मंडल के सूर्यकेंद्रित मॉडल का समर्थन किया, जिसने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी।

निम्नलिखित अंतरिक्ष शब्दों का उनके विवरण से मिलान करें:

शब्द	विवरण
1. थर्मोस्फीयर	A. पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडल की परत
2. समताप मंडल	B. जहाँ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परिक्रमा करता है
3. क्षोभमंडल	C. मध्यमंडल के ऊपर की परत
4. मध्यमंडल	D. वायुमंडल की वह परत जहाँ उल्काएँ जलती हैं

विकल्प:

(A) a-3, b-4, c-2, d-1

(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(C) a-2, b-3, c-4, d-1

(D) a-4, b-1, c-2, d-3

Ans:

Exp:

(B)

थर्मोस्फीयर: यह परत मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित है और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परिक्रमा करता है।

समताप मंडल: यह परत क्षोभमंडल के ठीक ऊपर है और इसमें ओजोन परत होती है।

क्षोभमंडल: पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जहाँ मौसम होता है।

मध्यमंडल: समताप मंडल के ऊपर की परत, जहाँ उल्काएँ जलती हैं।

28.

निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं का उनके संगत वर्षों से मिलान करें:

घटना	वर्ष
------	------

1. बर्लिन की दीवार का गिरना	A. 1776
2. स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर	B. 1989
3. अमेरिकी गृह युद्ध का अंत	C. 1865
4. पहली चंद्रमा लैंडिंग	D. 1969

विकल्प:

(A) a-3, b-2, c-1, d-4

(B) a-4, b-3, c-2, d-1

(C) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-2, b-4, c-1, d-3

Ans:

Exp:

(C) बर्लिन की दीवार का गिरना: यह घटना 1989 में हुई, जो शीत युद्ध के अंत में एक महत्वपूर्ण क्षण था।

स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर: यह 1776 में हुआ, जब अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।

अमेरिकी गृह युद्ध का अंत: यह 1865 में हुआ, जब गृह युद्ध संघीय बलों के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ।

पहली चंद्रमा लैंडिंग: पहली सफल मानवयुक्त चंद्रमा लैंडिंग 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान हुई थी।

30.

29.

निम्नलिखित का मिलान करें - चुनावी सुधार

प्रावधान / सुधार	वर्ष / अधिनियम / विवरण
(a) चुनावों में NOTA का विकल्प	1 - 1989 (केरल में पहली बार इस्तेमाल किया गया)
(b) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रचलन	2 - 1988 (61वाँ संविधान संशोधन)
(c) मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना	3 - 2002 (PUCI सुप्रीम कोर्ट का फैसला)
(d) उम्मीदवारों के बारे में सूचना का अधिकार	4 - 2013 (पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला)

विकल्प:

(A) a-4, b-1, c-2, d-3

(B) a-3, b-2, c-1, d-4

(C) a-2, b-4, c-3, d-1

(D) a-1, b-3, c-4, d-2

Ans:

Exp:

(A) (a) चुनावों में नोटा विकल्प → 2013

पीपुल्स यूनिन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को मतदाताओं की पसंद को मज़बूत करने के लिए ईवीएम में

"इनमें से कोई नहीं" (नोटा) विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

(b) ईवीएम का परिचय → 1989

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग पहली बार 1989 में केरल में प्रायोगिक तौर पर किया गया था। बाद में, 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद, इनका व्यापक रूप से उपयोग होने लगा।

(c) मतदान की आयु में कमी → 1988 (61वाँ सीएए)

61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जो 1989 के आम चुनावों से प्रभावी हुई।

(d) उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार → 2002 एक अन्य पीयूसीएल मामले (2002) में सर्वोच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों के लिए हलफनामों में आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया।

निम्नलिखित का मिलान करें - भारत में प्रमुख कर सुधार

प्रावधान / सुधार	वर्ष / अधिनियम / विवरण
(a) वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत	1 - 1994 (डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा केंद्रीय बजट)
(b) भारत में वैट की शुरुआत	2 - 2017 (101वाँ संविधान संशोधन)
(c) प्रत्यक्ष करों पर केलकर समिति	3 - 2005 (पहले हरियाणा में लागू, फिर पूरे देश में)
(d) सेवा कर की शुरुआत	4 - 2002 (कर प्रणाली के सरलीकरण की सिफारिश)

विकल्प:

(A) a-2, b-3, c-4, d-1

(B) a-3, b-2, c-1, d-4

(C) a-1, b-4, c-2, d-3

(D) a-4, b-1, c-3, d-2

Ans:

Exp:

(A)

जीएसटी → 2017 - 101वें संशोधन के अंतर्गत लाया गया, अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल किया गया।

वैट → 2005 - पहले हरियाणा में, बाद में पूरे देश में।

केलकर समिति → 2002 - प्रत्यक्ष करों को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया।

सेवा कर → 1994 - कुछ सेवाओं पर लागू किया गया, बाद में इसका विस्तार किया गया।

31. भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित क्रांतिकारी/राजनीतिक घटनाओं का उनकी संबद्ध विशेषताओं या परिणामों से मिलान कीजिए:

घटना	संबद्ध विशेषता/परिणाम
(a) काकोरी रेलगाड़ी कार्रवाई (1925)	1 – हिंसा के बाद गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना
(b) चौरी चौरा कांड (1922)	2 – HRA गतिविधियों के लिए सरकारी खजाने के धन को जब्त करने का क्रांतिकारी प्रयास
(c) कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन (1929)	3 – कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में "पूर्ण स्वराज" की घोषणा
(d) अगस्त प्रस्ताव (1940)	4 – युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट्स का प्रस्ताव, लेकिन कांग्रेस द्वारा अस्वीकार

विकल्प:

(A) a-2, b-1, c-3, d-4

(B) a-3, b-2, c-4, d-1

(C) a-4, b-3, c-2, d-1

(D) a-1, b-4, c-2, d-3

Ans:

Exp:

(a) काकोरी रेलगाड़ी कार्रवाई (1925) → सरकारी खजाने को जब्त करने का क्रांतिकारी प्रयास (2):

हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला खान जैसे सदस्यों द्वारा संचालित, इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के वित्तपोषण के लिए ट्रेनों में ले जाए जा रहे सरकारी धन को लूटना था। इसके परिणामस्वरूप क्रांतिकारियों पर कठोर दमन, फाँसी और मुकदमे चलाए गए।

(b) चौरी चौरा कांड (1922) → गांधीजी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया (1):

गोरखपुर जिले में हिंसक झड़प हुई, जहाँ एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई। इसने गांधीजी को राष्ट्रव्यापी गति के बावजूद, असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने के लिए मजबूर किया, जो अहिंसा के प्रति उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाता है।

(c) कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन (1929) → पूर्ण स्वराज (3):

जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इस अधिवेशन ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता को अपना उद्देश्य घोषित किया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को "स्वतंत्रता दिवस" के रूप में मनाने का भी आह्वान किया गया, जिसे बाद में भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया।

(d) अगस्त प्रस्ताव (1940) → डोमिनियन स्टेट्स का वादा (4):

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा घोषित, इसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट्स और भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि का प्रस्ताव था, लेकिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया।

32.

नागरिकों के लिए निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों का उनके विशिष्ट सूक्ष्म अंतर्ग/उन्नत संदर्भों से मिलान करें:

प्रावधान	उन्नत संदर्भ/सूक्ष्म अंतर
(a) अनुच्छेद 16(4A)	1 – अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का विशेष प्रावधान (77वें संशोधन, 1995 द्वारा जोड़ा गया)
(b) अनुच्छेद 18(1)	2 – सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टताओं को छोड़कर सभी उपाधियों को समाप्त करता है, जिससे स्थिति की समानता सुनिश्चित होती है
(c) अनुच्छेद 22(3)	3 – निवारक निरोध केवल सलाहकार बोर्ड की स्वीकृति से 3 महीने से अधिक समय तक निरोध की अनुमति देता है
(d) अनुच्छेद 29(1)	4 – विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के एक वर्ग का उसे संरक्षित करने का अधिकार

विकल्प:

(A) a-3, b-4, c-1, d-2

(B) a-1, b-2, c-3, d-4

(C) a-2, b-1, c-4, d-3

(D) a-4, b-3, c-2, d-1

(B)

Ans:

Exp:

(a) अनुच्छेद 16(4A) → पदोन्नति में आरक्षण (1):

यह 77वें संशोधन, 1995 के माध्यम से जोड़ा गया था ताकि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कर सकें। बाद में एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) में इसे बरकरार रखा गया और स्पष्ट किया गया।

(b) अनुच्छेद 18(1) → उपाधियों का उन्मूलन (2):

यह राज्य को उपाधियाँ (जैसे, महाराजा, राय बहादुर) प्रदान करने से स्पष्ट रूप से रोकता है। अपवाद: सैन्य और शैक्षणिक उपाधियाँ। ऐतिहासिक मामला: बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) ने स्पष्ट किया कि भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार 'उपाधियाँ' नहीं हैं।

(c) अनुच्छेद 22(3) → निवारक निरोध (3):

एक विवादास्पद प्रावधान जो न्यायाधीशों के एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने पर ही 3 महीने से अधिक समय तक निरोध की अनुमति देता है। अधिकतम सीमा: 12 महीने (सामान्यतः) जब तक कि संसद अन्यथा कानून न बनाए। संविधान में "औपनिवेशिक विरासत" के रूप में आलोचना की गई।

(d) अनुच्छेद 29(1) → सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (4):

विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले वर्ग के नागरिकों के उसे संरक्षित रखने के अधिकार की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण।

33. निम्नलिखित का मिलान करें - भारत में नव नामित राष्ट्रीय उद्यान -

राष्ट्रीय उद्यान	सही सुविधा/विवरण
(a) सिमिलिपल नेशनल पार्क	1 - असम का 8 वां एनपी, मानस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा
(b) सिखना JHWLAWO नेशनल पार्क	2 - 2018 में एनपी में अपग्रेड किया गया, पुनर्संयोजन योजनाओं का हिस्सा
(c) रायमोना नेशनल पार्क	3 - असम का 6 वां एनपी, बफर टू मानस टाइगर रिजर्व
(d) कुनो नेशनल पार्क	4 - ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान; भारत में 107 वां एनपी

विकल्प:

(A) a-4, b-1, c-3, d-2

(B) a-2, b-3, c-1, d-4

(C) a-3, b-2, c-4, d-1

(D) a-1, b-4, c-2, d-3

Ans: (A)

Exp: (a) सिमिलिपल नेशनल पार्क - 8 ओडिशा में स्थित, सिमिलिपल राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसे भारत के 107 वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई थी।

(b) सिख JHWLAWO नेशनल पार्क - 1

2021 में घोषित, यह असम का 8 वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया।

(c) रायमोना नेशनल पार्क - 3

2021 में घोषित, रायमोना असम का 6 वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया।

(d) कुनो नेशनल पार्क - 2

मूल रूप से मध्य प्रदेश में एक वन्यजीव अभयारण्य, इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था।

निम्नलिखित से मिलान करें - प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके योगदान -

व्यक्तित्व	योगदान
(a) गोपाल हरि देशमुख (लोकहितवादी)	3 - शतपत्रे लेखों के माध्यम से सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों की आलोचना
(b) ईश्वर चंद्र विद्यासागर	4 - हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) के पारित होने में प्रमुख भूमिका
(c) सर सैयद अहमद खान	1 - अलीगढ़ आंदोलन व मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना
(d) ज्योतिबा फुले	2 - सत्यशोधक समाज की स्थापना, शूद्रों व महिलाओं के उत्थान हेतु संघर्ष

विकल्प:

(A) a-2, b-3, c-1, d-4

(B) a-3, b-4, c-1, d-2

(C) a-4, b-1, c-3, d-2

(D) a-1, b-2, c-4, d-3

Ans: (B)

Exp:

गोपाल हरि देशमुख (लोकहितवादी) → (3):

मराठी समाज सुधारक, जिनके शतपत्रे लेखों ने जातिगत भेदभाव, बाल विवाह व अंधविश्वास पर तीखी चोट की।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर → (4):

महिलाओं की शिक्षा व अधिकारों के पक्षधर। उनकी कोशिशों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 पारित हुआ।

सर सैयद अहमद खान → (1):

अलीगढ़ आंदोलन के जनक। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) की स्थापना की और मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा की ओर प्रेरित किया।

ज्योतिबा फुले → (2):

1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। स्त्रियों की शिक्षा और दलितों-शूद्रों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। गुलामगिरी जैसी रचना लिखी।

35.

सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों का उनके प्रमुख निर्णयों से मिलान करें:

मामला	निर्णय/सिद्धांत
(a) मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985)	1- प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार; उचित प्रतिबंध लगाने की

	सरकार की शक्ति को बरकरार रखा
(b) ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985)	2- अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आजीविका का अधिकार शामिल
(c) बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ (1973)	3- धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार
(d) भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल (1985)	4- राष्ट्रीय सुरक्षा या आपातकाल के मामलों में प्राकृतिक न्याय को बाहर रखा जा सकता है

विकल्प:

- (A) a-1, b-4, c-2, d-3
(B) a-2, b-3, c-4, d-1
(C) a-4, b-1, c-3, d-2
(D) a-3, b-2, c-1, d-4

Ans:

Exp:

शाह बानो मामला (1985): यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार को बरकरार रखा और धर्मनिरपेक्ष कानून को पर्सनल लॉ पर मजबूत बनाया।

ओल्गा टेलिस (1985): सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि "जीवन का अधिकार = आजीविका का अधिकार"; फुटपाथ पर रहने वालों को पुनर्वास के बिना बेदखल करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

बेनेट कोलमैन (1973): प्रेस की स्वतंत्रता का विस्तार किया और अखबारी कागज पर नियंत्रण आदेश को अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया।

तुलसीराम पटेल (1985): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आपातकालीन स्थितियों से जुड़े मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार किया जा सकता है।

36. निम्नलिखित खाड़ियों का उनके सामरिक/भौगोलिक महत्व मिलान करें:

खाड़ी	विवरण
(a) अदन की खाड़ी	1- ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करती है; तेल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण

(b) मन्नार की खाड़ी	2- भारत और श्रीलंका के बीच समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध
(c) फारस की खाड़ी	3- बाब-अल-मंडेब के माध्यम से अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है
(d) बोथनिया की खाड़ी	4- स्वीडन और फ़िनलैंड के बीच बाल्टिक सागर की सबसे उत्तरी भुजा

विकल्प:

- (A) a-3, b-2, c-1, d-4
(B) a-1, b-3, c-2, d-4
(C) a-4, b-1, c-3, d-2
(D) a-2, b-4, c-1, d-3

Ans:

Exp:

अदन की खाड़ी: बाब-अल-मंडेब के माध्यम से अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है; वैश्विक व्यापार और समुद्री डकैती संबंधी चिंताओं के लिए महत्वपूर्ण।

मन्नार की खाड़ी: भारत और श्रीलंका के बीच, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, प्रवाल भित्तियाँ और मोती बैंक।

फारस की खाड़ी: दुनिया का सबसे बड़ा तेल शिपिंग मार्ग; ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है।

बोथनिया की खाड़ी: बाल्टिक सागर की सबसे उत्तरी शाखा, स्वीडन और फ़िनलैंड के बीच स्थित है।

37.

निम्नलिखित देशों को उनके महत्वपूर्ण स्थलों से मिलाएं:

देश	स्थलचिह्न
1. ब्राज़ील	A. क्राइस्ट द रिडीमर
2. इटली	B. कोलोसियम
3. जापान	C. माउंट फूजी
4. ऑस्ट्रेलिया	D. सिडनी ओपेरा हाउस

विकल्प:

- (A) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D
(B) 1-B, 2-D, 3-A, 4-C
(C) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A
(D) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B

Ans:

Exp:

क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील में एक मील का पत्थर है।

कोलोसियम इटली में एक प्रसिद्ध मील का पत्थर है।

माउंट फूजी जापान में एक प्रसिद्ध मील का पत्थर है।

सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है।

38.

निम्नलिखित देशों को उनके सबसे प्रसिद्ध त्यौहारों से मिलाएं:

देश	त्यौहार
1. ब्राज़ील	A. कार्निवल
2. जापान	B. हनामी

3. स्पेन	C. रनिंग ऑफ़ द बुल्स
4. जर्मनी	D. ऑक्टोबरफेस्ट

विकल्प:

(A) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

(B) 1-D, 2-C, 3-B, 4-A

(C) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B

(D) 1-B, 2-D, 3-A, 4-C

Ans: (A)

Exp: कार्निवल ब्राज़ील में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है।

हनामी, या चेरी ब्लॉसम देखना, जापान में एक लोकप्रिय त्यौहार है।

बुल्स की दौड़ स्पेन में एक प्रसिद्ध त्यौहार है।

ऑक्टोबरफेस्ट जर्मनी में आयोजित होने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, जो अपनी बीयर और सांस्कृतिक समारोहों के लिए जाना जाता है।

39. निम्नलिखित विषाणु संक्रमणों का मिलान उनकी खोज/अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिकों से कीजिए:

विषाणु संक्रमण	वैज्ञानिक/आविष्कारक
(a) रेबीज	1- लुई पाश्चर
(b) पोलियो	2- जोनास साल्क
(c) डेंगू विषाणु	3- अल्बर्ट सैबिन
(d) रूबेला विषाणु	4- जॉर्ज डी स्टेफ़ानो / थॉमस वेलर (1962 पृथक्करण)

विकल्प:

(A) a-1, b-2, c-3, d-4

(B) a-3, b-4, c-1, d-2

(C) a-4, b-1, c-2, d-3

(D) a-2, b-3, c-4, d-1

Ans: (A)

Exp: (a) रेबीज़ → लुई पाश्चर

(b) पोलियो → जोनास साल्क

(c) डेंगू वायरस → अल्बर्ट साबिन

(d) रूबेला वायरस → जॉर्ज डी स्टेफ़ानो / थॉमस वेलर

40. निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष मिशनों का मिलान उनसे जुड़े प्रमुख वैज्ञानिकों/नेताओं से कीजिए:

अंतरिक्ष मिशन	प्रमुख व्यक्ति
(a) चंद्रयान-1	2- के. राधाकृष्णन (MOM के दौरान इसरो प्रमुख)
(b) मंगलयान (मंगल परिक्रमा यान)	4- माधवन नायर (2008 के दौरान इसरो प्रमुख)
(c) चंद्रयान-2	1- के. सिवन (इसरो प्रमुख, निर्देशित मिशन 2019)

(d) चंद्रयान-3	3- एस. सोमनाथ (वर्तमान इसरो प्रमुख, 2023)
----------------	---

विकल्प:

(A) a-1, b-2, c-4, d-3

(B) a-2, b-3, c-1, d-4

(C) a-4, b-2, c-1, d-3

(D) a-3, b-1, c-4, d-2

(C)

(a) चंद्रयान-1 → माधवन नायर (2008 में इसरो प्रमुख)

(b) मंगलयान (2013) → के. राधाकृष्णन (निर्देशित एमओएम सफलता)

(c) चंद्रयान -2 (2019) → के. सिवन (सॉफ्ट लैंडिंग पर मिशन का प्रयास)

(d) चंद्रयान-3 (2023) → एस. सोमनाथ (सफल सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की)

निम्नलिखित का मिलान करें - कम प्रमुख वर्षावन (बहुत प्रसिद्ध नहीं, मिश्रित)

वर्षावन	मुख्य विशेषता/स्थान
(a) डेनट्री वर्षावन	1- अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन
(b) कांगो वर्षावन	2- विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया
(c) वाल्डिवियन वर्षावन	3- ऑस्ट्रेलिया का प्राचीन वर्षावन, उच्च जैव विविधता
(d) न्यू गिनी वर्षावन	4- चिली का समशीतोष्ण वर्षावन, समृद्ध वनस्पति और जीव

विकल्प:

(A) a-3, b-1, c-4, d-2

(B) a-2, b-3, c-1, d-4

(C) a-1, b-2, c-3, d-4

(D) a-4, b-1, c-2, d-3

(A)

डेनट्री वर्षावन → 3: ऑस्ट्रेलिया में प्राचीन वर्षावन, उच्च जैव विविधता।

कांगो वर्षावन → 1: अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन।

वाल्विवियन वर्षावन → 4: चिली में अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों वाला समशीतोष्ण वर्षावन।

न्यू गिनी वर्षावन → 2: पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया में प्रमुख उष्णकटिबंधीय वर्षावन।

42.

निम्नलिखित का मिलान करें - कम प्रमुख संविधान संशोधन (बदल दिया गया)

संशोधन	मुख्य विशेषता/उद्देश्य
--------	------------------------

(a) 97वाँ संशोधन	1- 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया
(b) 95वाँ संशोधन	2- लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई
(c) 86वाँ संशोधन	3- उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते में वृद्धि की गई
(d) 91वाँ संशोधन	4- सहकारी समितियों और सहकारी शासन को सुदृढ़ बनाया गया

विकल्प:

(A) a-1, b-2, c-3, d-4

(B) a-3, b-4, c-2, d-1

(C) a-2, b-1, c-4, d-3

(D) a-4, b-3, c-1, d-2

Ans: (D)

Exp: 97वाँ संशोधन → 4: सहकारी समितियों और शासन को सुदृढ़ बनाया गया।

95वाँ संशोधन → 3: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते बढ़ाए गए।

86वाँ संशोधन → 1: 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार।

91वाँ संशोधन → 2: मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।

43. निम्नलिखित जीआई टैग की गई साड़ियों का मिलान करें:

(a) तमिलनाडु	1- कंठांगी साड़ी
(b) उत्तर प्रदेश	2- उप्पदा जामदानी साड़ी
(c) कर्नाटक	3- इलकल साड़ी
(d) आंध्र प्रदेश	4- बनारस ब्रोकेड

विकल्प

(A) a-1, b-4, c-3, d-2

(B) a-2, b-3, c-1, d-4

(C) a-1, b-2, c-4, d-3

(D) a-1, b-3, c-2, d-4

Ans: (A)

Exp: तमिलनाडु - कंठांगी साड़ी, थिरुबुवनम सिल्क साड़ी, कोवई कोरा कॉटन साड़ी

उत्तर प्रदेश - बनारस ब्रोकेड

कर्नाटक - इलकल साड़ी, मोलाकलमुरु साड़ी

आंध्र प्रदेश - उप्पदा जामदानी साड़ी, वेंकटगिरी साड़ी, मंगलगिरी साड़ी

44. निम्नलिखित का मिलान करें -

(a) लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ	1- केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट
--------------------------	-----------------------------

(b) द्रव्यमान के संरक्षण का नियम	2- फूरियर लॉ
(c) हबल लॉ	3- बेल्स प्रमेय

(A) a-1, b-2, c-3

(B) a-2, b-3, c-1

(C) a-3, b-2, c-1

(D) a-1, b-3, c-2

Ans: (A)

Exp: लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट
द्रव्यमान के संरक्षण का नियम फूरियर लॉ
हबल लॉ बेल्स प्रमेय

45. निम्नलिखित लोक नृत्यों को सुमेलित कीजिए -

(a) असम	1- डोंगी
(b) हरियाणा	2- गुग्गा
(c) कर्नाटक	3- पेनका
(d) ओडिशा	4- कुनिथा

विकल्प

(A) a-1, b-4, c-3, d-2

(B) a-2, b-3, c-1, d-4

(C) a-1, b-2, c-4, d-3

(D) a-1, b-3, c-2, d-4

Ans: (C)

Exp: असम - डोंगी
हरियाणा - गुग्गा
कर्नाटक - कुनिथा
ओडिशा - पेनका

46. निम्नलिखित बांधों और जलाशयों का मिलान करें -

(a) निजाम सागर बांध	1- मंजीरा नदी
(b) सोमसिला बांध	2- पेन्नार नदी
(c) उकाई बांध	3- ताप्ती नदी

विकल्प

(A) a-1, b-2, c-3

(B) a-2, b-3, c-1

(C) a-3, b-2, c-1

(D) a-1, b-3, c-2

Ans: (A)

Exp: निजाम सागर बांध - मंजीरा नदी
सोमसिला बांध - पेन्नार नदी
उकाई बांध - ताप्ती नदी

47. निम्नलिखित का मिलान करें -

थर्मल पावर स्टेशन	राज्य
(a) विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	1- महाराष्ट्र
(b) मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन	2- मध्य प्रदेश

(c) ट्रॉम्बे थर्मल पावर स्टेशन	3- गुजरात
(d) कोरबा थर्मल पावर स्टेशन	4- छत्तीसगढ़

विकल्प:

- (A) a-2, b-3, c-1, d-4
(B) a-4, b-3, c-1, d-2
(C) a-2, b-3, c-4, d-1
(D) a-3, b-2, c-1, d-4

Ans:

Exp:

(B)
विंध्याचल टीपीएस → मध्य प्रदेश
मुंद्रा टीपीएस → गुजरात
ट्रॉम्बे टीपीएस → महाराष्ट्र
कोरबा टीपीएस → छत्तीसगढ़

48. निम्नलिखित का मिलान करें -

स्तनपायी	वैज्ञानिक नाम
(a) नीलगिरि तहर	1- प्लेटनिस्टा गैंगेटिका
(b) डुगोंग	2- टेरोपस गिगेंटस
(c) इंडियन फ्लाईंग फॉक्स	3- नीलगिरिट्रैगस हाइलोक्रियस
(d) गंगा नदी डॉल्फिन	4- डुगोंग डुगोन

विकल्प:

- (A) a-3, b-4, c-2, d-1
(B) a-1, b-2, c-3, d-4
(C) a-4, b-3, c-1, d-2
(D) a-2, b-1, c-4, d-3

Ans:

Exp:

(A)
नीलगिरि तहर → नीलगिरिट्रैगस हाइलोक्रियस
डुगोंग → डुगोंग डुगोन
इंडियन फ्लाईंग फॉक्स → टेरोपस गिगेंटस
गंगा नदी डॉल्फिन → प्लेटनिस्टा गैंगेटिका

49. निम्नलिखित का मिलान करें -

महासागरीय धारा	विशेषताएँ / स्थान
(a) हम्बोल्ट (पेरू) धारा	1- मेक्सिको की खाड़ी से उत्तरी अटलांटिक तक बहने वाली गर्म धारा
(b) कुरोशियो धारा	2- उत्तरी अटलांटिक में कनाडा के तट के साथ बहने वाली ठंडी धारा
(c) गल्फ स्ट्रीम	3- जापान के पूर्वी तट के साथ बहने वाली गर्म धारा
(d) लैब्राडोर धारा	4- अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी तट के साथ बहने वाली ठंडी धारा

(e) बेंगुएला धारा	5- दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ बहने वाली ठंडी धारा
-------------------	--

विकल्प:

- (A) a-5, b-3, c-1, d-2, e-4
(B) a-4, b-1, c-3, d-5, e-2
(C) a-5, b-1, c-3, d-2, e-4
(D) a-2, b-3, c-1, d-4, e-5

Ans:

Exp:

(A)
हम्बोल्ट (पेरू) धारा (a-5): दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहने वाली एक ठंडी धारा, जो समुद्री जीवन से भरपूर है।
कुरोशियो धारा (b-3): इसे जापान धारा भी कहा जाता है, यह जापान के पूर्वी तट पर बहने वाली एक गर्म धारा है।
गल्फ स्ट्रीम (c-1): मेक्सिको की खाड़ी से निकलने वाली एक गर्म अटलांटिक धारा, जो अमेरिका के पूर्वी तट से होते हुए यूरोप की ओर बहती है।
लैब्राडोर धारा (d-2): उत्तरी अटलांटिक में कनाडा के उत्तर-पूर्वी तट पर बहने वाली एक ठंडी धारा।
बेंगुएला धारा (e-4): अफ्रीका के दक्षिण-पश्चिमी तट पर उत्तर की ओर बहने वाली एक ठंडी धारा।

50. निम्नलिखित का मिलान करें -

जलडमरूमध्य	स्थान / महत्व
(a) होर्मुज जलडमरूमध्य	1- अलास्का और रूस के बीच, बेरिंग सागर और बेरिंग जलडमरूमध्य को जोड़ता है
(b) मलक्का जलडमरूमध्य	2- डेनमार्क और स्वीडन के बीच, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है
(c) बेरिंग जलडमरूमध्य	3- भारत और श्रीलंका के बीच, हिंद महासागर व्यापार के लिए महत्वपूर्ण
(d) ओरेसंड जलडमरूमध्य	4- फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, रणनीतिक तेल नौवहन मार्ग
(e) पाक जलडमरूमध्य	5- प्रायद्वीपीय मलेशिया और सुमात्रा के बीच, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख समुद्री मार्ग

विकल्प:

- (A) a-4, b-3, c-5, d-2, e-1
(B) a-5, b-4, c-2, d-1, e-3
(C) a-4, b-5, c-1, d-2, e-3
(D) a-2, b-1, c-4, d-5, e-3

Ans:

(C)

Exp: होर्मुज जलडमरूमध्य (a-4): फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक रणनीतिक संकरा मार्ग, जो वैश्विक तेल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है।
मलक्का जलडमरूमध्य (b-5): प्रायद्वीपीय मलेशिया और सुमात्रा के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग, जो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है।
बेरिंग जलडमरूमध्य (c-1): अलास्का और रूस को अलग करता है, बेरिंग सागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है।

ओरेसंड जलडमरूमध्य (d-2): डेनमार्क और स्वीडन के बीच स्थित, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है।

पाक जलडमरूमध्य (e-3): भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जो क्षेत्रीय मछली पकड़ने और नौवहन के लिए महत्वपूर्ण है।

"जिन्दगी के लिए कभी खराब विचार आये तो एक बात हमेशा याद रखना !
तुम जो जिन्दगी जी रहे हो वो भी किसी के लिए सपने जैसी ही होगी !!"

"सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है !
सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत !!"

WORLD SUICIDE PREVENTION DAY



Inception: 2003

10
SEP

Importance

To provide worldwide commitment and action to prevent suicides, with various activities around the world since 2003.

Motto

To raise awareness around the globe that suicide can be prevented.

Organisation Involved

International Association for Suicide Prevention (IASP), World Health Organization (WHO) and the World Federation for Mental Health (WFMH).

2025 Theme

Changing the Narrative on Suicide.

Note

In 2014, the first WHO World Suicide report was released "Preventing Suicide: A Global Imperative".

PATRIOT DAY



Inception: 2002

11
SEP

Importance

To honor the memory of nearly 3,000 people who were killed in the September 11, 2001, terrorist attack in USA.

Note

4 September 2002, US President Bush proclaimed September 11, 2002, as the first Patriot Day.

History

• On September 11, 2001, four planes were hijacked. The hijackers then deliberately flew three of the planes into two important buildings, the Pentagon in Washington DC and the Twin Towers of the World Trade Center in New York. The fourth crashed into a field near Shanksville, Pennsylvania.

• **Note:** Patriot Day should not be confused with Patriots Day, also known as Patriots Day, which commemorates the battles of Lexington and Concord in 1775, which were two of the earliest battles in the American Revolutionary War.

क्विक बाइट्स

- भारतीय सेना ने अरुणाचल में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास सफलतापूर्वक किया
- सिंगापुर एशिया में सबसे सुरक्षित और वैश्विक शांति सूचकांक '25 में छठे स्थान पर
- भारत ने विदेशी पूंजी को बढ़ावा देने के लिए बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की घोषणा की
- नई दिल्ली अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा
- ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में असम को 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र उधार देगा
- भारतीय सेना पाँच 'भैरव' कमांडो बटालियन बनाएगी
- ऑस्ट्रेलिया ने गैर-वीज़ा धारकों के लिए नाउरू के साथ 267 मिलियन डॉलर के निवासन समझौते पर हस्ताक्षर किए
- सेना और ITBP ने अरुणाचल प्रदेश में अचूक प्रहार अभ्यास समाप्त किया
- भारत ने 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया 13 पदक
- भारत रिकॉर्ड 50 स्वर्ण पदकों के साथ एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर
- एजुकेट गर्ल्स 2025 मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय एनजीओ बन गया है।
- जीएसटी परिषद ने सितंबर 2025 से कर स्लैब को 5% और 18% तक सरल बनाया
- केरल आक्रामक सेना स्पेक्ट्राबिलिस के उन्मूलन में अग्रणी
- कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण के लिए ₹1,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी
- जीएम प्रणव वेंकटेश ने फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स 2025 जीता
- भारत ने पहली बार मेड-इन-इंडिया का अनावरण किया सेमीकॉन इंडिया'25 में 32-बिट प्रोसेसर
- भारत और जापान ने कार्बन व्यापार को मज़बूत करने, हरित निवेश को बढ़ावा देने और सतत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत एक ऐतिहासिक संयुक्त ऋण तंत्र (JCM) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- आईआईटी-मद्रास लगातार सातवें साल एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर
- सेल ने कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आर्ट ऑफ़ लिविंग के साथ साझेदारी की
- अडानी पावर, डुक ग्रीन भूटान में 6,000 करोड़ रुपये की जलविद्युत परियोजना स्थापित करेंगे
- एंड्रयू होलनेस जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरा कार्यकाल जीतेंगे
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा की
- श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
- अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा ने दो दशक के क्रिकेट करियर के बाद संन्यास लिया
- भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया
- सिंगापुर ने भारत की मलक्का जलडमरूमध्य गश्ती योजना का समर्थन किया
- अनुतिन चरनवीरकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए
- डेविड लैमी ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री नियुक्त
- सिटीबैंक ने कौस्तुभ कुलकर्णी को एशिया-प्रशांत आईबी का सह-प्रमुख नियुक्त किया
- आर गांधी को RBI द्वारा यस बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया
- स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को ब्रांड एंबेसडर बनाया
- आनंद वी. पाटिल को बेंगलुरु में प्रो. वी.के. गोकक पुरस्कार मिलेगा
- अमीश त्रिपाठी ने द चोला टाइगर्स: एवेंजर्स ऑफ़ सोमनाथ का शुभारंभ किया
- इतालवी फैशन आइकन जियोर्जियो अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन
- मैक्स वेरस्टेपेन ने 2025 इटैलियन ग्रां प्री जीती
- इज़राइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफ़ेक-19 लॉन्च किया
- लेवीज़ ने आलिया भट्ट को वैश्विक ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया
- एलडीपी की असफलताओं के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने इस्तीफा दिया
- रेनर के इस्तीफे के बाद डेविड लैमी ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री बने
- भारत ने कोरिया पर 4-1 की जीत के साथ चौथा पुरुष एशिया कप हॉकी खिताब जीता
- 102 वर्षीय कोकिची अकुज़ावा माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज़ व्यक्ति बने
- कार्लोस अल्काराज़ और आर्यना सबालेंका ने 2025 यूएस ओपन में खिताब जीते
- इरफ़ान अली गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए
- हरित अभियान के बीच भूपेंद्र गुप्ता एनएचपीसी के सीएमडी नियुक्त
- अनुपर्णा रॉय ने वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता
- अरुंधति रॉय की आत्मकथा 'मदर मैरी कम टू मी' का विमोचन
- भारत ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की कपाउंड तीरंदाजी में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता
- वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर का 63 वर्ष की आयु में निधन
- विश्वास मत के बाद फ्रांस्वा बायरू को फ्रांसीसी प्रधानमंत्री पद से हटाया गया
- भारत ने 4-1 से जीत के साथ एशिया कप 2025 हॉकी खिताब जीता
- बीजद नेता और विधायक राजेंद्र ढोलकिया का चेन्नई में 69 वर्ष की आयु में निधन

- भारत ने ओमान को हराकर सीएएफए नेशनल कप 2025 में कांस्य पदक जीता
- भारत की साक्षरता दर 2023-24 में बढ़कर 80.9% हो गई
- भूपेन हजारिका के लिए आरबीआई विशेष सिक्का जारी करेगा
- हर्षवर्धन चितले जनवरी 2026 से हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ नियुक्त
- अभिमन्यु मिश्रा: विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर
- रूस की एंटरोमिक्स कैसर वैक्सीन ने शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता दिखाई
- सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए
- प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए ₹1,600 करोड़ की राहत की घोषणा की
- HIRE अधिनियम 2025: भारत के 100 अरब डॉलर के आईटी निर्यात क्षेत्र को संभावित झटका
- इरफ़ान अली ने गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता
- कोल इंडिया और NSTFDC ने एकलव्य स्कूलों के माध्यम से आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- iDEX-DIO, EdCIL ने ASPIRE कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- भारतीय सशस्त्र बल रूस में ZAPAD 2025 अभ्यास में शामिल हुए
- 11वां गोला-बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल (ACTCM) बजरा, LSAM 25 (यार्ड 135) का शुभारंभ मेसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे में रियर एडमिरल विशाल बिश्रोई के मुख्य अतिथि के रूप में किया गया।
- डॉ. गीता वाणी रायसम ने एनआईएससीपीआर निदेशक का पदभार संभाला
- भारत ने दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय - आदि संस्कृति - शुरू किया
- मैक्रों ने सेबेस्टियन लोकोनू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया
- छात्र आत्महत्याओं से निपटने के लिए एम्स ने "नेवर अलोन" कार्यक्रम शुरू किया
- भारत, श्रीलंका ने मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- भारत और एडीबी ने सतत पर्यटन के लिए 126 मिलियन डॉलर के लोन पर हस्ताक्षर किए
- पीएम मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ राहत के लिए 1200 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की
- INS अरावली को गुरुग्राम में भारतीय नौसेना के नए बेस के रूप में शामिल किया गया।
- भारत की नॉन-फॉसिल फ्यूल पावर क्षमता 250 GW तक पहुंच गई।
- FSIB ने रवि रंजन को SBI के MD के लिए सिफारिश की।
- IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला विदेशी कैम्पस खोला।
- APEDA ने बिहार में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला।
- नेपाल को सुशीला कार्की के अंतरिम नेता के रूप में पहली महिला प्रधानमंत्री मिलेगी।
- प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति बने एआईआईए के डायरेक्टर
- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पवन कुमार शर्मा (1999 बैच, मध्य प्रदेश कैडर) को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया, और वी. ललितलक्ष्मी (2008 बैच, पश्चिम बंगाल कैडर) को उप-राष्ट्रपति सचिवालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया।
- विशाखा मुले आदित्य बिड़ला कैपिटल की एमडी और सीईओ बनीं
- भारतीय नौसेना ने एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शिप 'अंद्रोथ' को शामिल किया
- जैस्मिन लाम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग 2025 में स्वर्ण पदक जीता
- भारत ने स्विट्जरलैंड को हराकर 2026 डेविस कप के लिए क्वालीफाई किया
- मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डी.डी. लापांग का 91 वर्ष की आयु में निधन
- रिकी हैटन, बॉक्सिंग के दिग्गज का निधन
- टाटा ने नौसेना के लिए पहला स्पेनिश "लांजा-एन" 3D रडार बनाया
- न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
- आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली
- अल्बानिया ने दुनिया का पहला AI कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया
- अमित खरे को उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया
- कार्लोस फेलिप जारमिलो को वर्ल्ड बैंक के EAP VP के रूप में नियुक्त किया गया
- मुजफ्फरपुर स्टूडेंट इनोवेशन के लिए INSPIRE अवार्ड 2025 में टॉप पर
- INS निस्तर सिंगापुर में एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ
- मोहम्मद सिराज को ICC मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 चुना गया
- कलाक्षेत्र भरतनाट्यम गुरु शारदा हॉफमैन का 96 साल की उम्र में निधन
- EPFO के विवेकानंद गुप्ता को वर्ल्ड बैंक-मिलकेन PFAM प्रोग्राम के लिए चुना गया
- अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान ने संयुक्त "फ्रीडम एज" एक्सरसाइज शुरू की
- वैशाली रमेशबाबू लगातार दूसरी बार FIDE ग्रैंड स्विस् जीतीं
- चीनी एक्टर, सिंगर और डायरेक्टर एलन यू मंगलॉग का 37 साल की उम्र में निधन
- वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन: मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया ने गोल्ड जीता
- AIIMS दिल्ली पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज जो दा विंची रोबोट पर ट्रेनिंग देगा
- सबीता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनीं

- बॉक्सिंग लीजेंड रिगी हैटन का 46 साल की उम्र में निधन
- बाबा काल्यानी को इंजीनियरिंग लीडरशिप के लिए ASME होले मेडल से सम्मानित किया गया
- सेंट्रल ज़ोन ने 2025 दिलीप ट्रॉफी जीती, साउथ ज़ोन को 6 विकेट से हराया
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जॉब वर्गीकरण के लिए ILO के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए
- भारत ने डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित किया
- PNB ने श्री एम. परमशिवम का कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल बढ़ाया
- अपोलो टायर्स 579 करोड़ रुपये के सौदे में टीम इंडिया का नया प्रायोजक बना
- डॉ. सीमा बाहोस ने UN वूमैन में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया
- गिरी और वैशाली ने 2025 FIDE ग्रैंड स्विस् खिताब जीता
- नीरज घायवान की "होमबाउंड" को भारत की ऑस्कर एंट्री के लिए चुना गया
- असम की गायिका जुबिन गार्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 साल की उम्र में मौत
- भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स बनाने के लिए FAO के साथ साझेदारी की
- पीएम मोदी ने बिहार में सेक्स सॉर्टेड सीमन सुविधा का उद्घाटन किया
- अंतिम पंधल ने भारत के लिए विश्व चैंपियनशिप में दूसरा पदक जीता
- सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपसी रक्षा समझौता किया
- महाराष्ट्र ने छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फीट ऊंची प्रतिमा 'हिन्दू भूषण' का अनावरण किया
- मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर बनीं
- दक्षिण कोरिया और US ने कोरियाई परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता दोहराई
- गौरांगलाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया
- एम.के. स्टालिन ने अनाथ बच्चों के लिए 'अन्बु करंगल' योजना शुरू की
- भारत को कार्लबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के एक्सप्लोरेशन का विशेष अधिकार मिला
- न्यायमूर्ति पवनकुमार भीमप्पा बजंत्री ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली
- भारत 28वीं UPU कांग्रेस में एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए फिर से चुना गया
- मोहनलाल को 2023 दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया
- भारत ने मोरक्को में अपना पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया
- स्मृति मंधाना ने वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा
- आनंदकुमार वेलकुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा
- UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी
- NHAI ने टोल कर्मचारियों के बच्चों के लिए 'प्रोजेक्ट आरोहन' शुरू किया
- इंगे रुगिनिने लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री बनीं
- टेमर अबासगुलीयेव को नायारा एनर्जी का नया सीईओ नियुक्त किया गया
- मीराबाई चानू ने 2025 कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता
- फिडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा में होगा
- रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से संन्यास की चौकाने वाली घोषणा की
- जेएंडके बैंक ने एस कृष्णन को नया चेयरमैन नियुक्त किया
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना को पुनर्गठित किया, इसे 2030 तक बढ़ाया
- स्पेसएक्स ने स्टारशिप का 10वां सफल परीक्षण लॉन्च किया
- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कमजोर तबकों के लिए यूमेईडी मॉड्यूल लॉन्च किया
- भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए बड़ी OSAT सुविधा शुरू की
- मास्टरकार्ड और इंफोसिस ने क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की
- दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया
- उर्जित पटेल को 3 साल के कार्यकाल के लिए IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया
- OpenAI ने पूर्व Coursera प्रमुख राघव गुप्ता को भारत और एपीएसी के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया
- भारत और भूटान ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- Google ने 'नैनो बनाना' AI फोटो एडिटिंग टूल लॉन्च किया
- डाक विभाग ने DIGIPIN को लागू करने के लिए मैपमाईइंडिया के साथ साझेदारी की
- TCS ने AI यूनिट लॉन्च की, अमित कपूर को प्रमुख नियुक्त किया
- अजय बाबू वल्लूरी ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता

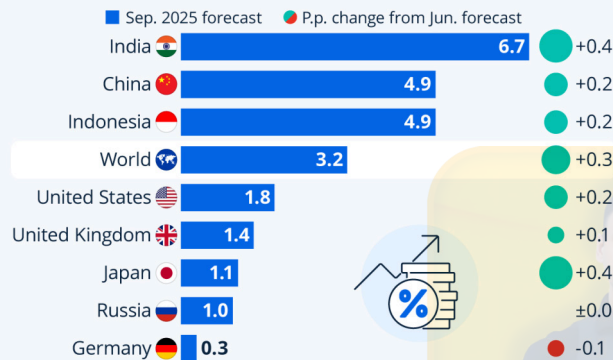
"जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की !
उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की !!"

"तक्रदीर बदल जाती है, जब जिन्दगी का हो कोई मक़सद !
वरना उम्र कट जाती है, तक्रदीर को इल्जाम देते देते !!"

इन्फोग्राफिक्स

OECD Raises India's GDP Growth Forecast to 6.7 Percent

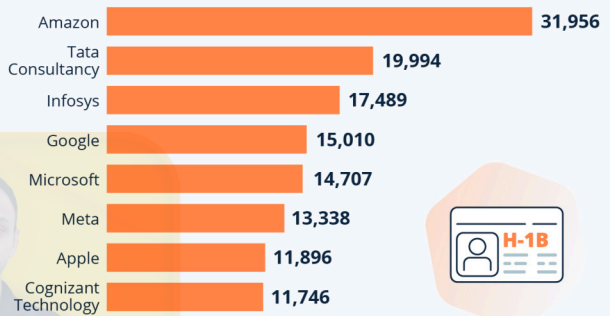
Real GDP growth projections compared to the previous year in selected countries (in percent)



Source: OECD Economic Outlook

Tech Giants Rely Heavily on H-1B Program

Top 8 employers of approved H-1B beneficiaries from FY 2023 to FY 2025*

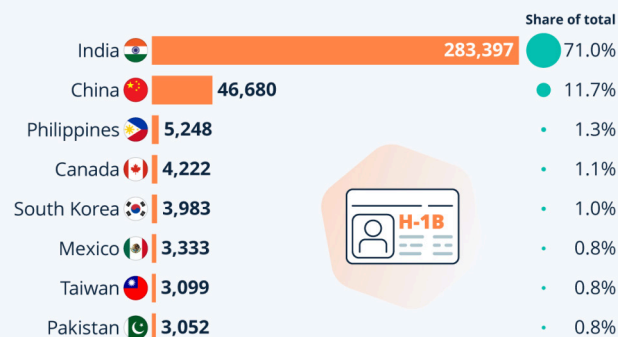


* Data as of June 30, 2025; figures may not include all subsidiaries
Source: U.S. Citizenship and Immigration Services

KUMAR
EDUTAINMENT

H-1B Visas Are the Main Pathway for Indian Tech Talent

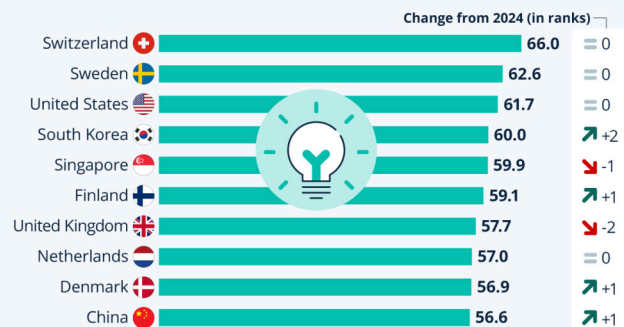
Origin countries of H-1B visa recipients in FY 2024*



* The H-1B is a non-immigrant, i.e. temporary visa that allows U.S. companies to employ foreign workers in high-skilled specialty occupations.
Source: U.S. Citizenship and Immigration Services

China Enters Top 10 of Most Innovative Countries

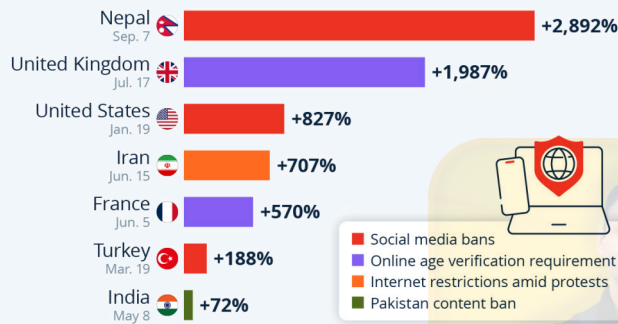
2025 ranking of the Global Innovation Index (100=most innovative)



Takes into account human capital, institutions, technology and creative output, market and business sophistication, among others
Source: World Intellectual Property Organization

Where VPN Demand Surged Due to Internet Blocks in 2025

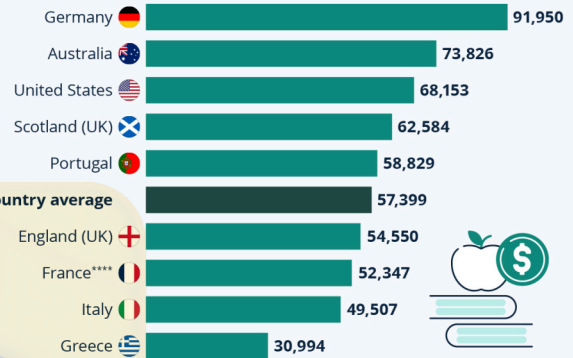
Increase in the search volume for VPNs* during global events in 2025 to date



* Compared with daily average of previous 30 days (or most similar time period possible)
 Source: Top10VPN

How Much Are Teachers Paid?

Average annual salaries* of primary school teachers** in selected countries in 2024 (in U.S. dollars***)

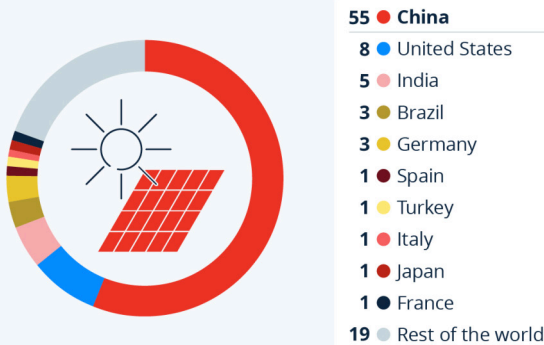


Source: OECD Education at a Glance

**KUMAR
EDUTAINMENT**

China Is the World Leader in Solar PV Deployment

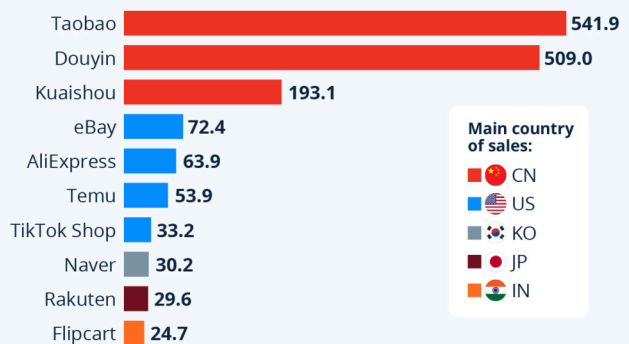
Share of total installed solar capacity in 2024, by country (in %)



Source: SolarPower Europe

The World's Biggest Online Marketplaces

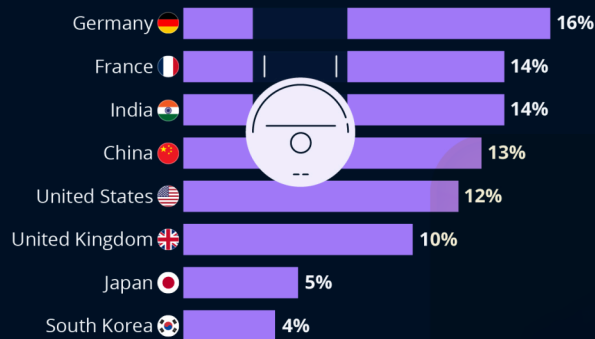
Online platforms with the biggest third-party gross merchandise volumes globally in 2024 (in US\$ billion)



Source: ECDB

Where Robots Do the Housework

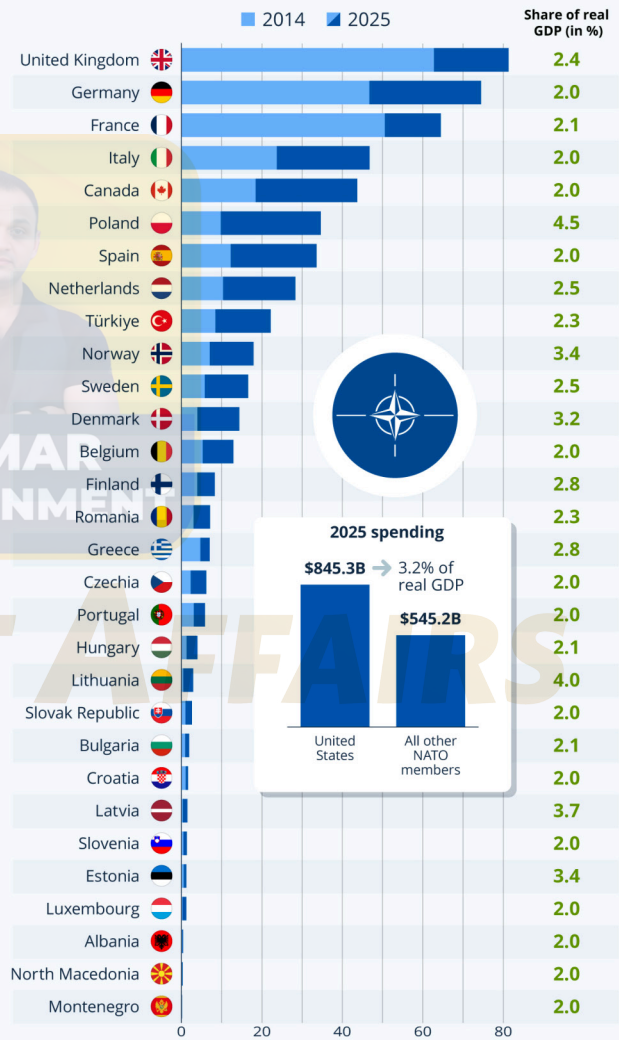
Share of respondents in selected countries who own a robot vacuum or a lawn-mowing robot



1,880 to 9,400 adults (18 - 64 y/o) surveyed per country Jul. 2024 - Jun. 2025
Source: Statista Consumer Insights

All NATO Members To Reach 2-Percent Goal in 2025

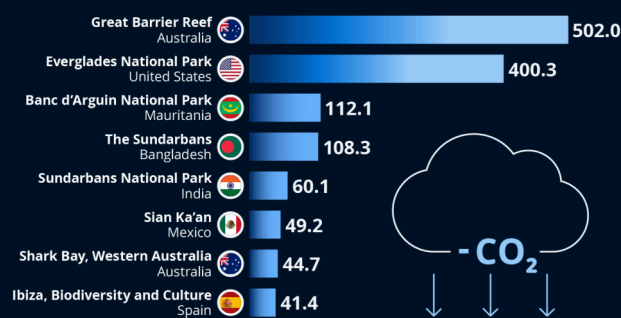
Estimated military spending of NATO countries in 2014 and 2025 (in billion constant 2021 U.S. dollars)



Germany: 2024 latest available
NATO member Iceland has no armed forces. Sweden, Finland, North Macedonia, Montenegro became members after 2014. Estimates as of mid-year
Source: NATO

The Biggest Protected Blue Carbon Sinks on Earth

Estimated blue carbon* stocks in UNESCO marine World Heritage Sites (in million tonnes of carbon)



As of 2021

* Blue carbon ecosystems include seagrass meadows, tidal marshes and mangroves

Source: UNESCO Marine World Heritage



Kumar Edutainment Presents

CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

 7 Jawahar Nagar, Khandari, Agra, Uttar Pradesh

 8882388888

 Kumariasacademy@gmail.com

 kumarsias.com

   Kumar Edutainment

 your_kumar_sir



Kumar Edutainment